सत्यमेव जयते

दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर निष्पादन लेखापरीक्षा

पर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन सं. 1

दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर निष्पादन लेखापरीक्षा

पर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन सं. 1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना		ix
कार्यकारी सारांश		xi
अध्याय I: परिचय		
परिचय	1.1	1
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.2	4
लेखापरीक्षा मानदंड	1.3	4
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.4	5
प्रतिवेदन की संरचना	1.5	6
अध्याय II: आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली		
परिचय	2.1	9
ईएससीआईएमएस का शराब की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ	2.2	12
बारकोड की स्कैनिंग को लागू करने के कमजोर प्रयासों के साथ 'स्टॉक-टेक-सोल्ड' अभ्यास ने ईएससीआईएमएस के उद्देश्य को विफल कर दिया	2.2.1	12
ईएससीआईएमएस डेटा के माध्यम से पूनरावृत चूककर्ता की पहचान करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना	2.2.2	14
अप्रयुक्त बारकोड्स के दुरुपयोग की संभावना	2.2.3	16
बारकोड्स को स्कैन किए बिना बिक्री प्रमाणित करने से जुड़े जोखिम	2.2.4	18
दुकान बिक्री डेटा विश्लेषण	2.2.5	18
कार्यान्वयन एजेंसी को ₹ 24.23 करोड़ का अनुचित लाभ	2.3	22
ईएससीआईएमएस के ईआईबी मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जाना	2.4	23
सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया	2.5	24
निकास प्रबंधन योजना का अभाव	2.6	25

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
विभाग द्वारा पीएमयू की भूमिका संभालने के बाद निगरानी का अभाव	2.7	26
एक्साइज ऐडहेसिव लेबल लागू करने में विफलता	2.8	27
निष्कर्ष	2.9	29
अध्याय III: लाइसेंस जारी करना		
परिचय	3.1	31
संबंधित पक्षों को लाइसेंस अनियमित रूप से जारी करना	3.2	32
आपराधिक पृष्ठभूमि के सत्यापन के बिना लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करना	3.3	35
जारी किए गए लाइसेंस के अनुवीक्षण के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों की गैर-अनुपालना	3.4	36
लाइसेंसधारियों की शोधनक्षमता सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करना	3.5	37
यह सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करना कि लाइसेंसधारी पर कोई सरकारी बकाया नहीं है	3.6	39
लाइसेंसधारियों द्वारा नियोजित व्यक्तियों के सत्यापन के बिना लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करना	3.7	41
एल1 लाइसेंसधारियों से जमानत के साथ व्यक्तिगत बांड प्राप्त किए बिना लाइसेंस जारी/नवीकरण करना	3.8	42
लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए बिना एल1एफ लाइसेंस जारी करना	3.9	43
बिक्री डेटा और थोक बिक्री मूल्य (डब्ल्यूएसपी) प्रस्तुत किए बिना एल1 और एल1एफ लाइसेंस जारी करना	3.10	43
"बाल्टिक 9" बियर की आपूर्ति के लिए एल1एफ लाइसेंस देने में अनियमितता	3.11	45
परिसर/विक्रेता का कानूनी कब्ज़ा सुनिश्चित किए बिना अनियमित रूप से लाइसेंस	3.12	46
आग और प्राकृतिक आपदा के खिलाफ बीमा सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी करना	3.13	48

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
सीसीटीवी सिस्टम सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी करना	3.14	50
लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए परिपत्र में उल्लिखित शर्तों के संबंध में घोषणा के बिना लाइसेंस जारी करना	3.15	51
पर्यटन विभाग से अपेक्षित अनुमोदन के बिना लाइसेंस जारी करना	3.16	52
निष्कर्ष	3.17	52
अध्याय IV: भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) तथा विदेशी शराब (एफएल) का मूल्य निर्धारण		
परिचय	4.1	55
आबकारी विभाग द्वारा आईएमएफएल की ईडीपी/ईबीपी को विनियमित नहीं किया गया	4.2	56
ईडीपी/ईबीपी की तर्कसंगतता सुनिश्चित नहीं की गयी	4.2.1	57
दिल्ली में अन्य राज्यों की तुलना में उच्च ईडीपी/ईबीपी का निर्धारण	4.2.2	58
विदेशी शराब के लाइसेंसधारियों को विवेकाधीन लाभ मार्जिन	4.3	59
निष्कर्ष	4.4	60
अध्याय V: गुणवत्ता मानदंडों का उल्लंघन		
परिचय	5.1	61
एफएसएसएआई अधिनियम/बीआईएस मानदंडों में लाइसेंस की शर्तों में अस्पष्टता/गुणवत्ता नियंत्रण का अनुपालन न होना	5.2	62
आबकारी विभाग द्वारा अमान्य गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणपत्रों की स्वीकृति	5.3	64
अनिवार्य गुणवत्ता मानदंडों का पालन नहीं करने के बावजूद लाइसेंस जारी करना	5.4	66
बीआईएस मानदंडों का पालन नहीं करने के बावजूद एल1 लाइसेंस (आईएमएफएल) जारी करना	5.4.1	66
गुणवत्ता आश्वासन के बिना एल1एफ लाइसेंस प्रदान करना तथा विदेशी शराब की आपूर्ति करना	5.4.2	68

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत संदिग्धता परीक्षण प्रमाणपत्र आबकारी विभाग द्वारा स्वीकार किए गए	5.5	71
गलत श्रेणी में ब्रांड का अनियमित पंजीकरण	5.6	73
पुराने प्रमाणपत्र के आधार पर लाइसेंस का अनियमित निर्गमन	5.7	74
निष्कर्ष	5.8	74
अध्याय VI: आबकारी खुफिया ब्यूरो और जब्ती		
परिचय	6.1	75
ईआईबी डेटा का विश्लेषण	6.2	76
देशी शराब खरीद में ढांचागत कमजोरियां जो इसकी तस्करी को बढ़ावा दे रही है	6.3	77
जब्ती शाखा की भूमिका और ईआईबी के साथ समन्वय का अभाव	6.4	79
अन्य कमियां और समन्वय का अभाव	6.5	82
निष्कर्ष	6.6	84
अध्याय VII: प्रवर्तन		
परिचय	7.1	87
प्रवर्तन प्रक्रिया और परिणाम में कमियां	7.2	89
निरीक्षण के लिए योजना और निर्धारित प्रक्रियाओं का अभाव	7.2.1	90
निरीक्षण का संचालन	7.2.2	92
निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) में विसंगतियाँ	7.2.3	96
निरीक्षण रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई	7.2.4	97
बार-बार उल्लंघन करने पर सजा नहीं बढ़ाई गई	7.2.5	100
निष्कर्ष और अनुशंसाएं	7.3	101
अध्याय VIII: आबकारी नीति 2021-22		
परिचय	8.1	104
आबकारी नीति 2021-22 के उद्देश्य	8.1.1	104
आबकारी नीति 2021-22 की विशेषताएं	8.1.2	105
आबकारी नीति 2021-22 में घटनाओं का कालक्रम	8.2	106

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना लिए गए निर्णय	8.2.1	107
विशेषज्ञ समिति और मंत्री समूह की सिफारिशों के रिपोर्ट की बीच अंतर	8.2.2	108
केवल निजी खिलाड़ियों को थोक (एल-1) लाइसेंस जारी करना	8.2.2.1	109
आबकारी शुल्क को शराब की वास्तविक बिक्री से अलग कर दिया जाना	8.2.2.2	110
सीमित निकायों को खुदरा लाइसेंस	8.2.2.3	110
पुरानी आबकारी नीति तथा नई आबकारी नीति की तुलना	8.2.3	110
आबकारी नीति 2021-22 में राजस्व मॉडल	8.3	112
लाइसेंस का डिज़ाइन और प्रदान करना	8.4	112
थोक लाइसेंस	8.4.1	113
लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया	8.4.1.1	113
विशिष्टता व्यवस्था से एकाधिकार का खतरा बढ़ रहा है	8.4.1.2	114
थोक परिचालन से राजस्व	8.4.1.3	114
संयुक्त उद्यम भागीदारी की प्रकृति	8.4.1.4	115
जोनल/रिटेल लाइसेंस	8.4.2	116
थोक और खुदरा लाइसेंसधारियों की संख्या में कमी के कारण एकाधिकार का बढ़ता खतरा	8.4.2.1	117
बोली दस्तावेजों के माध्यम से क्षेत्रीय लाइसेंस आवेदनों की व्यवहार्यता, सुनिश्चित नहीं की गई	8.4.2.2	118
ए7-जेड जोनल लाइसेंस की नवीकरणीय प्रकृति	8.4.2.3	119
जोनल लाइसेंस सरेंडर करने के लिए नीति प्रावधान का अभाव	8.4.2.4	120
निविदा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच नहीं की गई	8.4.2.5	120
आपूर्ति श्रृंखला में लाइसेंस रखने वाली संबंधित व्यावसायिक निकाय	8.4.3	121

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
संबंध निर्धारित करने के लिए मानदंड के दायरे को सीमित करना	8.4.3.1	122
संबध की पहचान करने के लिए अपर्याप्त दस्तावेजीकरण और विश्लेषण	8.4.3.2	123
विशिष्टता व्यवस्था और ब्रांड पुशिंग को जोखिम	8.4.4	124
लगभग ₹ 2,002.68 करोड़ की राशि का नुकसान	8.5	130
समय पर अनुमति न लेने के कारण लगभग ₹ 941.53 करोड़ के राजस्व का नुकसान	8.5.1	130
सरेंडर जोनों की दोबारा निविदा नहीं की गई जिससे लगभग ₹ 890.15 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ	8.5.2	132
जोनल लाइसेंसधारियों को कोविड के कारण छूट के अनियमित अनुदान के कारण ₹ 144 करोड़ के राजस्व का नुकसान	8.5.3	132
जोनल लाइसेंसधारियों से सुरक्षा जमा की गलत वसूली के परिणामस्वरूप लगभग ₹ 27 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ	8.5.4	134
अन्य मुद्दे	8.6	136
सुपर प्रीमियम दुकानों के लिए निविदा जारी नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर नहीं मिला	8.6.1	136
गैर-अनुरूपता वाले वार्डों में दुकानों को अनियमित खोलना	8.6.2	136
लंबित लाइसेंस शुल्क राशि की गणना में विसंगतियाँ	8.6.3	137
निगरानी और विनियमन के लिए उपायुक्त (थोक परिचालन) का महत्वपूर्ण पद निर्दिष्ट नहीं किया गया	8.6.4	138
आपूर्ति की गई शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई	8.6.5	139
दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र में शराब की बिक्री और खुदरा दुकानों के भौगोलिक वितरण के रुझान	8.6.6	143
आबकारी खुफिया ब्यूरो और जब्ती	8.6.7	144
निष्कर्ष	8.7	144

अनुलग्नक

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
I	नमूनीकृत	1.4	147
II	बिना स्कैनिंग के बिक्री के उच्च प्रतिशत वाले मामले	2.2.2	148
III	सामान्य निदेशक (समान वर्ष)	3.2	149
IV	सामान्य निदेशक (पिछले पांच वर्ष)	3.2	152
V	संदिग्ध एकाधिक खुदरा लाइसेंस	3.2	164
VI	ईडीपी में विवेकाधीन वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप बिक्री में गिरावट के कारण आबकारी राजस्व में गिरावट	4.2.1	165
VII	परीक्षण प्रयोगशालाओं का विवरण	5.3	182
VIII	एल1 लाइसेंसधारियों की परीक्षण रिपोर्ट का विवरण	5.4.1	183
IX	एल1एफ लाइसेंसधारी की परीक्षण रिपोर्ट का विवरण	5.4.2	185
X	निरीक्षण रिपोर्ट में स्टॉक संबंधी टिप्पणियों का सारांश	7.2.2 (ii)	187
XI	संदिग्ध बोतलों की स्थिति (एचसीआर)	7.2.2 (iii)	191
XII	संदिग्ध बोतलों की स्थिति (खुदरा विक्रेता)	7.2.4 (i)	192
XIII	अन्य विक्रेताओं को जारी एससीएन की स्थिति	7.2.4 (iii)	193
XIV	बार-बार होने वाले उल्लंघनों का सारांश	7.2.5	194
XV	कैबिनेट की मंजूरी और/या उपराज्यपाल की राय लिए बिना लिया गया फैसला	8.2	197
XVI	क्रॉस स्वामित्व	8.4.3.1	199
XVII	नॉन कॉन्फार्मिंग वार्डों में खुले जोन-23 की दुकानें	8.6.2	201

प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राराक्षे) दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के समक्ष रखा जा सके।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में परिकल्पना की गई है कि 'शराब' का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री राज्य सरकारों के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। तदनुसार, आबकारी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (राराक्षेदिस) दिल्ली में शराब की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। आबकारी विभाग शराब की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक नियंत्रित करता है। इस आपूर्ति श्रृंखला में कई हितधारक शामिल हैं जैसे, निर्माता (डिस्टिलरी और ब्रुअरीज), गोदाम, खुदरा विक्रेता (बिक्री केंद्र), होटल, क्लब और रेस्तरां (सेवा केंद्र), और अंततः उपभोक्ता। आबकारी विभाग दिल्ली में शराब की आपूर्ति पर उत्पाद शुल्क और कई अन्य शुल्क जैसे लाइसेंस शुल्क, परमिट शुल्क, आयात शुल्क आदि वसूल करता है। इस प्रतिवेदन में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली (ईएससीआईएमएस), लाइसेंसिंग नीति और लाइसेंस जारी करना, मूल्य निर्धारण नीति, गुणवत्ता नियंत्रण, आबकारी खुफिया ब्यूरो और जब्ती तथा आबकारी विभाग के प्रवर्तन शाखा के कामकाज से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है। नवंबर 2021 के बाद से आबकारी नीति व्यवस्था में व्यापक बदलाव के कारण और 01 सितंबर 2022 से इसकी वापसी को इस रिपोर्ट के दायरे में शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में ईएससीआईएमएस के माध्यम से शराब की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग के द्वारा अधिक कुशल विनियमन को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में विभिन्न कमियों को इंगित किया गया है। आबकारी विभाग ने विभिन्न लाइसेंसधारियों को आबकारी अधिनियम/नियमों एवं शर्तों के अनुसार विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन किये बिना लाइसेंस जारी किये। इसके अलावा, नियमों के उल्लंघन में, संबंधित पार्टियों (जिनमें कॉमन निदेशक हैं) को कई लाइसेंस जारी किए गए थे। भारत निर्मित विदेशी शराब के एक्स-डिस्टिलरी कीमत/एक्स ब्रुअरी कीमत

की औचित्यता सुनिश्चित करने के लिए लागत विवरण नहीं मांगा गया था। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानदंडों के अनुरूप परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के बावजूद थोक लाइसेंस के आवेदकों को लाइसेंस जारी किए गए थे। प्रवर्तन मामलों में, यह देखा गया कि संदिग्ध स्टॉक के चयन में कोई अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। प्रवर्तन शाखा में निरीक्षण रजिस्टर का खराब रखरखाव था। आबकारी नीति वर्ष 2021-22 के संबंध में, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नीति के कार्यान्वयन में कमी के साथ-साथ इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने में नीति की विफलता और इसकी अंतिम रूप से वापसी में योगदान करने वाले मुद्दों की ओर इंगित करता है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर राजस्व में आबकारी विभाग एक प्रमुख योगदानकर्ता (लगभग 14 *प्रतिशत*) है। राजस्व संग्रह की अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को पूरा करने के अलावा, विभाग शराब और नशीले पदार्थों के व्यापार को नियंत्रित और विनियमित करता है तथा उपभोक्ताओं को आवश्यक गुणवत्ता आश्वासन के साथ इसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। 1 जुलाई 2017 से, "मानव उपभोग के लिए शराब" को छोड़कर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर आबकारी को जीएसटी के तहत शामिल कर लिया गया था, इस प्रकार आबकारी विभाग के लिए राजस्व संग्रह मुख्य रूप से शराब की बिक्री से होता है।

शराब की आपूर्ति और वितरण में कई हितधारक जैसे- निर्माताओं/डिस्टिलरी (दिल्ली के बाहर स्थित) से शुरू होकर दिल्ली में स्थित संबंधित बॉण्डेड वेयरहाउस और फिर विभिन्न निगमों की दुकानें, निजी दुकानें, होटलों, क्लबों और रेस्तरां और अंत में उपभोक्ताओं आदि शामिल हैं। हितधारकों की बहुलता के अलावा, यहाँ शीर्षों की बहुलता है जिसके अंतर्गत आबकारी विभाग शराब उत्पादों पर राजस्व, अर्थात आबकारी शुल्क, लाइसेंस शुल्क, परमिट शुल्क, आयात/निर्यात शुल्क आदि एकत्र करता है। इसमें शराब की आपूर्ति की निगरानी, नियंत्रण और विनियमन के लिए एक जटिल आपूर्ति श्रृंखला तंत्र शामिल है। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार की शराब और नशीले पदार्थ (देशी शराब, भारत निर्मित विदेशी शराब, विदेशी शराब, विकृत स्प्रिट और नशीले पदार्थ) विभिन्न करों, मूल्य निर्धारण और प्रशासनिक तंत्र के अधीन हैं। “दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति” पर यह निष्पादन लेखापरीक्षा शराब पर आबकारी शुल्क का महत्व और राज्य की राजकोषीय स्थिति पर प्रभाव के कारण की गई है।

लेखापरीक्षा ने दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति की विस्तार से जांच करने के लिए 2017-18 से 2020-21 तक चार वर्षों की अवधि को कवर किया है। अध्याय VI में जब्ती गतिविधि के संबंध में देशी शराब की आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान दिया गया है। नवंबर 2021 से आबकारी नीति व्यवस्था में व्यापक बदलाव और इसके बाद 01 सितंबर 2022 से इसकी वापसी के कारण आबकारी नीति 2021-22 को इस रिपोर्ट के अध्याय VIII में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आबकारी विभाग द्वारा शराब की आपूर्ति की निगरानी और विनियमन के तरीके में कई विसंगतियां देखीं। आबकारी

विभाग की कार्यप्रणाली विभाग द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाने के तरीके पर कई सवाल खड़े करती है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल वित्तीय प्रभाव लगभग ₹ 2,026.91 करोड़ है।

(क) 2017-21 की अवधि के लिए आबकारी नीति में मुद्दे

- ***लाइसेंस प्रदान करने में उल्लंघन***

विभाग थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, होटल, क्लब और रेस्तरां (एचसीआर) आदि को कई प्रकार के लाइसेंस जारी करता है और वर्ष के लिए संबंधित लाइसेंस श्रेणी के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अधीन वार्षिक लाइसेंस जारी या नवीनीकृत करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 35 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित नहीं कर सका, जो संबंधित पक्षों को विभिन्न श्रेणी (थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, एचसीआर आदि) के कई लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाता है, जिससे विभिन्न लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं के बीच कॉमन निदेशन का अस्तित्व कायम हो जाता है।

इसके अलावा विभाग विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी करने के लिए आबकारी नियमों और नियमों एवं शर्तों से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं की जांच किए बिना लाइसेंस जारी कर रहा था। यह देखा गया कि सॉल्वेंसी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण जमा करने, अन्य राज्यों में और साल भर में घोषित बिक्री और थोक मूल्य के बारे में डेटा जमा करने, सक्षम प्राधिकारी से आपराधिक पृष्ठभूमि का सत्यापन आदि सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी किए गए थे।

यह अनिवार्य है कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के बीच क्रॉस स्वामित्व और प्रॉक्सी स्वामित्व के मामलों को कॉमन निदेशन, *प्रतिशत* शेयर-होल्डिंग, कंपनियों को असुरक्षित ऋण जैसे मानदंडों के आधार पर सख्ती से निपटाया जाए ताकि शराब व्यापार और ब्रांड प्रचार में गुटबंदी जैसी अनुचित प्रथाओं से बचा जा सके। इसके अलावा, लाइसेंस जारी करते समय विभिन्न नियमों और विनियमों के चयनात्मक पालन प्रक्रिया का गैर-अनुपालन है और इसके उल्लंघन के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

- ***आईएमएफएल के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता का अभाव***

इष्टतम आबकारी राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए शराब का मूल्य निर्धारण महत्वपूर्ण था। आबकारी विभाग ने एल1 लाइसेंसधारी (निर्माता और थोक विक्रेता) को एक निश्चित स्तर से ऊपर की कीमत वाली शराब के लिए अपनी एक्स-डिस्टिलरी प्राईस (ईडीपी) घोषित करने की छूट दी। निर्माण के बाद के सभी मूल्य घटकों, निर्माता के लाभ सहित, को उसके बाद जोड़ा गया था। लेखापरीक्षा में एक ही निर्णाता द्वारा आपूर्ति की गई शराब के लिए विभिन्न राज्यों में अलग-अलग ईडीपी देखी गई। इसके अलावा, इस विवेकाधिकार ने एल1 लाइसेंसधारी को ईडीपी में वृद्धि के माध्यम से अपने लाभ के लिए शराब की कीमतों में हेरफेर करने की अनुमति दी। कुछ ब्रांडों के मूल्य निर्धारण और बिक्री के विश्लेषण से पता चला कि विवेकाधीन ईडीपी के कारण बिक्री में गिरावट आई और परिणामस्वरूप आबकारी राजस्व में नुकसान हुआ। चूंकि ईडीपी की तर्कसंगतता का पता लगाने के लिए लागत विवरण नहीं मांगा गया था, इसलिए बढ़े हुए ईडीपी में छिपे मुनाफे से एल1 लाइसेंसधारी को मुआवजा मिलने का जोखिम था।

ईडीपी की अवधारणा को पारदर्शी रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है और घोषित ईडीपी के समर्थन में लागत पत्रकों को प्राप्त किया जाना चाहिए। विभाग को बिक्री पर मूल्य निर्धारण के प्रभाव का विश्लेषण करके मूल्य निर्धारण को विनियमित करना चाहिए ताकि आबकारी राजस्व का अनुकूलन किया जा सके।

- ***अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण***

यह सुनिश्चित करना कि दिल्ली में आपूर्ति की जाने वाली शराब निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है, आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है। मौजूदा नियामक ढांचे में प्रासंगिक प्रावधान शामिल हैं जो थोक लाइसेंसधारियों (एल1) के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के प्रावधानों के अनुसार, लाइसेंस जारी करने के समय विभिन्न परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाता है, चूंकि आबकारी आयुक्त ने अलग गुणवत्ता विनिर्देश जारी नहीं किए थे। लेखापरीक्षा में ऐसे कई मामले देखे गए जहां परीक्षण रिपोर्ट बीआईएस विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं थीं और आबकारी विभाग ने बड़ी कमियों के बावजूद लाइसेंस जारी किए। विभिन्न ब्रांडों के लिए पानी की गुणवत्ता, हानिकारक तत्व, भारी धातु, मिथाइल अल्कोहल, सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण रिपोर्ट आदि की महत्वपूर्ण परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गईं। इसके

अलावा, कुछ लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से नहीं थी। नमूना जांच की गई रिपोर्टों की जांच के दौरान त्रुटिपूर्ण परीक्षण प्रमाण-पत्र भी देखे गए। विदेशी शराब से संबंधित नमूना जांच की गई रिपोर्टों में से 51 *प्रतिशत* के संबंध में, यह पाया गया कि प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्टें एक वर्ष से अधिक पुरानी थीं/या कोई परीक्षण रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई थी/तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था।

इसकी तत्काल आवश्यकता है कि आबकारी विभाग सक्रिय रूप से शराब की गुणवत्ता की निगरानी करे और सख्त गुणवत्ता मानक बनाए और उनका अनुपालन सुनिश्चित करे।

- ***कमजोर नियामक कार्यप्रणाली***

विभाग द्वारा नियामक और प्रशासनिक कार्यों का प्रभावी और कुशल अभ्यास समय पर राजस्व रिसाव की पहचान करने और उसे रोकने और शराब की तस्करी के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आबकारी विभाग की भूमिका काफी हद तक जब्ती का रिकॉर्ड बनाने और केस संपत्ति के निपटान तक सीमित थी और डेटा से पता चला कि आबकारी खुफिया ब्यूरो (ईआईबी) एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करने में विफल रहा। विभाग द्वारा अनुरक्षित डेटा खंडित और अल्पविकसित था, जिसका कोई विश्लेषणात्मक मूल्य नहीं था, जिससे डेटा संचालित कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के किसी भी प्रयास में बाधा उत्पन्न हुई।

ईआईबी द्वारा जब्त की गई कुल शराब का 65 *प्रतिशत* भाग देशी शराब है, जो सबसे अधिक जब्त की गई शराब है। देशी शराब की तस्करी का कारण काफी हद तक संरचनात्मक था, जिसमें आपूर्ति की गई शराब के कोटे बोतल के आकार की उपलब्धता और सीमित संख्या में ब्रांडों की मौजूदगी पर आपूर्ति पक्ष की बाधा शामिल थी। दर्ज एफआईआर के विश्लेषण से एक पैटर्न का पता चला है कि कुछ क्षेत्र तस्करी के लिए हॉटस्पॉट हैं, और कुछ क्षेत्रीय ब्रांडों की तस्करी की शराब में भारी हिस्सेदारी है।

शराब तस्करी के हॉटस्पॉट, इसमें शामिल ब्रांड, तस्करी के संभावित कारण, अनुमानित राजस्व रिसाव आदि की पहचान करने के लिए जब्ती और ईआईबी मामलों के मामले-वार एकत्रित आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए। अन्य राज्य आबकारी प्रवर्तन मशीनरी के साथ एक समन्वित कार्रवाई से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।

- ***प्रवर्तन कार्य का ख़राब निष्पादन***

एक निवारक के रूप में अपनी भूमिका के अलावा, प्रवर्तन को दिल्ली आबकारी अधिनियम/नियमों आदि के उल्लंघन के लिए मौजूदा लाइसेंसधारियों को दंडित करना चाहिए। कई महत्वपूर्ण कमजोरियां देखी गईं, जो उल्लंघन को उचित रूप से दंडित करने या आगे के उल्लंघनों के खिलाफ पर्याप्त निवारक के रूप में कार्य करने की विभाग की क्षमता में बाधा उत्पन्न की। वास्तविक छापे विवेकाधीन थे और किसी मानक संचालन प्रक्रिया के अभाव में खंडित थे। इसके अलावा, ईएससीआईएमएस डेटा के उपयोग सहित साक्ष्य संग्रह और पुष्टिकरण में सख्ती की कमी ने मामलों को शुरुआत में कमजोर स्थिति में डाल दिया। प्रवर्तन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में गलत निरीक्षण रिपोर्ट से लेकर अपर्याप्त कारण बताओ नोटिस तक कमियां देखी गईं।

मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण, सावधानीपूर्वक साक्ष्य संग्रह तथा जांच एवं मामलों के शीघ्र निपटान से लेकर प्रवर्तन कार्य को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रवर्तन कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण रिपोर्टों और उसके बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

- ***इन्वेंटरी की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग में कमियां***

सभी हितधारकों के लिए इन्वेंट्री की बारकोड आधारित ट्रैकिंग और भुगतान समाधान के लिए दिसंबर 2013 में एक आईटी सक्षम प्रणाली चालू की गई थी। ईएससीआईएमएस का प्राथमिक उद्देश्य हर चरण में बारकोड कैप्चर के माध्यम से शराब की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग सुनिश्चित करना और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर बिक्री का प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना था। हालाँकि, स्कैनिंग के माध्यम से सभी शराब की बिक्री सुनिश्चित करने में विभाग की असमर्थता के कारण बिक्री के बाद

स्टॉक समाधान (मासिक स्टॉक सुलह - एमएसआर गैप) को अपनाया गया जो अनुबंध समझौते के दायरे से बाहर था। इस समाधान प्रक्रिया ने बिक्री डेटा में विभिन्न विसंगतियां उत्पन्न कीं और इन्वेंट्री ट्रैकिंग, डेटा सटीकता, नियामक प्रभावशीलता को कम कर दिया और डुप्लिकेट बारकोड के उपयोग के माध्यम से गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब के प्रसार के जोखिम को भी बढ़ा दिया।

इसके अलावा, लेबल की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक्साइज एडहेसिव लेबल की परियोजना को लागू नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति पक्ष की प्रामाणिकता, पता लगाने की क्षमता और सुरक्षा पहलुओं का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सका।

पुरानी एमएसआर-गैप विधि को रीयल टाइम एंड-टू-एंड बारकोड ट्रैकिंग से बदलने की आवश्यकता थी। बारकोड डुप्लिकेसी और दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षित बारकोड लेबल को तेजी से लागू किया जाना चाहिए। असंगत डेटा और आसान पहचान के लिए रेड फ्लैग्स के स्वचालित उत्पत्ति और विश्लेषण में मदद के लिए डेटा विश्लेषणात्मक उपकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम को अभिनियोजित किया जाना चाहिए।

(बी) नई आबकारी नीति (2021-22) में मुद्दे

वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति प्रकट रूप से जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई थी, उसमें शराब व्यापार में किसी भी एकाधिकार या कार्टेल का गठन न होने देना, दिल्ली के सभी वार्डों/क्षेत्रों में शराब की आपूर्ति की समान पहुंच सुनिश्चित करना और किसी भी प्रॉक्सी मॉडल का सहारा लिए बिना पारदर्शी तरीके से व्यापार करने हेतु उद्योग में जिम्मेदार खिलाड़ियों को अनुमति देना और नकली शराब की बिक्री को खत्म करने और अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम करना शामिल था।

- ***आबकारी नीति के निर्माण में खामियाँ***

नई आबकारी नीति के निर्माण हेतु परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को इसके गठन के दौरान नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका औचित्य उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। इन बदलावों में राज्य के स्वामित्व वाली थोक बिक्री इकाई के बजाय निजी संस्थाओं को थोक लाइसेंस देना,

प्रति बोतल लगने वाले आबकारी के स्थान पर लाइसेंस शुल्क में आबकारी शुल्क की अग्रिम वसूली, एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानें आवंटित करने के बजाए आवेदक को अधिकतम 54 खुदरा दुकानें प्राप्त करने की अनुमति दिया जाना शामिल था।

इसके अलावा, कैबिनेट के फैसले का उल्लंघन करते हुए, राजस्व निहितार्थ वाली महत्वपूर्ण छूट/रियायत देने से पहले कैबिनेट से आवश्यक अनुमति/उपराज्यपाल की राय प्राप्त नहीं की गई थी।

- ***लाइसेंस के डिजाइन और प्रदान में मुद्दा***

नीति का एक उद्देश्य एकाधिकार या कार्टेल के गठन को रोकना था। हालाँकि, नई नीति में अंतर्निहित डिज़ाइन मुद्दे थे जिनमें निर्माताओं और थोक विक्रेताओं के बीच थोपी गई विशिष्टता व्यवस्था और प्रत्येक जोन में न्यूनतम 27 वार्डों के साथ खुदरा जोन का गठन शामिल था। इन मुद्दों के परिणामस्वरूप कुल लाइसेंसधारियों की संख्या सीमित हो गई और एकाधिकार और कार्टेल गठन का खतरा बढ़ गया। यह देखा गया कि आईएमएफएल और एफएल की आपूर्ति के लिए थोक लाइसेंस 14 व्यावसायिक संस्थाओं को दिए गए थे, जबकि पुरानी नीति (2020-21) में आईएमएफएल के 77 निर्माताओं और एफएल के 24 आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए थे। इसी तरह खुदरा दुकानों के उद्देश्य से, दिल्ली को 32 जोनों (849 दुकानों वाले) में विभाजित किया गया था, जिनके लाइसेंस निविदा के माध्यम से 22 संस्थाओं को दिए गए थे, जबकि 377 खुदरा दुकानें चार सरकारी निगमों द्वारा चलाए गए थे और 262 खुदरा दुकानें पहले निजी व्यक्तियों को आवंटित की गई थीं। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला में लाइसेंस रखने वाली संबंधित व्यावसायिक संस्थाओं और विषम वितरण पैटर्न के मामलों ने विशिष्टता प्रबंध और ब्रांड पुशिंग के जोखिम को उजागर किया।

- ***आबकारी नीति के कार्यान्वयन में मुद्दे***

जहां कुछ खुदरा विक्रेताओं ने पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक लाइसेंस बरकरार रखा, वहीं कुछ ने पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पहले ही लाइसेंस वापस कर दिया। चूँकि खुदरा लाइसेंसधारियों की संख्या सीमित थी, इससे आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हुआ क्योंकि नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसके तहत

लाइसेंसधारियों को लाइसेंस सरेंडर करने से पहले अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता हो। इसके अलावा, सरकार को लगभग ₹ 890 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ क्योंकि इसने सरेंडर किए गए खुदरा लाइसेंसों का दोबारा टेंडर नहीं किया।

इस बात से अवगत होने के बावजूद कि समान वितरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गैर-अनुरूप वार्डों में दुकानें खोलने की आवश्यकता थी, विभाग ने तौर-तरीकों पर काम करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। इसके परिणामस्वरूप जोनल लाइसेंसधारियों को दी जाने वाली छूट के कारण लगभग ₹ 941 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

निविदा दस्तावेज़ की शर्तों में यह उल्लेख था कि कोई भी वाणिज्यिक जोखिम लाइसेंसधारी पर होगा, बोली-पूर्व बैठक के दौरान स्पष्टीकरण दिया गया कि *अप्रत्याशित घटना* के लिए कोई प्रावधान नहीं है और आबकारी विभाग की राय लाइसेंस शुल्क में छूट देने के खिलाफ थी। इन सबके बावजूद कोविड प्रतिबंधों (28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी, 2022) के आधार पर जोनल लाइसेंसधारियों को ₹ 144 करोड़ की लाइसेंस फीस की छूट दी गई, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ।

उपरोक्त तीनों के अलावा, जोनल लाइसेंसधारियों से सुरक्षा जमा राशि की गलत वसूली हुई, जिससे लगभग ₹ 27 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। इसलिए, नई नीति के कार्यान्वयन के मुद्दों के कारण लगभग ₹ 2,002 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ।

आबकारी नीति का उद्देश्य नकली शराब की बिक्री को खत्म करना और अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाना था। हालाँकि, नीति में योजनाबद्ध महत्वपूर्ण उपाय जैसे शराब परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, सख्त गुणवत्ता आश्वासन के लिए बैच परीक्षण और एक समर्पित पद के सृजन के माध्यम से निगरानी और विनियमन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

अध्याय I

परिचय

अध्याय I: परिचय

1.1 परिचय

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के अनुसार, 'शराब' का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद और बिक्री राज्य सरकार के विशेषाधिकार क्षेत्र में आता है। तदनुसार, आबकारी, मनोरंजन और विलासिता कर विभाग (आबकारी विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) दिल्ली में शराब की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। शराब आपूर्ति श्रृंखला के विनियमन की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए वैधानिक शक्तियां दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमों से ली गई हैं।

आबकारी विभाग शराब की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक नियंत्रित करता है। इस आपूर्ति श्रृंखला में कई हितधारक शामिल हैं अर्थात निर्माता (डिस्टिलरी और ब्रेवरीज), गोदाम, खुदरा विक्रेता (बिक्री केंद्र), होटल, क्लब और रेस्तरां (सेवा केंद्र) तथा अंततः उपभोक्ता जैसा कि **चार्ट 1.1** में दिखाया गया है।

चार्ट 1.1: शराब आपूर्ति श्रृंखला

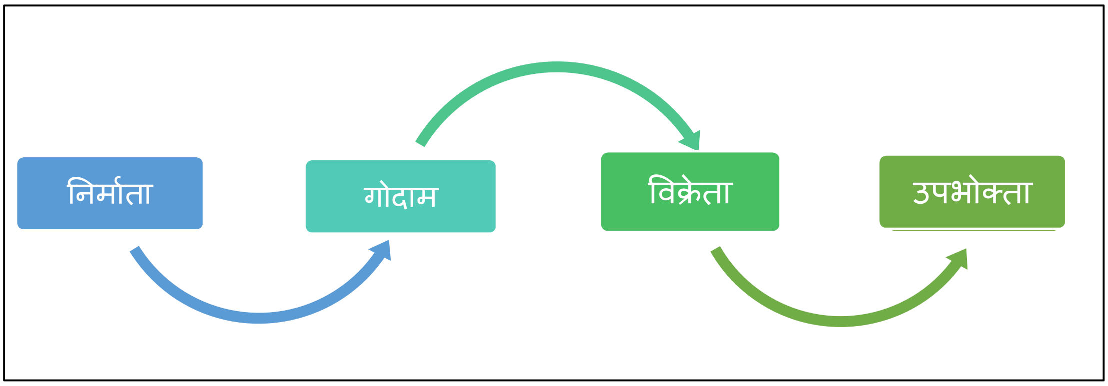

आबकारी विभाग दिल्ली में शराब की आपूर्ति पर आबकारी शुल्क[1] और कई अन्य शुल्क जैसे लाइसेंस शुल्क, परमिट शुल्क, आयात शुल्क आदि लगाता है। आबकारी विभाग द्वारा 'शराब' पर लगाए गए आबकारी शुल्क और अन्य शुल्क से राजस्व की प्राप्ति, रा.रा.क्षे.दि.स.

[1] 1 जुलाई 2017 से, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पूरे देश में लागू किया गया था, जिसमें मानव उपभोग के लिए 'शराब' को छोड़कर, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण और बिक्री पर आबकारी शुल्क को जीएसटी में शामिल किया गया था। इसलिए, 1 जुलाई 2017 से 'शराब' एकमात्र ऐसी वस्तु है जिस पर रा.रा.क्षे.दि.स. सहित राज्य सरकारों द्वारा आबकारी शुल्क लगाया जाता है।

के कर राजस्व में एक प्रमुख योगदानकर्ता है (वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए लगभग 14 *प्रतिशत*), जैसा कि **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

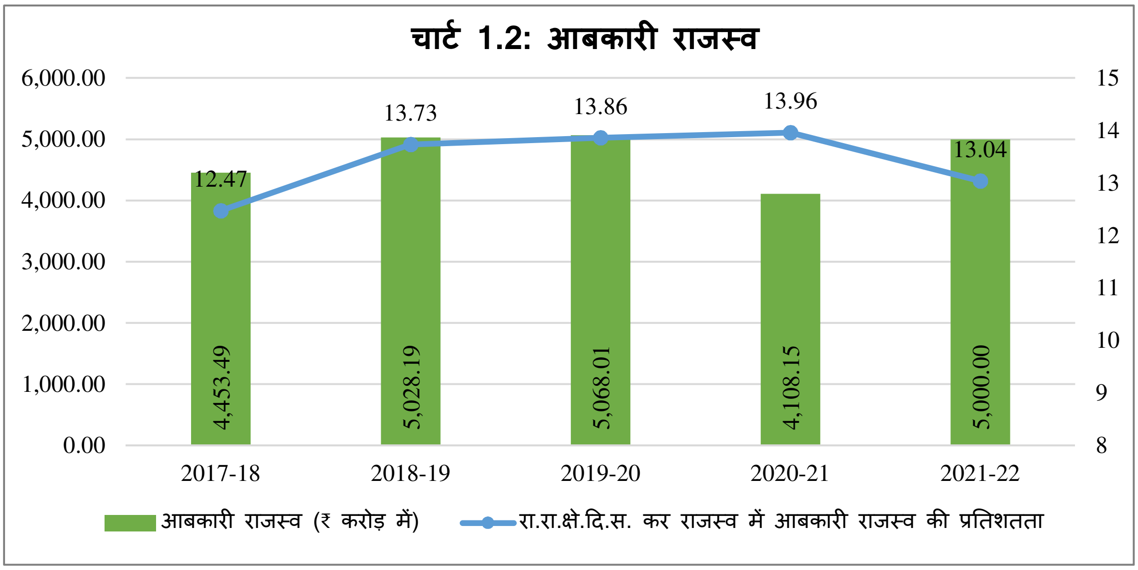

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. का वार्षिक वित्तीय विवरण

शराब के तीन अलग-अलग प्रकार होते हैं, अर्थात् भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल), विदेशी शराब (एफएल) और देशी शराब (सीएल), जो अपने उद्गम, मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता में भिन्न होते हैं। तदनुसार, तीनों प्रकार की शराब के लिए विनियम अलग-अलग होते हैं।

आईएमएफएल और एफएल की आपूर्ति श्रृंखला में हितधारकों को जारी किए गए लाइसेंस **चार्ट 1.3** में दिए गए हैं।

चार्ट 1.3: लाइसेंसधारियों[2] का पदानुक्रम

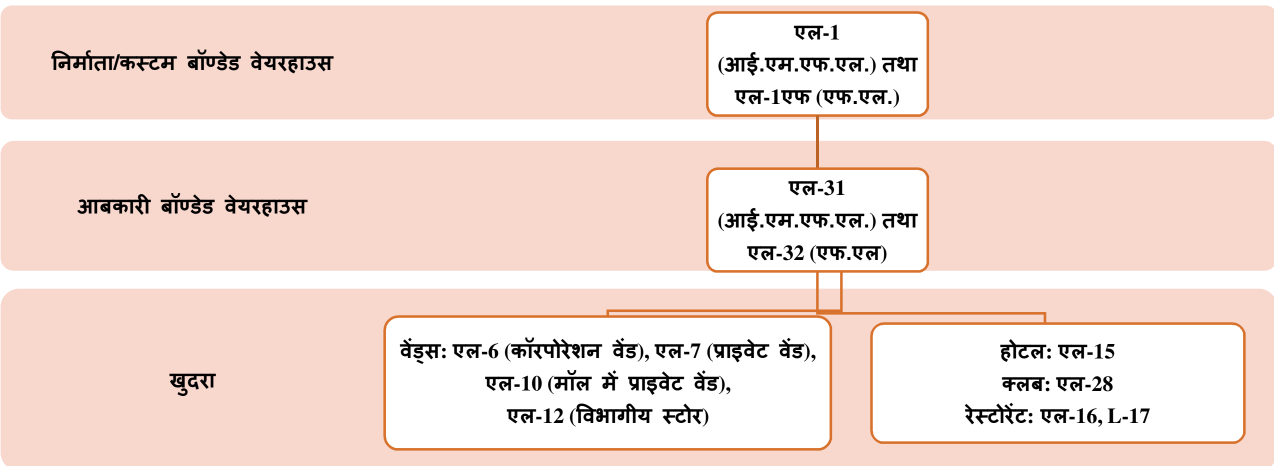

2 लाइसेंस का यह पदानुक्रम 17 नवंबर 2021 और 31 अगस्त 2022 के बीच प्रभावी आबकारी नीति व्यवस्था को छोड़कर अन्य अवधि के लिए लागू था। आबकारी नीति 2021-22 के लिए लाइसेंस के प्रकारों का उल्लेख अध्याय-VIII में किया गया है।

1 अप्रैल 2017 से 16 नवंबर 2021 की अवधि के दौरान आईएमएफएल की आपूर्ति निर्माताओं (रा रा क्षे दिल्ली के बाहर स्थित) द्वारा की गई थी, जो दिल्ली के राराक्षे (रा रा क्षे दि) में उनके आबकारी बॉण्डेड गोदामों में थोक लाइसेंसधारी भी थे। हालाँकि, थोक लाइसेंसधारियों द्वारा राराक्षेदि में आबकारी बॉण्डेड गोदामों को कस्टम बॉण्डेड गोदामों से एफएल की आपूर्ति की गई थी जहां इसे उनके उद्गम से प्राप्त किया गया था।

खुदरा विक्रेताओं में दुकानें, होटल, क्लब और रेस्तरां (एचसीआर) और कैंटीन स्टोर डिपो (सीएसडी) शामिल थे।

चार्ट 1.4: आबकारी विभाग के शराब आपूर्ति श्रृंखला का विनियमन

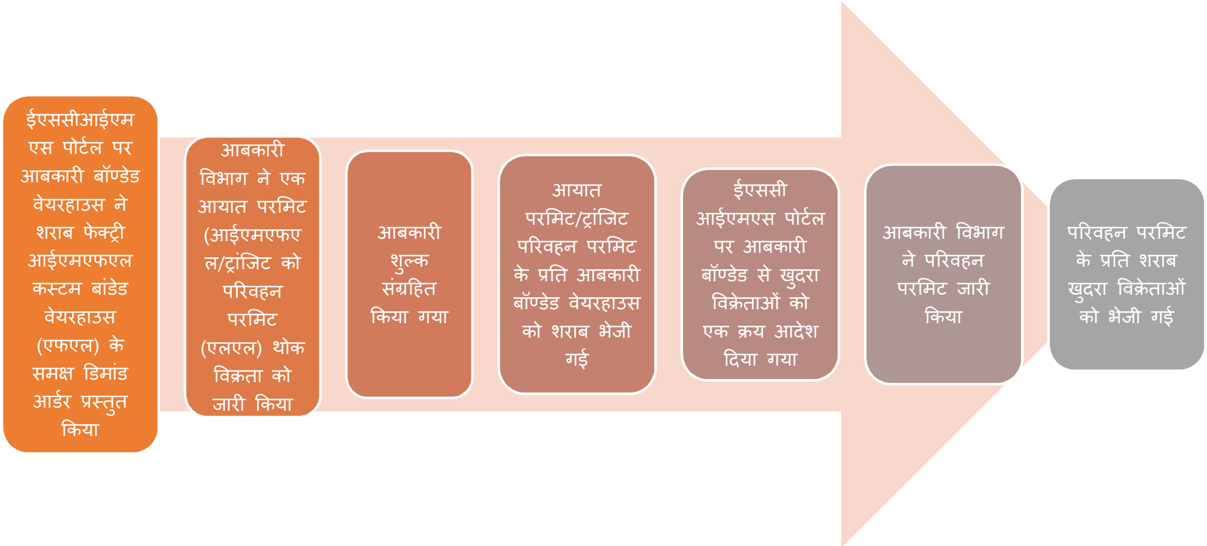

देशी शराब[3] के संबंध में, आपूर्ति श्रृंखला सीधे आबकारी विभाग द्वारा नियंत्रित होती थी क्योंकि यह प्रत्येक थोक लाइसेंसधारी के लिए कोटा (कुल कोटा का 33 *प्रतिशत* से अधिक नहीं) आवंटित करती थी और मासिक आवंटन[4] के आधार पर मांग का आदेश भी देती थी। बिक्री की मात्रा के संदर्भ में आईएमएफएल और एफएल के पास अप्रैल 2017 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान लगभग 90 *प्रतिशत* बाजार हिस्सेदारी थी और शेष 10 *प्रतिशत* बाजार हिस्सेदारी देशी शराब के पास थी।

---

[3] देशी शराब केवल रा.रा.क्षे.दिस. के चार उपक्रमों दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी), दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी), दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) और दिल्ली कंज्युमर्स को ऑपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड (डीसीसीडब्ल्यूएस) द्वारा प्रबंधित ठेकों के माध्यम से बेची जाती थी।

[4] आईएमएफएल और एफएल के लिए खरीद आदेश, आबकारी विभाग के किसी भी हस्तक्षेप के बिना, खुदरा विक्रेताओं द्वारा स्वमूल्यांकन के अनुसार दिया गया।

आबकारी विभाग अपने वेब-आधारित एप्लिकेशन ईएससीआईएमएस (आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से पूरी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करता है, जिसका उपयोग सभी उद्देश्यों जैसे लाइसेंस के लिए आवेदन, मांग आदेश प्रस्तुत करना, आयात परमिट जारी करना, सभी शराब की बारकोडिंग और सूची प्रबंधन तथा सभी हितधारकों के लिए भुगतान का समाधान आदि के लिए किया जाता है।

राजस्व संग्रह के अलावा आबकारी विभाग, शराब आपूर्ति की नियमन में लाइसेंस जारी करना, लाइसेंस शर्तों का प्रवर्तन, मूल्य निर्धारण, खराब गुणवत्ता और गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री की रोकथाम आदि शामिल हैं। ईएससीआईएमएस के माध्यम से उत्पन्न बारकोड को दिल्ली में आयात की जाने वाली सभी शराब की पेटियों तथा बोतलों पर चिपकाना आवश्यक था। आबकारी विभाग के आबकारी खुफिया ब्यूरो (ईआईबी) शराब की अंतर्राज्यीय तस्करी की जांच, अवैध शराब के निर्माण और बिक्री का पता लगाने, बिना लाइसेंस के परिसर में शराब परोसने की जांच और शराब की तस्करी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों के साथ संपर्क करने के लिए जिम्मेदार है। आबकारी विभाग की प्रवर्तन शाखा को लाइसेंसधारियों के आबकारी लाइसेंस प्राप्त परिसरों में आकस्मिक निरीक्षण करने तथा उल्लंघन पाए जाने पर रिपोर्ट करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है।

1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

"दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति" पर लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

i. लाइसेंसिंग प्रक्रिया निष्पक्ष, कुशल और प्रभावी है;

ii. मूल्य निर्धारण नीति निर्माताओं/डिस्टिलरी को अनुचित लाभ पहुंचाए बिना आबकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करती है;

iii. लाइसेंस शर्तों को लागू करने के लिए एक प्रभावी तंत्र मौजूद है; तथा

iv. ईएससीआईएमएस आबकारी प्रशासन में ई-गवर्नेंस को सक्रिय कर रही है;

1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009
- दिल्ली आबकारी नियमावली 2010

- ईएससीआईएमएस के लिए उपयोगगर्ता नियम पुस्तिका
- सामान्य वित्तीय नियमावली
- प्रशासनिक नियम पुस्तिका
- रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी आदेश और परिपत्र
- आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश, परिपत्र और नीति संबंधी कागजात

1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

इस लेखापरीक्षा के शुरूआत में (जुलाई 2021 और जनवरी 2022 के बीच) 2017-18 से 2020-21 तक चार वर्ष की अवधि को शामिल किया गया। हालांकि वर्ष 2021-22 में आबकारी नीति में एक बड़े बदलाव के कारण जो 17 नवंबर 2021 से प्रभावी हुआ और 31 अगस्त 2022 तक चला, इसे बदली हुई नीति और उसके निहितार्थों की लेखापरीक्षा करने हेतु विवेकपूर्ण माना गया। इसलिए इस अवधि को भी शामिल करने के लिए लेखापरीक्षा का विस्तार किया गया था और दिसंबर 2022 एवं जनवरी 2023 के दौरान लेखापरीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा में दिल्ली के रा.रा.क्षे. में आईएमएफएल और एफएल के विनियमन और आपूर्ति की विस्तार से जांच की गई। इस लेखापरीक्षा में देशी शराब की आपूर्ति श्रृंखला की लाइसेंस, बिक्री/खरीद आदि की दृष्टि से विस्तृत जांच नहीं की गई है। यद्यपि जब्त की गई शराब की गतिविधियों के तहत इसके कुछ हिस्से की जांच की गयी है जिसका विवरण अध्याय VI में दिया गया है। लेखापरीक्षा पद्धति में आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और ईएससीआईएमएस ऐप्लिकेशन से प्राप्त डेटा की जांच शामिल थी। नमूना-जांच के लिए यादृच्छिक नमूना पद्धति के माध्यम से 59 लाइसेंसधारियों का चयन किया गया था जिसमें से 46 लाइसेंसधारियों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे। विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र पर चर्चा करने के लिए 30 जून 2021 को विभाग प्रमुख के साथ एक औपचारिक बैठक आयोजित की गई थी। विस्तृत अभ्युक्तियों पर चर्चा करने के लिए निर्गम सम्मेलन 10 जून 2022 को राराक्षेदिस के प्रतिनिधियों[5] के साथ आयोजित किया गया था। जून 2022 में सरकार द्वारा दिए गए जवाबों को संबंधित पैराग्राफों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

---

[5] सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे.दि.स.; विशेष सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे.दि.स.; आयुक्त, आबकारी विभाग; संयुक्त निदेशक (वित्त), रा.रा.क्षे.दि.स. और अन्य सदस्य

आबकारी नीति 2021-22 को लागू करने और उसके कार्यान्वयन से संबंधित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए सरकार को जवाब बार-बार अनुस्मारक जारी करने के बावजूद प्राप्त नहीं हुए। प्रधान सचिव (वित्त), राराक्षेदिस ने पत्र सं एफ.6 (30)/पूर्व/लेखा परीक्षा/2022-23/1395 दिनांक 2 जून 2023 के माध्यम से सूचित किया कि "लाइसेंस आधारित नीति के प्रत्येक पहलू की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है और इस विभाग द्वारा टिप्पणी प्रस्तुत करना जांच के लिए प्रतिकूल हो सकता है।" आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए निर्गम सम्मेलन आयोजित करने के संबंध में यह भी कहा गया था कि "इस स्तर पर निर्गम सम्मेलन आयोजित करना और अधिकारी की कोई भी टिप्पणी/व्याख्या करना, चल रही जांच के लिए प्रतिकूल हो सकता है"। विभाग द्वारा दिनांक 6 नवंबर 2023 के पत्र के माध्यम से जवाब दोहराया गया था। यहां पर यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि चल रही जांच के कारण इस हिस्से से संबंधित लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सीमित फाइलों के आधार पर किया गया था। इसलिए नीति के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की पर्याप्तता और पूर्णता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

1.5 प्रतिवेदन की संरचना

लेखा परीक्षा में राराक्षे दिल्ली में शराब की आपूर्ति की निगरानी और विनियमन के आबकारी विभाग के तरीके में कई विसंगतियां पाई गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कुल वित्तीय निहितार्थ लगभग ₹ 2,026.91 करोड़ है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय-II में शराब की आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करने के लिए आबकारी विभाग का एक वेब आधारित एप्लीकेशन, आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है।

अध्याय-III में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान लाइसेंस नीति और लाइसेंस जारी करने से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है।

अध्याय-IV में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान मूल्य निर्धारण नीति से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है।

अध्याय-V में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान गुणवत्ता मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है।

अध्याय-VI में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान आबकारी खुफिया ब्यूरो और जब्ती से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है।

अध्याय-VII में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान आबकारी विभाग की प्रवर्तन शाखा की कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है।

अध्याय-VIII में आबकारी नीति 2021-22 को लागू करने और कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है।

अध्याय II

आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली

अध्याय II: आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली

प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला ट्रैकिंग, निगरानी और विनियमन के लिए एक मजबूत और कुशल सूचना प्रबंधन प्रणाली एक पूर्व-आवश्यकता है। आबकारी विभाग ने एक मासिक स्टॉक मिलान (एमएसआर) पद्धति शुरू की, जिसने आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली (ईएससीआईएमएस) परियोजना के माध्यम से इन्वेंट्री ट्रैकिंग, डेटा सटीकता और नियामक प्रभावशीलता को कमजोर कर दिया। शराब का एक बड़ा हिस्सा ईएससीआईएमएस के माध्यम से स्कैन किए बिना बेचा गया था। ईएससीआईएमएस का एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो (ईआइबी) मॉड्यूल गैर-कार्यात्मक था। परियोजना निगरानी और सेवा स्तर अनुपालन निगरानी संतोषजनक नहीं थी। प्रवर्तन कार्यों के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए कैप्चर किए गए डेटा के विश्लेषणात्मक मूल्य का उपयोग नहीं किया गया था। ईएससीआईएमएस की शुरुआत के दस वर्ष बाद भी, विभाग निकास प्रबंधन योजना के अभाव में उसी कार्यान्वयन एजेंसी पर निर्भर रहा। सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक्साइज एडहेसिव लेबल का प्रोजेक्ट कैबिनेट की मंजूरी के ढाई वर्ष बाद भी लागू नहीं हो सका।

2.1 परिचय

फरवरी 2010 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि दिल्ली में बेची जाने वाली सभी शराब की बारकोडिंग की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिल्ली में कोई तस्करी न हो और किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में शराब के स्रोत का पता लगाया जा सके। आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली (ईएससीआइएमएस) नामक परियोजना को एक कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के माध्यम[6] से लागू करने का निर्णय लिया गया था, जिसे बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाना था। ईएससीआईएमएस ने अपने दायरे में सभी शराब की बारकोडिंग सभी हितधारकों (आबकारी विभाग, थोक लाइसेंसधारियों और खुदरा दुकानों) के लिए इन्वेंट्री प्रबंधन और भुगतान समाधान को कवर किया।

[6] डीबीओओटी (डिज़ाइन, निर्माण, स्वामित्व, संचालन और स्थानांतरण) मॉडल के माध्यम से

हार्डवेयर की स्थापना, सॉफ्टवेयर के विकास, आबकारी डेटा केन्द्र और आपदा पुनर्वास केन्द्र के लिए अनुकूलन को कवर करने वाली परियोजना के लिए संपूर्ण निवेश कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन किया जाना था। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किए गए निवेश पर रिटर्न का भुगतान आबकारी डेटा सेंटर में कैप्चर किए गए डेटा की प्रत्येक इकाई के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उद्धृत दर पर किया जाना था।

तदनुसार, आबकारी विभाग ने मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया (नवंबर 2011), जो कि कार्यान्वयन के लिए 78 सप्ताह की प्रस्तावित समय-सीमा के साथ शराब को मूल स्थान से बिक्री केन्द्र तक एंड-टू-एंड ट्रैकिंग की तकनीक सक्षम प्रक्रिया प्रदान करने के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी थी। इस परियोजना को फरवरी 2013 में पायलट चरण के रूप में शुरू किया गया था और दिसंबर 2013 में परिचालित किया गया था। यह समझौता दिसंबर 2013 के बाद सात वर्ष की अवधि के लिए था तथा इसे और दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता था।

समझौते की शर्तों[7] के अनुसार, एल1/एल1एफ[8] लाइसेंसधारियों पर बोतलों और शराब पेटी से जुड़े प्रत्येक बारकोड के लिए 15 पैसे[9] का बारकोड शुल्क लगाया जाना तथा कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात टीसीएस को भुगतान किया जाना था। कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान के लिए केवल बेचे गये, लौटाए गए या टूटे हुए और अंततः प्रमाणित किये गये बारकोड पर ही विचार किया जाना चाहिए था। यह राजस्व बंटवारे का समझौता नहीं था और बारकोड शुल्क केवल टीसीएस के प्रति भुगतान दायित्व के निपटान के लिए एकत्र किया जाना था।

हालांकि, विभाग ने पायलट चरण के दौरान पाया कि खुदरा दुकानों पर प्रमाणित बारकोड का प्रतिशत बहुत कम[10] था और इस प्रकार, खुदरा दुकानों पर एक 'स्टॉक-टेक-सोल्ड'/मासिक स्टॉक मिलान (एमएसआर) प्रक्रिया शुरू की गई (दिसंबर 2013)। 'स्टॉक-टेक-सोल्ड' प्रक्रिया मूल रूप से तार्किक इन्वेंट्री (ईएससीआईएमएस के अनुसार इन्वेंट्री)

7 अनुसूची VI

8 एल1-भारत निर्मित देश विदेशी शराब की बिक्री के लिए थोक लाईसेंस, एलआईएफ-विदेशी शराब की बिक्री के लिए थोक लाईसेंस

9 लागू दरों पर सेवा कर/जीएसटी को छोड़कर

10 ईएससीआईएमएस के पायलट चरण की प्रारंभिक तिमाही (फरवरी 2013 से अप्रैल 2013) के दौरान प्रमाणित बारकोड बनाम उत्पन्न बारकोड का प्रतिशत 0.04 प्रतिशत था जो गो-लाइव से पहले अंतिम तिमाही (सितंबर 2013 से नवंबर 2013) के दौरान बढ़कर केवल 30.27 प्रतिशत हो गया।

और भौतिक इन्वेंट्री का एक मिलान था, जिसमें भौतिक इन्वेंट्री से गायब बारकोड को सिस्टम में बेचे जाने के रूप में अपडेट किया गया।

ईएससीआईएमएस के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन ऐजेंसी को भुगतान एल1/एल1एफ लाइसेंसधारियों पर लगाए गए बारकोड शुल्क के माध्यम से किया गया था। दिसंबर 2013 में परियोजना कार्यान्वयन से नवंबर 2022 तक, बारकोड शुल्क के कारण एल1/एल1एफ लाइसेंसधारियों से ₹ 112.00 करोड़ (सेवा कर/जीएसटी सहित) एकत्र किए गए थे और ₹ 90.11 करोड़ (सेवा कर/जीएसटी को छोड़कर) का भुगतान दायित्व कार्यान्वयन ऐजेंसी[11] को आगे के भुगतान के लिए बनाया गया था।

कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समझौते को बढ़ा दिया गया था और विस्तारित अवधि भी नवंबर 2022 में समाप्त हो गई थी। इसके बाद, परियोजना को विभाग को या एक प्रतिस्थापन कार्यान्वयन एजेंसी को हस्तांतरित किया जाना था, जिसे नए सिरे से निविदा के माध्यम से चुना जाना था। इसके बाद, फरवरी 2024 तक परियोजना को जारी रखने के लिए टीसीएस को तीन लघु विस्तार दिए गए हैं।

एक नए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के विकास के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) की तैयारी के लिए एक परामर्श फर्म को काम पर रखने की प्रक्रिया अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी। कोविड महामारी के कारण देरी के बाद, मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और ₹ 93.38 लाख (लागत ₹ 2.34 करोड़ का 40 *प्रतिशत*) के प्रारंभिक भुगतान के बाद मई 2022 में कार्य आरंभ किया गया। खरीद चरण (सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के चयन के लिए आरएफपी और बोली प्रबंधन) को पूरा करने के लिए छह महीने की समयसीमा की योजना बनाई गई थी। दिसंबर 2023 तक, मसौदा डीपीआर सलाहकार द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, और आरएफपी, बोली प्रबंधन, एसआई के चयन आदि बाद के कार्य लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने ईएससीआईएमएस के कार्यान्वयन की जांच की और कई कमियां और अनियमितताएं देखीं, जिनकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफ में की गई है।

---

[11] अक्टूबर 2022 तक टीसीएस को वास्तविक भुगतान ₹ 97.55 करोड़ (सेवा कर/जीएसटी सहित) था।

2.2 ईएससीआईएमएस का शराब की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग का उद्देश्य पूरा नहीं होना

ईएससीआईएमएस का उद्देश्य शराब की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग करना था। इसे आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर शराब की बोतलों और पेटियों पर बारकोड को कैप्चर करने के माध्यम से प्राप्त किया जाना था और अंततः व्यक्तिगत स्टॉक कीपिंग इकाइयों (एसकेयू[12]) के बारकोड को स्कैन करके बिक्री केन्द्र (पीओएस) पर प्रमाणित किया जाना था। बारकोड सबसे पहले थोक विक्रेताओं द्वारा तैयार किए जाते थे, जिनसे बारकोड शुल्क लिया जाता था। बाद में, आयात परमिट बनाते समय आबकारी का भुगतान किया जाता था और थोक विक्रेताओं द्वारा बारकोड को आयात परमिट से भी जोड़ा जाना था।

मार्च 2021 तक 482.62 करोड़ बारकोड बेचे हुए दिखाए गए थे। इसमें से केवल 346.09 करोड़ (71.71 *प्रतिशत*) को या तो पीओएस पर स्कैन किया गया या बारकोड को स्कैन करने के बाद (क्षतिग्रस्त, समाप्त हो गया आदि के रूप में), वर्गीकृत किया गया था। जबकि शेष 136.53 करोड़ (28.29 *प्रतिशत*) को 'स्टॉक-टेक सोल्ड/एम एस आर गैप[13] अभ्यास के माध्यम से बेचा गया दिखाया गया था। अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 तक और 118.14 करोड़ बारकोड बिक्री के रूप में दिखाए गए थे, जिसमें बिक्री की दर्ज प्रतिशतता बारकोड स्कैन किए बिना 21.18 *प्रतिशत* थी। इस प्रकार, शराब का एक बड़ा हिस्सा ईएससीआईएमएस प्रणाली के माध्यम से स्कैन किए बिना बेचा गया, जिससे शराब की एंड-टू-एंड ट्रेसिंग का उद्देश्य विफल हो गया।

2.2.1 बारकोड की स्कैनिंग को लागू करने के कमजोर प्रयासों के साथ 'स्टॉक-टेक-सोल्ड' अभ्यास ने ईएससीआईएमएस के उद्देश्य को विफल कर दिया

ईएससीआईएमएस की पायलट प्रक्रिया के दौरान, कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान के लिए प्रथम चालान की प्रस्तुति से पहले (मार्च 2014), यह देखा गया कि खुदरा दुकानों/पीओएस पर स्कैनिंग प्रतिशत कम था। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, दुकानों पर स्टॉक -टेक-सोल्ड प्रक्रिया/एमएसआर गैप शुरू किया गया था जो स्टॉक का मासिक/द्विमासिक मिलान था।

---

[12] एसकेयू- स्टॉक प्रबंधन में, स्टॉक कीपिंग यूनिट बिक्री के लिए, खरीदी गई या इन्वेंट्री में ट्रैक की जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की वस्तु होती है, (शराब के मामले में-विशेष ब्रांड आकार (एमएल) कन्टेनर का प्रकार (कैन/बोतल) मिलकर एक यूनिक (एस के यू) बनायेंगे)

[13] एमएसआर गैप/स्टॉक-टेक-सोल्ड-टर्म संबंधित बारकोड की गैर स्कैनिंग के बावजूद बेचे गए के रूप में चिन्हित स्टॉक के संदर्भ में उपयोग किया गया। यह महीने के अंत में, खुदरा दुकानों में मौजूद सभी स्टॉक को स्कैन करके, और लापता स्टॉक को एमएसआर गैप के रूप में चिन्हित करके किया गया था, यह मानते हुए कि चूंकि ये ईएससीआईएमएस तार्किक सूची स्थिति के अनुसार दुकान में नहीं पाए गए थे, इसलिए उन्हें बेच दिया गया होगा।

विभाग ने ईएससीआईएमएस के कार्यान्वयन के सात वर्षों के बाद भी 'स्टॉक-टेक-सोल्ड' का उपयोग करना जारी रखा। इस प्रकार ईएससीआईएमएस यानी शराब की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग का उद्देश्य विफल हो गया।

1 अप्रैल 2017 से 15 नवंबर 2021 की अवधि के दौरान बिना स्कैनिंग के बेची गई बोतलों का प्रतिशत 14.48 *प्रतिशत* से 48.41 *प्रतिशत* रहा, जैसा कि **चार्ट 2.1** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.1: बिना स्कैनिंग के बेचे गए स्टॉक की प्रतिशतता[14]

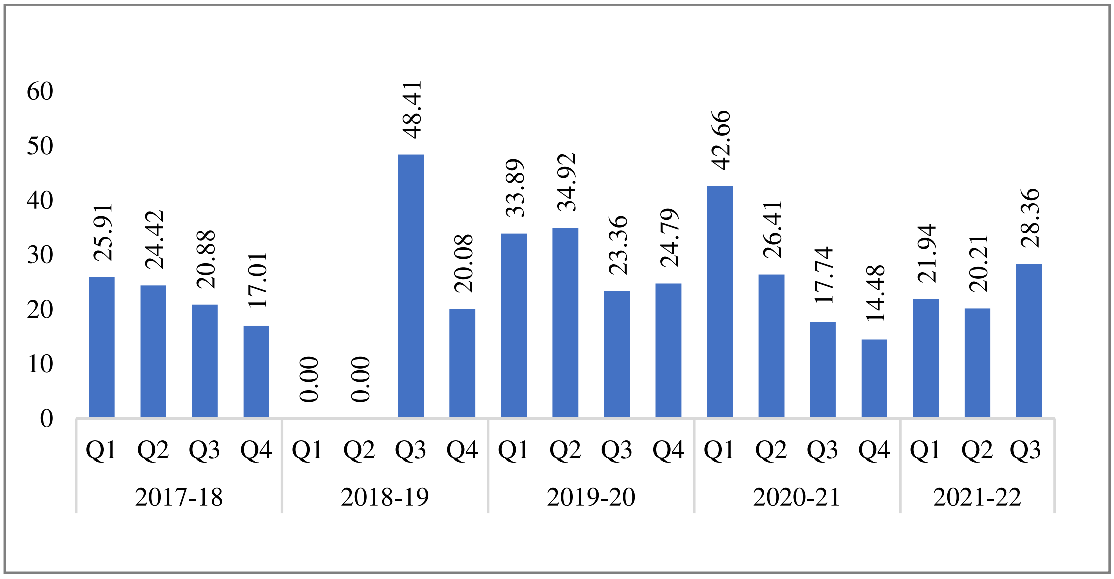

विभाग ने अपने जवाब में कहा (जून 2022 और मार्च 2023) कि ईएससीआईएमएस के उद्देश्य पूरे हो गए हैं, क्योंकि "वर्ष दर वर्ष राजस्व में वृद्धि हुई है और इसकी शुरूआत के बाद से एमएसआर गैप में कमी आई है (कोविड वर्षों में संक्रमण और नई नीति से पुरानी नीति पर वापसी को छोड़कर)"। विभाग ने खुदरा दुकानों को पूर्ण स्कैनिंग के लिए नियमित निर्देश जारी किए थे और इस संबंध में प्रशिक्षण भी दिए गए थे। जवाब में आगे उल्लेख किया गया है कि 8 अगस्त 2020 के आदेश के तहत दंडात्मक प्रावधान तैयार किए गए थे। साथ ही, त्रुटिपूर्ण मामले में भविष्य के परिवहन परमिट भी रोक दिए गए थे। जवाब में बताया गया कि विभाग को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है और ईएससीआईएमएस जहरीली शराब त्रासदी को रोकने में सक्षम है। इसमें आगे उल्लेख

[14] मार्च से सितंबर 2018 के दौरान एमएसआर गैप अभ्यास नहीं किया गया था, जो वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में असामान्य रूप से उच्च एमएसआर गैप के लिए भी जिम्मेदार था।

किया गया है कि ईएससीआईएमएस के कार्यान्वयन के माध्यम से मिली सीख पर ध्यान दिया गया है और विभाग ईएससीआईएमएस 2.0 की ओर बढ़ रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यद्धपि आबकारी विभाग ने बारकोड की स्कैनिंग को अनिवार्य करने के लिए परिपत्र (जनवरी 2018 और अप्रैल 2019) जारी किया, तथापि, उसके द्वारा केवल अगस्त 2020 में अपने परिपत्रों का अनुपालन नहीं करने के लिए विशिष्ट दंडात्मक प्रावधान तैयार किए गए। बेची गई सभी शराब की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग सात वर्ष बाद भी हासिल नहीं की जा सकी। प्रारंभिक परिपत्रों और प्रशिक्षण में थोड़ा सुधार हुआ क्योंकि अप्रैल 2017 से 15 नवंबर 2021 की अवधि के दौरान बिना स्कैनिंग के बेची गई शराब का प्रतिशत 14.48 *प्रतिशत* और 48.41 *प्रतिशत* के बीच था।

2.2.2 ईएससीआईएमएस डेटा के माध्यम से पुनरावृत चूककर्ता की पहचान करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने कैलेंडर वर्ष 2019 के लिए ईएससीआईएमएस से शराब की बिक्री के आंकड़ों का विश्लेषण किया। शराब की बिक्री में विभिन्न खुदरा विक्रेताओं की हिस्सेदारी **चार्ट 2.2** में दर्शाई गई है और इकाई-वार त्रैमासिक एमएसआर गैप **तालिका 2.1** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.2: मात्रा के अनुसार शराब की बिक्री (बोतलों की संख्या)

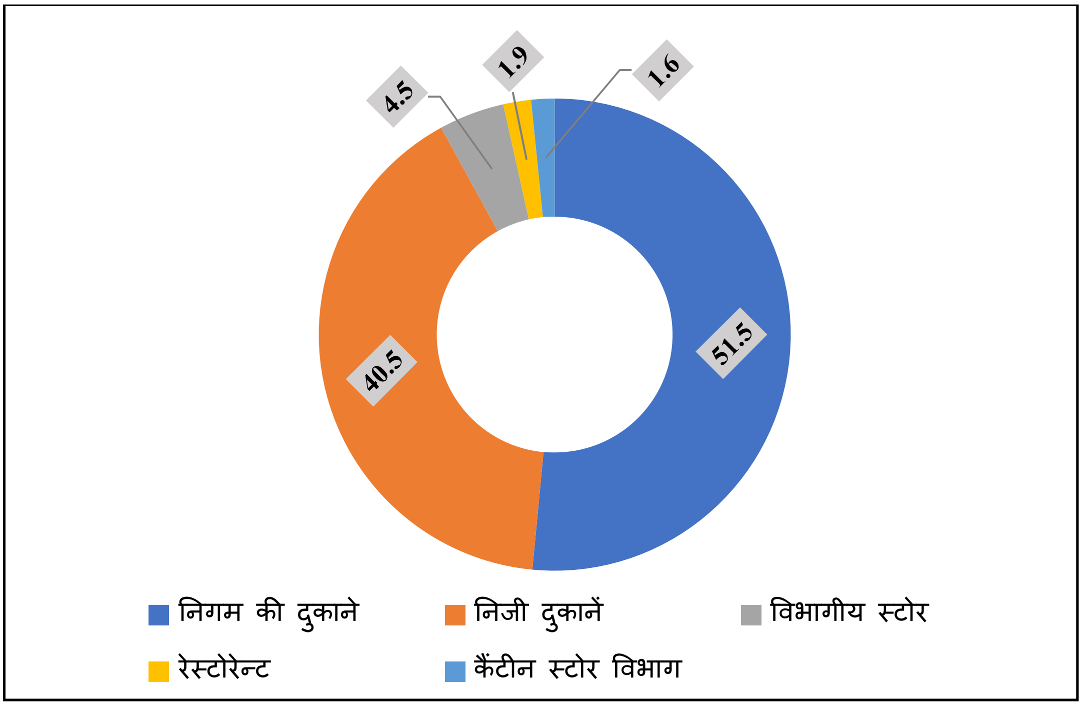

तालिका 2.1: कैलेंडर वर्ष 2019 में इकाई-वार एमएसआर गैप रिपोर्ट

(*प्रतिशत में* - पूर्णांकित)

	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4	कुल योग
दिल्ली राज्य आपूर्ति निगम लिमिटेड	36	44	36	27	36
विभागीय स्टोर	17	30	25	32	27
दिल्ली राज्य आपूर्ति निगम लिमिटेड	25	29	16	16	22
दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढ़ांचा निकास निगम	32	66	43	34	45
दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम	25	38	30	25	30
निजी दुकानें/शापिंग मॉल/एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री शाप	15	28	44	23	29
कुल योग	**23**	**37**	**37**	**25**	**31**

तालिका 2.1 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2019 के दौरान कुल एमएसआर गैप 30.87 *प्रतिशत* था। हालाँकि, यह दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) दुकानों में 45 *प्रतिशत* से लेकर दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससी) दुकानों में 22 *प्रतिशत* तक था। 2019 की दूसरी और तीसरी तिमाही में सरकारी और निजी दुकानों के लिए असामान्य रूप से उच्च एमएसआर गैप दिखाई दिया।

लेखापरीक्षा ने सभी संस्थाओं के लिए कैलेंडर वर्ष 2019 के लिए शराब की बोतलों के ईएससीआईएमएस बिक्री डेटा का भी विश्लेषण किया। ऐसे उदाहरण सामने आए जहां कैलेंडर वर्ष 2019 की कुछ अवधि के दौरान स्कैनिंग के बिना बिक्री का प्रतिशत 70 से 98 *प्रतिशत* के बीच बहुत अधिक था, जो **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

विस्तृत स्तर पर बिक्री डेटा के आगे के विश्लेषण से भी पता चला कुछ खुदरा दुकानों के संबंध में विभिन्न महीनों के बीच रिपोर्ट की गई बिक्री और स्कैन की गई बिक्री में असामान्य रूप से व्यापक भिन्नता थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

i. एक दुकान[15] के मामले में, वर्ष 2019 के छह महीनों (जुलाई-दिसंबर) के दौरान केवल 3.6 लाख बोतलें स्कैन की गईं, जबकि 13.69 लाख बोतलें बिना स्कैनिंग के बेची गईं (एमएसआर गैप के रूप में दिखाया गया है)। इन 13.69 लाख

[15] अनुलग्नक II की क्रम संख्या 5

बोतलों में से 9.94 लाख बोतलों को अकेले एक महीने में एमएसआर गैप के रूप में दिखाया गया था।

ii. यह देखा गया कि कुछ महीनों के दौरान बिक्री स्कैनिंग के माध्यम से होती थी, जबकि अन्य अवधियों के दौरान, अधिकांश बिक्री बिना स्कैनिंग के होती थी। उदाहरण के लिए, एक मामले[16] में, मई 2019 के बिक्री डेटा से पता चला कि 9.59 लाख बोतलें स्कैनिंग के माध्यम से बेची गईं, जिसमें शून्य एमएसआर गैप बताया गया। हालाँकि, कैलेंडर वर्ष 2019 के आखिरी छह महीनों के लिए, औसत एमएसआर गैप, कुल बिक्री का 83 *प्रतिशत* था।

iii. एक दुकान[17] के लिए तीसरी तिमाही में बहुत अधिक एमएसआर गैप (70 *प्रतिशत)* दर्ज किया गया, जबकि पहली तिमाही में उसका एमएसआर शून्य था। डेटा में व्यापक मासिक बिक्री भिन्नता भी दिखाई गई, क्योंकि जून में पहली तिमाही के दौरान 1.06 लाख बोतलों की औसत बिक्री के मुकाबले 8.15 लाख बोतलों की बिक्री हुई।

स्कैनिंग के बिना बिक्री ईएससीआईएमएस में बिक्री डेटा की सटीकता से समझौता करती है। ईएससीआईएमएस ने आबकारी विभाग को उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करने और जहां बारकोड की स्कैनिंग बारम्बार खराब थी, वहाँ व्यक्तिगत खुदरा दुकानों की पहचान करने का अवसर प्रदान किया, हालाँकि, विभाग द्वारा ईएससीआईएमएस डेटा के विश्लेषण के माध्यम से ऐसे व्यक्तिगत खुदरा दुकानों की पहचान करने का कोई प्रयास लेखापरीक्षा द्वारा नहीं पाया गया।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि आबकारी विभाग ने उपरोक्त लाइसेंसधारियों के खिलाफ जुर्माना लगाया था। हालाँकि, उत्तर के साथ कोई दस्तावेजी प्रमाण (जुर्माना आदेश, चालान, जुर्माने का कारण, जुर्माने की अवधि आदि) संलग्न नहीं किया गया था और इसे ईएससीआईएमएस पोर्टल के माध्यम से भी सत्यापित नहीं किया जा सका।

2.2.3 अप्रयुक्त बारकोड्स के दुरुपयोग की संभावना

फरवरी 2013 से नवंबर 2013 की अवधि के दौरान, अर्थात् ईएससीआईएमएस परियोजना के शुरू होने से पहले, थोक बिक्री लाइसेंसधारियों द्वारा 44.64 करोड़ बारकोड

---

[16] अनुलग्नक II की क्रम संख्या 7

[17] अनुलग्नक II की क्रम संख्या 10

बनाए गए थे। इनमें से, केवल 18.94 करोड़ बारकोड को ट्रैक किया गया और मार्च 2021 तक बेचा हुआ दिखाया गया। बेचे गए बारकोड में से, 9.39 करोड़ बारकोड स्कैन किए गए, और 9.55 करोड़ बारकोड को स्टॉक-टेक-सोल्ड की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए विक्रय के रूप में चिह्नित किया गया। इसलिए, 25.70 करोड़ से अधिक बारकोड का हिसाब नहीं दिया गया क्योंकि इनमें से अधिकांश बारकोड को या तो गोदामों में प्राप्ति के रूप में दिखाया गया था या बिक्री के लिए दुकानों को भेजा गया (पारगमन में) दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद ट्रैक नहीं किया गया था।

इसके अलावा, अतिरिक्त 13.90 करोड़ बारकोड जनरेट किए गए और मार्च 2017 तक अप्रयुक्त/संग्रहीत बताए गए थे। इन बारकोड के लिए थोक लाइसेंसधारी से शुल्क नहीं लिया गया था और ये आयात परमिट से जुड़े नहीं थे।

इस प्रकार, ये बारकोड सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए थे जो कि बेहिसाब थे, का उपयोग गैर शुल्क भुगतान वाली शराब (एनडीपीएल) को शुल्क भुगतान वाली शराब के रूप में छिपाने के लिए किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को राजस्व की हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त, चूंकि बारकोड स्वयं सुरक्षित लेबल पर मुद्रित नहीं होते हैं, इससे यह बहुत अधिक जोखिम होता है कि बोतलों पर निरीक्षण के दौरान पाए गए बारकोड वास्तव में डुप्लिकेट हैं और इस प्रकार, एनडीपीएल के लिए यह एक कवर हैं।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि आज की तारीख में बारकोड एक बार जेनरेट होने के बाद डिस्टिलरी से नहीं भेजे जाने पर 90 दिनों की अवधि के बाद संग्रहीत हो जाता है। जो बारकोड संग्रहीत हो जाते हैं उन्हें दोबारा नहीं भेजा जा सकता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पन्न और मुद्रित बारकोड, हालांकि संग्रहीत हैं, का उपयोग गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब को छुपाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे बारकोड के संबंध में उत्तर मौन है जो पहले ही गोदामों में भेज दिए गए थे या दुकानों (पारगमन में) में थे किंतु उसके बाद अप्रयुक्त/अनट्रेक रह गए।

बारकोड जारी करने, ट्रैकिंग और लेखांकन की तदर्थ व्यवस्था जारी रखने के साथ-साथ, स्कैनिंग के कमजोर प्रवर्तन और डिफॉल्टरों की पहचान करने के लिए डेटा का उपयोग नहीं करने से, शराब की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग का उद्देश्य विफल हो गया।

2.2.4 बारकोड्स को स्कैन किए बिना बिक्री प्रमाणित करने से जुड़े जोखिम

शराब के बारकोड की अपूर्ण स्कैनिंग के कारण शराब की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग संभव नहीं थी। आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित 'स्टॉक-टेक-सोल्ड' अभ्यास (मासिक स्टॉक मिलान का प्रचलन) आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के उद्देश्य को विफल करती है।

होटल, क्लब और रेस्तरां को विशेष रूप से थोक लाईसेंसधारी (एल1) से शराब खरीदनी होती है, जिस पर खुदरा दुकानों पर बेची जाने वाली शराब की तुलना में 20-30 *प्रतिशत* (थोक मूल्य-एचसीआर द्वारा भुगतान किया जाना) का अतिरिक्त शुल्क लगता है। यदि एचसीआर अवैध रूप से खुदरा दुकानों से शराब प्राप्त करता है, तो इससे अतिरिक्त आबकारी शुल्क की हानि होगी।

लेखापरीक्षा ने 11 प्रवर्तन मामलों से संबंधित नौ होटल लाइसेंसधारियों के अभिलेखों की नमूना जांच की। इन मामलों में, (ईएससीआईएमएस में) "अन्य दुकानों पर बेची गई" के रूप में दर्ज की गई 548 संदिग्ध बोतलों में से 298 एचसीआर में पाई गईं। इन खुदरा दुकानों को, जिनकी बोतलें एचसीआर में मिलीं थी, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया और न ही यह पता लगाने के लिए पूरी तरह से जांच की गई कि क्या गायब स्टॉक दुकान द्वारा "बिका हुआ नहीं" या "एमएसआर गैप के रूप में चिह्नित" किया गया था। स्कैनिंग से जारी करने का समय पता चल जाता और जिम्मेदारी निश्चित करने में मदद मिलती।

2.2.5 दुकान बिक्री डेटा विश्लेषण

विश्लेषण के लिए, कुल 36 दुकानों का एक नमूना चुना गया था (निजी और सरकारी निगमों प्रत्येक में स्थित 18 निकटवर्ती क्षेत्र)। जून 2019 और जनवरी 2020 के महीनों के लिए बेची गई बोतलों की संख्या के संदर्भ में बिक्री डेटा किसी भी मौसमी विचलन को सुचारू करने के लिए सभी दुकानों से लिया गया था।

(i) अनधिकृत चैनलों के लिए शराब के विपथन का खतरा

दिल्ली में सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांडों में से पांच, जिनकी बाजार हिस्सेदारी एक प्रतिशत से अधिक थी, पर विचार किया गया। ब्रांडों और इकाई स्वामित्व (कॉर्पोरेशन की दुकान बनाम प्राइवेट दुकान) में एमएसआर गैप (बोतलों को बिक्री से पहले स्कैन नहीं किया गया और बाद में बेचा गया मान लिया गया) में पर्याप्त भिन्नता देखी गई,

जैसा कि **चार्ट 2.3** में दिखाया गया है। कुछ ब्रांडों की बिक्री के आंकड़े ज्यादा होने के बावजूद एमएसआर गैप कम रहा जबकि कुछ ब्रांडों की बिक्री कम होने के बावजूद एमएसआर गैप असामान्य रूप से अधिक रहा।

चार्ट 2.3: ब्रांड वार और इकाई वार एमएसआर गैप

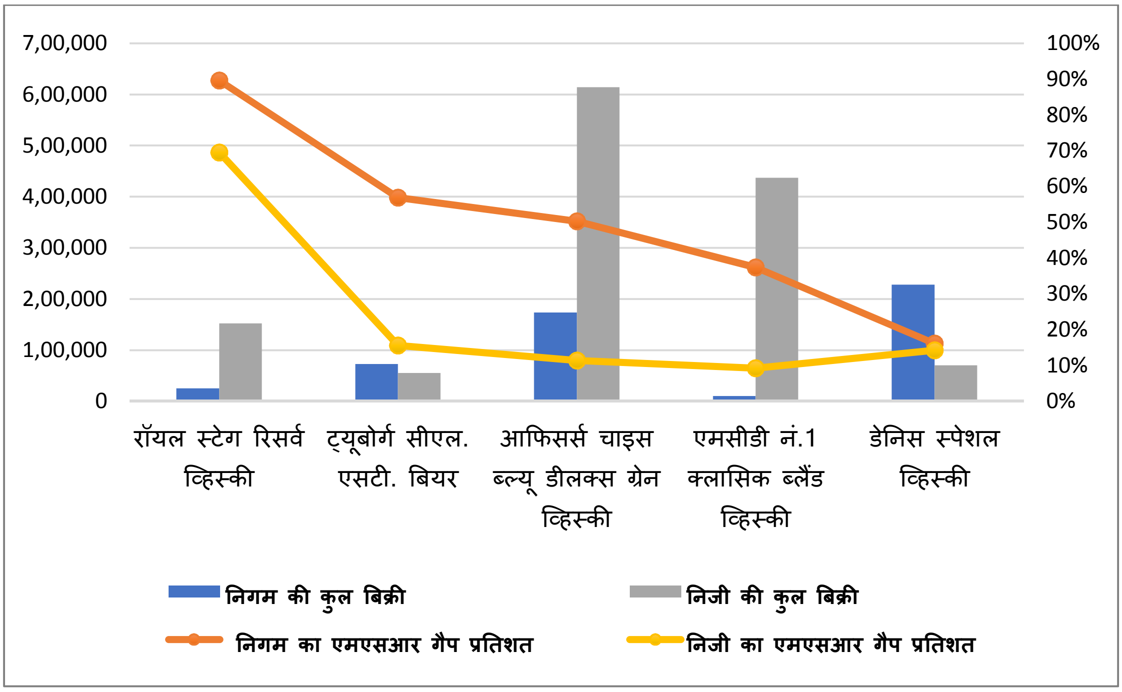

आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ ब्रांडों की स्कैनिंग नहीं की गई थी और बिक्री की मात्रा का उस ब्रांड के लिए पंजीकृत एमएसआर गैप से कोई संबंध नहीं था। निश्चित ब्रांडों के अनधिकृत चैनलों को विपथन की संभावना को नकारने के लिए आबकारी विभाग द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।

(ii) सरकारी निगमों[18] की दुकानों द्वारा ब्रांड को आगे बढ़ाने का जोखिम

18 नमूना सरकारी दुकानों और 18 नमूना निजी दुकानों में व्हिस्की के सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांडों में से चार की बिक्री के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। इनमें से कोई भी ब्रांड निगमों के सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांडों में शामिल नहीं था और निजी क्षेत्र में ये सभी आंकड़े हमेशा सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांडों के रूप में सामने आते हैं।

[18] डीटीटीडीसी, डीएसआईआईडीसी, डीएससीएससी और डीसीसीडब्ल्यूएस

चार्ट 2.4: "भारत में चार सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांड" के लिए नमूना दुकानों (निजी बनाम सरकारी निगम) में सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी

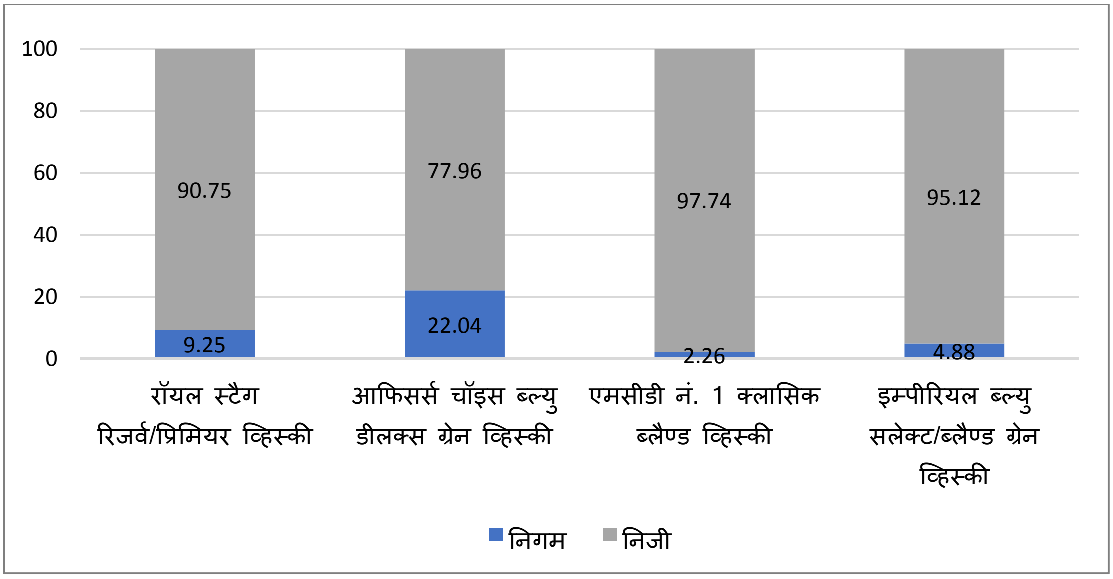

इससे पता चलता है कि ब्रांड वरीयता के संदर्भ में निगम दुकानों की बिक्री सामान्य मांग का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इसके बाद, तुलनात्मक बिक्री का विश्लेषण उन ब्रांडों के लिए लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था जो कॉर्पोरेशन दुकानों में लोकप्रिय थे, और यह देखा गया कि कुछ ब्रांड जो कॉर्पोरेशन दुकानों में लोकप्रिय थे, उनकी निजी दुकानों पर सीमित अपील थी, जैसा कि **चार्ट 2.5** में दिखाया गया है।

चार्ट 2.5: "निगम दुकानों में अधिक बिकने वाले ब्रांड" के लिए नमूना दुकानों (निजी बनाम सरकारी निगम) में सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी

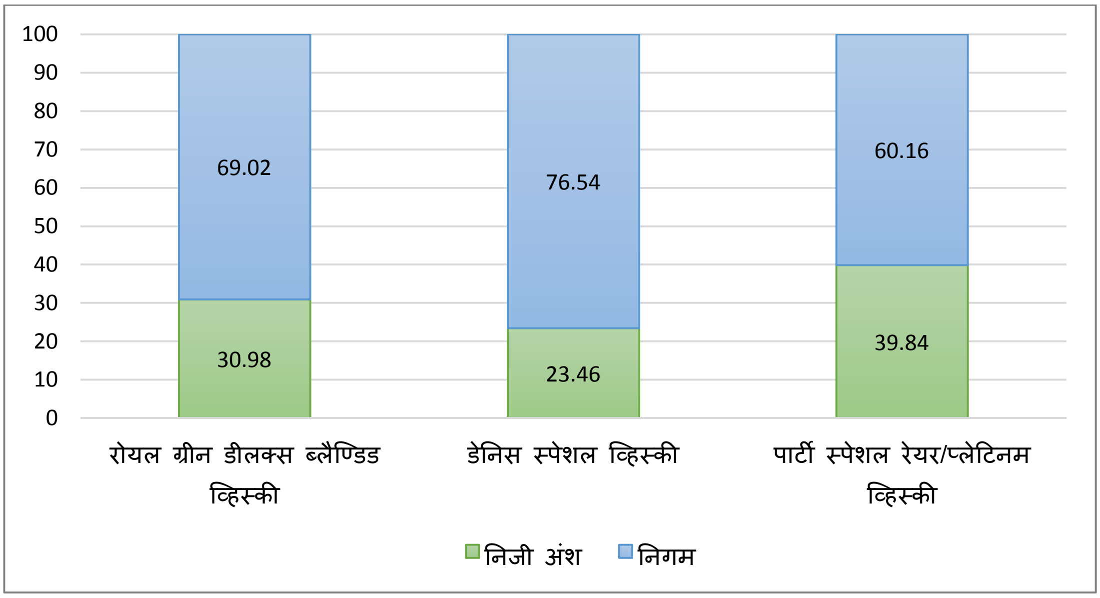

यह विश्लेषण आबकारी विभाग द्वारा विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता को इंगित करता है। कि निगम दुकानें किसी विशेष ब्रांड को अनुचित प्राथमिकता नहीं दे रहे थी।

(iii) निजी दुकानों द्वारा ब्रांड को आगे बढ़ाने का जोखिम

नमूना विक्रेताओं के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कुछ ब्रांडों के लिए निजी दुकानों द्वारा एक स्पष्ट रूप से तरजीह दी गई थी। 18 निजी दुकानों में, 10 सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांडों के लिए विश्लेषण किए गए आंकड़ों से, निम्नलिखित देखा गया:

- गोवा स्पिरिट ऑफ स्मूथनेस व्हिस्की की कुल 1.79 लाख बोतलों की बिक्री हुई, जिनमें से अकेले दो दुकानों ने कुल इकाइयों का 81 *प्रतिशत* और 14 *प्रतिशत* बेचा।
- दो दुकानों ने एक किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बीयर की शून्य इकाइयां बेचीं, जबकि अन्य दुकानों के लिए इसकी औसत बिक्री 50,000 इकाइयों से अधिक थी।
- डेनिस स्पेशल व्हिस्की ब्रांड की कुल 70,053 इकाइयों में से अकेले तीन दुकानों ने केवल 67 की बिक्री की।
- व्हिस्की के लोकप्रिय ब्रांडों में से एक (एमसीडी नंबर 1 क्लासिक ब्लेंड व्हिस्की) की प्रति दुकान औसतन 24,000 बोतलें बिकती थीं और दिल्ली भर में कुल बिक्री का 27 प्रतिशत अकेले एक दुकान द्वारा बेचा गया था।
- एक अन्य लोकप्रिय ब्रांड - ऑफिसर्स चॉइस ब्लू डीलक्स ग्रेन व्हिस्की की प्रति दुकान 38,000 से अधिक बोतलों की औसत बिक्री हुई, जबकि दो विशेष दुकानों ने उसकी शून्य इकाइयाँ बेचीं।

लेखापरीक्षा द्वारा उपर्युक्त विश्लेषण अनधिकृत विचलन और ब्रांड पुशिंग के जोखिम से निपटने के लिए आबकारी विभाग द्वारा विस्तृत और गहन समीक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अनुशंसा:

2.1: वास्तविक समय एंड-टू-एंड बारकोड ट्रैकिंग से पुरानी एमएसआर-गैप विधि को प्रतिस्थापित करना चाहिए, जबकि बारकोड दोहराव और दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षित बारकोड लेबल को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। अनुपालन में कमी के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

2.2: असंगत डेटा और आसान पहचान के लिए रेड फ्लैग्स के स्वचालित उत्पत्ति और विश्लेषण में मदद के लिए डेटा विश्लेषणात्मक उपकरण तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिद्म का उपयोग किया जाना चाहिए।

2.3 कार्यान्वयन एजेंसी को ₹ 24.23 करोड़ का अनुचित लाभ

कार्यान्वयन एजेंसी प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) पर बिक्री के दौरान स्कैनिंग द्वारा केवल प्रमाणित बारकोड के लिए भुगतान की हकदार थी। परियोजना की शुरुआत से नवंबर 2022 तक, यह राशि ₹ 65.88 करोड़[19] थी, जबकि उसी अवधि के दौरान कार्यान्वयन एजेंसी को ₹ 90.11 करोड़ की वास्तविक भुगतान देयता सृजित की गई थी। पीओएस पर वास्तविक प्रमाणीकरण के बिना अर्थात् स्टॉक-टेक-सोल्ड एक्सरसाइज के माध्यम से बेची गई बोतलो के लिए गैप राशि ₹ 24.23 करोड़ (सेवा कर/जीएसटी को छोड़कर) के भुगतान पर विचार किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शुरूआत में खराब स्कैनिंग और भुगतान के लिए परिणामी अयोग्यता के बावजूद, एक विभागीय समिति ने स्टॉक-टेक-सोल्ड श्रेणी के लिए भी तीन महीनों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को तदर्थ भुगतान की सिफारिश की थी। मामला वित्त विभाग को भेजा गया था जिसने उठाए गए मुद्दों का समाधान किए बिना भुगतान की मंज़ूरी दे दी (मई 2014)। तत्पश्चात, आबकारी विभाग ने वित्त विभाग की राय/अनुमोदन मांगा (अप्रैल 2015) जिस पर वित्त विभाग ने बनाए गए और बेचे गए बारकोड के मिलान का आदेश दिया। मिलान संतोषजनक रूप से नहीं किया गया था, लेकिन भुगतान जारी रहा।

स्टॉक-टेक-सोल्ड श्रेणी के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान के मुद्दे पर पुनर्विचार नहीं किया गया था और विभाग ने स्टॉक-टेक-सोल्ड श्रेणी अर्थात् बोतलें/पेटी जिन्हें

[19] प्रत्येक बारकोड पर 15 पैसे भुगतान देयता सहित, मार्च 2021 तक 346.09 करोड़ बारकोड स्कैन किए गए, और अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 के बीच 93.12 करोड़ बारकोड स्कैन किए गए।

स्कैन किए बिना बिका हुआ के रूप में दिखाया गया था के लिए भी कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान जारी करना जारी रखा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिना स्कैन की गई बोतलों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान जारी करना अनुबंध की शर्तों के अनुसार नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन एजेंसी को अनुचित लाभ हुआ।

सरकार ने, अपने जवाब में, मास्टर सर्विस ऐग्रीमेंट की अनुसूची VI का हवाला देते हुए कहा कि डेटा सेंटर में "कैप्चर किए गए डेटा" के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान जारी किया गया है और भुगतान बिक्री के दौरान अंतिम स्कैनिंग पर निर्भर नहीं था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुसूची VI के खंड सी(i) से सी(iv) की उपेक्षा की है जो कैप्चर किए गए डेटा के लिए भुगतान पात्रता को रेखांकित करता है। अनुसूची VI में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कार्यान्वयन एजेन्सी को भुगतान के लिए पात्र होने से पहले डेटा सेंटर में कैप्चर किए गए डेटा (पीओएस पर बेचा, क्षतिग्रस्त, समाप्त आदि के रूप में चिह्नित) को प्रमाणित किया जाना चाहिए। एमएसआर-गैप के लिए भुगतान करने का निर्णय अनुसूची VI के विपरीत था।

2.4 ईएससीआईएमएस के ईआईबी मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जाना

मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) की धारा 2.1 के अनुसार, परियोजना के चरण-II में आबकारी खुफिया ब्यूरो (ईआईबी) के लिए एक मॉड्यूल के कार्यान्वयन की आवश्यकता है। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मॉड्यूल पूरी तरह से निष्क्रिय था जिसमें कोई डेटा नहीं था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि विभाग में अवैध शराब की जब्ती से संबंधित डेटा (सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में) रखा जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार उसका विश्लेषण किया जा रहा है। साथ ही, ईएससीआईएमएस में एसीपी (ईआईबी) और इंस्पेक्टर (ईआईबी) की भूमिका की व्यवस्था की गई है और भविष्य में इसका उचित उपयोग किया जाएगा।

ईआईबी आबकारी विभाग के नियामक कार्य के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है और एकत्र किए गए डेटा का उपयोग तस्करी संभावित क्षेत्रों के मैपिंग, तस्करी के अधिक प्रवण ब्रांडों पर कार्रवाई करने और एनडीपीएल के स्रोत/उत्पत्ति के बारे में जानकारी के माध्यम से तस्करी की जांच करने के लिए अन्य राज्य के आबकारी विभाग

के साथ समन्वय आदि पर आधारित ईआईबी/प्रवर्तन छापे की योजना बनाने में खुफिया कार्रवाई हेतु विभाग की सहायता के लिए किया जा सकता है।

इस प्रकार, आबकारी विभाग ने राजस्व रिसाव को रोकने या अपने नियामक कार्य में सहायता करने के लिए मॉड्यूल का लाभ नहीं उठाया।

अनुशंसा *2.3: अधिक प्रभावी प्रवर्तन कार्य के लिए कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी उत्पन्न करने के लिए ईआईबी मॉड्यूल का उपयोग किया जाना चाहिए।*

2.5 सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया

मास्टर सेवा अनुबंध (एमएसए) की अनुसूची VIII के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी के निष्पादन का आकलन करने के लिए आबकारी विभाग द्वारा एसएलए अनुपालन रिपोर्ट तैयार की जानी थी। इस आधार पर कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान पर निर्णय लेने के लिए एक आवश्यक पद्धति का निर्माण किया जाएगा।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये एसएलए अनुपालन प्रतिवेदन कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ही तैयार और प्रस्तुत किए गए थे तथा विभाग द्वारा विस्तृत जांच के बिना स्वीकार कर लिए गए थे। जबकि, एसएलए की वार्षिक रूप से विस्तृत विवरण और समीक्षा[20] की जानी थी।

साथ ही, डेटा शुद्धता जैसे कुछ महत्वपूर्ण एसएलए मीट्रिक्स की बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं की गई थी। एमएसए के अनुसार, डेटा शुद्धता की माप रोज की जानी थी और साप्ताहिक आधार पर 99.99 (*प्रतिशत*) के लक्ष्य मूल्य के साथ रिपोर्ट किया जाना था। पीएमयू ने यह भी कहा (अप्रैल 2014) कि बाद में मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) लेखापरीक्षा डेटा शुद्धता की पुष्टि करेगा। ऐसी कोई तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने ईएससीआईएमएस डेटा में अशुद्धियों के विभिन्न उदाहरण देखे, जिन्हें कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार एसएलए प्रतिवेदनों में कभी रिपोर्ट नहीं किया गया था, इसका प्रभाव कार्यान्वयन एजेंसी को किए गए भुगतान पर होता है। यदि पद्धति का अनुपालन और प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया तो कार्यान्वयन समिति से वसूली (एन लगातार महीनों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी की राशि का एन*0.1 प्रतिशत) की जानी थी।

---

[20] अनुसूची के 1.3(iii) के अनुसार

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कई मामलों में, ईएससीआईएमएस डेटा के अनुसार एक लाइसेंसधारी के पास पाई गई बोतलें/पेंटी दूसरे लाइसेंसधारी के पास मौजूद थीं। ऐसे मामलों में, कोई सिस्टम रेड फ़्लैग नहीं बनाया गया जिसके कारण डेटा विसंगति का पता नहीं चला। लेखापरीक्षा ने आबकारी विभाग के 17 अगस्त 2021 के आदेश से आगे देखा कि डुप्लिकेट परिवहन परमिट ईएससीआईएमएस प्रणाली द्वारा बनाये गये थे।

विशेष रूप से, ईएससीआईएमएस की हैकिंग का एक मामला जुलाई 2019 के दौरान नोट किया गया था, फाईल में न तो प्रासंगिक एसएलए (पोर्टल सुरक्षा) पर इसके प्रभाव का उल्लेख है और न ही इस तरह के उल्लंघन का कारण बताया गया है। लेखापरीक्षा ने सुरक्षा उल्लंघन के लिए जिम्मेदार कमजोरियों की जानकारी मांगी तथा पूछा कि क्या कमजोरियों को बाद में ठीक कर लिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया।

सरकार ने अपने जबाव में केवल एमएसए से केवल एसएलए अनुपालन मापदंडों का उल्लेख किया और कहा कि अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी की जा रही थी।

जवाब संतोषजनक नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा को एसएलए निगरानी उपकरण तक पहुंच प्रदान नहीं की गई थी। दावे के समर्थन में विस्तृत मासिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई थी। डेटा शुद्धता तथा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्वयं एसएलए रिपोर्ट तैयार करने से संबंधित अन्य मुद्दों पर टिप्पणी नहीं की गई थी।

अनुशंसा 2.4: सेवा स्तर का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाना चाहिए और विभाग द्वारा विशेष रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

2.6 निकास प्रबंधन योजना का अभाव

टीसीएस के साथ अनुबंधित अवधि[21] के बाद, परियोजना और उसकी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए एक निकास प्रबंधन योजना, समझौते की प्रभावी तिथि से 90 दिनों की अवधि में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार और प्रस्तुत की जानी थी, और उसके बाद अनुसूची II की धारा 1.2 के अनुसार, वार्षिक रूप से पुनः तैयार की जानी थी।

[21] टीसीएस यानी कार्यान्वयन एजेंसी के साथ अनुबंध शुरुआती 7 साल की अवधि के लिए था जिसे समान शर्तों पर 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता था। इसके बाद परियोजना को आबकारी विभाग या एक अलग कार्यान्वयन एजेंसी को हस्तांतरित किया जाना था।

विभाग निकास प्रबंधन योजना उपलब्ध नहीं करा सका। निकास प्रबंधन योजना के अभाव में, आबकारी विभाग आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कार्य को स्वतंत्र रूप से संभालने में सक्षम नहीं था, न ही इसे किसी अन्य प्रतिस्थापन कार्यान्वयन एजेंसी को देने में सक्षम था।

ईएससीआईएमएस एक डीबीओओटी परियोजना थी, जिसका अनिवार्य रूप से अर्थ है किसी संपत्ति को विभाग को हस्तांतरित करना। एमएसए में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रचलन के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं थे। इस प्रकार, दस वर्षों के कामकाज के बाद, विभाग के लिए कोई मूर्त/अमूर्त संपत्ति नहीं बनाई गई।

एमएसए में आवश्यकता के अनुसार परियोजना निदेशक (विभाग) के कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के दायित्व पर एक धारा भी थी। हालाँकि, विभाग निर्माण क्षमता और ज्ञान हस्तांतरण की प्रगति के संबंध में कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहा।

अद्यतन निकास प्रबंधन योजना के अभाव के साथ-साथ क्षमता निर्माण उपायों की कमी के कारण, विभाग को सिस्टम स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हो सका।

सरकार ने अपने जबाव में कहा कि निकास प्रबंधन योजना 14 मार्च 2022 को विभाग को प्रस्तुत की गई है। हालाँकि, निकास प्रबंधन योजना की प्रति लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

अनुशंसा 2.5: कार्यान्वयन एजेंसी से ज्ञान हस्तांतरण और विभाग द्वारा सिस्टम स्वामित्व को सक्षम करने के लिए निकास प्रबंधन योजना को अद्यतन किया जाना चाहिए।

2.7 विभाग द्वारा पीएमयू की भूमिका संभालने के बाद निगरानी का अभाव

दिसंबर 2012 में, आबकारी विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) के रूप में नियुक्त किया था (बाद में जून 2016 तक बढ़ा दिया गया)। एनआईएसजी, पीएमयू के रूप में, परियोजना की योजना और निगरानी के लिए जिम्मेदार था। बाद में, आबकारी विभाग ने एनआईएसजी से पीएमयू की भूमिका ग्रहण की (जुलाई 2016)।

प्रारंभ में, एमएसए की अनुसूची IV के अनुसार नियम प्रक्रियाओं के प्रबंधन की सुविधा के लिए एनआईएसजी को पीएमयू के रूप में नियुक्त किया गया था। यह मुख्य रूप

से मासिक निष्पादन रिपोर्ट, परिवर्तन नियंत्रण, विवाद समाधान आदि के मूल्यांकन के संबंध में मासिक बैठकों को कवर करता है। जुलाई 2016 के बाद, विभाग ने एनआईएसजी से पीएमयू की भूमिका अधिग्रहण किया। लेखापरीक्षा अवधि के लिए बैठकों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। एक क्रियाशील पीएमयू के अभाव में, सेवा प्रदाता की दक्षता और प्रभावशीलता का पता नहीं लगाया जा सका। इससे समझौते में परिकल्पित परियोजना उद्देश्यों की प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न हुई।

निकास प्रबंधन योजना के अभाव के साथ-साथ अपर्याप्त परियोजना निगरानी के कारण वेंडर यानी कार्यान्वयन एजेंसी पर विभाग की निर्भरता लगातार बनी हुई है।

सरकार ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया और अपने जवाब में कहा कि आबकारी विभाग आईटी संवर्ग अधिकारियों की भारी कमी के तहत काम कर रहा है और रिक्त पदों को भरने और पदों के निर्माण का प्रस्ताव पहले ही सितंबर 2020 में कैडर नियंत्रण प्राधिकरण को भेजा जा चुका है।

अनुशंसा 2.6: परियोजना को लंबे समय तक टिकाऊ और उपयोगी बनाने के लिए एक कुशल परियोजना निगरानी टीम का गठन किया जाना चाहिए।

2.8 एक्साइज ऐडहेसिव लेबल लागू करने में विफलता

ईएससीआईएमएस द्वारा अपने लक्षित उद्देश्य को पूरा करने में विफलता, लेबल के दुरूपयोग और दोहराव के साक्ष्य के बावजूद, विभाग ने कमियों को दूर करने और सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रक्रिया शुरू नहीं की।

उन्नत सुरक्षा सुविधाओं सहित, एक्साइज ऐडहेसिव लेबल (ईएएल) सुरक्षित लेबल हैं, जो आपूर्ति की प्रामाणिकता, पता लगाने की क्षमता और सुरक्षा पहलुओं को सुनिश्चित करता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (भा.स.) ने दिल्ली में ईएएल के कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस की सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया था। इसकी सूचना आबकारी विभाग को पत्र (दिनांक 19 मार्च 2019) के माध्यम से दी गई थी। यह पत्र मिलने के बाद आबकारी विभाग ने इस मुद्दे को उठाया। अंत में, कर अपवंचन से बचने और आपूर्ति श्रृंखला में रिसाव को रोकने के लिए ईएएल की शुरूआत के लिए केबिनेट (30 जुलाई 2020) की मंजूरी एक साल और तीन महीने की देरी के बाद प्राप्त की गई थी।

यह भी देखा गया कि विभाग ने इएएल के साथ उपयोग की जाने वाली एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र रूप से आईआईटी कानपुर (नेशनल सेंटर फॉर फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स) को शामिल किया (सितम्बर 2019)। आईआईटी कानपुर ने एक तकनीक की पेशकश की जिसे ट्रांसपैक्स टेक्नोलॉजीज द्वारा पेटेंट किया गया था। हालांकि, इसके बारे में कोई पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि इस प्रौद्योगिकी को शामिल करने से इएएल में सुधार कैसे होगा। इसके अलावा, इस सुविधा को शामिल करने से लाइसेंसिंग और तकनीकी हस्तांतरण के लिए लागत में वृद्धि हो सकती है और 3 डी टैग की उच्च रिज़ॉल्यूशन छवि के भंडारण के लिए अलग क्लाउड आधारित समाधान की आवश्यकता हो सकती है।

एसपीएमसीआईएल[22] के एक संघटक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस (एसएसपीएच), हैदराबाद और आबकारी विभाग के द्वारा समझौते पर 7 सितम्बर 2020 को हस्ताक्षर किया गया। जिसमें उस तकनीक का उपयोग करने के उद्देश्य से आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग के लिए एक शर्त शामिल थी। हालांकि, दोनों प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हुए ड्राई रन (पिछली बार अप्रैल 2022 में आयोजित) के दौरान, हार्डवेयर असंगति, आकार और लेबल के डिजाइन से संबंधित मुद्दे देखे गए लेकिन इनका समाधान नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, समझौते पर हस्ताक्षर करने से 19 महीने (अप्रैल 2022 तक) के अंतराल के बाद भी, सुनिश्चित डिजाइन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और कैबिनेट की मंजूरी के बाद काफी समय बीत जाने के बाद भी परियोजना को लागू नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि उसके बाद ईएएल के कार्यान्वयन के संबंध में फाइल पर कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई थी। मूल्य निर्धारण के संबंध में प्रारंभिक शर्तें वर्ष 2022-23 के अंत में समाप्त हो गईं।

ईएएल के कार्यान्वयन की विफलता के संबंध में, विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि विलंब का कारण कोविड 19 महामारी, नई नीति का कार्यान्वयन और बाद में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा नई नीति की जांच थी। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि 2010 से जो अध्ययन किया गया, उसके परिणामस्वरूप ईएएल के पक्ष में निर्णय आया है। हालाँकि, ईएएल को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से निर्णय नहीं लेने के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा, परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई

[22] सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

प्रगति नहीं देखी जा सकी (मार्च 2023)। परिणामस्वरूप, ईएएल के माध्यम से शराब की आपूर्ति पक्ष की प्रमाणिकता, पता लगाने और सुरक्षा पहलुओं का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सका।

2.9 निष्कर्ष

आबकारी आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली (ईएससीआईएमएस) को मुख्य रूप से शराब की एंड-टू-एंड ट्रैकिंग के माध्यम से अधिक कुशल विनियमन को सक्षम बनाने के लिए लागू किया गया था। हालांकि, शराब की बारकोड आधारित ट्रैकिंग का कार्यान्वयन प्रभावी नहीं था। पूर्ण स्कैनिंग को लागू करने के प्रयास कमजोर थे और बिक्री डेटा की असंगत रिपोर्टिंग का विश्लेषण करके चूककर्ताओं की पहचान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे। इनवेंटरी के मिलान के लिए एमएसआर-गैप पद्धति का प्रयोग सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ। डेटा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा, इसने एंड-टू-एंड ट्रैकिंग के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया क्योंकि स्टॉक के एक बड़े हिस्से को स्कैनिंग के द्वारा प्रमाणित किए बिना बेचा हुआ माना गया था।

ईएससीआईएमएस के प्रबंधन और निगरानी में विभाग की भागीदारी कम थी। सेवा स्तर के अनुपालन की निगरानी कम की गई है। विभाग द्वारा यह भूमिका संभालने के बाद से परियोजना निगरानी कार्य निराशाजनक रहा था। इसके अतिरिक्त, राजस्व की बर्बादी को रोकने हेतु कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए ईआईबी मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया गया था। निकास प्रबंधन योजना की कमी ने विभाग को वेंडर लॉक-इन स्थिति में डाल दिया। नियोजित डीबीओओटी परियोजना कार्यान्वयन मॉडल के विपरीत, विभाग कार्यान्वयन एजेंसी टीम पर निर्भर रहा। सुरक्षा बढाने के लिए एक्साइज एडहेसिव लेबल की परियोजना, मंत्रिमंडल की मंजूरी के ढाई वर्ष बाद भी लागू नहीं हो सका।

अध्याय III

लाइसेंस जारी करना

अध्याय III: लाइसेंस जारी करना

शराब की आपूर्ति से संबंधित खुदरा और थोक संचालन के लिए दिल्ली आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के लाइसेंस दिये जाते हैं और संबंधित लाइसेंस श्रेणी के लिए "लाइसेंस देने हेतु नियम और शर्तों" में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने पर वार्षिक रूप से पुनः जारी या नवीनीकृत किया जाता है। "नियम और शर्तों" का आबकारी अधिनियम, 2009 और आबकारी नियमावली, 2010 के प्रासंगिक परिचालन प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। लाइसेंस जारी/नवीनीकरण करने से पहले अनुपालन जांच में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लाइसेंसधारी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से व्यवसाय करता हो तथा उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं हो और वह शोधन-क्षम हो इत्यादि।

लेखापरीक्षा में कई अनियमितताएं पाई गई संबंधित पार्टियों को लाइसेंस जारी किए गए जोकि दिल्ली आबकारी नियमों के नियम 35 का उल्लंघन था। आबकारी अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में, विभाग ने लाइसेंसधारी से अपराधिक पृष्ठभूमि, कर्मचारियों की आयु, आदि की शर्तों जैसे मामलों पर केवल एक हलफनामा लिया है। अन्य राज्यों द्वारा वर्ष भर में घोषित बिक्री और थोक मूल्य, के संबंध में डेटा प्रस्तुत न करने के बावजूद लाइसेंस जारी किए गए थे।

3.1 परिचय

विभाग दिल्ली में शराब आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों को निम्नलिखित प्रकार के लाइसेंस जारी करता है।

चार्ट 3.1: लाइसेंस के प्रकार[23]

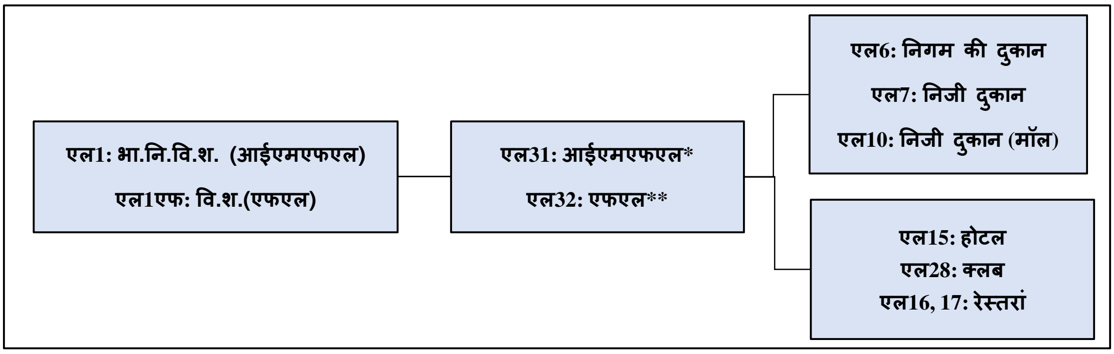

** एल31 की एल1 के बॉन्डेड वेयरहाउस के लिए दिया गया है, ** एल32 को एल1एफ के बॉन्डेड वेयरहाउस के लिए दिया गया है।*

[23] ये लाइसेंस के प्रकार 17 नवंबर 2021 और 31 अगस्त 2022 के बीच प्रभावी आबकारी नीति व्यवस्था के अतिरिक्त अवधि के लिए लागू थी। आबकारी नीति 2021-22 की अवधि हेतु लाइसेंस के प्रकारों का उल्लेख अध्याय VIII में किया गया है।

आबकारी विभाग द्वारा उचित लाइसेंस जारी करने/नवीनीकरण के लिए हर साल इच्छुक पार्टियों को आवेदन करना होता है। लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए 59 लाइसेंसधारियों का चयन किया था, जिन्हें 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान लाइसेंस जारी किए गए थे। इनमें से केवल 46 लाइसेंसधारियों[24] से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे। इन 46 लाइसेंसधारियों को लाइसेंस जारी करने/नवीकरण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में विभिन्न अनियमितताएँ पायी गयी। जिसकी चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

अनुशंसा 3.1: 13 लाइसेंसधारियों की लेखापरीक्षा से संबंधित अभिलेखों की गैर प्रस्तुति के लिए उत्तरदायित्व नियत किया जाना चाहिए।

3.2 संबंधित पक्षों को लाइसेंस अनियमित रूप से जारी करना

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 का नियम 35 निम्नलिखित निर्धारित करता है:

- किसी भी व्यक्ति को एक[25] से अधिक थोक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
- थोक लाइसेंस धारक को शराब की खुदरा बिक्री[26] के लिए और खुदरा लाइसेंसधारक को शराब की थोक बिक्री के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
- परिसर के बाहर शराब के सेवन के लिए कोई खुदरा लाइसेंस किसी अन्य खुदरा लाइसेंस रखने वाले[27] व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।

सभी लाइसेंसधारियों को सभी निदेशकों, भागीदारों आदि के नाम घोषित करने[28] और एक भागीदार को जोड़ने और हटाने तथा इस संबंध में एक शपथ पत्र[29] प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। उपर्युक्त प्रावधानों को मुख्य रूप से एकाधिकार के गठन को रोकने और उपभोक्ता वरीयताओं के अनुसार शराब के ब्रांडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के

---

24 11 एल1, 3 एल1 एफ, 8 एल6, 4 एल7, 8 एल10, 12 एचसीआर

25 बशर्ते कि फॉर्म एल-1 में लाइसेंस धारक को फॉर्म एल1एफ में लाइसेंस दिया जा सकता है: बशर्ते कि फॉर्म एल-1 और एल-9 में लाइसेंस के उद्देश्य के लिए, प्रत्येक डिस्टिलरी, ब्रूवरी, वाइनरी और बॉटलिंग प्लांट को एक अलग इकाई के रूप में माना जाएगा।

26 परिसर के "बंद" उपभोग के लिए और परिसर में "खुला" उपभोग के लिए; बशर्ते कि एल-1 लाइसेंस धारक को फॉर्म एल-9 में उसके द्वारा उत्पादित ब्रांडों की खुदरा बिक्री के लिए विशेष रूप से लाइसेंस दिया जा सकता है।

27 बशर्ते कि फॉर्म एल-6, एल-8 और एल-14 में एक से अधिक लाइसेंस किसी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं

28 दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 37 और नियम 38

29 दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 13 और दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 23 और 35 के तहत, आवेदक को आवेदन की तिथि से पहले पांच साल की अवधि के दौरान किसी भी लाइसेंस धारी के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है।

लिए तथाकथित शामिल किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में देखे गए मामले जहाँ संबंधित पक्षों[30] को एक से अधिक लाइसेंस जारी किए गए को **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: संबंधित पक्षों को एकाधिक लाइसेंस

<table>
<tr><th>नियम का उल्लंघन</th><th colspan="6">लाइसेंसधारी का नाम और प्रकार</th><th>टिप्पणियां</th></tr>
<tr><td rowspan="3">एक दूसरे से संबंधित थोक लाइसेंसधारी</td><td colspan="3">(क)</td><td colspan="3">(ख)</td><td rowspan="2">उसी वर्ष में (2019-20, 2020-21 के लिए) सामान्य निदेशक साथ ही सामान्य निदेशक (निदेशकों) के माध्यम से लाइसेंस जारी करने से पहले 5 वर्ष की अवधि में जुड़ा हुआ था।</td></tr>
<tr><td colspan="3">एडी ब्रोसवॉन ब्रिवरीज प्राइवेट लिमिटेड (एल 1)</td><td colspan="3">एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड (एल 1)</td></tr>
<tr><td colspan="3">इंडोस्पिरिट्स डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (एल1एफ)</td><td colspan="3">इंडोस्पिरिट्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (एल1एफ)</td><td>उसी वर्ष (2017-18, 2018-19 के लिए) में सामान्य निदेशक। साथ ही सामान्य निदेशक (निदेशकों) के माध्यम से लाइसेंस जारी करने से पहले 5 वर्ष की अवधि में जुड़ा हुआ था।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">खुदरा बिक्री लाइसेंसधारियों से संबंधित थोक लाइसेंसधारी</td><td colspan="3">बद्दी (पंजाब) बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड (एल 1)</td><td colspan="3">बद्दी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (एल 10),
बद्दी मंत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एल 10),
बद्दी मंत्रा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (एल 10),
बद्दी टी1 दिल्ली रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (एल 10),
बद्दी (टी3 दिल्ली) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (एल 10),
वीतराग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>उसी वर्ष (2018-19, 2019-20 के लिए) में सामान्य निदेशक। साथ ही सामान्य निदेशक (निदेशकों) के माध्यम से लाइसेंस जारी करने से पहले 5 वर्ष की अवधि में जुड़ा हुआ था।</td></tr>
<tr><td colspan="3">इंडो-स्पिरिट बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड (एल 1),
इंडो-स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (एल1एफ),
इंडो-स्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (एल1एफ)</td><td colspan="3">इंडो-स्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड (एचसीआर),
ए2जेड ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>उसी वर्ष (2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए) सामान्य निदेशक। साथ ही सामान्य निदेशक (निदेशकों) के माध्यम से लाइसेंस जारी करने से पहले 5 वर्ष की अवधि में जुड़ा हुआ था।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">एक दूसरे से संबंधित खुदरा बिक्री लाइसेंसधारी</td><td colspan="3">इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड (एचसीआर);</td><td colspan="3">ए2जेड ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>उसी वर्ष (2017-18 के लिए) सामान्य निदेशक। साथ ही सामान्य निदेशकों के माध्यम से लाइसेंस जारी करने से पहले 5 वर्ष की अवधि में जुड़ा हुआ था।</td></tr>
<tr><td>बद्दी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>बद्दी मंत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>बद्दी मंत्रा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>बद्दी टी1 दिल्ली रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>बद्दी (टी3 दिल्ली) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>वीतराग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (एल 10)</td><td>निदेशक (ओं) के माध्यम से लाइसेंस जारी करने से पहले 5 वर्ष की अवधि में जुड़ा हुआ था। उसी वर्ष (2017-18 के लिए) सामान्य निदेशक।</td></tr>
</table>

** उसी वर्ष में सामान्य निदेशकों की सूची **अनुलग्नक** III में दी गई है।*

*** लाइसेंस जारी करने से पहले पांच साल की अवधि में जुड़े निदेशकों की सूची **अनुलग्नक** IV में दी गई है।*

[30] सामान्य निदेशकों

तालिका 3.1 में, सैल (क) में उल्लिखित लाइसेंसधारी उसी पंक्ति के सैल (ख) में उल्लिखित लाइसेंसधारियों से संबंधित हैं। लेखापरीक्षा ने लाइसेंस जारी करने और समाप्ति तिथियों के लिए इएससीआइएमएस के डेटा का उपयोग किया है; तथा निदेशकों की नियुक्ति की मूल तिथि और समाप्ति की तिथि की सूची के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की वेबसाइट से डेटा का इस्तेमाल किया।

तालिका 3.1 की अंतिम पंक्ति में उल्लिखित छः लाइसेंसधारी (एल10) सामान्य निदेशक से संबंधित पाए गए। सभी मामलों में कंपनी का ईमेल डोमेन, जैसाकि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट में कंपनी के मेल पते में दिखाया गया था, वही था। कुछ मामलों में, कंपनी का ई-मेल पता भी वही था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि तत्काल मामलों में नियम 35 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि तालिका में उल्लिखित सभी छः थोक लाइसेंसधारी अलग-अलग संस्थाओं से थे और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत थे।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दो अलग-अलग कंपनियों में सामान्य निदेशक निर्णय लेने को प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में, जिन कंपनियों ने अपना लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत किया था, उनके लिए यह पाया गया कि निदेशकों ने सहयोगी कंपनी को असुरक्षित ऋण दिया था और मूल शेयरधारक थे। कंपनियों को संबद्ध कंपनी के रूप में भी उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, एल7 और एल10 के मामले में, यह नियमों और शर्तों का भी स्पष्ट उल्लंघन था कि एल1 लाइसेंस रखने वाले किसी भी डिस्टिलरी में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के पास एल7/एल10 लाइसेंस नहीं होना चाहिए।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि लाइसेंसधारियों के अन्य समूह (एल-7 और एल-10) भी थे, जिनके पास संबंधित दुकानों का मालिकाना हक भी था और जो संबंधित भी हो सकते थे। ऐसे पांच मामले थे, जिनमें दो या दो से अधिक लाइसेंसधारियों के समान लाइसेंसधारी नाम थे जिसका विवरण **अनुलग्नक V** में दिया गया है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि एल7 लाइसेंस वर्ष 2002-03 के दौरान प्रदान किए गए थे और उस वर्ष के नियम और शर्तों (नि. एंड श.) के खंड 1.4 के अनुसार, दिल्ली में एक राजस्व जिले में दो एल-52 (अब एल7) लाइसेंस प्राप्त हो सकते हैं और राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली में कुल सात लाइसेंस प्राप्त हो सकते थे। इसलिए नियम 35 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 उपर्युक्त नियमों और शर्तों के बाद अधिनियमित किए गए थे इसलिए नियम 35 को नियम एवं शर्तों पर वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस के नवीनीकरण की शर्तों के खंड 6 में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन होना चाहिए। इस प्रकार यह, नियम 35 का स्पष्ट उल्लंघन था।

अनुशंसा 3.2: सरकार को दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी लाइसेसों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। सरकार को इन सभी मामलों की भी जांच करनी चाहिए और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघन मे लाइसेंसधारियों के बीच संबंध स्थापित करने वाली जानकारी की अनदेखी के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इसके अलावा, संबंधित पक्षों को एकाधिक लाइसेंस जारी नहीं किए जाने चाहिए। इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए जाने चाहिए।

3.3 अपराधिक पृष्ठभूमि के सत्यापन के बिना लाइसेंस जारी/नवीकरण करना

आबकारी अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) के अनुसार, एक लाइसेंसधारी को लाइसेंस जारी करने के तीस दिन के भीतर जिले के पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस देने के लिए अपने नियमों और शर्तों में ऐसे प्रमाणपत्र की आवश्यकता की अनदेखी की गई और इसके बजाय अनुपालन के संबंध में केवल एक हलफनामा/ब्यौरा मांगा गया। इस प्रकार, 2017-21 की अवधि के लिए नमूना-जांच किए गए 46 लाइसेंसधारियों में से किसी के भी अभिलेखों में ऐसा कोई प्रमाण-पत्र नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा ने आबकारी विभाग को एक शिकायत के माध्यम से एक लाइसेंसधारी के खिलाफ एफ.आई.आर. की प्रति दी, जबकि विभाग को एफ.आई.आर. के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी। तत्पश्चात शुरू में सितंबर 2018 में लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था क्योंकि लाइसेंसधारी एफआईआर और कई अन्य

आपत्तियों के बारे में सूचित करने में विफल रहा था। लेकिन दिनांक 6 नवंबर 2018 के आदेश में ₹ 8 लाख का जुर्माना लगाकर लाइसेंस बहाल कर दिया गया।

इस प्रकार, लाइसेंसधारियों की पात्रता को सत्यापित किए बिना लाइसेंस जारी किए गए, जिससे आबकारी विभाग को आवेदक के वास्तविक पृष्ठभूमि के बारे में अंधेरे में रहा।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि सभी लाइसेंसधारियों से इस आशय का एक वचन पत्र/शपथ पत्र लिया गया था कि धारा 13(1)(सी) के अनुपालन में उनके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अन्य मामला लंबित नहीं है। इसके अलावा, यदि शपथ पत्र झूठा/फर्जी पाया गया तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता था और लाइसेंसधारी दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि आबकारी विभाग ने अच्छे नैतिक चरित्र और कोई अपराधी रिकॉर्ड न होने के संबंध में लाइसेंसधारी से स्व-शपथ पत्र लिया जो प्रमाण पत्र जिलें के अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से प्राप्त करना था जिसके कारण दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 13 (1) (सी) का अक्षरशः पालन नहीं किया।

अनुशंसा 3.3: आबकारी विभाग द्वारा सभी लाइसेंसधारियों के लिए इस अपराधिक पृष्ठभूमि को सत्यापित किया जाना चाहिए और दिल्ली आबकारी अधिनियम का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। नियम और शर्तों के खंड जो आबकारी अधिनियम और नियमों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

3.4 जारी किए गए लाइसेंस के अनुवीक्षण के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों की गैर-अनुपालना

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2019-20 के लिए एक एल1 लाइसेंसधारी (एडीएस स्पिरिट्स) के लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन पर विचार करते हुए, उपायुक्त (आबकारी) ने लाइसेंसधारी से संबंधित जब्त की गई शराब का डेटा मांगा (अगस्त 2019)। तदनुसार, पिछले वर्ष में जब्त की गई शराब का डेटा प्रदान किया गया, जिससे पता चला कि एनडीपीएल/अवैध शराब के लिए ईआईबी द्वारा दर्ज (अगस्त 2018 से अगस्त 2019 तक) कुल 736 एफआईआर में से 307 एक लाइसेंसधारी के ब्रांड्स की थीं। 2018-20 के दौरान, कुल जब्त की गई 1,08,704 बोतलों में से, 49640 बोतलें (अर्थात् 46 *प्रतिशत*) लाइसेंसधारी द्वारा पंजीकृत ब्रांड से संबंधित थी।

जब्त की गई शराब के मामलों में इस लाइसेंसधारी की प्रधानता के बावजूद विभाग ने उसकी संलिप्तता की जांच किए बिना लाइसेंस का नवीकरण किया उपायुक्त (आबकारी) के इस निर्देश के साथ कि इस लाइसेंसधारी की तिमाही के आधार पर अनुविक्षण की जाएगी। हालांकि, दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि लाइसेंसधारियों के बजाय व्यक्तिगत/वाहनों के व्यक्तियों के नाम पर शराब तस्करों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और जब्त किए गए ब्रांड दिल्ली में पंजीकृत नहीं थे। इसके अलावा, लाइसेंसधारी ने दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 13 के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आबकारी विभाग के कार्मिकों ने लाइसेंसधारी के प्रत्येक तीन महीनों की गतिविधियों के अनुवीक्षण करने के उपायुक्त (आबकारी) के निर्देशों को नज़रअंदाज किया था। प्रवर्तन रजिस्टरों ने उसके बाद दर्शाया कि लाइसेंसधारी के प्रति एक निरीक्षण भी कार्यान्वित नहीं किया गया था तथा यहाँ तक कि विभाग की प्रवर्तन गतिविधियों ने निर्देशों का पालन भी नहीं किया।

3.5 लाइसेंसधारियों की शोधनक्षमता सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी/नवीकरण करना

दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 13(1) (लाइसेंस देने की योग्यता) के अनुसार, लाइसेंस देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को यह ध्यान रखना होगा कि लाइसेंसधारी में शोधनक्षमता है।

तदनुसार, लाइसेंसधारी को निर्दिष्ट राशि के लिए नियम तथा शर्तों का एक शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था जैसाकि **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की आवश्यकता

लाइसेंस के प्रकार	शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की आवश्यकता
एल1	एसडीएम के पद अथवा ऊपर के पद के मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित दो लाख रुपये तक का शोधनक्षमता का प्रमाणपत्र
एल1एफ	शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं
एल7	मूल शर्तों पर नवीनीकरण, जिसमें ₹ 25 लाख का शोधनक्षमता प्रमाणपत्र शामिल था
एल10	एसडीएम/वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी ₹ 50 लाख का शोधनक्षमता प्रमाणपत्र
एल 6	शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं
होटल, क्लब और रेस्टोरेंट	शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि विभिन्न प्रकार के लाइसेंसधारियों के लिए शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की आवश्यकता सुसंगत नहीं थी, जैसा कि नीचे बताया गया है।

- थोक विक्रेताओं में जहां एल1 लाइसेंसधारियों को ₹ 2 लाख का शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था, वहीं एल1एफ लाइसेंसधारियों को इस तरह का कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। यह अनुचित और असंगत प्रतीत होता है, उनके लिए एक अधिक उदार नियम स्थापित करके विदेशी शराब के लाइसेंसधारियों के पक्ष में एक पूर्वाग्रह दिखा रहा है।
- थोक व्यापारी की व्यापार की क्षमता एक खुदरा विक्रेता की तुलना में बहुत अधिक है, हालांकि, एल10 खुदरा विक्रेता से मांग की गई शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की राशि (₹ 50 लाख) एक थोक व्यापारी (₹ 2 लाख) से मांग की गई राशि की तुलना में 25 गुना अधिक थी, जो अनुचित और तर्क से रहित प्रतीत होती है।
- आबकारी विभाग एल7 लाइसेंसधारियों को नियम एवं शर्तों जो प्रारंभ में (लाइसेंस जारी करने के समय) लागू थे, के आधार पर नवीकृत कर रहा था, अर्थात, ₹ 25 लाख के शोधनक्षमता प्रमाणपत्र के साथ। हालांकि, नए शोधनक्षमता प्रमाणपत्र लिए बिना लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया।
- शराब परोसने वाले होटल, क्लब और रेस्तरां के लिए शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई थी। उन्हें प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से छूट देने के कारण भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इस प्रकार, केवल एल1, एल7 और एल10 लाइसेंसधारियों को क्रमशः ₹ 2 लाख, ₹ 25 लाख और ₹ 50 लाख के लिए शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने 11 एल1 लाइसेंसधारियों, चार एल7 लाइसेंसधारियों और आठ एल10 लाइसेंसधारियों के अभिलेखों की जांच की, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या लाइसेंसधारी द्वारा अपेक्षित शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया और लाइसेंस जारी करने/नवीकरण से पहले विभाग द्वारा विचार किया गया।

इन 23 लाइसेंसधारियों से संबंधित 84 मामलों की वर्ष 2017-21 की जांच से पता चला कि केवल दो मामलों में, लाइसेंसधारियों ने इन लाइसेंसों के नियमों और शर्तों के अनुसार अपेक्षित शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 80 मामलों में, लाइसेंसधारी अपेक्षित शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल

रहे थे और शेष दो मामलों में, लाइसेंसधारी ने उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

आवेदक की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए शोधनक्षमता प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण है। हालांकि, आबकारी विभाग द्वारा शोधनक्षमता प्रमाणपत्र की आवश्यकता की उपेक्षा की गई तथा अपेक्षित शोधनक्षमता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के बावजूद आवेदकों को अंधाधुंध लाईसेंस जारी किये गये।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि अधिकांश एल-1 लाइसेंस धारक दिल्ली में कई वर्षों से लाइसेंसधारी थे। एल-1 द्वारा इम्पोर्ट परमिट (आईपी) प्रस्तुत करते ही आबकारी शुल्क अग्रिम ली जाती थी। इसके अलावा यह उल्लेख किया गया था कि, सरकारी राजस्व को कई तरह से जैसे सभी पंजीकृत ब्रांडों के लिए सावधि जमा प्रमाणपत्र लेना, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में आईपी/बार कोड आदि के लिए विभिन्न शुल्क/शुल्क का भुगतान करने के लिए अग्रिम राशि संरक्षित की गई थी। जवाब में आगे आश्वासन दिया गया कि अनुमोदित आबकारी नीति तथा नियम और शर्तों के अनुसार जहां कहीं भी आवश्यकता होगी, शोधनक्षमता प्रमाणपत्र ले लिए जाएंगे।

होटल, क्लब और रेस्तरां के संबंध में (एचसीआर) यह कहा गया था कि शोधनक्षमता प्रमाणपत्र नियम एवं शर्तों, आबकारी नियमों और नीति के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 ने विदेशी शराब के दीर्घकालिक लाइसेंसधारियों और प्रमुख आयातकों को शोधनक्षमता प्रमाणपत्र से कोई छूट प्रदान नहीं की।

3.6 यह सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी/नवीकरण करना कि लाइसेंसधारी पर कोई सरकारी बकाया नहीं है

दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 13(1)(डी) के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि लाइसेंसधारी का कोई सरकारी या सार्वजनिक बकाया नहीं है। इसके अलावा आबकारी विभाग और डी वी ए टी विभाग से नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एल1 लाइसेंस के नियमों और शर्तों में उचित खंड शामिल किए गए है। परंतु, खुदरा लाइसेंसधारी (एल-7 और एल-10) के नियमों और शर्तों में ऐसा

कोई खंड शामिल नहीं किया गया था, इसके विपरीत आवेदक से एक शपथपत्र मांगा गया था कि उनके खिलाफ कोई सरकारी बकाया नहीं था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एल7 और एल10 लाइसेंसधारियों को निर्धारण आदेश के साथ आयकर निकासी प्रमाणपत्र या नवीनतम आईटीआर जमा करना आवश्यक था, जबकि एल1 और एल1एफ को आईटीआर के साथ निर्धारण आदेश जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि आबकारी विभाग ने आईटीआर के माध्यम से, कर निर्धारण आदेश को सत्यापित किए बिना, यह कैसे सुनिश्चित किया कि आयकर विभाग के प्रति एल1 तथा एलएफ लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कोई बकाया लम्बित नहीं था। इस तरह की कमियां धारा 13 (1) (डी) की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थीं।

तालिका 3.3: एल-1, एल-7 और एल-10 लाइसेंसधारियों द्वारा अदेय प्रमाणपत्र जमा करने की स्थिति (2017-21 की अवधि के लिए 23 लाइसेंसधारियों के 84 मामलों से संबंधित)

	वैट विभाग से अदेय प्रमाणपत्र	**आबकारी विभाग से अदेय प्रमाणपत्र**
प्रस्तुत	14	0
प्रस्तुत नहीं किया गया/फाईल में नहीं मिला	22 (त्रैमासिक रिटर्न का प्रमाणपत्र फाइल किया गया) 48 (प्रस्तुत नहीं किया गया/नहीं मिला)	84

विशेष रूप से, आबकारी विभाग ने स्वयं एक भी बकाया राशि का प्रमाणपत्र जारी नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि लाइसेंसधारियों पर कोई भी सरकारी या सार्वजनिक बकाया नहीं था यह स्थापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के बावजूद धारा 13 (1) (डी) के उल्लंघन में इन लाइसेंसधारियों को आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी किए थे।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि एल-1 लाइसेंस के आवेदक को पिछले वर्ष के आयकर विवरणी/निर्धारण आदेश की प्रति, कंपनी/फर्म के पैन कार्ड की प्रति, आबकारी विभाग के संबंध में कोई बकाया नहीं होने का शपथ पत्र तथा वैट अधिकारी द्वारा जारी अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने थे। इसके अलावा, सरकार ने अपने जवाब में सुनिश्चित किया कि कोई भी लाइसेंस तब तक प्रदान नहीं किया जाता जब तक कि लाइसेंसधारी द्वारा आबकारी विभाग को सभी देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2017-18 से 2020-21 तक एल-1 लाइसेंस के नियम और शर्तों के अनुबंध-I के खंड एफ (iii) के अनुसार, आवेदक को उपायुक्त (आबकारी), दिल्ली द्वारा जारी एक अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार ने अपने जवाब में हलफनामे का उल्लेख करके इस तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। यहां तक कि जवाब भी अधूरा है क्योंकि सरकार ने आवेदक द्वारा पूरे दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना लाइसेंस जारी करने के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया।

3.7 लाइसेंसधारियों द्वारा नियोजित व्यक्तियों के सत्यापन के बिना लाइसेंस जारी/नवीकरण करना

दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 13 (1) (जी) के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को इस बात का ध्यान होगा कि आवेदक किसी ऐसे सेल्समैन या प्रतिनिधि को नियुक्त नहीं करेगा जो

- अपराधिक पृष्ठभूमि का है, या
- किसी संक्रामक और छूत की बीमारी से पीड़ित है, या
- 21 वर्ष से कम आयु का है।

इसके अलावा दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, कोई भी लाइसेंसधारी 21 वर्ष से कम आयु के या छूत की बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को अपने परिसर में नियुक्त या नियोजित करने की अनुमति नहीं देगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आबकारी विभाग ने "लाइसेंस देने के नियम और शर्तों" में कर्मचारियों की अपराधिक पृष्ठभूमि की जांच और संक्रामक/संक्रामक रोगों के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं किया है और लाइसेंसधारी भी यह जानकारी प्रस्तुत नहीं कर रहे थे।

कर्मचारियों की आयु के संबंध में, यदि कोई लाइसेंसधारी 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, तो आबकारी अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत तीन माह तक कारावास और/या ₹ 50,000 तक का जुर्माना निर्धारित किया गया था। अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि 2019-20 के दौरान दो एल1 लाइसेंसधारियों ने अपने गोदामों में 21 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को नियोजित किया था। हालांकि, आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंसधारी के आवेदन पर विचार एवं अनुमोदन करते समय इस तथ्य की उपेक्षा की गयी।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि यह मुद्दा लाइसेंसधारियों के समक्ष उठाया गया था और दोनों ही मामलों में धारा 13(1) (जी) का उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी ने बताया कि उपरोक्त कर्मचारी डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे और उनका काम शराब के काम से संबंधित नहीं था। लाइसेंसधारियों का यह जवाब कि ये कर्मचारी डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 24 लाइसेंसधारी के परिसर में 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रोजगार पर रोक लगाती है, भले ही नौकरी की प्रकृति कुछ भी हो।

अनुशंसा 3.4: कमियों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए लाइसेंसधारी के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

3.8 एल1 लाइसेंसधारियों से जमानत के साथ व्यक्तिगत बांड प्राप्त किए बिना लाइसेंस जारी/नवीकरण करना

लाइसेंस के नियमों और शर्तों के साथ पठित दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम 50 के अनुसार, एल1 लाइसेंसधारी को ₹ 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) की जमानत के साथ एक व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करना होगा।

2017-2021 की अवधि के लिए 11 नमूना जांच किए गए एल1 लाइसेंसधारियों से संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि लाइसेंसधारक ने 36 में से 10 मामलों में जमानत के साथ व्यक्तिगत बांड जमा नहीं की थी। 12 अन्य मामलों में, जमानत या तो संबंधित कंपनी, उसी कंपनी के निदेशक या कंपनी के कर्मचारी द्वारा दी गई थी। इस तरह के ज़मानत बांड को स्वीकार करना नियमों के विरुद्ध था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि संबंधित कंपनी, उसी कंपनी के निदेशक या कंपनी के कर्मचारी द्वारा दी गई जमानत को स्वीकार करने में दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 50 का कोई उल्लंघन नहीं था क्योंकि लाइसेंसिंग प्राधिकरण इससे संतुष्ट था। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया था कि अधिकांश एल1 लाइसेंसधारी पुराने थे और दिल्ली में पिछले कई वर्षों से अपना संचालन जारी रखे हुए थे।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ज़मानत न लेना नियम की भावना का उल्लंघन करता है जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र आश्वासन प्राप्त करना है। आबकारी विभाग का कर्तव्य ज़मानत बांड का ऐसा प्रारूप तैयार करना था जो नियम की वास्तविक आवश्यकता का

पालन कर सके। हालांकि, विभाग एक फुल प्रूफ ज़मानत बांड विकसित करने में विफल रहा जो नियम की वास्तविक भावना का पालन कर सके।

3.9 लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए बिना एल1एफ लाइसेंस जारी करना

लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, आवेदक को "वार्षिक खातों की एक सत्यापित प्रति और विधिवत लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, अंतिम लेखा अवधि के लिए, जिसके लिए ऐसे लेखा परीक्षित वार्षिक खाते / बैलेंस शीट उपलब्ध हैं" जमा करना आवश्यक है। नमूना जांच के दौरान, यह पाया गया कि तीन नमूना-जांच किए गए एल1एफ लाइसेंसधारियों में से किसी ने भी वर्ष 2020-21 के लिए उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए थे। हालांकि आबकारी विभाग द्वारा बिना किसी आपत्ति के लाइसेंस जारी कर दिया गया था।

सरकार ने अपने जवाब में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि कोविड लॉकडाउन के कारण, वर्ष 2020-21 के लिए नीति में अनुमोदित किसी अन्य दस्तावेज की मांग के बिना केवल शपथ पत्र के आधार पर लाइसेंस प्रदान किए गए थे।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिल्ली आबकारी अधिनियम/नियमों के उल्लंघन में नीति नहीं बनाई जा सकती है। इसके अलावा, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अधिनियम और नियमों के उल्लंघन का कोई कारण नहीं है।

3.10 बिक्री डेटा और थोक बिक्री मूल्य (डब्ल्यूएसपी) प्रस्तुत किए बिना एल1 और एल1एफ लाइसेंस जारी करना

एल1 लाइसेंस शर्तों के अनुलग्नक-बी के अनुसार, लाइसेंस के आवेदक को पिछले दो वर्षों के दौरान पूरे भारत में वास्तविक बिक्री आंकड़े और एक्स-डिस्टिलरी मूल्य (ईडीपी) घोषित करने वाले प्रत्येक ब्रांड के लिए एक हलफनामा देना होगा (चाहे उसका ईडीपी किसी भी मूल्य वर्ग में आता हो)।

2017-21 की अवधि के लिए 11 एल1 लाइसेंस फाइलों की नमूना जांच से पता चला कि केवल तीन लाइसेंसधारियों ने वास्तविक बिक्री के आंकड़े और अन्य राज्यों के ईडीपी का विवरण दिया था जैसा कि परिशिष्ट-बी की क्रम संख्या-1 कहा गया था। यहां तक कि इन तीन लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान किए गए विवरण कुछ वर्षों में पूर्ण[31] नहीं थे/ कुछ वर्षों में उपलब्ध नहीं कराए गए थे। अन्य ने कहा है कि मुफ्त मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार

[31] सभी ब्रांडों के लिए सभी राज्यों के बिक्री आंकड़ें और ईडीपी प्रदान नहीं किये गये थे।

इसकी आवश्यकता नहीं है या यह एल1 लाइसेंसधारी के नियमों और शर्तों के पैरा 2.3 (ई) (iv) और 7.4 (ए) (i) के अनुसार लागू नहीं है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि एल-1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम एवं शर्तों के पैरा 7.4 (ए) (i) के अनुसार, लाइसेंसधारी ईडीपी घोषित करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि कुछ प्रकार की शराब की एमआरपी की निर्धारित सीमा उपरोक्त खंड में दी गई सीमा को पार कर जाती है। इसके अलावा, सरकार ने एल-1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम और शर्तों के खंड 2.3 (ई) को संदर्भित किया, जहां विभिन्न श्रेणियों के लिए एमआरपी रेंज निर्धारित की गई थी, जिसके लिए बिक्री के आंकड़ों की आवश्यकता नहीं थी। लाइसेंसिंग वर्ष 2021-22 में मुफ्त[32] ईडीपी नीति को हटा दिया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये दो शर्तें पिछले वर्षों में बिक्री के आंकड़ों की एक निश्चित संख्या और एमआरपी मूल्य निर्धारण पर प्रतिबंध के लिए मुफ्त मूल्य निर्धारण नीति के तहत लाइसेंसधारी की पात्रता से संबंधित नहीं हैं। ये शर्तें मुफ्त मूल्य निर्धारण नीति के तहत आने वाले आवेदक को परिशिष्ट-बी की क्रम संख्या 1 में मांगे गए विवरण देने से छूट नहीं देती हैं। नियमों और शर्तों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था कि कुछ आवेदकों को परिशिष्ट बी के पैरा 1 (बिक्री के आंकड़े और अन्य राज्यों में ईडीपी) में विवरण जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि परिशिष्ट बी के पैरा 2 (भारत में न्यूनतम ईडीपी) में उल्लिखित है।

इसी प्रकार, दिल्ली/अखिल भारतीय और अन्य राज्यों में जहां पिछले दो वर्षों में ब्रांड बेचा गया है, लाइसेंस की शर्तों के लिए एल1एफ लाइसेंसधारकों को बिक्री डेटा (परिशिष्ट सी, भाग-II), ब्रांड के लिए प्रति मामले लैंडिंग मूल्य और ब्रांड के ब्रांड-वार प्रचलित डब्ल्यूएसपी (परिशिष्ट सी, भाग-III) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

तीन चयनित एल1एफ लाइसेंसधारियों से संबंधित ब्रांडों की नमूना-जांच के दौरान पाया गया कि दो[33] लाइसेंसधारियों ने अन्य राज्यों में बिक्री के संबंध में डेटा प्रदान किया। एक लाइसेंसधारी[34] ने वर्ष 2017-21 के लिए अपने ब्रांडों के लिए बिक्री डेटा प्रस्तुत

---

[32] निःशुल्क ईडीपी नीति वह प्रथा है जहाँ एक थोक लाइसेंसधारी एमआरपी एक निश्चित स्तर से ऊपर अर्थात ब्हिस्की के लिये ₹ 400 प्रति बोतल होने पर अपने एक्स डिस्टिलरी मूल्य की घोषणा करने के लिये स्वतंत्र है। जिन ब्रांडों में इसकी कीमत इस स्तर से नीचे है, आबकारी विभाग दिल्ली में ईडीपी की माँग करता है जो भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है।

[33] ब्रिन्डको सेल्स और आर्यन वाइंस

[34] इंडोस्पिरिट वितरण

नहीं किया था। अन्य राज्यों में डब्ल्यूएसपी की घोषणा के संबंध में किसी भी लाइसेंसधारी ने अन्य राज्यों में प्रचलित डब्ल्यूएसपी प्रस्तुत नहीं किया था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि विदेशी शराब के संबंध में विभिन्न राज्यों के डब्ल्यूएसपी की आवश्यकता नियम और शर्तों में कहीं भी निर्धारित नहीं की गई थी। कथन गलत है क्योंकि एल1एफ (2017-18 से 2020-21) के नियमों और शर्तों के अनुसार अन्य राज्यों में डब्ल्यूएसपी देते हुए संबंधित अनुलग्नक सी के भाग III में एक घोषणा की आवश्यकता थी। इसके अलावा, 2019-20 से इस संबंध में एक हलफनामा भी प्रस्तुत करना आवश्यक था।

3.11 "बाल्टिका 9" बियर की आपूर्ति के लिए एल1एफ लाइसेंस देने में अनियमितता

विदेशी शराब का निर्माता अपने शराब ब्रांडों के वितरण और बिक्री के लिए भारत में एक प्रमुख आयातक को प्राधिकृत करता है। यह प्रमुख आयातक आमतौर पर क्षेत्र-वार वितरकों को शराब की बिक्री के लिए अधिकृत करता है। आमतौर पर ये क्षेत्रीय वितरक दिल्ली में एल-1एफ लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं।

आबकारी विभाग ने आर्यन वाइन को वर्ष 2020-21 के लिए बाल्टिका बीयर के लिए एल1एफ लाइसेंस जारी किया। आर्यन वाइन को वोस्को बेवरेजेज द्वारा बाल्टिका बीयर के एकमात्र वितरक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे दिल्ली में बाल्टिका बीयर की बिक्री और विपणन तथा लेबल पंजीकरण के लिए प्रमुख आयातक (वीशा फूड एंड बेवरेजेज) द्वारा अधिकृत किया गया था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित विसंगतियां देखीं:

- वोसको बेवरेजेज ने आर्यन वाइन को 2020-24 की अवधि के लिए बाल्टिका बीयर के एकमात्र वितरक के रूप में नियुक्त किया, हालांकि, जिस अवधि के लिए प्रधान आयातक को ब्रांड वितरित करने के लिए अधिकृत किया गया था, उसके प्राधिकार के बारे में पत्र में उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार वोसको बेवरेजेज ने आर्यन वाइन को किस आधार पर चार साल के लिए नियुक्त किया यह स्पष्ट नहीं है।
- वोसको बेवरेजेज ने 1 जुलाई 2020 को आर्यन वाइन को बाल्टिका बीयर का एकमात्र वितरक नियुक्त किया, हालांकि, वोसको बेवरेजेज को केवल 2 जुलाई 2020 को ही प्रधान आयातक द्वारा अधिकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने लाइसेंस फ़ाइल में यह भी देखा कि बाल्टिका बीयर पर एक लेबल में मुख्य आयातक के रूप में 'वीशा फूड एंड बेवरेजेज' का उल्लेख किया गया था और दूसरे लेबल में 'वोस्को बेवरेजेज' का प्रमुख आयातक के रूप में उल्लेख किया गया था। इस अस्पष्टता और गलत सूचना का अंतिम उपभोक्ता पर प्रभाव पड़ता हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उत्पाद से संबंधित कार्रवाई हो सकती हैं। इस अनियमितता को आबकारी विभाग द्वारा अनदेखा किया गया था और ब्रांड को उचित कार्रवाई के बिना मंजूरी दे दी गई।

उपरोक्त टिप्पणियों के संबंध में, सरकार ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार कर लिया है।

3.12 परिसर/विक्रेता का कानूनी कब्जा सुनिश्चित किए बिना अनियमित रूप से लाइसेंस

लाइसेंस शर्तों के लिए आवश्यक है कि दुकान/परिसर वेंड/एचसीआर लाइसेंसधारक के कानूनी कब्जे में हों, अर्थात् लीज एग्रीमेंट को लागू स्टांप शुल्क के साथ विधिवत पंजीकृत होना चाहिए।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- **एल 6 (निगम वेंड):** 2017-21 की अवधि के लिए जिन आठ एल6 लाइसेंसधारियों के रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे उनमें से छः लाइसेंसधारियों के पंजीकृत पट्टा समझौते फाइल में उपलब्ध नहीं थे।

  उपरोक्त दिए गए छः मामलों में से एक में लाइसेंसधारी द्वारा दो व्यक्तियों से 2006 में दो दुकानों को किराए पर लिया गया था जिन्हें ये दुकानें संपदा निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए आवंटित की गई थीं और किसी भी मामले में किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं की जानी थी। इस प्रकार, इन दुकानों को शराब की बिक्री के लिए लाइसेंसधारी को अनियमित रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था। लाइसेंस शर्तों के लिए यह भी आवश्यक है कि संपत्ति सभी कानूनी विवादों से मुक्त होनी चाहिए, हालांकि, लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार सराय पीपल थला में डीएसआईडीई का एक एल6 वेंड वर्ष 1992 से मुकदमेबाजी के तहत पाया गया था। संपत्ति की मुकदमेबाजी की स्थिति के बावजूद, आबकारी विभाग द्वारा इस संपत्ति पर बिक्री की अनुमति दी गई।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि एक हलफनामा लिया गया था कि "जिस परिसर में एल6 को खोलने का प्रस्ताव था, उस परिसर के मालिक और निगम के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आबकारी विभाग इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा"।

सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केवल शपथ पत्र लेने से यह सुनिश्चित नहीं होता कि मालिक का परिसर पर कानूनी कब्जा था और नवीनीकरण शर्तों के अनुसार लाइसेंस जारी करने से पहले वैधता की जांच करना आबकारी विभाग का कर्तव्य था।

- **एल7 (निजी विक्रेता):** चार एल7 लाइसेंसधारियों में से जिनके रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, एक लाइसेंसधारी का लीज एंग्रीमेंट 2017-2021 की अवधि के लिए फाईल में नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त सभी चार वर्षों (2017-21) के लिए एक अन्य लाइसेंसधारी का लीज एग्रीमेंट पंजीकृत नहीं था, जबकि तीसरे लाइसेंसधारी का लीज एग्रीमेंट दो वर्षों (2019-21) के लिए पंजीकृत नहीं था।
- **एल10 (शॉपिंग मॉल में निजी विक्रेता):** आठ लाइसेंसधारियों में से, जिनके रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, सभी चार वर्षों (2017-21) के लिए सात लाइसेंसधारियों का पट्टा अनुबंध विधिवत रूप से पंजीकृत नहीं था।

सरकार ने एल7 और एल10 के अपने जवाब में कहा कि ठेका के संबंधित परिसर की किराया अवधि एक वर्ष से कम (11 महीने) थी, इसलिए इन किराया अनुबंधों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं किया जाना था।

जवाब सही नहीं है क्योंकि उपरोक्त सभी दुकानों की किराया अवधि एक वर्ष से अधिक थी। इस प्रकार इन दुकानों के किराए/पट्टा अनुबंध को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना था। इसके अलावा, पंजीकरण लाइसेंस की एक शर्त है।

- **होटल, क्लब एवं रेस्तरां (एचसीआर):** जिन 11 लाइसेंसधारियों के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, उनमें से चार लाइसेंसधारियों के पट्टा अनुबंध विधिवत रूप से पंजीकृत नहीं थे जबकि एक लाइसेंसधारी के मामले में, 2017-21 अवधि के लिए फाईल में कोई पट्टा अनुबंध उपलब्ध नहीं था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि लेखापरीक्षा दल द्वारा संदर्भित पट्टा अनुबंध 11 माह से कम की अवधि के लिए थे, इसलिए इन किराया अनुबंधों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं किया जाना था।

जवाब गलत है क्योंकि सभी प्रस्तुत समझौते 11 महीने से अधिक की अवधि के लिए थे जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है।

एक उदाहरण में, एल-10 लाइसेंसधारी ने आबकारी शुल्क विभाग को एक संदिग्ध जाली पट्टा विलेख प्रस्तुत किया था और आबकारी शुल्क विभाग ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। लाइसेंसधारी ने मूल लीज अवधि 15 अप्रैल 2012 से 14 अप्रैल 2017 से 15 अप्रैल 2012 से 14 अप्रैल 2021 में हेरफेर करके एक पुराने लीज डीड की फोटो कॉपी में हेराफेरी की थी।

इस मामले में सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है।

अनुशंसा 3.5: संदिग्ध जाली दस्तावेज की स्वीकृति आवकारी विभाग की ओर से उचित तत्परता की कमी को दर्शाता है। इस मामले में उचित जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

3.13 आग और प्राकृतिक आपदा के खिलाफ बीमा सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी करना

लाइसेंस की शर्तों के लिए आवश्यक है कि लाइसेंस प्राप्त परिसर का आग और प्राकृतिक खतरों के खिलाफ विधिवत रूप से बीमा किया जाएगा। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- **एल6 (निगम वेंड):** आठ एल6 लाइसेंसधारियों में से जिनके रिकॉर्ड लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, लाइसेंस जारी करने के बाद से किसी भी लाइसेंसधारक ने बीमा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे।
- **एल7 (निजी विक्रेता):** 2017-21 की अवधि के लिए चार एल7 लाइसेंसधारियों के संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि:
  - चारों लाइसेंसधारियों ने 2020-21 के लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं दी।
  - एक लाइसेंसधारी के मामले में, फाईल में शेष तीन वर्षों की कोई बीमा पॉलिसी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

- एक अन्य लाइसेंसधारी की फाइल में वर्ष 2018-19 के लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं मिली।
- तीसरे लाइसेंसधारी की फाइल में 2018-20 की अवधि के लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं मिली और,
- चौथे लाइसेंसधारी ने 2017-21 की अवधि के दौरान जून 2017 से जून 2018 तक बीमा पॉलिसी जमा की।

- **एल10 (शॉपिंग मॉल में निजी विक्रेता):** 2017-21 की अवधि के लिए आठ एल10 लाइसेंसधारियों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि किसी भी लाइसेंसधारी ने 2020-21 की अवधि के लिए कोई बीमा पॉलिसी प्रदान नहीं की थी, इन आठ लाइसेंसधारियों की फाइल में 2018-20 के लिए बीमा पॉलिसी नहीं मिली थी और पांच लाइसेंसधारियों ने 2017-18 के पूरे वर्ष के लिए बीमा पॉलिसी जमा नहीं की थी।

  सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ईएससीआईएमएस पोर्टल के लागू होने के बाद 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण (एल7, एल10 के लिए 30 सितंबर 2021 तक और एल6 के लिए 16 नवंबर 2021 तक)- केवल ऑनलाइन पोर्टल से किया जा रहा था जहां लाइसेंसधारक को अग्नि बीमा, पट्टा समझौते और घोषणाओं के प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करके विवरण प्रस्तुत करना था। विभाग द्वारा विवरण की जाँच और सत्यापन किया गया था। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया था कि लेखापरीक्षा दल ने इन दस्तावेजों को ईएससीआईएमएस पोर्टल पर सत्यापित नहीं किया है।

  जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रदान की गई ईएससीआईएमएस अभिलेख में उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं था और सरकार ने जवाब के साथ कोई सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किया था। विभाग को जारी किए गए 16 अनुस्मारकों (जून 2021 से जनवरी 2022 तक) के बावजूद, लेखापरीक्षा को उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान नहीं कराए गए थे।

- **एचसीआर:** 11 लाइसेंसधारियों (2017-21) में से जिनकी फाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गईं, दो लाइसेंसधारियों की फाइलों में आग, प्राकृतिक खतरे आदि के खिलाफ बीमा नहीं पाई गईं। इसके अलावा, कई अनुस्मारकों के बावजूद एचसीआर फाइलों के ईएससीआईएमएस अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

इन सभी प्रकरणों में आबकारी विभाग ने इन लाइसेंसधारियों के लाइसेंस की शर्तों पर विचार किए बिना ही उनके लाइसेंस जारी/नवीनीकृत किए थे। यह लाइसेंस जारी करने से पहले आवेदकों की पात्रता के सत्यापन की अपनी सबसे प्राथमिक भूमिका में आबकारी विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की कमी को दर्शाता है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि दस्तावेज ईएससीआईएमएस पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 16 अनुस्मारकों (जून 2021 से जनवरी 2022 तक) के बाद भी विभिन्न लाइसेंसधारियों के लिए ईएससीआईएमएस पोर्टल तक पहुंच नहीं थी न ही लेखापरीक्षा को डाउनलोड दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध करवाईं थीं।

3.14 सीसीटीवी सिस्टम सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी करना

खुदरा विक्रेताओं की नवीनीकरण शर्तों की क्रम संख्या 5 के अनुसार लाइसेंसधारियों को कम से कम 50 मीटर की कवरेज वाली सीसीटीवी कैमरा प्रणाली स्थापित करने और अच्छी कामकाजी स्थिति में 30 दिनों की अभिलेखीय अवधि स्थापित करने तथा नवीनीकरण आवेदन के साथ इस संबंध में एक ब्यौरा प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच किए गए चार एल7 और आठ एल10 लाइसेंसधारियों में से 11 लाइसेंसधारियों ने घोषणा प्रस्तुत की, परंतु 2017-18 के दौरान तथा शेष मामलों में, फाइल में ब्यौरे नहीं पाए गए। हालांकि, आबकारी विभाग से बिना किसी आपत्ति के इन सभी लाइसेंसधारियों के लाइसेंस नियमित रूप से नवीनीकृत किए गए थे।

सीसीटीवी सिस्टम के ठीक से काम न करने से आबकारी विभाग के लिए ओवरचार्जिंग और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की शिकायतों को दूर करना मुश्किल होगा। छापेमारी और निरीक्षण के दौरान साक्ष्य एकत्र करना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रवर्तन छापे के दौरान यह भी देखा गया कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं था जो नियमों के उल्लंघन को साबित करने में मदद कर सकता था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि लाइसेंसधारी दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 13 के अनुसार आवश्यक विवरण घोषित करते हैं, जिसमें दुकान के परिसर में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना और उचित संचालन शामिल है। सीसीटीवी कैमरों के लिए अलग से शपथपत्र देना अनिवार्य नहीं था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 की धारा 13 में सीसीटीवी प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं है, यहां तक कि जवाब के साथ संलग्न शपथपत्र प्रोफार्मा की नमूना प्रति में सीसीटीवी प्रणाली से संबंधित बिंदु शामिल नहीं थे। इसके अलावा, लाइसेंसधारी को नवीनीकरण शर्तों के अनुसार कम से कम 50 मीटर की कवरेज वाले सीसीटीवी कैमरे सिस्टम की स्थापना और अच्छी तरह काम करने की स्थिति में 30 दिनों की अभिलेखीय अवधि का शपथपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था।

3.15 लाइसेंस के नवीकरण के लिए परिपत्र में उल्लिखित शर्तों के संबंध में घोषणा के बिना लाइसेंस जारी करना

2017-21 की अवधि के लिए नवीनीकरण की शर्त के अनुसार, एल7 और एल10 लाइसेंसधारी को 15 शर्तों के संबंध में एक ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है, जैसे 'दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 13 के तहत कंपनी/फर्म के किसी भी निदेशक/भागीदारों/मालिक को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; कंपनी/फर्म के निदेशकों/भागीदारों/मालिकों के पास शराब का कोई थोक लाइसेंस या कोई अन्य खुदरा लाइसेंस नहीं है; लाइसेंस प्राप्त परिसर का विधिवत रूप से बीमा किया गया है; और कंपनी/फर्म के निदेशक/भागीदारों/मालिक आबकारी विभाग आदि द्वारा जारी सभी निर्देशों/आदेशों का पालन करेंगे। इसके अलावा नवीनीकरण शर्तों के अनुसार आवेदक को शपथपत्र प्रस्तुत किए बिना नवीनीकरण आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 2017-21 की अवधि के लिए चयनित आठ एल10 लाइसेंसधारियों से संबंधित फाइलों की जांच से पता चला कि 2018-21 की अवधि के लिए फाइलों में शपथपत्र का कोई दस्तावेज नहीं मिला। इसके अतिरिक्त 2017-21 की अवधि के लिए चयनित चार एल7 लाइसेंसधारियों से संबंधित फाइलों की जांच से पता चला कि वर्ष 2017-18 में केवल तीन लाइसेंसधारियों ने यह 15-सूत्रीय शपथपत्र दिया था, और एक लाइसेंसधारक ने वर्ष 2019-20 के लिए 5-सूत्रीय शपथपत्र दी थी, और बाकी लाइसेंसधारियों की फाइलों में शपथपत्र का कोई दस्तावेज नहीं मिला। बिना घोषणा पत्र के लाइसेंस जारी करना उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ईएससीआईएमएस पोर्टल के लागू होने के बाद 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण (एल7, एल10 के लिए 30 सितंबर 2021 तक और एल6 के लिए 16 नवंबर 2021 तक) केवल ऑनलाइन पोर्टल से किया जा रहा था जहां लाइसेंसधारक को अग्नि बीमा, पट्टा समझौते और

ब्यौरे के प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करके विवरण प्रस्तुत करना था। विभाग द्वारा विवरण की जांच और सत्यापन किया गया था। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया था कि लेखापरीक्षा दल ने इन दस्तावेजों को ईएससीआईएमएस पोर्टल पर सत्यापित नहीं किया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रदान की गई ईएससीआईएमएस के अभिलेख में उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज नहीं था, और सरकार ने जवाब के साथ कोई सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किया था। विभाग को जारी किए गए 16 अनुस्मारक (जून 2021 से जनवरी 2022 तक) के बावजूद, लेखापरीक्षा को उपर्युक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था।

3.16 पर्यटन विभाग से अपेक्षित अनुमोदन के बिना लाइसेंस जारी करना

एचसीआर लाइसेंस के आवेदकों को आवेदन के साथ, पर्यटन विभाग (प.वि.) का अनुमोदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। 11 एचसीआर लाइसेंसधारियों में से जिनके अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, तीन लाइसेंसधारियों द्वारा पर्यटन विभाग से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, आबकारी विभाग ने इन तीनों में से एक लाइसेंसधारी के मामले में दस्तावेज प्राप्त किए बिना ही लाइसेंस जारी किया।

सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया।

अनुशंसा 3.6: लाइसेंस जारी करते समय विभिन्न नियमों और विनियमों के चयनात्मक पालन पर सख्ती से कार्यवाई की जानी चाहिए और विभिन्न प्रकार की लाइसेंस फाइलों की नमूना जांच उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। साथ ही इस संबंध में जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।

3.17 निष्कर्ष

आबकारी विभाग ने कई लाइसेंसधारियों (थोक, खुदरा और एचसीआर) को दिल्ली आबकारी अधिनियम/नियमों तथा शर्तों के अनुसार आवश्यक विभिन्न दस्तावेजों को सत्यापित किए बिना लाइसेंस जारी किए। विभाग ने दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 13 का उल्लंघन करते हुये केवल एक शपथपत्र लिया जिसके आधार पर यह निर्णित किया गया कि लाइसेंसधारी और उसके कर्मचारियों के अपराधिक इतिहास, शोधनक्षमता आदि की जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा ज़मानत

बांड, निष्पादन रिपोर्ट आदि लिए बिना एल1 लाइसेंस जारी किए गए। खुदरा लाइसेंसधारी (एल6, एल7 और एल10) तथा एचसीआर को जारी लाइसेंस के संबंध में, आबकारी विभाग ने यह सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस जारी किए थे कि लाइसेंसधारी ठेके/परिसर के कानूनी कब्जे में थे। यहां तक कि बीमा और अनिवार्य घोषणा पत्रों के दस्तावेजों की भी जांच नहीं की गई।

आवेदकों द्वारा पिछले वर्षों के अनिवार्य बिक्री डेटा, डब्ल्यूएसपी विवरण आदि प्रस्तुत नहीं करने के बावजूद एल1 और एल1एफ लाइसेंस जारी किए गए थे। अगले वर्ष बेहतर विनियमन एवं आबकारी राजस्व अधिकतम करने हेतु बेहतर नीति तैयार करने लिए ऐसे डेटा सरकार के लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा, नियमों तथा लाइसेंस के नियमों और शर्तों के उल्लंघन में, संबंधित पार्टियों (सामान्य निदेशकों वाले) को कई लाइसेंस जारी किए गए थे।

नियमों और विनियमों की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा किए बिना लाइसेंस जारी करना एक गंभीर मुद्दा है। इस तरह की प्रथा से लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारण के हाथों में विवेकाधीन शक्तियां आ सकता है और बेईमानी से व्यवहार हो सकता है।

अध्याय IV

भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) तथा विदेशी शराब (एफएल) का मूल्य निर्धारण

अध्याय IV: भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) तथा विदेशी शराब (एफएल) का मूल्य निर्धारण

शराब का मूल्य निर्धारण खपत को निर्धारित करने, आपूर्तिकर्ताओं के बीच उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और आबकारी राजस्व संग्रह को अनुकूलित करने में एक अत्यधिक संवेदनशील और प्रमुख निर्धारक है। अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का निर्धारण आबकारी विभाग द्वारा थोक लाइसेंसधारी से प्रारंभिक लागत इनपुट के आधार पर किया जाता है और बाद में लाभ मार्जिन के लिए भत्ता निर्धारित करते समय निश्चित प्रतिशत के आधार पर आबकारी शुल्क और वैट को जोड़ा जाता है। यह पाया गया कि सरकार ने ईडीपी/ईबीपी की तर्कसंगतता सुनिश्चित करने के लिए लागत विवरण नहीं मांगे थे।

4.1 परिचय

वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए आबकारी नीतियों के अनुसार आईएमएफएल के मूल्य निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली **चार्ट 4.1** में दी गई है। आईएमएफएल के मूल्य निर्धारण में प्राथमिक परिवर्तनीय कारक इसका एक्स-डिस्टिलरी मूल्य (ईडीपी)/एक्स-ब्रेवरीज मूल्य (ईबीपी) है।लाभ मार्जिन/शुल्क/कर आदि को ईडीपी/ईबीपी के *प्रतिशत* के रूप में अनुमत किया जाता है/लगाया जाता है।

चार्ट 4.1: आईएमएफएल के लागत घटक

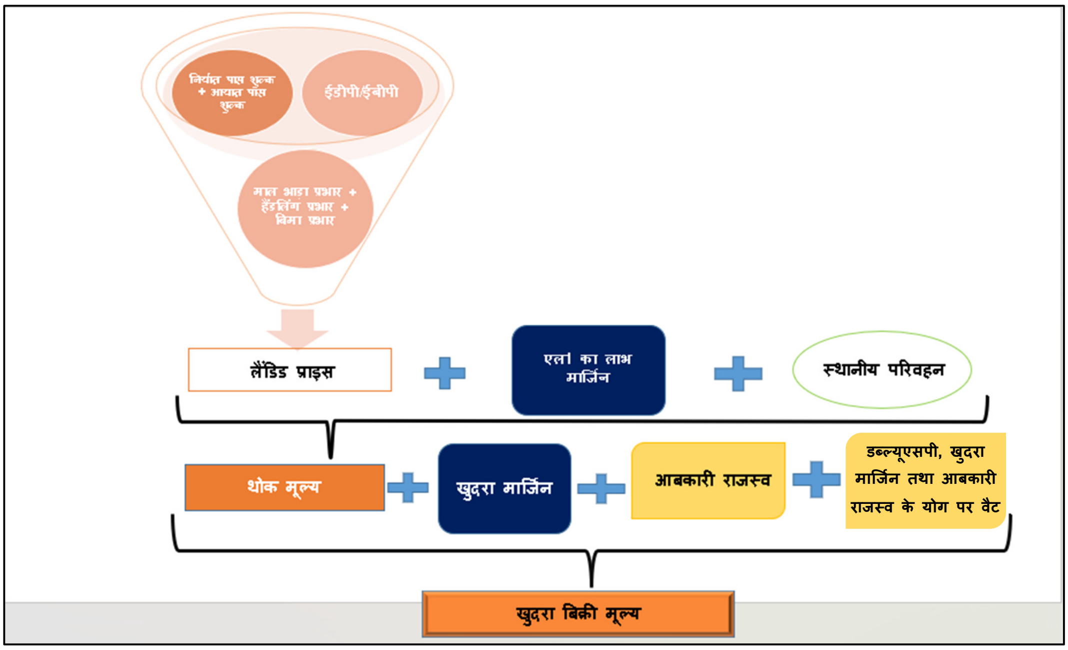

विदेशी शराब (एफएल) के संबंध में, **चार्ट 4.2** में दर्शाई गई मूल्य निर्धारण पद्धति थोड़ी भिन्न है। आईएमएफएल पर जहां डिस्टिलरी स्थित राज्य द्वारा निर्यात शुल्क लिया जाता है, और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा आयात शुल्क लिया जाता है, जबकि विदेशी शराब पर भारत सरकार द्वारा सीमा शुल्क लगाया जाता है।

चार्ट 4.2: विदेशी शराब के लागत घटक

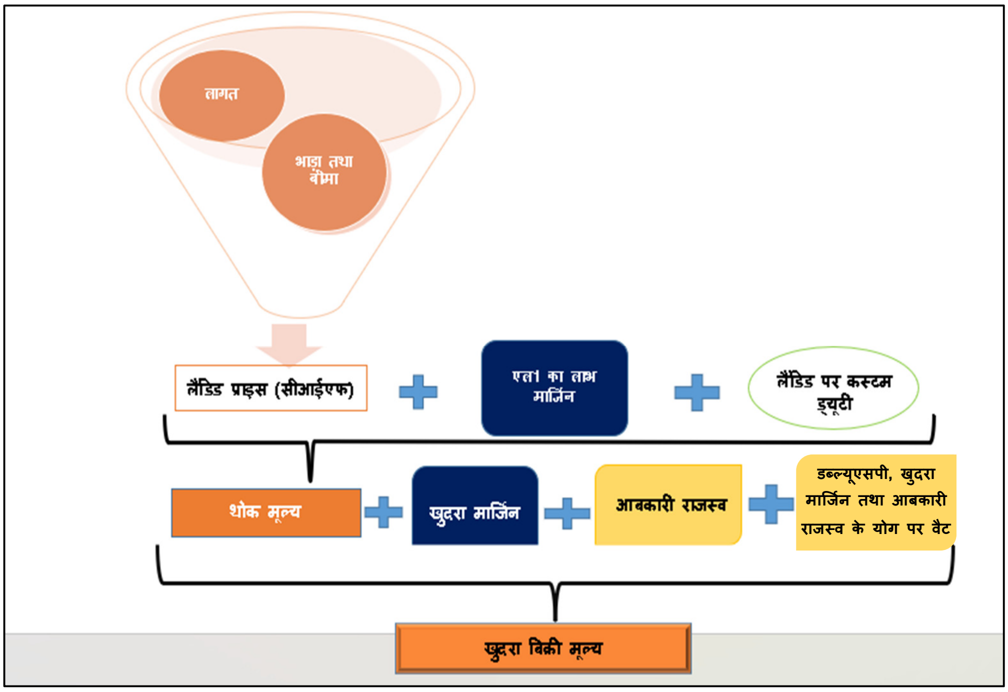

आबकारी विभाग द्वारा आईएमएफएल की कीमतों के विनियमन से संबंधित अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों को देखा:

4.2 आबकारी विभाग द्वारा आईएमएफएल की ईडीपी/ईबीपी को विनियमित नहीं किया गया

एल1 लाइसेंसधारी का लाभ मार्जिन आबकारी विभाग द्वारा अलग से प्रदान किया जाता है। इस प्रकार घोषित ईडीपी/ईबीपी वास्तविक लागत घटकों तथा अन्य मार्जिनों पर आधारित होना चाहिए तथा इसे लाइसेंसधारी के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हालांकि एल1 लाइसेंसधारी रा.रा.क्षे.दि.स. की आबकारी नीतियों के अनुसार अपने विवेक से ईडीपी/ईबीपी निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र था।

सरकार ने जवाब दिया कि एल1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए स्वीकृत नियमों एवं शर्तों में लागत मानदंड के उपयोग का उल्लेख नहीं था। यह भी उल्लेख किया गया था कि नई आबकारी नीति में, ईडीपी को पूरे भारत में किसी भी राज्य में अनुमत न्यूनतम

ईडीपी के आधार पर घोषित किया जाएगा और इस संबंध में लाइसेंसधारियों से एक हलफनामा मांगा जाएगा।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि ईडीपी की अवधारणा अपरिभाषित और अस्पष्ट है। मूल्य निर्धारण के आधार के रूप में ईडीपी के उपयोग से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा बाद के पैराग्राफों में की गई है।

4.2.1 ईडीपी/ईबीपी की तर्कसंगतता सुनिश्चित नहीं की गयी

आरंभ में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ईडीपी/ईबीपी में वृद्धि से आबकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। हालांकि ईडीपी में वृद्धि एमआरपी को प्रभावित करती है जिससे बिक्री में कमी का जोखिम भी होता है जिसके परिणामस्वरूप आबकारी राजस्व की हानि हो सकती है। हालांकि चूंकि सरकार ने ईडीपी/ईबीपी की तर्कसंगतता को निश्चित करने के लिए लागत विवरण नहीं मांगे, बढ़े हुए ईडीपी/ईबीपी में छिपे लाभ से एल 1 लाइसेंसधारी को मुनाफा मिलने का जोखिम था।

लेखापरीक्षा ने 2017-21 की अवधि के लिए नमूना-जांच किए गए 11 लाइसेंसधारियों के ब्रांडों के ईडीपी/ईबीपी का विश्लेषण किया। इस अवधि के दौरान जिन ब्रांडों की ईडीपी में वृद्धि हुई थी उनमें से अधिकांश मामलों में आबकारी राजस्व में कमी आई। यह देखा गया कि इन सभी मामलों में आबकारी राजस्व में शुद्ध प्रभाव ₹ 165 करोड़ की कमी थी जहाँ ईडीपी में वृद्धि की गई थी। विवरण **अनुलग्नक VI** में दिए गए हैं।

ईडीपी घोषित करने की विवेकाधीन शक्ति से पड़ोसी राज्यों में कीमतों में भिन्नता हो सकती है जिससे तस्करी को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

सरकार ने जवाब दिया कि एक निश्चित एमआरपी सीमा से अधिक के ब्रांड अपना ईडीपी घोषित करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि मात्रा के मामले में तीन सबसे ज्यादा बिकने वाली व्हिस्की मुफ्त ईडीपी वाली हैं, यह सुझाव देते हुए कि प्रतिबंधित ईडीपी के कारण कम एमआरपी शराब की लोकप्रियता को निर्धारित नहीं करती है। इसने आगे उल्लेख किया कि सभी ब्रांडों के लिए एक समान न्यूनतम ईडीपी तय करने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति में बदलाव किया गया है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि किसी ब्रांड की लोकप्रियता का केवल उसकी कीमत से संबंध नहीं हो सकता है। किसी ब्रांड की बिक्री कम से कम कुछ सीमा तक मूल्य

परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती है जो स्वयं ईडीपी से प्राप्त होती है। इस प्रकार, ईडीपी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर बन जाता है जिसे प्रभावी ढंग से विनियमित किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 4.1: एक्स-डिस्टिलरी मूल्य को सभी लागत घटकों के साथ परिभाषित किया जाना चाहिए और यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या इसमें लाभ का कोई घटक शामिल है। साथ ही विवेकाधीन ईडीपी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

4.2.2 दिल्ली में अन्य राज्यों की तुलना में उच्च ईडीपी/ईबीपी का निर्धारण

वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए आबकारी नीतियों के अनुसार एल1 लाइसेंसधारी को ₹ 400 तक एमआरपी वाले व्हिस्की/वाइन, ₹ 250 तक एमआरपी वाले रम/जिन/ वोदका/ब्रांडी और ₹ 100 तक एमआरपी वाली (दिल्ली में एमआरपी) बीयर के लिए दिल्ली में न्यूनतम ईडीपी/ईबीपी रखने की आवश्यकता है। जबकि उनके पास इस सीमा से अधिक एमआरपी वाले ब्रांडों के ईडीपी/ईबीपी निश्चित करने की स्वतंत्रता थी।

लेखापरीक्षा ने सीमा से अधिक एमआरपी वाले ब्रांडों के विवेकाधीन ईडीपी/ईबीपी के प्रभाव का विश्लेषण किया। आवश्यक विवरण प्रदान करने वाले तीन एल1 लाइसेंसधारियों के सभी 14 ब्रांडों के ईडीपी/ईबीपी के विस्तृत विश्लेषण पर यह देखा गया कि दिल्ली की तुलना में अन्य राज्यों में सात ब्रांडों का ईडीपी/ईबीपी कम था।

तालिका-4.1: एल1 लाइसेंसधारियों को अतिरिक्त लाभ

साल	ब्रांड	एल1 लाइसेंसधारी	दिल्ली में ईडीपी	न्यूनतम ईडीपी (राज्य)	दिल्ली में अतिरिक्त ईडीपी	दिल्ली में बिक्री	लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ
2017-18	रॉयल ग्रीन डीलक्स ब्लेंडेड व्हिस्की	मैसर्स एडीएस स्पिरिट	1323	1260 (उत्तराखंड)	63	7,03,515	4,43,21,445
	जनरेशन डीलक्स ब्लेंडेड व्हिस्की	मैसर्स एडीएस स्पिरिट	2969	2689.31 (झारखंड)	279.69	2,135	5,97,138
	ओल्ड हेबिट रम	मैसर्स एम्पायर	899	780 (केरल)	119	95,135	1,13,21,065
	ओल्ड हेबिट वोदका	मैसर्स एम्पायर	1089	902 (केरल)	189	27,005	51,03,945
	ओल्ड हेबिट व्हिस्की	मैसर्स एम्पायर	1327	1125 (केरल)	202	46,551	94,03,302
	कार्ल्सबर्ग एलीफेंट स्ट्रांग सुपर प्रीमियम बीयर (500 एमएल)	मैसर्स मोहन गोल्डवाटर ब्रेवरीज लिमिटेड	724	533 (दमन)	191	73,020	1,39,46,820
	कार्ल्सबर्ग एलीफेंट स्ट्रांग सुपर प्रीमियम बीयर (650 एमएल)	मैसर्स मोहन गोल्डवाटर ब्रेवरीज लिमिटेड	461	419 (दमन)	42	1,61,432	67,80,144

साल	ब्रांड	एल1 लाइसेंसधारी	दिल्ली में ईडीपी	न्यूनतम ईडीपी (राज्य)	दिल्ली में अतिरिक्त ईडीपी	दिल्ली में बिक्री	लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ
2018-19	रॉयल ग्रीन डीलक्स ब्लेंडेड व्हिस्की	मैसर्स एडीएस स्पिरिट	1323	1305 (गोवा)	18	11,05,225	1,98,94,050
	जनरेशन डीलक्स ब्लेंडेड व्हिस्की	मेसर्स एडीएस स्पिरिट	2969	2688.96 (यूपी)	280.04	4550	12,74,182
	कार्ल्सबर्ग एलीफैंट स्ट्रांग सुपर प्रीमियम बीयर (500 एमएल)	मैसर्स मोहन गोल्डवाटर ब्रेवरीज लिमिटेड	857	533 (दमन)	324	26901	87,15,924
	कार्ल्सबर्ग एलीफैंट स्ट्रांग सुपर प्रीमियम बीयर (650 एमएल)	मैसर्स मोहन गोल्डवाटर ब्रेवरीज लिमिटेड	525	419 (दमन)	106	75426	79,95,156
2019-20	रॉयल ग्रीन डीलक्स ब्लेंडेड व्हिस्की	मैसर्स एडीएस स्पिरिट	1518	1305 (गोवा)	213	10,39,194	22,13,48,322
कुल							**35,07,01,493**

इस तंत्र में, एल 1 लाईसेंसधारियों को बढ़े हुए ईडीपी में उनका लाभ देने का जोखिम शामिल था, जिसमें यद्पि आबकारी विभाग द्वारा लाभ मार्जिन के रूप में ईडीपी को अन्यथा पांच *प्रतिशत* पर सीमित कर दिया गया था जबकि ईडीपी/ईबीपी को काफी हद तक अनियमित छोड़ दिया गया था।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि एल1 लाइसेंसधारियों को ₹ 35.07 करोड़ की सीमा तक अतिरिक्त लाभ की राशि दी गई थी।

सरकार ने अपने जवाब में पैरा संख्या 4.2.1 में बताई गई बात को दोहराया।

अनुशंसा 4.2: सरकार को कीमतों को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने और राजस्व को बढ़ाने के लिए अपनी मूल्य निर्धारण नीति की समीक्षा करनी चाहिए।

4.3 विदेशी शराब के लाइसेंसधारियों को विवेकाधीन लाभ मार्जिन

विदेशी शराब के मामले में सरकार ने एक बहुत ही उदार नीति अपनाई क्योंकि एल1एफ लाइसेंसधारी अपने विवेक पर अपने लाभ मार्जिन निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन नमूना जांच किए गए एल1एफ लाइसेंसधारियों का लाभ मार्जिन लैंडेड प्राइस के 44 *प्रतिशत* से 347 *प्रतिशत* के बीच था और 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 वर्षों के दौरान लैंडिड प्राइस पर लाभ मार्जिन के *प्रतिशत* का औसत क्रमशः 255, 243, 169 और 172 *प्रतिशत* था। इसके परिणामस्वरूप आयात की बहुत कम लागत के बावजूद विदेशी शराब के लिए एमआरपी में वृद्धि हुई।

आबकारी नीति में सुधार के उपाय सुझाने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 2020 में गठित रवि धवन समिति द्वारा मूल्य अंतर के कारण पोरस सीमाओं के माध्यम से शराब की आमद को भी उजागर किया गया है। आबकारी नीति और लाइसेंस की आवश्यकता के अनुसार एल1एफ (एफएल लाइसेंसधारियों) को अन्य सभी राज्यों के थोक मूल्य घोषित करने की आवश्यकता है जहां वह शराब की आपूर्ति करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस शर्त का उल्लंघन किया गया था तब भी आबकारी विभाग द्वारा कोई आपत्ति उठायी नहीं गई थी (जैसा कि **पैराग्राफ 3.10** में चर्चा की गई है)।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि विदेशी शराब के लिए थोक मुल्य 2019-20 से पूरे भारत में सबसे कम थोक मूल्य के आधार पर तय किया गया है। आगे यह भी कहा गया कि बाजार गतिशील है और कीमतें नजदीकी राज्यों के मूल्य निर्धारण के अनुसार निर्धारित होती हैं। यह भी उल्लेख किया गया था कि चूंकि एफएल पर आबकारी शुल्क 85 *प्रतिशत* था, इसलिए कीमत में कोई भी वृद्धि केवल उत्पाद शुल्क को बढ़ाने में मदद करेगी। यह भी उल्लेख किया गया था कि चूंकि एफएल की बाजार हिस्सेदारी 2.5 *प्रतिशत* है, इसलिए इसका राजस्व पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्तर में आगे बताया गया कि पिछले तीन वर्षों के आबकारी शुल्क के आंकड़े राजस्व में वृद्धि दर्शाते हैं। आबकारी राजस्व में वृद्धि के संबंध में उत्तर को इस तथ्य से देखा जाना चाहिए कि 2019-20 से 2021-22 तक, आबकारी राजस्व में 8.28 *प्रतिशत* तक वृद्धि हुई जबकि 2016-17 से 2018-19 में आबकारी राजस्व में वृद्धि 18.27 *प्रतिशत* तक थी।

4.4 निष्कर्ष

आईएमएफएल के एक्स-डिस्टिलरी मूल्य का मूल आधार अपरिभाषित था। आबकारी विभाग ने ईडीपी/ईबीपी को बड़े पैमाने पर अनियमित छोड़ते हुए लाभ मार्जिन पांच *प्रतिशत* निर्धारित किया। इससे एल1 लाइसेंसधारियों द्वारा अपना लाभ ईडीपी/ईबीपी में छिपाने का जिखिम था, विशेषकर इसलिए क्योंकि आबकारी विभाग ने लागत विवरण नहीं मांगा था। मूल्य निर्धारण नीति को और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है।

अध्याय V

गुणवत्ता मानदंडों का उल्लंघन

अध्याय V: गुणवत्ता मानदंडों का उल्लंघन

शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी पूरी जिम्मेदारी आबकारी विभाग की है। दिल्ली में आपूर्ति की जाने वाली शराब की गुणवत्ता और दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 एवं "थोक लाइसेंसधारी के अनुदान के लिए नियम और शर्तों" में निहित सक्षम प्रावधानों को सुनिश्चित करने में आबकारी विभाग की भूमिका से जुड़े विभिन्न मुद्दों को देखा गया था जिनका एल1 (आइएमएफएल) और एल1एफ (एफएल) के थोक लाइसेंसधारियों द्वारा पालन किया जाता है। विभिन्न अनियमितताएं देखी गईं जो परीक्षण रिपोर्टों की दोषपूर्ण क्रॉस चेक की ओर इशारा करती हैं। विभाग द्वारा अविश्वसनीय परीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने और स्वीकार किए जाने के मामले देखे गए। गुणवत्ता अनुपालन के लिए परीक्षण रिपोर्टें गैर-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से थीं। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानदंडों के अनुसार निर्धारित मानदंडों के पूर्ण अनुपालन वाली परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता के बावजूद थोक लाइसेंसधारियों (एल1 और एल1एफ) के आवेदकों को लाइसेंस जारी किए गए थे।

5.1 परिचय

शराब स्वाभाविक रूप से गुणवत्ता के मुद्दों से ग्रस्त है क्योंकि निर्माण प्रक्रिया में आसवन, शुद्धिकरण आदि के कई चरण शामिल हैं और निर्माता के पास लाभप्रदता बढ़ाने के लिए लागत में कटौती करने हेतु एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है। शराब गुणवत्ता नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है और इसमें संभावित दूषित पदार्थों, उनके नियंत्रण और उनके स्वीकार्य स्तरों की बहुत कठोर जांच शामिल है।

दिल्ली में आपूर्ति की जाने वाली शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आबकारी विभाग के प्राथमिक उद्देश्य अर्थात शराब की बिक्री और खपत को विनियमित, नियंत्रित और निगरानी करने के अनुरूप है।

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 और थोक लाइसेंसधारी के नियम और शर्तों में शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रावधान हैं। शराब की विभिन्न श्रेणियों (व्हिस्की, रम, वोदका, बीयर आदि) के लिए एक लाइसेंसधारी विभिन्न परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होता है।

लेखापरीक्षा ने शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में आबकारी विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की नमूना जांच की है। इस प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न अभ्युक्तियों को इस अध्याय के बाद के पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है।

5.2 एफएसएसएआई अधिनियम/बीआईएस मानदंडों में लाइसेंस की शर्तों में अस्पष्टता/गुणवत्ता नियंत्रण का अनुपालन न होना

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) अधिनियम एल्कोहल को खाद्य पदार्थ के रूप में मान्यता देता है। एफएसएसएआई नियमित रूप से परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की एक सूची प्रकाशित करता है। एल्कोहलिक पेय पदार्थों के परीक्षण के लिए पैरामीटरों का उल्लेख खाद्य सुरक्षा और मानक (एल्कोहलिक पेय पदार्थ) विनियम 2018 में किया गया है। विभिन्न प्रकार की शराब के परीक्षण के लिए पृथक बीआईएस मानक भी हैं।

लेखापरीक्षा ने 2017-21 की अवधि के दौरान दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत बनाए गए नियमों, दिशा-निर्देशों आदि में उपलब्ध कराई गई शराब की गुणवत्ता से संबंधित विभिन्न मौजूदा प्रावधानों और थोक लाइसेंस प्रदान करने के नियमों और शर्तों का विश्लेषण किया।

- दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 7 में कहा गया है कि "शराब का आयात भारत में या उसके बाहर किसी भी स्थान से किया जा सकता है, बशर्ते कि यह आबकारी आयुक्त द्वारा सरकार की पूर्व स्वीकृति से दिए गए आदेश में आवश्यक विनिर्देशों के अनुरूप हो या यदि ऐसा आदेश नहीं दिया गया है, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा शराब की मानक शक्ति के संबंध में निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप है।"

  लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त नियम 7 के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा अलग से कोई विनिर्देश जारी नहीं किया गया है, इसलिए मौजूदा बीआईएस मानक शराब की गुणवत्ता को निर्देशित करते हैं।

  आगे यह देखा गया कि इसमें भारत के बाहर से आयातित टकीला के मामले में अस्पष्टता छोड़ दी, क्योंकि टकीला के लिए कोई बीआईएस विनिर्देश नहीं थे। भारत के बाहर से आयातित शराब की अन्य श्रेणियों के लिए, विभाग विदेशी

निर्माताओं से स्वीकार किए जाने वाले विनिर्देशों से संबंधित आदेश जारी करने में विफल रहा, जो कुछ अन्य विनिर्देशों (बीआईएस के अलावा) का पालन कर रहे होंगे।

- एल 1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियमों और शर्तों के खंड 7.3 (डी) में कहा गया है कि "लाइसेंसधारी को विशेष ब्रांड की गुणवत्ता के संबंध में सरकारी अधिकृत प्रयोगशाला या अन्य प्रतिष्ठित निजी संस्थान से प्रमाणपत्र देना होगा और यह प्रमाणित करना होगा कि यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करता है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है।"

  हालांकि इस प्रावधान में यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि क्या सरकारी प्रयोगशाला या निजी प्रयोगशाला को एनएबीएल से मान्यता की आवश्यकता है।

- इसी तरह एल1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम और शर्तों के खंड 2.3 (बी) में कहा गया है कि "यह (अल्कोहल ड्रिंक) न्यूट्रल अल्कोहल (डबल डिस्टिल्ड), एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल आदि से बनाया जाएगा। दिल्ली में आयातित भारतीय शराब की प्रत्येक खेप के साथ इकाई के तकनीकी प्रमुख और आबकारी प्राधिकरण दोनों द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित गुणवत्ता रिपोर्ट का एक प्रमाणपत्र संलग्न रहेगा जो यह प्रमाणित करेगा कि उत्पाद बीआईएस मानक के अनुसार है और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) से बने हैं।"

लेखापरीक्षा ने देखा कि उपरोक्त आवश्यकता के अनुपालन में 12 लाइसेंसधारियों से संबंधित 38 चयनित मामलों में से 16 में, इकाइयों से जुड़े स्थानीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए थे जिसमें, गुणवत्ता पैरामीटरों के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण दिए बिना कहा गया कि उत्पाद ईएनए से बनाया गया था, जैसा कि ऊपर बताया गया है। आठ मामलों में फाइल में कोई प्रमाणपत्र/रासायनिक रिपोर्ट नहीं मिली और एक मामले में एक रासायनिक रिपोर्ट दी गई थी (13 मामलों में ईएनए प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं थी)। हालांकि 24 रिपोर्टो/प्रमाणपत्रों के संबंध में आबकारी विभाग की ओर से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई जो या तो प्रस्तुत नहीं किए गए थे या उनमें उल्लेखित गुणवता मानदंडों के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण नहीं था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ब्रांड के पंजीकरण के समय आवेदक को एल1 आवेदक द्वारा किसी प्रकार का वचन/गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक था कि उसका उत्पाद बीआईएस मानक की पुष्टि करेगा। आगे यह उल्लेख किया कि इकाई के तकनीकी प्रमुख और आबकारी प्राधिकरण द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र इस नियम और शर्त का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाइसेंसधारी द्वारा एक वचनबद्धता प्रस्तुत करना बीआईएस विनिर्देशों के पालन की कोई गारंटी नहीं थी। पैरा 7.3 (डी) के अनुसार, लाइसेंसधारी को आवश्यकतानुसार एक प्रमाणपत्र देना था। इसके अतिरिक्त एफएसएसएआई अधिनियम के अनुसार एक गैर-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला बीआईएस अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सकती है इसलिए इन-हाउस प्रयोगशाला ऐसा करने के लिए योग्य नहीं थी। हालांकि एफएसएसएआई अधिनियम का अनुपालन आबकारी विभाग की जिम्मेदारी थी और आबकारी नीति के नियमों और शर्तों में इसे शामिल नहीं करना आबकारी विभाग/सरकार की एक कमी थी। इसके अलावा, निर्माण इकाई से जुड़े आबकारी प्राधिकरण ईएनए प्रमाणपत्र जारी करने के लिए योग्य नहीं थे।

ऊपर वर्णित नियम 7 के अनुसार विभाग लाइसेंसधारी द्वारा पालन किए जाने वाले विनिर्देशों के संबंध में कोई विशिष्ट आदेश जारी करने में विफल रहा।

अनुशंसा 5.1: नियमों और शर्तों में एफएसएसएआई मानदंडों के विरुद्ध सत्यापन का उल्लेख विशेष रूप से किया जाना चाहिए ताकि पालन किए जाने वाले मानदंडों के संबंध में कोई अस्पष्टता न हो।

5.3 आबकारी विभाग द्वारा अमान्य गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणपत्रों की स्वीकृति

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 7 के अनुसार जैसाकि पूर्व पैराग्राफ में कहा गया है, चूंकि आबकारी आयुक्त द्वारा कोई गुणवत्ता विनिर्देश अधिसूचित नहीं किया गया है, उन्हें एल्कोहलिक क्षमता के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप होना होगा।

लेखापरीक्षा ने 12 एल1 लाइसेंसधारियों से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच की जिन्हें 2017-20 की अवधि के दौरान लाइसेंस जारी किए गए थे। इन 12 लाइसेंसधारियों ने 15 प्रयोगशालाओं से किए गए गुणवत्ता परीक्षणों के संबंध में 173 प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत एवं आबकारी विभाग द्वारा

स्वीकार किए गए गुणवत्ता परीक्षण प्रमाण-पत्रों के संबंध में निम्नलिखित मुद्दे देखे गए।

- इन 15 प्रयोगशालाओं में से तीन प्रयोगशालाएं एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं थीं, दो प्रयोगशालाएं मादक पेय पदार्थों के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थीं, दो प्रयोगशालाएं जैविक परीक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं थीं और एक प्रयोगशाला रासायनिक विश्लेषण करने के लिए अधिकृत नहीं थी (**अनुलग्नक VII**)। विभाग को एनएबीएल से इन प्रयोगशालाओं की स्थिति का सत्यापन करना चाहिए और उसके बाद उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
- खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के लिए एफएसएसएआई दिशानिर्देश के परिशिष्ट 3 (बी) के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट के प्रपत्र में नमूने पर एक "राय" (उदाहरण के लिए मानव उपभोग के लिए उपयुक्त) शामिल होती है।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि 173 परीक्षण प्रमाणपत्रों में से केवल 9 में उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक राय शामिल थी, जिसके बिना रिपोर्ट अधूरी मानी जाएगी।

विभाग ने अपने जवाब में कहा कि नियम एवं शर्तों के अनुसार एनएबीएल से मान्यता की आवश्यकता नहीं थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक खाद्य व्यवसाय को एफएसएसएआई के दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए और एफएसएसएआई अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल से मान्यता की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कहा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उजागर की गई अधिकतर प्रयोगशालाएं वास्तव में स्वयं विनिर्माताओं से जुड़ी हुई थीं। यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विभाग के पास गुणवत्ता जांच का कोई तृतीय पक्ष निरीक्षण नहीं था। आबकारी विभाग ने इन अवैध गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणपत्रों को स्वीकार किया जो कर्मठता की कमी को दर्शाता है।

अनुशंसा 5.2: एक प्रामाणिक और निष्पक्ष परीक्षण रिपोर्ट के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परीक्षण रिपोर्ट जारी करने वाली प्रयोगशालाओं को शराब के प्रासंगिक मापदंडों के परीक्षण के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

5.4 अनिवार्य गुणवत्ता मानदंडों का पालन नहीं करने के बावजूद लाइसेंस जारी करना

2017-21 की अवधि के लिए 12 एल1 लाइसेंसधारियों (आईएमएफएल) और 3 एल1एफ (एफएल) लाइसेंसधारियों से संबंधित फाइलों की जांच में शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया में कई कमियां सामने आईं जिसका विवरण बाद के पैराग्राफों में स्पष्ट किया गया है।

5.4.1 बीआईएस मानदंडों का पालन नहीं करने के बावजूद एल1 लाइसेंस (आईएमएफएल) जारी करना

लाइसेंस की शर्तों के अनुसार प्रत्येक एल1 लाइसेंसधारी को बीआईएस मानकों का पालन करते हुए एक गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। बीआईएस विनिर्देशों के विवरण **तालिका 5.1** में दिये गये है।

तालिका 5.1: बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार परीक्षणों की संख्या

क्र.सं.	शराब का प्रकार	विनिर्देश	परीक्षणों की संख्या
1	बीयर	आईएस 3865: 2001, आईएस 7585 (सल्फर डाइऑक्साइड), पेयजल- विनिर्देश आईएस 10500: 2012	11
2	रम	आईएस 3811: 2005, पेयजल-विनिर्देश आईएस 10500:2012	14
3	जिन	आईएस 4100: 2005, पेयजल-विनिर्देश आईएस 10500:2012	14
4	व्हिस्की	आईएस 4449: 2005, पेयजल-विनिर्देश आईएस 10500:2012	12
5	वोदका	आईएस 5286: 2005, पेयजल-विनिर्देश आईएस 10500:2012	13
6	वाईन	आईएस 7058: 2005, पेयजल-विनिर्देश आईएस 10500:2012	20
7	कम मादक पेय पदार्थ	आईएस 15588:2005, पेयजल-विनिर्देश आईएस 10500:2012	15

लेखापरीक्षा द्बारा 12 विभिन्न एल1 लाइसेंसधारियों द्वारा आपूर्ति की गई 173 ब्रांड की शराब (व्हिस्की, रम, वोदका, जिन, बीयर, मिश्रित मादक पेय पदार्थ, वाइन आदि) और लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता अनुपालन के प्रमाणपत्रों की जांच की गई जिन्हें आबकारी विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था और लाइसेंस जारी किए गए थे।

वर्ष 2020-21 के दौरान नमूना-जांच किए गए किसी भी 12 एल1 लाइसेंसधारियों द्वारा उनके आवेदन के साथ गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के पश्चात भी आबकारी विभाग द्वारा बिना किसी टिप्पणी/आपत्ति के लाइसेंस जारी किए गए थे।

2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 12 लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्टों **(अनुलग्नक VIII)** की जांच में निम्नलिखित मुद्दे देखे गए:

- नमूना-जांच किए गए 12 एल1 लाइसेंसधारियों के संबंध में, बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार 2,323 मापदंडों का परीक्षण किया जाना था। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि 37 *प्रतिशत* परीक्षण बिल्कुल नहीं किया गया और दो *प्रतिशत* मापदंडों का बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार परीक्षण नहीं किया गया था/आंशिक किया गया था। शेष में से नौ *प्रतिशत* मापदंडों के लिए परीक्षण मूल्यों को ठीक से रिपोर्ट नहीं किया गया था। इस प्रकार मात्र 52 *प्रतिशत* परीक्षण बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार किए गए थे।
- बीयर के संबंध में, सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण अनिवार्य थे। नमूना जांच किए गए 12 एल1 लाइसेंसधारियों में से तीन लाइसेंसधारियों ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान बीयर के 31 ब्रांड पंजीकृत किए थे। हालांकि, बीयर के 31 ब्रांडों में से केवल छः के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण प्रस्तुत किए गए थे।
- सभी श्रेणी की शराब के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य था। प्रस्तुत की जाने वाली 173 परीक्षण रिपोर्टों में से 96 *प्रतिशत* मामलों में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई और शेष मामलों में आंशिक रिपोर्ट प्रदान की गई।
- सभी श्रेणियों की शराब के लिए रिपोर्ट में घोषित किए जाने वाले हानिकारक अवयवों से मुक्ति भी एक आवश्यक मापदंड है। उदाहरण- बीयर "क्लोरल हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पाइरीडीन डायजेपाम और पैराल्डिहाइड से मुक्त होगी"। नमूना जांच किये गये प्रकरणों में 173 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने थे जिनमें से केवल 13 प्रकरणों में अनुपालन दर्शाया गया था।
- अनुचित रूप से डिस्टील किए गए शराब में मिथाइल अल्कोहल की उपस्थिति अल्कोहल विषाक्तता का प्रमुख कारण है और इसलिए, सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता है। 2017-20 की अवधि के दौरान आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित 173 ब्रांडों के लिए 173 परीक्षण किए जाने थे। हालांकि यह पाया गया कि चार मामलों में मिथाइल अल्कोहल के लिए कोई परीक्षण नहीं किया गया था। 56 मामलों में, रिपोर्ट में पता लगाने की सीमा/मानदंड निर्दिष्ट किए बिना अस्पष्ट रूप से "मिथाइल अल्कोहल नहीं मिला/नकारात्मक" का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार दिल्ली में आपूर्ति की जाने वाली शराब में मिथाइल अल्कोहल की उपस्थिति के लिए उचित रूप से परीक्षण नहीं किया गया था जो गंभीर जोखिम को दर्शाता है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मेथनॉल परीक्षण के दो तरीके हैं, एक तरीके में पीपीएम में पहचान सीमा बताना संभव है, दूसरे तरीके के संबंध में पीपीएम में उपस्थिति बताना संभव नहीं है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईएस 3753:2005 के अनुसार, दोनों तरीकों से मेथनॉल की सटीक सांद्रता (v/v) का पता लगाना संभव है।

सरकार ने अपने जवाब में आगे कहा कि मापदंडों के विवरण का कहीं भी उल्लेख नहीं है जिस पर परीक्षण किया जाना है। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अल्कोहल और पानी आदि की विभिन्न श्रेणियों के लिए बीआईएस विनिर्देशों में मानदंड स्पष्ट रूप से दिए गए हैं।

आबकारी विभाग ने प्रस्तुत प्रतिवेदनों की गहन जांच नहीं की। विशेष रूप से, किसी एक भी ब्रांड की सभी परीक्षण रिपोर्ट बीआईएस मानकों का अनुपालन करते हुए प्रस्तुत नहीं की गई।

अनुशंसा 5.3: दिल्ली आबकारी विभाग को अल्कोहल की गुणवत्ता की सक्रिय रूप से निगरानी करनी चाहिए और बीआईएस मानकों द्वारा निर्धारित मानदंडों से ओर ऊपर जाकर कड़े गुणवत्ता मानक तैयार करना चाहिए। दिल्ली आबकारी नियम 7 ऐसे विनिर्देशों को स्पष्ट रूप से तैयार करने के लिए एक सक्षम प्रावधान है।

5.4.2 गुणवत्ता आश्वासन के बिना एल1एफ लाइसेंस प्रदान करना तथा विदेशी शराब की आपूर्ति करना

एल1एफ के लिए लाइसेंस के नियम और शर्तों के खंड 7.9 में कहा गया है कि शराब की गुणवत्ता आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किसी भी विनिर्देशों का पालन करना चाहिए और यदि ऐसा कोई विनिर्देश निर्धारित नहीं है, तो उसे बीआईएस मानकों या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय विनिर्देशों का पालन करना चाहिए। 2017-21 की अवधि के लिए, लेखापरीक्षा ने तीन विभिन्न एल1एफ लाइसेंसधारियों द्वारा आपूर्ति की गई शराब (व्हिस्की, रम, वोदका, जिन, बीयर, मिश्रित मादक पेय पदार्थ, वाइन आदि) के ब्रांडों के लिए की गई रिपोर्ट/परीक्षणों की जांच की और लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया गुणवत्ता अनुपालन के प्रमाणपत्र की जांच की गई जिसमें निम्नलिखित मुद्दे देखे गए:

1. नमूना जांच के लिए चयनित तीन एल1एफ में से विभिन्न श्रेणियों के लिए बीआईएस विनिर्देशों के अनुसार किए जाने वाले गुणवत्ता परीक्षणों की संख्या 5280 (कुल) थी। हालांकि, परीक्षण प्रतिवेदनों की जांच से पता चला कि केवल 35.64 *प्रतिशत* परीक्षण बीआईएस विनिर्देश के अनुसार किए गए थे, 64.17 *प्रतिशत* परीक्षण लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार नहीं किए गए थे। किए गए परीक्षणों का श्रेणी-वार विवरण इस प्रकार है:

तालिका 5.2: आवश्यक और किए गए परीक्षणों की संख्या

श्रेणी	कंपनियों की संख्या	संबंधित परीक्षण रिपोर्ट[35]	बीआईएस के अनुसार किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या	बीआईएस के अनुसार वास्तव में किए गए परीक्षणों की संख्या	बिल्कुल नहीं किए गए परीक्षणों की संख्या	बीआईएस के अनुसार नहीं किया गया/आंशिक अनुपालन
व्हिस्की	2	130	1560	650	904	6
रम	1	4	56	16	40	0
बीयर	3	51	576	162	414	0
जिन	2	15	210	86	124	0
वोदका	2	26	338	106	231	1
वाइन	2	127	2540	862	1675	3
	कुल	**353**	**5280**	**1882**	**3388**	**10**
	प्रतिशतता			35.64%	64.17%	

2. ब्रांड पंजीकरण (58.70 *प्रतिशत*) के 226 मामलों में, इन-हाउस प्रयोगशालाओं या संबंधित कंपनियों से गुणवत्ता अनुपालन रिपोर्ट प्रदान की गई या रिपोर्ट प्रदान ही नहीं की गई थी। ऐसी रिपोर्टें शराब की गुणवत्ता के स्वतंत्र मूल्यांकन का वर्णन नहीं करती थीं और इसलिए भरोसेमंद नहीं थीं।

3. 35 मामलों में चालू वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई या पिछले वर्षों के दौरान पहले ही प्रस्तुत रिपोर्ट सुसज्जित की गई थी। विभाग ने इस तरह के कार्य पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

4. 254 मामलों (65.97 *प्रतिशत*) में, रिपोर्ट में परीक्षण अनुपालन के लिए अपनाए गए अंतराष्ट्रीय मानक का उल्लेख नहीं था या अंतराष्ट्रीय मानकों को लागू नहीं किया गया था या रिपोर्ट बिल्कुल भी प्रदान नहीं की गई थी। इस तरह के स्वतंत्र मानक के अभाव में शराब की गुणवत्ता को सिद्ध करना मुश्किल था।

---

[35] 32 परीक्षण रिपोर्टें जो अंग्रेजी में नहीं थी, सारांश में शामिल नहीं की गई थी

5. बीयर और वाइन के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षणों की आवश्यकता अनिवार्य है। बीयर के 40 ब्रांड पंजीकरण (78.43 *प्रतिशत*) के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण नहीं किए गए थे। वाइन के लिए, 125 ब्रांड पंजीकरणों (98.43 *प्रतिशत*) ने मोल्ड, जीवाणु वृद्धि आदि के लिए मानकों के विरुद्ध परीक्षण रिपोर्ट प्रदान नहीं की थी। 32 मामलों में अनुपालन सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि रिपोर्ट अंग्रेजी के अलावा भाषाओं में थी।
6. शराब की सभी श्रेणियों के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य था। 353 ब्रांडों में से किसी ने भी पानी की गुणवत्ता के लिए अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया था।
7. शराब की सभी श्रेणियों के लिए रिपोर्ट में घोषित किए जाने वाले हानिकारक अवयवों से स्वतंत्रता भी एक आवश्यक मानदंड है। नमूना जांच किए गए मामलों में, 353 ब्रांडों में से केवल तीन ने ही शर्तों का अनुपालन प्रस्तुत किया था।
8. शराब के लिए मिथाइल अल्कोहल का स्तर इसकी गंभीर विषाक्तता के कारण महत्वपूर्ण है। 207 ब्रांड पंजीकरण (58.64 *प्रतिशत*) के मामले में, रिपोर्ट में मिथाइल अल्कोहल के स्तर का उल्लेख नहीं किया गया था या रिपोर्ट बिल्कुल भी प्रदान नहीं की गई थी। इस प्रकार, इनका कोई अनुपालन स्थापित नहीं किया जा सका।
9. एल1 के समान, खुदरा वितरण से पहले बैचों/खेप का कोई नमूना नहीं लिया गया था।
10. प्रस्तुत की जाने वाली कुल 385 परीक्षण रिपोर्टों में से, प्रस्तुत 196 (50.91 *प्रतिशत*) परीक्षण रिपोर्ट एक वर्ष से अधिक पुरानी थी/या कोई परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी/तिथि का उल्लेख नहीं किया गया था। एक मामले में नौ वर्ष पुरानी एक परीक्षण रिपोर्ट को आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए स्वीकार किया गया था। इस प्रकार आपूर्ति की गई शराब के बारे में कोई गुणवत्ता का दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रिपोर्टें पूरी तरह से अलग, पुराने बैचों की थी।

एफएल के लिए गुणवत्ता परीक्षणों का विवरण **अनुलग्नक IX** में दिया गया है।

इसी प्रकार आईएमएफएल (एल1) के घरेलू ब्रांडों के मामले में, विदेशी शराब आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता रिपोर्ट के मामले में काफी हद तक अनुपालन नहीं

किया गया था। इसके अलावा, विभाग ने विशिष्ट मानकों का पालन करने का सुझाव नहीं दिया है, जो अस्पष्टता को दर्शाता है। विदेशी शराब (जैसे टकीला) के कुछ मामलों में बीआईएस मानदंड मिथाइल अल्कोहल के स्वीकार्य स्तर को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। टकीला के लिए मिथाइल अल्कोहल का स्तर व्हिस्की के लिए स्वीकार्य स्तर से काफी अधिक है। विभाग ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इसके अलावा आवेदन की तिथि से एक वर्ष से अधिक पुरानी परीक्षण रिपोर्ट (विभाग द्वारा) की स्वीकृति अनियमित थी। लाइसेंस प्रदान करने के लिए पुरानी, अमान्य और अस्पष्ट परीक्षण रिपोर्टों को स्वीकार करने में इस तरह की लापरवाही सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।

अनुशंसा 5.4: बीआईएस/एफएसएसएआई मानदंडों के आधार पर परीक्षण रिपोर्टों के सत्यापन से संबंधित चेकलिस्ट/मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जानी चाहिए। लागू गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए चेकलिस्ट/एसओपी के आधार पर जाँच को सत्यापन अनिवार्य किया जाना चाहिए।

5.5 लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत संदिग्धता परीक्षण प्रमाणपत्र आबकारी विभाग द्वारा स्वीकार किए गए

(क) कार्ल्सबर्ग एलिफैंट प्रीमियम बीयर, टुबौर्ग गोल्ड बियर, टुबौर्ग क्लासिक स्ट्रौंग बीयर **(चित्र 5.1)**, टुबौर्ग ब्लैक सुपर प्रीमियम स्ट्रॉग बीयर, और कार्ल्सबर्ग स्मूथ चिल ऑल माल्ट प्रीमियम बीयर के संबंध में मोहन गोल्ड वाटर के नमूना जांच किए गए एल1 लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणपत्रों (2018-19 के पांच प्रमाणपत्र तथा 2019-20 के पांच प्रमाणपत्र) की जांच करने पर यह पाया गया कि रिपोर्ट समान है तथा प्रत्येक वर्ष लाइसेंस आवेदन के साथ प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट अनुक्रम संख्या तथा नमूना बैच संख्या को बदलने के लिए परिवर्तन किया गया।

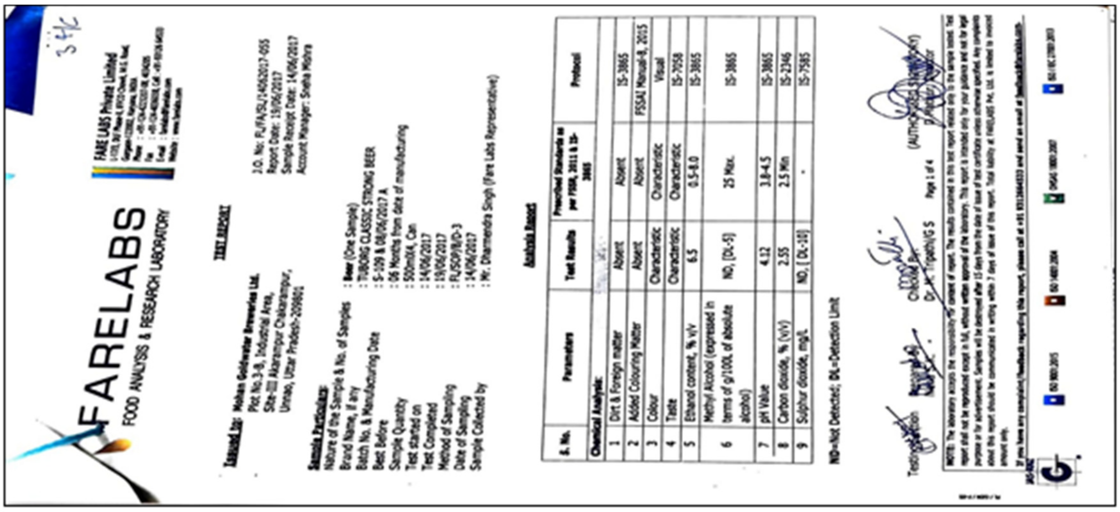

FARELABS
FOOD ANALYSIS & RESEARCH LABORATORY

FARE LABS Private Limited

TEST REPORT

Issued to: Mohan Goldwater Breweries Ltd.
Plot No.3-B, Industrial Area,
Site-III Akarampur Chakarampur,
Unnao, Uttar Pradesh-209801

J.O. No: FL/FA/SL/14062017-055
Report Date: 19/06/2017
Sample Receipt Date: 14/06/2017
Account Manager: Sneha Mishra

Sample Particulars:

Nature of the Sample & No. of Samples	: Beer (One Sample)
Brand Name, if any	: TUBORG CLASSIC STRONG BEER
Batch No. & Manufacturing Date	: S-109 & 08/06/2017 A
Best Before	: 06 Months from date of manufacturing
Sample Quantity	: 500mlX4, Can
Test started on	: 14/06/2017
Test Completed	: 19/06/2017
Method of Sampling	: FL/SOP/B/D-3
Date of Sampling	: 14/06/2017
Sample Collected by	: Mr. Dharmendra Singh (Fare Labs Representative)

Analysis Report

S. No.	Parameters	Test Results	Prescribed Standards as per FSSR, 2011 & IS-3865	Protocol
Chemical Analysis:				
1	Dirt & Foreign matter	Absent	Absent	IS-3865
2	Added Colouring Matter	Absent	Absent	FSSAI Manual-8, 2015
3	Colour	Characteristic	Characteristic	Visual
4	Taste	Characteristic	Characteristic	IS-7058
5	Ethanol content, % v/v	6.5	0.5-8.0	IS-3865
6	Methyl Alcohol (expressed in terms of g/100L of absolute alcohol)	ND, [DL-5]	25 Max.	IS-3865
7	pH Value	4.12	3.8-4.5	IS-3865
8	Carbon dioxide, % (v/v)	2.55	2.5 Min	IS-2346
9	Sulphur dioxide, mg/L	ND, [DL-10]	-	IS-7585

ND=Not Detected; DL=Detection Limit

Tested by / Checked By: Dr. M. Tripathi/G S / Page 1 of 4 / (AUTHORISED SIGNATORY)

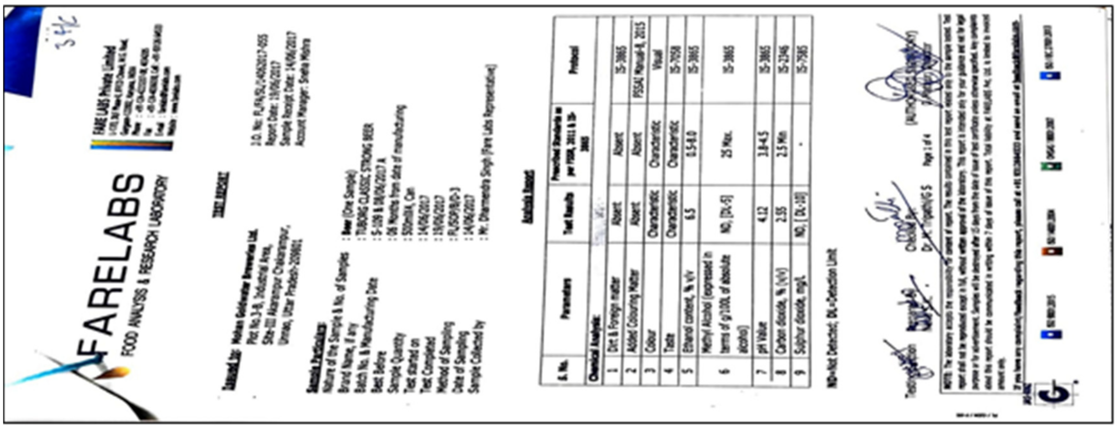

FARELABS
FOOD ANALYSIS & RESEARCH LABORATORY

FARE LABS Private Limited

TEST REPORT

Issued to: Mohan Goldwater Breweries Ltd.
Plot No.3-B, Industrial Area,
Site-III Akarampur Chakarampur,
Unnao, Uttar Pradesh-209801

J.O. No: FL/FA/SL/14062017-055
Report Date: 19/06/2017
Sample Receipt Date: 14/06/2017
Account Manager: Sneha Mishra

Sample Particulars:

Nature of the Sample & No. of Samples	: Beer (One Sample)
Brand Name, if any	: TUBORG CLASSIC STRONG BEER
Batch No. & Manufacturing Date	: S-109 & 08/06/2017 A
Best Before	: 06 Months from date of manufacturing
Sample Quantity	: 500mlX4, Can
Test started on	: 14/06/2017
Test Completed	: 19/06/2017
Method of Sampling	: FL/SOP/B/D-3
Date of Sampling	: 14/06/2017
Sample Collected by	: Mr. Dharmendra Singh (Fare Labs Representative)

Analysis Report

S. No.	Parameters	Test Results	Prescribed Standards as per FSSR, 2011 & IS-3865	Protocol
Chemical Analysis:				
1	Dirt & Foreign matter	Absent	Absent	IS-3865
2	Added Colouring Matter	Absent	Absent	FSSAI Manual-8, 2015
3	Colour	Characteristic	Characteristic	Visual
4	Taste	Characteristic	Characteristic	IS-7058
5	Ethanol content, % v/v	6.5	0.5-8.0	IS-3865
6	Methyl Alcohol (expressed in terms of g/100L of absolute alcohol)	ND, [DL-5]	25 Max.	IS-3865
7	pH Value	4.12	3.8-4.5	IS-3865
8	Carbon dioxide, % (v/v)	2.55	2.5 Min	IS-2346
9	Sulphur dioxide, mg/L	ND, [DL-10]	-	IS-7585

ND=Not Detected; DL=Detection Limit

Tested by / Checked By: Dr. M. Tripathi/G S / Page 1 of 4 / (AUTHORISED SIGNATORY)

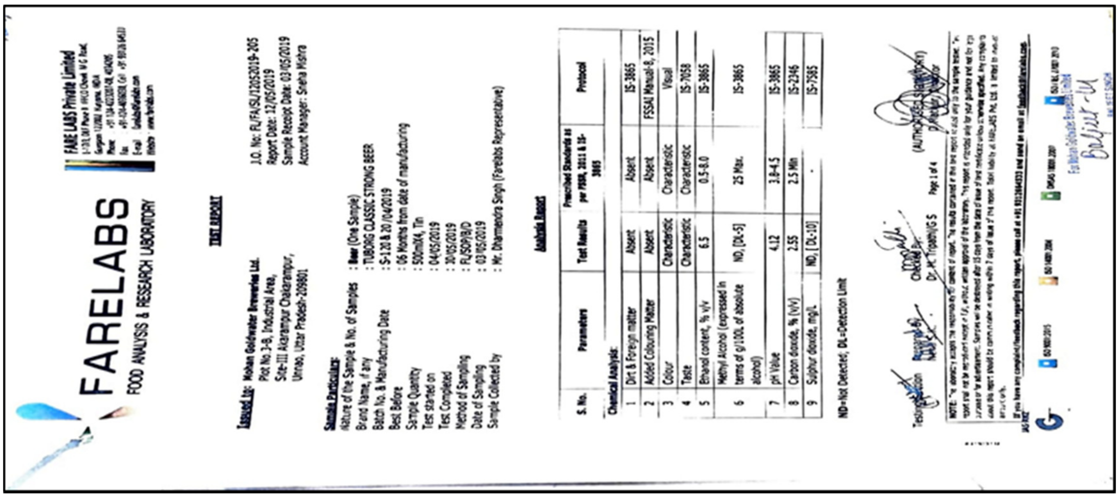

FARELABS
FOOD ANALYSIS & RESEARCH LABORATORY

FARE LABS Private Limited

TEST REPORT

Issued to: Mohan Goldwater Breweries Ltd.
Plot No.3-B, Industrial Area,
Site-III Akarampur Chakarampur,
Unnao, Uttar Pradesh-209801

J.O. No: FL/FA/SL/12052019-205
Report Date: 12/05/2019
Sample Receipt Date: 03/05/2019
Account Manager: Sneha Mishra

Sample Particulars:

Nature of the Sample & No. of Samples	: Beer (One Sample)
Brand Name, if any	: TUBORG CLASSIC STRONG BEER
Batch No. & Manufacturing Date	: S-120 & 20/04/2019
Best Before	: 06 Months from date of manufacturing
Sample Quantity	: 500mlX4, Tin
Test started on	: 04/05/2019
Test Completed	: 10/05/2019
Method of Sampling	: FL/SOP/B/D
Date of Sampling	: 03/05/2019
Sample Collected by	: Mr. Dharmendra Singh (Farelabs Representative)

Analysis Report

S. No.	Parameters	Test Results	Prescribed Standards as per FSSR, 2011 & IS-3865	Protocol
Chemical Analysis:				
1	Dirt & Foreign matter	Absent	Absent	IS-3865
2	Added Colouring Matter	Absent	Absent	FSSAI Manual-8, 2015
3	Colour	Characteristic	Characteristic	Visual
4	Taste	Characteristic	Characteristic	IS-7058
5	Ethanol content, % v/v	6.5	0.5-8.0	IS-3865
6	Methyl Alcohol (expressed in terms of g/100L of absolute alcohol)	ND, [DL-5]	25 Max.	IS-3865
7	pH Value	4.12	3.8-4.5	IS-3865
8	Carbon dioxide, % (v/v)	2.55	2.5 Min	IS-2346
9	Sulphur dioxide, mg/L	ND, [DL-10]	-	IS-7585

ND=Not Detected; DL=Detection Limit

Tested by / Checked By: Dr. M. Tripathi/G S / Page 1 of 4 / (AUTHORISED SIGNATORY)

For Mohan Goldwater Breweries Limited

चित्र 5.1: लैब परीक्षण रिपोर्ट

(ख) एल्कोपॉप के दो ब्रांडों (वर्ष 2019-20 के लिए लिमोन फ़िज़ और ऑरेंज फिज) के एक अन्य मामले में परीक्षण मापदंडों के सभी मूल्य समान थे जो सांख्यिकीय रूप से काफी असंभव है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि लाइसेंस प्रदान करते समय पिछले वर्ष की रासायनिक रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाता है और लाइसेंसधारी से संदिग्ध जाली रासायनिक रिपोर्ट के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाइसेंसधारी से स्पष्टीकरण मांगने के बजाय मामले को सत्यापित करने के लिए फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना चाहिए था।

अनुशंसा 5.5: फोरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन किया जाए और मामले की जांच की जानी चाहिए। ऐसी गंभीर चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

5.6 गलत श्रेणी में ब्रांड का अनियमित पंजीकरण

नमूना-जांच किए गए लाइसेंसधारियों द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता परीक्षण-प्रमाणपत्रों के विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि आबकारी विभाग द्वारा एक ब्रांड इंडो स्पिरिट बेवरेजेज (एल1) के, 'ब्रो कोड क्राफ्टेड ब्रूट 5' को 2018-19 को "वाईन" की श्रेणी के तहत अनुमोदित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणपत्र 'वाईन' श्रेणी के बजाय 'कम मादक पेय पदार्थ' श्रेणी के लिए था। हालांकि, इन प्रमाणपत्रों को आबकारी विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था और लाइसेंसधारी ने 61,488 बोतलें (वर्ष 2018-19 के लिए 59,064 और वर्ष 2019-20 के लिए 2,424) बेचीं।

अप्रैल 2019 में आबकारी विभाग ने एफएसएसएआई मानदंडों का पालन नहीं करने के संबंध में लाइसेंसधारी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जिसमें वाइन के लिए न्यूनतम सात *प्रतिशत* अल्कोहल की मात्रा अनिवार्य है। 5 अप्रैल 2019 को, आइएमएफएल अनुभाग ने उपरोक्त ब्रांड की बिक्री/खरीद को रोकने का प्रस्ताव दिया क्योंकि कंपनी ने गलत दस्तावेजों पर ब्रांड को वाईन श्रेणी के तहत पंजीकृत किया था, क्योंकि ब्रांड में अल्कोहल की मात्रा केवल 5 *प्रतिशत* v/v थी, जिससे कि उपभोक्ताओं के साथ-साथ विभाग को भी गुमराह किया जा रहा था। आबकारी आयुक्त ने 10 अप्रैल 2019 को प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि, 10 अप्रैल 2019 को कार्रवाई शुरू करने के बाद भी 1128 बोतलों के लिए छः परिवहन परमिट (10 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक) जारी किए गए थे।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मामला विचाराधीन है और आबकारी अधिनियम/नियमों के अनुसार इसका शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

अनुशंसा 5.6: बिना उचित परिश्रम और गुणवत्ता परीक्षण प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के लाइसेंसधारी को लाइसेंस जारी करने और लाइसेंसधारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ होने के बाद भी परिवहन परमिट देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए।

5.7 पुराने प्रमाणपत्र के आधार पर लाइसेंस का अनियमित निर्गमन

वर्ष 2018-19 के लिए इंडो स्पिरिट बेवरेजेज (एल1 लाइसेंसधारी) द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता परीक्षण प्रमाणपत्रों की जांच करने पर यह पाया गया कि लाइसेंसधारी ने शराब के तीन ब्रांडों (ब्रो कोड 5, ब्रो कोड 10 और ब्रो कोड 15) के संबंध में वर्ष 2017-18 के लिये प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की थी। हालांकि आबकारी विभाग इसका पता लगाने में विफल रहा और नवीनतम प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर जोर नहीं दिया।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मामला विचाराधीन है और आबकारी अधिनियम/ नियमों के अनुसार इसका शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

5.8 निष्कर्ष

लाइसेंसधारियों द्वारा गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट लाइसेंस जारी करने के लिए ब्रांड पंजीकरण के समय प्रस्तुत की गई थी। लाइसेंस जारी करते समय विभाग बीआईएस मानदंडों के साथ प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्टों के अनुपालन की जांच करने में विफल रहा। आबकारी विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट के उचित सत्यापन का अभाव दिल्ली में आपूर्ति की जा रही शराब की गुणवत्ता को लेकर चिंता पैदा करती है। लाइसेंस जारी करते समय उपयोग किये गये पानी की गुणवत्ता, हानिकारक तत्वों, सूक्ष्म जीवों, सटीक मिथाइल अल्कोहल मात्रा आदि से संबंधित महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अलावा कुछ परीक्षण प्रयोगशालाएं जिन्होंने लाइसेंसधारियों के लिए गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं, वे एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे जो कि एफएसएसएआई मानदंडों के अनुसार अनिवार्य है।

विभाग द्वारा, लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ संलग्न की जाने वाली परीक्षण रिपोर्ट तथा शराब की नियमित खेप की जांच के लिए कोई चेकलिस्ट/एसओपी तैयार नहीं किया गया था।

अध्याय VI

आबकारी खुफिया ब्यूरो और जब्ती

अध्याय VI: आबकारी खुफिया ब्यूरो और जब्ती

आबकारी खुफिया ब्यूरो की खुफिया जानकारी एकत्र करने और बाद में समन्वित छापे तथा जब्ती के माध्यम से शराब की अवैध तस्करी और शराब की अंतर्राज्यीय तस्करी से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर पर आगे की जांच और अभियोजन के लिये कार्रवाई की जाती है। जब्ती शाखा सभी दर्ज एफआईआर (दिल्ली पुलिस द्वारा स्वतंत्र रूप से दर्ज की गई एफआईआर सहित) का रिकॉर्ड रखती है और जब्त की गई संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया की जानकारी रखती है।

यह देखा गया कि ईआईबी और जब्ती शाखा कम समन्वय के साथ कम इष्टतम ढंग से काम कर रहे थे। एफआईआर और बरामदगी पर नियमित डेटा को अल्पविकसित तरीके से रखा गया था जिसका विश्लेषणात्मक मूल्य कम था। तस्करी के मूल कारण पर रोक लगाने के लिए कोई भी कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी तैयार नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने देशी शराब की तस्करी के लिए संभावित संरचनात्मक कारकों को इंगित करने के लिए नमूना डेटा का विश्लेषण किया।

6.1 परिचय

आबकारी खुफिया ब्यूरो (ईआईबी) नियामक कार्य करने वाली आबकारी विभाग की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसे निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गयी है:

- विभिन्न नशीले पदार्थों और नशीली दवाओं की अंतर्राज्यीय तस्करी की रोकथाम करना
- अवैध शराब और नशीली दवाओं के निर्माण और बिक्री का पता लगाना
- बिना लाइसेंस के परिसरों में अवैध रूप से शराब परोसने की जांच करना और पी-10 लाइसेंस[36] का अनुपालन सुनिश्चित करना
- अवैध शराब की बिक्री का रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों के साथ संपर्क करना

[36] पी-10 परमिट आवासीय स्थानों और सामुदायिक केंद्रों पर आयोजित होने वाली व्यक्तिगत पार्टियों में भारतीय शराब और विदेशी शराब की सेवा के लिए एक परमिट है।

ईआईबी में दिल्ली पुलिस के समर्पित फील्ड कर्मी और पुलिस की सहायता करने वाले मुखबिरों का एक नेटवर्क शामिल है। ईआईबी छापेमारी करता है, अवैध शराब और संबंधित वाहन को जब्त करता है, जब्ती ज्ञापन तैयार करता है और स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराता है।

आबकारी विभाग की जब्ती शाखा, आबकारी अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज सभी एफआईआर के रिकॉर्ड एकत्र करती है और आबकारी अधिनियम के तहत जब्त शराब को नष्ट करने और जब्त किए गए वाहनों की नीलामी की कार्यवाही करती है।

6.2 ईआईबी डेटा का विश्लेषण

ईआईबी के पिछले चार वर्षों (2017-21) के जब्ती के सभी मामलों और एफआईआर विवरण के इलेक्ट्रॉनिक डेटा का विश्लेषण शराब की तस्करी के पैटर्न से संबंधित कुछ अंतःदृष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया था तथा आबकारी विभाग द्वारा मामलों के संज्ञान की जांच करने के लिए भौतिक अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी।

अप्रैल 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए ईआईबी डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(i) ईआईबी द्वारा कुल 3580 एफआईआर दर्ज की गईं।

(ii) जब्त आईएमएफएल की कुल मात्रा 4.38 लाख क्वॉर्ट[37] (एक क्वार्ट में 750 एमएल होती है) थी और जब्त की गई देशी शराब 9.12 लाख क्वॉर्ट थी।

(iii) वर्ष 2018 (774), 2019 (876) और 2020 (1068) में एफआईआर की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई। हरियाणा की सीमा से लगे दिल्ली के जिलों (दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, बाहरी) में आबकारी अधिनियम के तहत कुल एफआईआर का 83 *प्रतिशत* और शराब (आईएमएफएल और सीएल) मात्रा के हिसाब से 77 *प्रतिशत* है।

(iv) देशी शराब सबसे अधिक जब्त की गई शराब है जो ईआईबी द्वारा जब्त की गई कुल शराब का 65 *प्रतिशत* है। इसके कुछ कारणों पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

[37] विभिन्न बोतल आकारों का उल्लेख किया गया है लेकिन क्वॉर्ट समकक्ष के रूप में एकत्रित किया गया है

6.3 देशी शराब खरीद में ढांचागत कमजोरियां जो इसकी तस्करी को बढ़ावा दे रही है

लेखापरीक्षा ने थोक जब्ती से संबंधित कुल 34 एफआईआर (2017-21) का इस प्रकार चयन किया कि यह प्रत्येक वर्ष में जब्त की गई कुल देशी शराब का कम से कम 10 *प्रतिशत* हो। इन चयनित एफआईआर का विस्तार से विश्लेषण किया गया। देशी शराब की तस्करी, देशी शराब की खरीद और लाइसेंस नीति की संरचनात्मक कमजोरियों की ओर इंगित करती है:

(i) डेटा से पता चलता है कि लगभग सभी जब्त शराब की बोतलें "निप्स (180 एमएल)" थीं। देशी शराब की सोर्सिंग नीति ने कुल कोटे में निप्स की संख्या पर प्रतिबंध लगा दिया। निप्स कुल आपूर्ति का केवल 20 *प्रतिशत* ही बन सका। यह प्रतिबंध कृत्रिम और अनुचित था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईएमएफएल के मामले में, "निप्स" सबसे अधिक लोकप्रिय शराब की बोतल का आकार था, जो बेची गई बोतलों के 50[38] *प्रतिशत* से अधिक का योगदान करता था, जो कि अन्य सभी आकारों की संयुक्त बिक्री से अधिक था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि लेखापरीक्षा की आपत्ति विचारणीय है और देशी शराब सोर्सिंग नीति में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा जा रहा था ताकि निप्स के अनुपात में वृद्धि की जा सके। हालांकि, यह भी कहा गया कि चूंकि देशी शराब सबसे सस्ती है, इसलिए डिस्टिलरी के लिए पूरी बोतल बेचना किफायती हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने जवाब के अंतिम भाग को असंतोषजनक पाया, क्योंकि बेहतर आपूर्ति और राजस्व का अनुकूलन आबकारी विभाग की चिंता होनी चाहिए न कि डिस्टिलरी की आर्थिक चिंता। निविदा प्रक्रिया वैसे भी उचित मूल्य पर उपयुक्त कोटा के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं की खोज कर लेगी।

(ii) दिल्ली में देशी शराब की वास्तविक मांग का कोई वास्तविक आंकलन नहीं किया गया था। पिछले आठ वर्षों से, देशी शराब की आपूर्ति 300 लाख बीएल (बल्क लीटर) प्रति वर्ष सीमित थी, जो कि प्लस या माइनस 25 *प्रतिशत* तक भिन्नता के अधीन थी (वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक वास्तविक आपूर्ति औसत 240 लाख बीएल काफी कम थी)। दिलचस्प बात यह है कि 2009-10 और 2010-11

[38] इस रिपोर्ट के अध्याय-2 में ठेका बिक्री डेटा विश्लेषण के नमूने के अनुसार

में देशी शराब की आपूर्ति क्रमशः 520.65 लाख बीएल और 495 लाख बीएल थी। वर्ष 2013-14 में देशी शराब की आपूर्ति अचानक पिछले स्तर के आधे से भी कम 236 लाख बीएल तक कम हो गई थी। शुरू में उद्धृत कारण था, "बेहतर गुणवत्ता वाली शराब की ओर उपभोक्ता की पसंद में धीरे-धीरे बदलाव" एक ऐसा दावा जो निराधार था। यह मूल रूप से 2012-13 में दिल्ली मीडियम लीकर (डीएमएल) को देशी शराब के विकल्प के रूप में पेश करने के लिए मंत्रीमंडल के एक निर्णय द्वारा किया गया था, हालांकि, यह एक विफलता के रूप में समाप्त हो गया और 2015-16 की नीति में डीएमएल परियोजना को बंद कर दिया गया। संयोग से, देशी शराब का कोटा कभी भी पिछले स्तरों तक पुन: स्थापित नहीं किया गया और कम किए गए 300 लाख बीएल के रूप में रहा। आपूर्ति पक्ष की बाधा के कारण देशी शराब की तस्करी और अवैध बिक्री का जोखिम होता है जिससे अंततः आबकारी राजस्व में हानि होती है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि देशी शराब की आपूर्ति के लिए वार्षिक निविदा 33 लाख पेटी के लिए थी और आपूर्ति की गई वास्तविक मात्रा 30 लाख पेटी से कम थी, जिससे यह अनुमान लगता है कि देशी शराब की आपूर्ति वास्तव में पर्याप्त थी।

जवाब असंतोषजनक है, क्योंकि डेटा (देशी शराब की कोटा यूटिलाइज्ड रिपोर्ट) से पता चलता है कि वर्ष 2017-18 से 2020-2021 के लिए, आबकारी विभाग द्वारा आपूर्ति के लिए आवंटित औसत कोटा वास्तव में जवाब में उल्लिखित 33 लाख पेटी न होकर 27.32 लाख पेटी थी। इसके अलावा, देशी शराब के थोक लाइसेंसधारियों से आपूर्ति में भी कमी थी और देशी शराब की वास्तविक आपूर्ति औसतन 26.52 लाख पेटी थी। दुकानों की संख्या की पर्याप्तता, देशी शराब की दुकानों के उचित भौगोलिक वितरण, शुल्क भुगतान की गई शराब की मांग पर देशी शराब की तस्करी के प्रभाव आदि के आधार पर वास्तविक मांग आकलन की आवश्यकता है।

(iii) देशी शराब के मामले में, निर्माताओं को आबकारी शुल्क विभाग द्वारा कोटा की नीलामी के अनुसार चुना गया था, इस प्रकार आपूर्ति किये गये ब्रांड कुछ[39]

[39] वर्षवार देशी शराब के उपलब्ध ब्रांड 2017-18 -6 ब्रांड, 2018-19 -8 ब्रांड, 2019-20 -7 ब्रांड, 2020-21 -7 ब्रांड

निर्माताओं पर निर्भर थे जो चुने गये थे। देशी शराब के विशिष्ट ब्रांडों (जैसे असली संतरा, रसीला संतरा) की बड़े पैमाने पर तस्करी ग्राहकों की पसंद का संकेत हो सकती है क्योंकि इन ब्रांड के निर्माता दिल्ली देशी शराब कोटा के लिये आपूर्तिकर्ता नहीं थे और वस्तुतः एक समानांतर आपूर्ति श्रंखला चला रहे थे।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि देशी शराब के लिये थोक लाइसेंस एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया गया था, जहाँ सभी डिस्टिलरी भाग लेने के लिये स्वतंत्र थी और किसी भी निर्माता को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी।

जवाब असंतोषजनक है क्योंकि निविदा प्रक्रिया वास्तव में प्रतिबंधात्मक थी क्योंकि "एल3 लाइसेंस के लिये निविदा के नियम और शर्तें" में स्पष्ट रूप से उन आपूर्तिकर्ताओं की भागीदारी की अनुमति नहीं दी गई जो कुल कोटा के 10 *प्रतिशत* से कम आपूर्ति करने के इच्छुक थे, इस प्रकार एक वर्ष में अधिकतम 10 देशी शराब ब्रांड ही हो सकते थे। देशी शराब के लिये विकल्प की यह कमी अतार्किक थी।

इस प्रकार विभाग द्वारा उचित मांग मूल्यांकन की कमी के साथ-साथ एल3 लाइसेंस के लिये निविदा की प्रतिबंधात्मक शर्तों और, ग्राहकों की प्राथमिकताओं की अनदेखी ने देशी शराब की समानांतर आपूर्ति में योगदान दिया, जिससे सरकार को राजस्व की संभावित हानि हुई।

6.4 जब्ती शाखा की भूमिका और ईआईबी के साथ समन्वय का अभाव

विभाग द्वारा वर्ष 2010 से 2021 तक की जब्ती के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 की अवधि के मामलों का विश्लेषण किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा कुल 12,556 एफआईआर दर्ज की गई। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। जब्ती के आंकड़ों में ईआईबी मामलों को शामिल किया गया था क्योंकि जब्ती शाखा ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को उठाने और निपटाने के रिकॉर्ड रखे थे।

दिल्ली में आपूर्ति की जा रही अवैध शराब (आबकारी विभाग के नियामक दायरे से बाहर) की जब्ती के लिए ईआईबी और दिल्ली पुलिस एक साथ (कुल जब्ती मामलों में योगदान देने के लिये) जिम्मेदार है।

जब्ती डेटा को हॉटस्पॉट और फोकस क्षेत्रों को उपलब्ध करने में सक्षम होना चाहिए जहां ईआईबी उनके बाद के प्रयासों को निर्देशित कर सकता है। **चार्ट 6.1** से पता चलता है कि ईआईबी द्वारा कई हॉटस्पॉट की अनदेखी की जा रही थी क्योंकि नियोजित छापों की संख्या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई द्वारा सामने आए मामलों के समान अनुपात में नहीं थी। यह स्पष्ट है कि जब्ती डेटा की जानकारी का उपयोग ईआईबी के छापे की योजना बनाने के लिए नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि ईआईबी ने कुछ क्षेत्रों/पुलिस थानों (पी.एस.) के सभी मामलों में बड़े अनुपात में योगदान दिया (जैसा कि जब्ती के आंकड़ों से पता चलता है)। उदाहरण के लिए, अलीपुर थाने में कुल 253 मामलों में ईआईबी के 164 मामले दर्ज थे। हालांकि, यह कई क्षेत्रों के लिए सही नहीं है, जहाँ दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन ईआईबी ने उन क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं दी। सुल्तानपुरी पी.एस. में सबसे अधिक एफआईआर यानी 387 दर्ज थी, लेकिन ईआईबी ने इनमें से केवल 27 में योगदान दिया था। इसी तरह, बहुत से हॉटस्पॉट्स पर ईआईबी का अतिरिक्त जोर नहीं देखा गया है, जो ईआईबी द्वारा एक कमजोर और असमन्वित/अनियोजित संचालन को दर्शाता है (**चार्ट 6.1** देखें)।

चार्ट 6.1: 2017-21 एफआईआर की तुलना

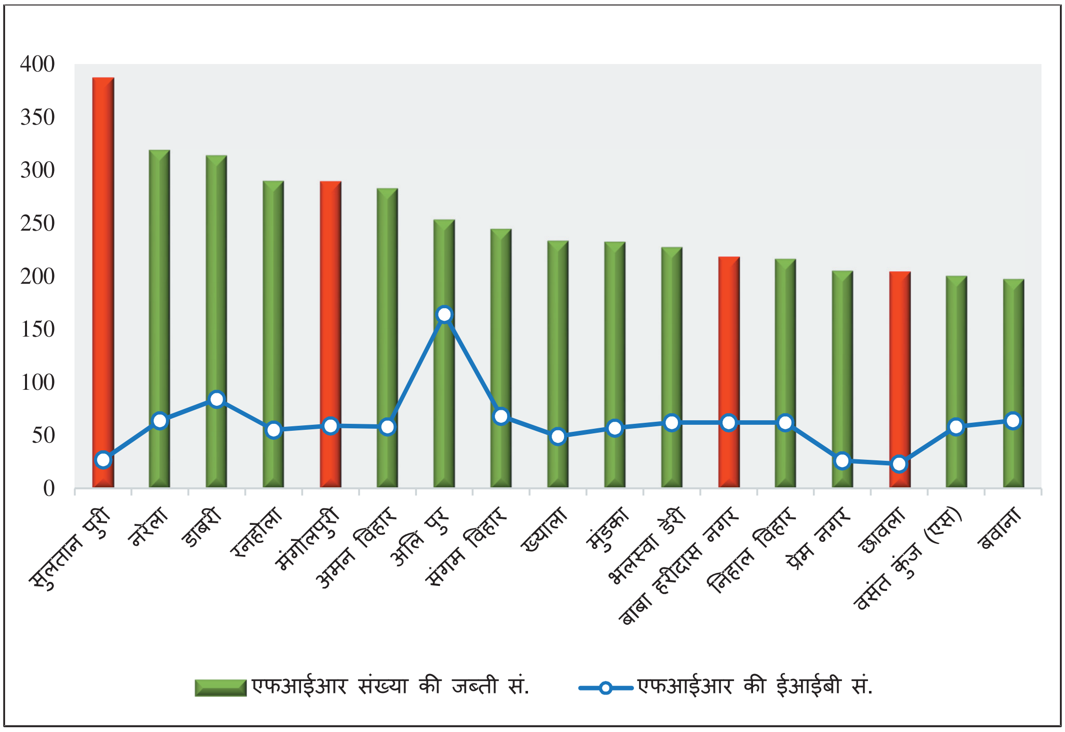

ईआईबी को आबकारी विभाग की प्रवर्तन/जब्ती शाखा के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि ईआईबी की खुफिया जानकारी के बिना, शराब की तस्करी की रोकथाम के प्रयास अप्रभावी और निष्क्रिय हो जाते है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ईआईबी इस तथ्य पर विचार करता है कि कुछ क्षेत्र तस्करी के लिए अतिसंवेदनशील हैं और यह तदनुसार उन क्षेत्रों पर स्थानीय पुलिस मुखबिरों का उपयोग करने पर जोर देता है। ईआईबी टीमों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है (बैठक के कार्यवृत्त संलग्न नहीं थे) और रिकवरी डेटा का विश्लेषण किया जाता है। ईआईबी, शराब पकड़ने के बाद जांच एजेंसी यानी दिल्ली पुलिस को औपचारिक शिकायत देता है जो एफआईआर दर्ज करती है और नजदीकी समन्वय बनाए रखा जाता है। हॉटस्पॉट की पहचान और समन्वित छापेमारी के साथ-साथ ईआईबी, जब्ती, प्रवर्तन और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय पर जोर दिया गया।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि ईआईबी, प्रवर्तन शाखा और ज़ब्ती शाखा के बीच ऐसी सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय, जैसा कि जवाब में दिया गया है, के बारे में कोई सहायक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया। यहां तक कि डेटा को खंडित तरीके से या एक्सेल शीट में कई डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के साथ रखा गया था। पिछले वर्षों में समान ब्राण्डों की बढ़ती संख्या के साथ तस्करी के बढ़ते मामले, सख्ती के दावे को झुठलाता है। इसके अलावा, निश्चित क्षेत्रों में ईआईबी द्वारा उठाए गए मामलों की संख्या दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए मामलों के अनुपात में नहीं थी, जो समन्वय और फोकस की कमी को दर्शाता है। प्रवर्तन शाखा के साथ समन्वय की कमी इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2018-19 में एल1, एल1एफ/एल31, एल32 लाइसेंसधारी परिसरों पर योजनाबद्ध प्रवर्तन छापे के 75 *प्रतिशत* मामलों में उल्लंघन पाए जाने के बावजूद (12 प्रवर्तन छापों में से 9 में उल्लंघन पाया गया), 2019-20 में केवल दो प्रवर्तन छापे मारे गए।

अनुशंसा 6.1: इएससीआईएमएस का उपयोग ईआईबी, जब्ती और प्रवर्तन मामलों से संबंधित सूक्ष्म डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। शराब की तस्करी के हॉटस्पॉट, शामिल ब्रांड, तस्करी के संभावित कारणों, अनुमानित राजस्व रिसाव आदि को पहचानने के लिए जब्ती और ईआईबी मामलों के मामलेवार एकत्रित आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए।

6.5 अन्य कमियां और समन्वय का अभाव

लेखापरीक्षा ने 2017-21 के दौरान पंजीकृत 70 एफआईआर (आईएमएफएल-16, एफएल-20, सीएल-34) की जांच की और निम्नलिखित पाया:

(i) लेखापरीक्षा ने पाया कि ईआईबी की भूमिका सामान्य रूप से आबकारी विभाग के कामकाज (लाइसेंस जारी करना और प्रबंधन तथा उसके बाद विनियमन) से काफी हद तक अलग रहा। ईआईबी छापे से तस्करी की दृष्टि से अधिक संवेदनशील क्षेत्रों और तस्करी की गई शराब के प्रकार और ब्राडों आदि के संदर्भ में शराब की तस्करी के एक व्यवस्थित और बहुत ही अनुमानित पैटर्न सामने आया। डेटा से पता चलता है कि एक डिस्टिलरी (एडीएस स्पिरिट्स) द्वारा निर्मित चार आईएमएफएल ब्रांड में सभी आईएमएफएल बरामदगी का 38 *प्रतिशत* शामिल है और इसी डिस्टलरी से संबंधित एक ब्रांड में कुल देशी शराब की बरामदगी का 69 *प्रतिशत* शामिल है। दिल्ली में पकड़ी गई "असली संतरा" और "संतरा मसालादार" ब्रांड नाम वाली तस्करी की शराब पर लगभग विशेषरूप से "हरियाणा में बिक्री के लिए" अंकित था। "क्रेज़ी रोमियो" नामक ब्रांड के मामले में, दिल्ली में आमतौर पर जब्त की गई शराब पर "अरुणाचल प्रदेश में बिक्री के लिए" अंकित किया गया था।

केस फाइलों के अनुसार, मामलों की कार्यवाई आरोपियों को नोटिस जारी करने, वाहन की नीलामी और शराब को नष्ट करने तक ही सीमित थी। समस्या के आपूर्ति पक्ष के मुद्दों को सामने लाने के लिये शराब की आपूर्ति के प्रबंधन/विनियमन पर असर डालने वाले अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की आगे जांच नहीं की गई।

इसके अलावा, विभाग के पास उपलब्ध रिकार्ड में समान/प्रतिस्पर्धी ब्रांडों की घरेलू बिक्री पर कुछ ब्रांडों की तस्करी के प्रभाव या राजस्व पर इसके संभावित प्रभाव के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया गया था।

अन्य राज्यों के आबकारी अधिकारियों के साथ एक ठोस कार्रवाई से तस्करी की जा रही शराब के स्त्रोत के बारे में सबूत इकट्ठा करने और इसकी कार्यप्रणाली को समझने में मदद मिलती।

(ii) एफआईआर और जब्ती ज्ञापन को ठीक से तैयार नहीं किया गया था और तस्करी के ब्रांड और उक्त शराब के निर्माता के सटीक नाम को नजरअंदाज कर दिया गया था। दो एफआईआर में, एफआईआर, जब्ती ज्ञापन और आबकारी विभाग द्वारा जारी जब्ती नोटिस में दर्ज ब्रांड/मात्रा के बीच विसंगतियां देखी गई थी। एफआईआर में हाई स्पीड व्हिस्की (क्वीन डिस्टिलरी) को जब्ती ज्ञापन में बेस्टो व्हिस्की (एनवी डिस्टिलरी) के रूप में लिखा गया था, आबकारी विभाग द्वारा जारी नोटिस में 'असली संतरा' ब्रांड की जब्त की गई बोतलों की संख्या यानी 6,900 निप्स का उल्लेख नहीं किया गया था।

(iii) नवम्बर 2014 और फरवरी 2020 के बीच, पैलेट फेस्ट प्रा.लिमिटेड को 7.8 लाख बोतल शराब खरीदने की अनुमति 29पी-10ए लाइसेंस जारी करके दी गई थी। हालांकि 31 अक्टूबर 2014 को, पैलेट फेस्ट प्रा. लिमिटेड ने तीन दिन के आयोजन के लिए तीन लाख बोतल शराब खरीदने के लिए तीन परमिट के लिए आवेदन किया था और इसके लिए अनुमति प्रदान की गई थी। बाद में, एक एफआईआर (साउथ कैंपस) में पैलेट फेस्ट प्रा. लिमिटेड को पी-10ए लाइसेंस पर जारी शराब की जमाखोरी को दर्शाया गया जिसका उपयोग नहीं किया गया और उसे कथित तौर पर रेस्तरां को आपूर्ति के लिए भेजा जा रहा था (रेस्तरां पर लगाए गए अतिरिक्त आबकारी शुल्क से बचने के लिए)। आबकारी विभाग द्वारा मामले की आगे जांच नहीं की गई कि इकाई को पी10ए लाइसेंस पर इतनी भारी मात्रा में शराब क्यों जारी की गई, जो पाँच वर्षों से अधिक समय से उनके सामान्य माँग पैटर्न से बहुत अधिक थी।

नमूना जांच की गयी सभी 70 एफआईआर में यह पाया गया कि किसी भी एफआईआर में, आबकारी विभाग ने जब्त शराब की आपूर्ति पक्ष के मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश नहीं की।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि आबकारी अधिनियम, 2009 के अनुसार लाइसेंस देने में ईआईबी की कोई भूमिका नहीं है। यह भी उल्लेख है कि ईआईबी डेटा का उपयोग किया जाता है, टीमों के प्रदर्शन की निगरानी की जाती है और रिकवरी डेटा का विश्लेषण किया जाता है और ईआईबी, प्रवर्तन और प्रवर्तन गतिविधियों के बीच धनिष्ठ समन्वय बनाये रखा जाता है। खराब तरीके से तैयार की गई एफआईआर के संबंध में कहा गया

कि सावधानी के बावजूद, कुछ अनजानी त्रुटियां हो सकती हैं। तस्करी के बारे में, यह जवाब दिया गया कि तस्करों ने मूल्य अंतर का लाभ उठाने के लिए निकटवर्ती राज्यों से कानूनी रूप से शराब खरीदी होगी। यह उल्लेख किया गया था कि वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति निर्माताओं की भूमिका को हटा देगी क्योंकि वे लाइसेंसधारी नहीं हैं। पी-10ए परमिट के कथित दुरुपयोग के संबंध में कहा गया कि पी-10ए परमिट के द्वारा खरीदी गई शराब को परमिट के साथ टैग नहीं किया जाता है और शराब और परमिट के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि कोई भी रेस्तरां गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब नहीं परोसता क्योंकि यह एक बड़ा अपराध है।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि ईआईबी, प्रवर्तन और जब्ती के बीच ऐसी सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय के लिये कोई सहायक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था जैसा कि जवाब में कहा गया है। यहाँ तक कि डेटा को खंडित तरीके से एक्सेल शीट में कई डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के साथ रखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में तस्करी के बढ़ते मामले एवं समान ब्रांडों की बढ़ती संख्या सख्ती के दावे को झुठलाते है। इसके अलावा, विभाग ने एफआईआर में पी-10ए परमिट के कथित दुरुपयोग के निष्कर्षों का खंडन किया है और तर्क दिया है कि रेस्तरां एनडीपीएल की सेवा नहीं देते हैं, जो प्रवर्तन दल और ईआईबी के निष्कर्षों के विपरीत है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एफआईआर के बाद जांच के परिणामों को जोड़ा जा सकता है।

अनुशंसा 6.2: लाइसेंस जारी करने और प्रवर्तन छापे की योजना बनाने जैसे आबकारी विभाग के प्रशासनिक और नियामक कार्यों को मजबूत करने के लिए ईआईबी और जब्ती शाखा से प्रतिपुष्टि शामिल की जानी चाहिए।

अनुशंसा 6.3: अवैध शराब आपूर्ति श्रृंखला पर जांच-पड़ताल करने के लिए अन्य राज्यों के आबकारी विभागों के साथ समन्वित कार्रवाई की योजना बनाई जानी चाहिए।

6.6 निष्कर्ष

देशी शराब सोर्सिंग नीति ने कुल कोटे में निप्स की संख्या पर प्रतिबंध (कुल आपूर्ति का 20 *प्रतिशत*) लगाए रखा, जो कृत्रिम था और तस्करी को बढ़ावा देने वाला था। वर्ष 2013-14 में देशी शराब के विकल्प के रूप में दिल्ली मीडियम लीकर (डीएमएल) को शुरू करने के आधार पर देशी शराब की आपूर्ति पिछले वर्ष की आपूर्ति की आधी पर

सीमित कर दी गई थी। यद्यपि डीएमएल परियोजना को 2015-16 में छोड़ दिया गया था, पर देशी शराब का कोटा पिछले स्तरों पर बहाल नहीं किया गया था। कृत्रिम मांग और आपूर्ति अंतर तस्करी वाली शराब को बढ़ावा देता है। ईआईबी एवं जब्ती शाखा समन्वित रूप में काम नहीं कर रही थी। जब्ती के आंकड़ों का इस्तेमाल ईआईबी छापे की योजना बनाने के लिए नहीं किया जा रहा था। एफआईआर और जब्ती ज्ञापन ठीक से तैयार नहीं किए गए थे और आमतौर पर कई मामलों में तस्करी के ब्रांड और उक्त शराब के निर्माता के सटीक नाम को नजरअंदाज कर दिया गया था।

अध्याय VII

प्रवर्तन

अध्याय VII: प्रवर्तन

आबकारी विभाग के पास निहित अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर्तन शाखा को लाइसेंस वाले परिसरों में निरीक्षण करने और निरीक्षण के दौरान दिल्ली आबकारी अधिनियम/नियमों का कोई उल्लंघन होने पर, आगे अभियोजन के लिए साक्ष्य के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रक्रिया के कई चरणों में निरीक्षण की योजना बनाने से लेकर इन्हें संचालित करने और बाद में मुकदमा चलाने तक कमियां देखी गईं। प्रवर्तन निरीक्षण सुनियोजित और समन्वित नहीं थे। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अभाव में, की गयी छापेमारी किसी भी उचित मानदंड जैसे जोखिम आधारित रैंकिंग, सिस्टम जनित रेड फ्लैग, और डेटा विसंगति के अन्तर्गत नहीं थे। इसके फलस्वरूप, खराब साक्ष्य संग्रह, अपर्याप्त कारण बताओ नोटिस, गलत निरीक्षण रिपोर्ट, ईएससीआईएमएस में उपयोग की जाने वाली त्रुटिपूर्ण मिलान विधियों, आदि के कारण मामलों की कमजोर प्रस्तुति हुई। इस तरह के अनियोजित दृष्टिकोण से प्रवर्तन शाखा गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री को रोकने में अप्रभावी हो जाती है और सरकार को राजस्व हानि का खतरा बढ़ जाता है।

7.1 परिचय

प्रवर्तन शाखा आबकारी विभाग की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसे आबकारी लाइसेंस वाले परिसरों में औचक निरीक्षण करने और नियमों के उल्लंघन (आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत) की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रवर्तन दल उच्च अधिकारियों के निर्देश पर या विभिन्न लाइसेंसधारियों के खिलाफ शिकायतों के आधार पर निरीक्षण करते हैं। यह इन उल्लंघनों के साक्ष्य एकत्र करता है और एक निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर) तैयार करता है जो आगे की जांच और अभियोजन का आधार बनता है जैसा कि **चार्ट 7.1** में दिखाया गया है।

चार्ट 7.1: जांच और अभियोजन प्रक्रिया

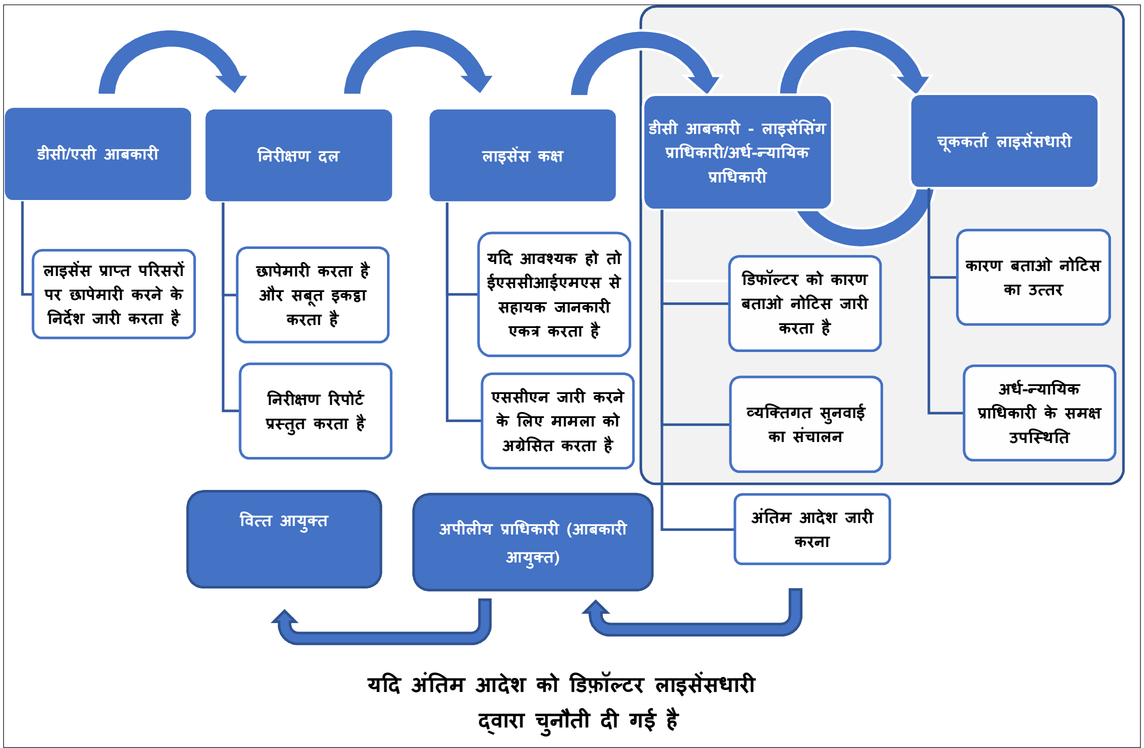

आबकारी विभाग को इस संबंध में निर्णय लेने की अर्ध-न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। कारण बताओ नोटिस जारी करने वाला प्राधिकारी और अर्ध-न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वाला प्राधिकारी उपायुक्त होता है। आयुक्त (आबकारी) अपीलीय प्राधिकारी होते हैं, और यदि आयुक्त द्वारा अपील खारिज कर दी जाती है, तो लाइसेंसधारी वित्त आयुक्त के न्यायालय में जा सकता है और निर्णय से असंतुष्ट होने पर दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

प्रवर्तन शाखा उनके द्वारा किए गए निरीक्षणों की एक वार्षिक पंजिका रखता है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए प्रवर्तन शाखा द्वारा किए गए निरीक्षणों का विवरण ब्यौरा (वर्ष 2017-18, 2020-21 और 2021-22 के लिए निरीक्षण पंजिकाएं लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई) **तालिका 7.1** में दिया गया है:

तालिका 7.1: निरीक्षण और उल्लंघन - तुलना

अवधि	2018-19		2019-20	
लाइसेंस के प्रकार	निरीक्षणों की संख्या	पाए गए उल्लंघनों की संख्या	निरीक्षणों की संख्या	उल्लंघनों की संख्या
एल-15, एल16, एल17, एल18	344	87	98	66
एल1/एल1एफ और एल31/एल32	12	9	2	1
एल6	40	1	55	26
एल8	6	1	3	2
एल-10	44	10	19	8

अवधि	2018-19		2019-20	
लाइसेंस के प्रकार	**निरीक्षणों की संख्या**	**पाए गए उल्लंघनों की संख्या**	**निरीक्षणों की संख्या**	**उल्लंघनों की संख्या**
एल7	26	4	23	13
एल12	14	5	7	6
एल3 और एल33	0	0	0	0

लेखापरीक्षा ने नमूना जांच के लिए 37 अपेक्षित लाइसेंसधारियों की फाइलों के प्रति केवल 19 फाईलें (1 एल1, 2 एल7, 3 एल10, और 12 रेस्तरां, 1 क्लब) प्राप्त की, जिसमें 38 निरीक्षणों (इसके बाद "निरीक्षण मामलों" के रूप में उल्लिखित) के बारे में विवरण शामिल थे।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि वर्ष 2017-18 और 2020-21 के लिए निरीक्षण पंजिका की प्रति उपलब्ध करा दी गयी थी। हालांकि यह न तो लेखापरीक्षा को प्राप्त हुई और न ही जवाब के साथ उसकी कोई प्रति संलग्न पाई गई थी।

7.2 प्रवर्तन प्रक्रिया और परिणाम में कमियां

प्रवर्तन मामलों के प्रक्रिया प्रवाह और प्रत्येक चरण के दायरे की समझ हासिल करना अनिवार्य है ताकि खामियों की पहचान की जा सके। इसे **चार्ट 7.2** में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

चार्ट 7.2: प्रवर्तन मामले - प्रक्रिया और परिणाम

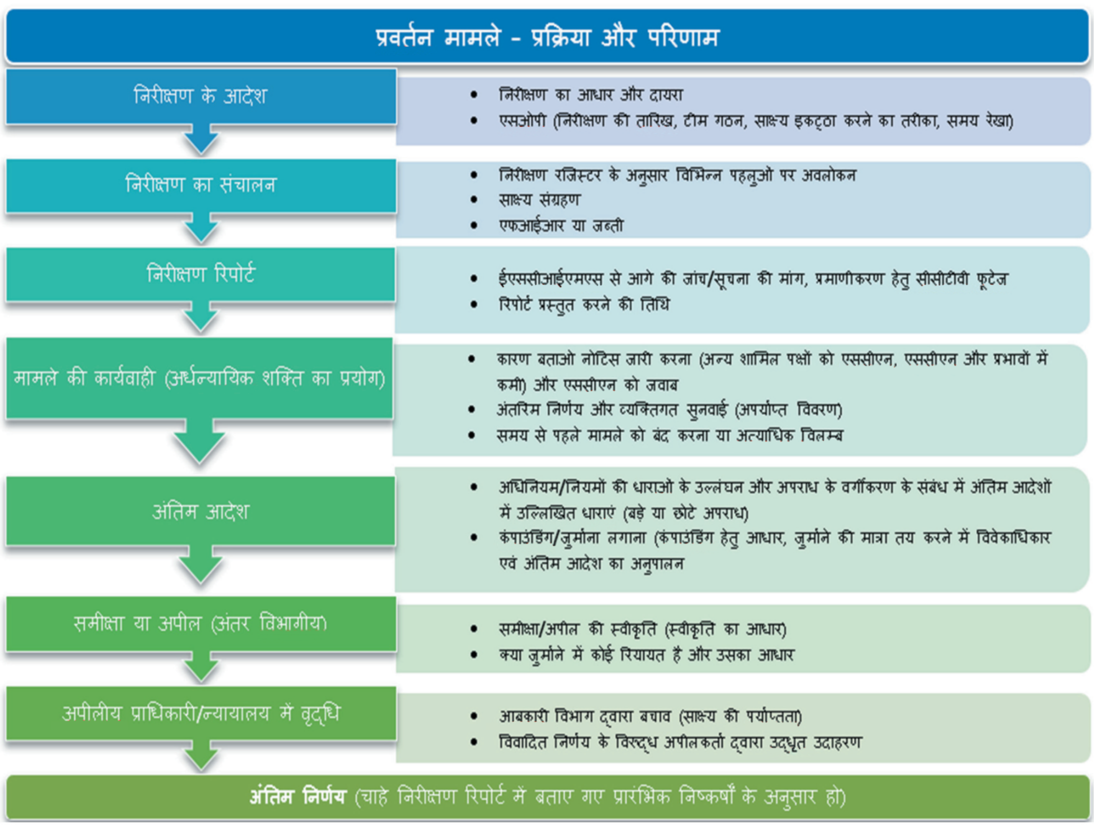

प्रवर्तन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण में देखी गई विभिन्न कमियों पर आगे के पैरा में चर्चा की गई है।

7.2.1 निरीक्षण के लिए योजना और निर्धारित प्रक्रियाओं का अभाव

प्रवर्तन प्रयासों को प्रभावी बनाने के लिए, निरीक्षण के लिए उचित योजना और निर्धारित कार्यवाही आवश्यक है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने इन पहलुओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया।

(i) निरीक्षण के लिए योजना

आबकारी विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन शाखा द्वारा कोई नियमित निरीक्षण नहीं किए जाते हैं। इसके बजाय, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर या शिकायत के आधार पर औचक निरीक्षण किए जाते हैं। लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए सभी मामलों में, यह स्पष्ट नहीं था कि निरीक्षण उच्च प्राधिकारी के निर्देशों के आधार पर शुरू किया गया था या बाहरी शिकायत और जोखिम मूल्यांकन के आधार पर औचक निरीक्षण करना पड़ा। विभाग द्वारा ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं रखा गया है।

इसके अलावा, नियोजित निरीक्षण ठोस खुफिया जानकारी पर आधारित होना चाहिए या डेटा आधारित होना चाहिए। नियोजित निरीक्षण के अभाव और ईआईबी मॉड्यूल (जिसमें कोई डेटा नहीं है जिसका उपयोग प्रवर्तन छापे की योजना बनाने के लिए किया जा सकता था, जैसा कि **पैराग्राफ 2.4** में बताया गया है), का गैर-संचालन आबकारी विभाग के नियामक कार्य के निष्पादन के लिए जोखिम पैदा करता है।

(ii) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अभाव

निरीक्षण की योजना और संचालन के संबंध में कोई एसओपी/मैनुअल तैयार नहीं किया गया था। किसी भी एसओपी/मैनुअल के अभाव में, निरीक्षण टीमों ने विवेकाधीन, खंडित और अनियोजित तरीके से छापे/निरीक्षण किए। एसओपी को निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जो लेखापरीक्षा जांच के दौरान नहीं पाए गए थे:

क) **संदिग्ध स्टॉक की जांच के लिए कोई नमूना प्रक्रिया नहीं** - लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण की गई 38 निरीक्षण रिपोर्टों में से किसी एक में भी नमूना जांच प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया था। कुछ निरीक्षणों में यह बताया गया कि स्टॉक की यादृच्छिक जांच की गई। कुछ अन्य दूसरे मामलों में सभी स्टॉक की जाँच की गई। कुछ मामलों में यह स्पष्ट नहीं था कि कितनी बोतलों/पेटियों की जांच की गई। उन मामलों के लिए

जहां स्टॉक को यादृच्छिक रूप से जांचा गया था, यादृच्छिक चयन के लिए अपनाई गई विधि का उल्लेख नहीं किया गया था। किसी भी दस्तावेजी प्रक्रिया के अभाव में, निरीक्षण दल केवल अपने निर्णय और समझ के आधार पर निरीक्षण कर रहे थे जिससे महत्वपूर्ण उल्लंघनों से चूकने का जोखिम था जिससे प्रवर्तन कार्य की प्रभावशीलता पर समझौता हो रहा था।

ख) **अपर्याप्त साक्ष्य एकत्र करना** - यह देखा गया कि एकत्र किए गए साक्ष्य अक्सर बहुत खराब होते थे और न्यायिक प्रक्रिया की जांच में सक्षम नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप मामला कमजोर हो जाता था या पर्याप्त साक्ष्यों के बिना समझौता हो जाता था। साक्ष्य जुटाने में कमियों वाले मामलों पर **पैराग्राफ 7.2.2 (iii)** में चर्चा की गई है।

ग) **अंतरिम निर्णय** - जब मामले की कार्यवाही चल रही हो साक्ष्यों के साथ छेड़-छाड़ के जोखिम को कम करने के लिए, प्रारंभिक निष्कर्ष के आधार पर, जो निर्णय लेना है, जैसा कि ट्रांसफर परमिट (टीपी) को बंद करने, शराब की दुकान को सील करने या लाइसेंसधारी आदि को निलंबित करने, उसे स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। एक उदाहरण में, लेखापरीक्षा ने देखा कि एक एचसीआर लाइसेंसधारी के परिसर में 12 बोतलें पाई गई, जिनकी बारकोड स्थिति से संकेत मिलता है कि वे "वेयरहाउस" में थी। आबकारी विभाग इन बोतलों के बारकोड को ब्लाक करने या उनके टीपी को रोकने में विफल रहा। नतीजतन, निरीक्षण के तीन महीने बाद, जबकि जाँच अभी भी चल रही थी, समान बारकोड वाली वही 12 बोतलें टीपी के साथ जोड़कर वेयरहाउस से भेज दी गई और बाद में लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त की गई।

घ) **समयसीमा** - निरीक्षण रिपोर्ट और सहायक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समयसीमा और कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करने के लिए समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए।

(iii) कारण बताओ नोटिस की संरचना - एक टिप्पणी कॉलम के साथ एससीएन की एक मानक संरचना निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें विशेष रूप से उल्लंघनों पर लागू होने वाले आबकारी अधिनियम/नियमों की धाराओं का उल्लेख हो जिनके बिना एससीएन अस्पष्ट और गैर-संगत हो सकते है जिससे अभियोजन प्रक्रिया कमजोर होती है।

(iv) निरीक्षण का दायरा परिभाषित नहीं है

पूर्णतया परिभाषित एसओपी के अभाव में, निरीक्षण का आदेश देने वाले प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह विशिष्ट मामलों के लिए निरीक्षण दल को स्पष्ट आदेश प्रदान करे। इसमें मुख्य रूप से निरीक्षण के दौरान जांच किए जाने वाले विभिन्न पहलुओं जैसे एनडीपीएल, एमएसआर गैप, स्वीकृत क्षमता से अधिक सीटें, रिकॉर्ड का रखरखाव न करना, कम उम्र में शराब पीना आदि के बारे में एक चेकलिस्ट शामिल होगी। उन कुछ क्षेत्रों पर भी आश्वासन दिया जाना चाहिए जिनकी जांच की गई थी और विशेष रूप से वर्तमान निरीक्षण के दायरे से बाहर रखे गए क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहिए। किसी भी मामले में, ऐसा विशिष्ट शासनादेश नहीं मिला।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) उपलब्ध नहीं थी, लेकिन सभी लेखापरीक्षा टिप्पणियों को शामिल करने के लिए एक नया एसओपी तैयार किया जा रहा था, जिससे प्रवर्तन शाखा की दक्षता बढ़ाई जा सके। फरवरी 2023 तक एसओपी को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

7.2.2 निरीक्षण का संचालन

निरीक्षण में विभिन्न कमियाँ इस प्रकार थीं:

(i) निरीक्षण रजिस्टर का खराब रखरखाव

विभाग द्वारा निरीक्षण रजिस्टरों को मौलिक तरीके से बनाए रखा गया था, जिसमें केवल तारीख, लाइसेंसधारी का नाम और क्या कोई उल्लंघन पाया गया था या नहीं का उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण रजिस्टरों का रख-रखाव इएससीआईएमएस के प्रवर्तन मॉडयूल में नहीं किया गया था। प्रवर्तन मॉड्यूल उल्लंघन के प्रकार, लगाए गए जुर्माने आदि पर अतिरिक्त डेटा फ़ील्ड प्रदान करता है जिसके अद्यतनीकरण से मामलों की निगरानी के लिए बेहतर तस्वीर उपलब्ध होती। यह निरीक्षण रिकॉर्ड की प्रमाणिकता को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।

(ii) स्टॉक से संबंधित पहलुओं पर रिपोर्टिंग में असंगति

निरीक्षण के दौरान रिपोर्ट किए गए निष्कर्षों में उन क्षेत्रों का उल्लेख होना चाहिए जिनकी जांच की गई थी, और उस पर आश्वासन प्रदान किया जाना चाहिए। कई मामलों में स्टॉक निरीक्षण रिपोर्ट में विसंगतियों की सूचना नहीं दी गई। यह स्पष्ट नहीं है कि स्टॉक की जांच की गई थी, और निरीक्षण के दौरान आश्वासन मिला था।

एचसीआर के कुल 28 मामलों में से सात में स्टॉक मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। कुछ मामलों में निरीक्षण रिपोर्ट में एक विशिष्ट टिप्पणी की गई है- "कोई एनडीपीएल नहीं मिला"। निरीक्षण रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से स्टॉक की मात्रा बताई जानी चाहिए जिसे यादृच्छिक रूप से जांचा गया था और स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहिए कि जांच किए गए स्टॉक के भीतर एनडीपीएल पाया गया या नहीं। बारकोड स्थिति रिपोर्ट के साथ इस तरह के आश्वासन के आधार का उल्लेख, अर्थात् इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नमूनाकरण प्रक्रिया रिपोर्ट में किया जाना चाहिए, इन 28 मामलों के विवरण **अनुलग्नक X** में दिए गए हैं।

सरकार ने अपने जवाब में यह कहते हुए अभ्युक्ति का खंडन किया कि यदि स्टॉक से संबंधित पहलुओं पर कोई टिप्पणी नहीं है तो स्टॉक की जांच की गई है और ठीक पाया गया है। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि जो नया एसओपी तैयार किया जा रहा है, उससे इस मुद्दे का समाधान होने की संभावना है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि स्टॉक पर आश्वासन की कल्पना नहीं की जा सकती है, बल्कि किए गए निरीक्षण से तार्किक रूप से निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, जो निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के तरीके में संभव नहीं था।

(iii) ख़राब साक्ष्य संग्रह

यह देखा गया कि निरीक्षण के दौरान, निष्कर्ष को सिद्ध करने और न्यायिक/ अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया के लिए सक्षम साक्ष्यों को बनाए रखने पर पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। उचित साक्ष्य के अभाव में, मामलों की तार्किक निष्कर्ष तक जांच भी नहीं की गई।

अमान्य/नकली/कोई बारकोड नहीं/अन्य दुकान बोतल/एक्सपायर्ड स्टॉक/एमएसआर गैप (स्टॉक की बिक्री पहले से ही बेची गई के रूप में चिह्नित) पाया गया लेकिन अंततः आरोपों को संदेह से परे स्थापित नहीं किया जा सका और अधिकांश मामलों में कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की जा सकी। निरीक्षण दल के निष्कर्ष की उचित जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। स्टॉक भिन्नता वाले मामलों में, बारकोड की सटीक स्थिति की पुष्टि करने के लिए निर्णायक साक्ष्य (समय-मुद्रांकित डेटा, परमिट की मैपिंग और पाए गए स्टॉक के रूप में) ईएससीआईएमएस से लिया जाना चाहिए था।

स्टॉक विसंगतियों और अपर्याप्त साक्ष्य संग्रहण से संबंधित आपत्तियों का सार इस प्रकार है:

बोतलों का अधूरा विवरण पहले से ही बेचा हुआ दिखाया गया है (एमएसआर गैप के रूप में घोषित) लेकिन निरीक्षण के दौरान फिर से दुकानों पर पाए गये - यदि ऐसे स्टॉक जिसे ईएससीआईएमएस में एमएसआर गैप के रूप में घोषित किया गया है, निरीक्षण के दौरान संबंधित बारकोड में पाया जाता है, तो डुप्लिकेट/नकली बारकोड की संभावना को स्थापित/विस्थापित करने के लिए बारकोड/टीपी/आईपी आदि के समय-मुद्रांकित डेटा के माध्यम से बारीकी से जांच की जानी चाहिए। सात खुदरा लाइसेंसधारियों से संबंधित 10 निरीक्षण के दौरान कुल 8,119 संदिग्ध बोतलें पाई गईं, जिनमें से 1,632 बोतलों को पहले ही बेचा हुआ दिखाया गया था और "एमएसआर गैप" के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए तीन निरीक्षणों में से, जिनमें खुदरा विक्रेता में संदिग्ध बोतलें पाई गई, केवल एक मामले में ऐसे एमएसआर गैप चिह्नित स्टॉक का पूरा विवरण प्रदान किया गया था। अन्य सभी मामलों में, निरीक्षण रिपोर्ट, एससीएन या सुनवाई के दौरान प्राप्त ईएससीआईएमएस रिपोर्ट से विवरण गायब थे। आबकारी विभाग द्वारा मामले की कार्यवाही से इन महत्वपूर्ण विवरणों की चूक अनिवार्य रूप से डिफॉल्टर के खिलाफ मामले को कमजोर करता है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ऐसे एमएसआर गैप चिह्नित वाले स्टॉक नियमित पाए जाते हैं क्योंकि उन्हें पिछली समाधान प्रक्रिया के दौरान स्कैन किए बिना छोड़ दिया गया था और इसलिए माना जाता है कि यह एनडीपीएल नहीं हैं।

उत्तर लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है क्योंकि सबसे पहले एमएसआर गैप प्रणाली में एक महत्वपूर्ण खामी पेश करता है, जिसका उपयोग एमएसआर गैप के रूप में चिह्नित स्टॉक के डुप्लिकेट बारकोड के उपयोग के माध्यम से गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब बेचने के लिए आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसे कभी भी निर्णायक रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है कि स्टॉक वास्तव में बेचा गया था या नहीं, और दूसरी बात यह कि इस तरह के गलत एमएसआर से ईएससीआईएमएस और बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से शराब की बोतलों को ट्रैक करने का उद्देश्य विफल हो जाता है।

जब्त नहीं की गई संदिग्ध बोतलें - संदिग्ध बोतलें लाइसेंसधारी परिसर में पाए जाने वाले किसी भी अनियमित स्टॉक को संदर्भित करती हैं, जिसमें गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब, "एमएसआर-गैप के रूप में बेची गई", समाप्त हो चुका स्टॉक नष्ट नहीं हुआ, "अन्य विक्रेताओं का स्टॉक", "ट्रांजिट में स्टॉक", "अतिरिक्त स्टॉक" आदि। विभाग ने सबूत के तौर पर इन संदिग्ध बोतलों को जब्त नहीं किया, जिन्हें अगर लाइसेंसधारी

के परिसर में (सील करने के बाद) छोड़ दिया जाता है, तो लाइसेंसधारी द्वारा छेड़छाड़ की जा सकती है। विभाग ने नकली शराब की संभावना को खारिज करने के लिए इन संदिग्ध बोतलों का परीक्षण भी नहीं किया।

होटल/रेस्तरां को उनके द्वारा ग्राहकों को परोसी जाने वाली शराब पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क का भुगतान करना होगा। इसलिए, होटल और रेस्तरां केवल एल1 लाइसेंसधारियों से शराब खरीदने के लिए अधिकृत हैं। एचसीआर में 11 निरीक्षणों के दौरान वेंड्स की 298 बोतलें और एल1 लाइसेंसधारी की 12 बोतलें पाई गईं। हालांकि, इन होटलों/रेस्तरां पर न तो अतिरिक्त आबकारी शुल्क की चोरी का कोई विशेष आरोप लगाया गया था और न ही खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

बियर की समयावधि समाप्त बोतलें स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। यदि ये बोतलें होटल/रेस्तरां में ग्राहकों को परोसी जाती है, तो इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। खुदरा लाइसेंसधारियों के दो निरीक्षणों के दौरान, 195 समयावधि समाप्त बोतलें पाई गई और एचसीआर लाइसेंसधारियों के दो निरीक्षणों के दौरान, 143 समयावधि समाप्त बोतलें पाई गई। हालांकि, निरीक्षण दल द्वारा इन्हें जब्त नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए 10 निरीक्षणों के दौरान जब्त की गई/जब्त नहीं की गई बोतलों का विवरण **तालिका 7.2** में दिया गया है।

तालिका 7.2: निरीक्षण के दौरान जब्त की गई बोतलों का विवरण

क्र.सं.	लाइसेंस के प्रकार	लाइसेंसधारी की संख्या	निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण के दौरान मिली संदिग्ध बोतलों की संख्या	जब्त की गई बोतलों की संख्या
1	खुदरा लाइसेंस (एल7, एल10 और एल6)	7	10	8119	53
2	एचसीआर	10	12	3592	52
3	एल1	1	1	19428	0

सरकार ने जवाब दिया कि वह केवल छोटे अपराध की श्रेणी में आने वाली एनडीपीएल बोतलें और अन्य संदिग्ध बोतलें जब्त करती है, जिन्हें दुकान परिसर में सील कर दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर आगे की जांच के दौरान इस्तेमाल किया जाता है।

उत्तर असंतोषजनक है क्योंकि निरीक्षण दल, आगे की जांच के बिना, यह तय नहीं कर सकता कि जब्त बोतलें एनडीपीएल है या नहीं।

एचसीआर लाइसेंसधारी के संबंध में, सरकार ने जवाब दिया कि समाप्त स्टॉक कोविड लॉकडाउन के दौरान सफदरजंग क्लब से संबंधित है। इसे सील कर दिया गया और कार्यवाही के समापन के बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा।

एचसीआर से संबंधित संदिग्ध बोतलों का विवरण **अनुलग्नक XI** में दिया गया है।

7.2.3 निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) में विसंगतियाँ

लेखापरीक्षा ने निरीक्षण के दस्तावेज़ीकरण में निम्नलिखित कमियां देखीं:

- एक एल-1 लाइसेंसधारी (अप्रैल 2019 के निरीक्षण) के मामले में, आईआर में "केस बारकोड" के बजाय बैच नंबर की सूचना दी गई थी।

  सरकार ने अपने जवाब में कहा कि लाइसेंसधारियों के लिए बैच नंबर के बजाय बारकोड का उल्लेख किया जाना चाहिए था और एसओपी तैयार की जा रही थी। टीसीएस (ईएससीआईएमएस सर्विस प्रोवाइडर) ने इस संबंध में आबकारी विभाग को रिपोर्ट दी है। हालांकि, इसे लेखापरीक्षा के साथ साझा नहीं किया गया।

- एक एल-7 लाइसेंसधारी के मामले में, निरीक्षण के दौरान (26 नवंबर 2020), दुकान पर पाई गई शराब की 20 पेटियां और 696 बोतलें स्कैनिंग के माध्यम से ग्राहकों को पहले ही बेची हुई दर्शाई गई थीं। हालाकि, इस महत्वपूर्ण पहलू को आईआर में अन्य स्टॉक विसंगतियों के साथ जोड़ दिया गया था।

- अन्य एल-10 लाइसेंसधारी के मामले में, दो निरीक्षण रिपोर्टें थीं, एक दुकान मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित और दूसरी अहस्ताक्षरित। यदि निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसी अस्पष्टता मौजूद है, तो यह मामले को कमजोर कर देती है।

  निरीक्षण रिपोर्ट के दो संस्करणों की उपस्थिति के संबंध में, यह उत्तर दिया गया कि विजिट रिपोर्ट की हस्ताक्षरित प्रति (दुकान मैनेजर द्वारा) दुकान पर रखे गए निरीक्षण रजिस्टर में लिखी जाती है और विभाग को वापस भेजी गई विस्तृत विजिट रिपोर्ट को दुकान मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता नहीं है।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दोनों निरीक्षण रिपोर्टें निरीक्षण के अलग-अलग संस्करण देती है। एक रिपोर्ट "निरीक्षण के दौरान कोई गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब नहीं मिली" का प्रमाण पत्र देती है और दूसरी रिपोर्ट बिना स्कैन की गई शराब की बोतलों के बारे में बात करती है। यह भी देखा गया कि पहली रिपोर्ट का अभियोजन प्रक्रिया में आगे उपयोग किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के अलग-अलग संस्करणों का विद्यमान होना एक गंभीर मुद्दा है जिसकी जांच की जानी चाहिए।

7.2.4 निरीक्षण रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई

निरीक्षण को कदाचार निवारक बनाने के निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों की आगे जांच की जानी चाहिए और चूककर्ताओं को दंडित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कई उल्लंघनों की पूरी तरह से जांच नहीं की गई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) अनियमित स्टॉक (ईएससीआईएमएस और भौतिक सूची) की जांच नहीं की गई

10 निरीक्षणों में, सात खुदरा लाइसेंसधारियों के परिसर में 1077 संदिग्ध बोतलें पाई गईं। ईएससीआईएमएस तार्किक सूची के अनुसार, इन 1077 बोतलों में से 330 बोतलें एल1 लाइसेंसधारियों से संबंधित और 15 बोतलें अन्य दुकानों से संबंधित थीं। हालांकि, अन्य लाइसेंसधारियों (थोक और खुदरा विक्रेताओं) को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

ईएससीआईएमएस स्थिति "समान बारकोड" वाली 55 बोतलें और "अमान्य / ईएससीआईएमएस का हिस्सा नहीं" स्थिति वाली बोतलें एनडीपीएल/अवैध शराब को छिपाने के लिए डुप्लिकेट बारकोड का उपयोग किए जाने के जोखिम को दर्शाती है, जिससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए था। हालांकि, निरीक्षण दल ने अपने मामले को मजबूत करने के लिए सबूत के तौर पर ऐसी बोतलें जब्त नहीं की। इसके अलावा, कारण बताओ नोटिस केवल जब्त की गई बोतलों को स्टॉक भिन्नता के रूप में संयुक्त रूप से प्रस्तुत करता है क्योंकि इस मुद्दे की आगे जांच नहीं की गई।

समय सीमा समाप्त परिवहन परमिट (टीपी) से संबंधित बोतलें (ऐसे समय सीमा समाप्त टीपी से संबंधित स्टॉक संबंधित गोदाम में वापस लौटाए जाने योग्य हैं) प्राप्त की गई और बिना स्कैनिंग के दुकानों पर बेची गई। यह स्पष्ट नहीं है कि इन बोतलों को थोक विक्रेता (एल1) को वापस न करने के बावजूद, बॉन्ड निरीक्षकों ने बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टॉक का मिलान कैसे किया। समय सीमा समाप्त हो चुके टीपी को ट्रैक करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टॉक को आसानी से होटल और रेस्तरां में ले जाया जा सकता है जिससे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (डब्ल्यूएसपी का 20 *प्रतिशत* / 30 *प्रतिशत)* का नुकसान हो सकता है। प्रवर्तन शाखा द्वारा इस पहलू की जांच नहीं की गई।

खुदरा विक्रेताओं से संबंधित उपर्युक्त अनियमित स्टॉक का विवरण **अनुलग्नक XII** में दिया गया है।

सरकार ने अपने जवाब में लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये मामलों का समाधान किए बिना नकली बारकोड और एनडीपीएल की संभावना से इनकार किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जाता है और आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में अधिक ध्यान रखा जाएगा।

(ii) त्रुटिपूर्ण कारण बताओ नोटिस (एससीएन)

एससीएन से महत्वपूर्ण विवरण छूट जाने से डिफॉल्टर को पहले राहत मिलती है क्योंकि उसे स्पष्टीकरण के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। लेखापरीक्षा में विचार किए गए कुछ निरीक्षणों का विवरण इस प्रकार है:

- एक एल-10 लाइसेंसधारी के मामले में, 11 जनवरी 2021 के निरीक्षण में, दुकान पर "एमएसआर गैप" चिह्नित स्टॉक पाया गया था, लेकिन जिस अवधि के दौरान बोतल पर एमएसआर चिह्नित किया गया (1.5 वर्ष पूर्व) एससीएन में छोड़ दिया गया था। यह अवधि नकली/डुप्लिकेट बारकोड का मजबूत संकेत देती है, लेकिन लाइसेंसधारी ने "स्टॉक भिन्नता" का अनुरोध किया, बिना यह उल्लेख किए कि बेचा गया इतना पुराना स्टॉक उसकी दुकान पर कैसे पाया जा सकता है।
- एल-7 लाइसेंसधारी के एक मामले में, कुछ बोतलों की निरीक्षण स्थिति "बॉन्डेड वेयरहाउस में प्राप्त" और "बॉन्डेड वेयरहाउस में क्षतिग्रस्त" के रूप में दिखाई गई थी, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि ये बोतलें डिस्टिलरी/वेयरहाउस की थीं। लेकिन स्टॉक विवरण जैसे ब्रांड नाम और इससे संबंधित डिस्टिलरीज का निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया था और इसमें शामिल डिस्टिलरी/गोदामों को कोई एससीएन जारी नहीं किया गया था।

  सरकार ने जवाब दिया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को गंभीरता से स्वीकार किया गया है और आश्वासन दिया कि आईएमएफएल शाखा द्वारा टिप्पणियों का पालन किया जाएगा। हालांकि, वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति के कार्यान्वयन के कारण 30 सितंबर 2021 से एल-7 लाइसेंस निरर्थक हो गए हैं, इसलिए मामले पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

  उत्तर असंतोषजनक है क्योंकि अपराध पहले ही आबकारी अधिनियम के तहत किया जा चुका था जब पार्टी मौजूदा आबकारी व्यवस्था की लाइसेंसधारी थी। इसके अलावा, सरकार 1 सितंबर 2022 से पुरानी नीति पर वापस लौट आई है।

- खुदरा विक्रेताओं के 10 मामलों में स्कैनिंग के माध्यम से पहले बेची गई 72 बोतलें, निरीक्षण के समय खुदरा विक्रेताओं के पास फिर से पाई गई जो नकली/डुप्लीकेट बारकोड के उपयोग के जोखिम को उजागर करती है। हालांकि, कारण बताओ नोटिस में आरोपों के विशिष्ट विवरण का उल्लेख नहीं किया गया था।
- एल7 लाइसेंसधारियों के दो मामलों में, ईएससीआईएमएस डेटा की तुलना में 632 अतिरिक्त बोतलें पाई गईं और 4,784 बोतलें गायब थीं। मामले को केवल स्टॉक भिन्नता के रूप में एससीएन में प्रस्तुत किया गया था। 632 अतिरिक्त बोतलों की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, क्या ये बिना बारकोड वाली एनडीपीएल/अवैध शराब/ट्रांजिट में स्टॉक/अन्य दुकानों से संबंधित स्टॉक आदि थे।
- एल-1 लाइसेंसधारी से संबंधित एक मामले में, 19428 बोतलें अधिक पाई गईं और 8808 बोतलें गायब थीं, लेकिन एससीएन में निरीक्षण के समय अतिरिक्त या कम पाए गए स्टॉक के बारे में विशिष्ट जानकारी दिए बिना इस मुद्दे को सिर्फ स्टॉक भिन्नता के रूप में दिखाया। एससीएन में लाइसेंसधारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में भी खास नहीं बताया। दिल्ली आबकारी अधिनियम/नियमों से संबंधित प्रासंगिक खंड, जिनका उल्लंघन कथित "स्टॉक भिन्नता" के कारण हुआ, का कारण बताओ नोटिस में उल्लेख नहीं किया गया।

एक अन्य मामले में उसी लाइसेंसधारी का, जहां निरीक्षण दल ने 1-डी बारकोड के बजाय 20 मामलों का बैच नबंर नोट किया था, टीसीएस द्वारा इन 20 मामलों के 1 डी बारकोड की स्थिति प्रस्तुत करने के बाद भी, इस मामले को कारण बताओ नोटिस में नहीं उठाया गया, जिससे एल1 लाइसेंसधारी को लाभ हुआ।

सरकार ने उत्तर दिया कि निरीक्षण रिपोर्ट तार्किक सूची का विवरण देती है जबकि भौतिक सूची शून्य है। बिक्री के समय स्कैन न होने के कारण बोतलें गायब है। अतिरिक्त बोतल इसलिए है क्योंकि एक कर्मचारी ने बाहर से खरीदकर टूटी हुई बोतल को बदल दिया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह, स्पष्ट करने में विफल है कि गायब स्टॉक के लिए एमएसआर गैप मार्किंग क्यों नहीं की गई थी।

सरकार ने अपने उत्तर में आगे कहा कि निरीक्षण करने वाली टीम इस भिन्नता को निम्नानुसार इंगित करती है:

1. दुकान पर बेचा गया- स्टॉक को सील कर दिया गया है और उक्त स्टॉक को न बेचने के निर्देश के साथ अलग रखा गया है। इसे स्टॉक भिन्नता माना जाता है
2. दुकान पर- यदि बार काउंटर पर पाया जाता है तो उसे न बेचने के निर्देश के साथ सील कर दिया जाएगा और अलग रखा जाएगा। इसे स्टॉक भिन्नता माना जाता है
3. एक्सपायर हो चुकी बियर - सील करके अलग रखा गया और न बेचने के निर्देश दिया गया तथा लाइसेंसधारी को एससीएन जारी किया गया।

   उपरोक्त मामलों को स्वतः ही लघु अपराध माना जाता है तथा स्टॉक को विभागीय कार्यवाही के दौरान साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है।
4. एनडीपीएल- बोतलों को सील किया गया, जब्त किया गया और औपचारिक शिकायत और एफआईआर के साथ स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।

उत्तर असंतोषजनक है क्योंकि इसमें अतिरिक्त स्टॉक के कारणों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। इसके अलावा, पहले तीन मामलों में इसे स्वचालित रूप से एक मामूली अपराध माना जाता है, जबकि, जब तक बाद की जांच से इनकार नहीं किया जाता है, तब तक संभावना है कि पाए गए बारकोड डुप्लिकेट हैं और मूल स्टॉक पहले ही बेचा जा चुका है या एमएसआर के रूप में चिह्नित किया गया है।

(iii) सम्मिलित अन्य लाइसेंसधारियों/विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया सात मामलों में, विदेशी विक्रेता बोतल या बोतल उद्भव के कारण अन्य लाइसेंसधारी शामिल थे, लेकिन इन पार्टियों को कोई एससीएन जारी नहीं किया गया था। ऐसे मामलों में, आबकारी विभाग मुद्दे की ठीक से जांच न करके और सभी पक्षों को जवाबदेह न ठहराकर अपना नियामक कार्य करने में विफल रहा। विवरण **अनुलग्नक XIII** में हैं।

सरकार ने अपने जवाब में एससीएन जारी न होने की बात स्वीकार की और कहा कि भविष्य में सभी जुड़े लाइसेंसधारियों को एससीएन जारी किया जाएगा।

7.2.5 बार-बार उल्लंघन करने पर सजा नहीं बढ़ाई गई

आबकारी अधिनियम की धारा 53 में "पिछली सजा के बाद सजा में वृद्धि" के प्रावधान का उल्लेख है। 11 मामले ऐसे पाए गए जहां पिछले निरीक्षण में देखे गए उल्लंघन

बाद में दोहराए गए। निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार बार-बार उल्लंघन के बावजूद धारा 53 लागू नहीं की गई। विवरण **अनुलग्नक XIV** में दिया गया है।

सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि उपरोक्त मामलों में धारा 53 लागू नहीं की गई थी और इसके लिए खेद है।

7.3 निष्कर्ष और अनुशंसाएं

आबकारी विभाग को अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिनका कुशल प्रयोग प्रवर्तन कार्य की पारदर्शिता, प्रमाणिकता और निष्पक्षता पर निर्भर है। आबकारी विभाग की प्रवर्तन शाखा जिसे लाइसेंस प्राप्त परिसरों में निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया है, योजना की कमी, मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अभाव और कमजोर साक्ष्य संग्रह के कारण महत्वपूर्ण कमियों से ग्रस्त है। प्रवर्तन कार्य की प्रभावशीलता राजस्व रिसाव को रोकने, आबकारी उल्लंघनों के लिए प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करने और एक प्रभावी नियामक व्यवस्था बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है। असंगत और अपर्याप्त रिपोर्टिंग के साथ-साथ जोखिम मूल्यांकन पर आधारित अच्छी तरह से समन्वित निरीक्षणों की अनुपस्थिति, प्रवर्तन गतिविधियों की प्रभावशीलता को कमजोर करती है जिससे गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री के जोखिम बढ़ जाते हैं। प्रवर्तन कार्य को प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए ऊपर उल्लिखित कमजोरियों और निरीक्षण को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उनका समाधान किया जाना चाहिए। ऊपर चर्चा किए गए सभी मामले विस्तृत परीक्षण और अन्वेषण के योग्य हैं।

अनुशंसा 7.1: मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण, सावधानीपूर्वक साक्ष्य संग्रहण और अन्वेषण तथा मामले के शीघ्र निपटान से प्रवर्तन कार्यों को मजबूत किया जाना चाहिए।

अनुशंसा 7.2: मामले के विवरण के संबंध में विस्तृत डेटा वाले प्रवर्तन पंजिका को ईएससीआईएमएस में रखा जाना चाहिए, जो कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी उत्पन्न करने के लिए डेटा के विश्लेषण में मदद कर सकता है।

अनुशंसा 7.3: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण रिपोर्टों और उसके बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण किया जाना चाहिए।

अध्याय VIII

आबकारी नीति 2021-22

अध्याय VIII: आबकारी नीति 2021-22

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 शराब व्यापार को सरल बनाने पारदर्शिता लाने, एकाधिकार की रोकथाम करने, इष्टम राजस्व उत्पन्न करने के साथ-साथ बेहतर उपभोक्ता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। हालांकि, नीति को लागू करने के लिए किए गए परिवर्तन त्रुटिपूर्ण थे और वास्तविक कार्यान्वयन इष्टतम से कम था। नीति में बदलाव हेतु बताए गए लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। लाइसेंस शुल्क जमा करने के लिए अथवा दोषियों के विरूद्ध सुधारात्मक कार्रवाई नहीं करने अथवा मूल्य निर्धारित करने के लिए दी गई छूट/रियायत देते समय मंत्रिमंडल से आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की गई थीं। नई नीति में निर्माताओं और थोक विक्रेताओं के बीच थोपी गई विशिष्टता व्यवस्था और प्रत्येक क्षेत्र में न्यूनतम 27 वार्डों के साथ खुदरा क्षेत्र के गठन से कुल लाइसेंसधारियों की संख्या को सीमित करने और एकाधिकार और उत्पादक संघ के जोखिम को बढ़ाने सहित डिजाइन संबंधी अंतर्निहित मुद्दे थे।

आबकारी नीति 2021-22 में आबकारी शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण, शराब आपूर्ति श्रृंखला का प्रशासन और खुदरा संचालन के कवरेज के सम्बन्ध में कई मूलभूत परिवर्तन किये गये। नई आबकारी नीति 2021-22 में बोतलों की प्रति यूनिट की बिक्री पर आबकारी शुल्क वसूलने के बजाय 2019-20 के बिक्री आंकड़े पर आधारित प्रकल्पित आबकारी शुल्क और 10 प्रतिशत ग्रोथ फैक्टर को जोनल लाइसेंस फीस में शामिल कर लिया गया। एक बार जोनल लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर दिया गया तो सरकार को आनुपातिक राजस्व के बिना बिक्री की मात्रा (पैमाने की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ गहरी छूट के माध्यम से) बढ़ाने के लिए खुदरा विक्रेताओं को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद कार्यान्वयन मुद्दों के कारण लगभग ₹ 2,002.68 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

जोनल लाइसेंसधारियों के पास के वित्तीय क्षमता, प्रबंधन विशेषज्ञता और एक चालु संस्था के रूप में जीवित रहने की क्षमता के संबंध में विभाग द्वारा जांच की कमी थी। निविदा मूल्यांकन चरण में पहले की शिकायतों के बावजूद शराब आपूर्ति श्रृंखला में व्यावसायिक निकायों के बीच संबंध के उदाहरण भी देखे गए थे, जिनकी उचित जांच नहीं की गई थी। आपूर्ति श्रृंखला के आंकड़ों से पता चलता है कि विषम आपूर्ति प्रणाली ने लाइसेंसधारियों और ब्रांड पुशिंग के बीच विशिष्टता व्यवस्था का जोखिम दिखाया। अन्य महत्वपूर्ण उपाय जो नीति में योजनाबद्ध थे जैसे शराब परीक्षण प्रयोगशालाओं की

स्थापना, कठोर गुणवत्ता आश्वासन के लिए बैच परीक्षण और एक समर्पित पद के सृजन के माध्यम से निगरानी और विनियमन को लागू नहीं किया गया।

8.1 परिचय

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में एक संशोधित आबकारी नीति की आवश्यकता का उल्लेख किया गया था, जिसमें कहा गया है कि "दिल्ली में आबकारी व्यवस्था की वर्तमान प्रणाली अत्यधिक बोझिल है और शराब का व्यापार पुरातन तरीके से किया जाता है। वर्तमान में दिल्ली में उत्पन्न आबकारी राजस्व उप-इष्टतम स्तर पर है और राजस्व वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण क्षमता है तथा ग्राहक के अनुभव को एक अच्छा मानक भी प्रदान करता है"।

विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों के लिए विस्तृत नियम एवं शर्तों के साथ आबकारी नीति 2021-22, 17 नवंबर 2021 से लागू की गई थी और इसे 31 अगस्त 2022 तक बढ़ाया[40] गया था।

सरकार द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया।

8.1.1 आबकारी नीति 2021-22 के उद्देश्य

आबकारी नीति निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार की गई थी:

(i) सरकार के लिए अधिकतम राजस्व सृजन सुनिश्चित करने, दिल्ली में नकली शराब/गैर शुल्क शराब की बिक्री को समाप्त करने तथा उपभोक्ता अनुभव को बदलने के लिए।

(ii) समग्र व्यापार में व्यवसाय करने में आसानी को सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक जटिल, अत्यधिक विनियमित आबकारी व्यवस्था को सरल बनाना।

(iii) किसी भी एकाधिकार अथवा उत्पादक संघ का गठन न होने देना।

(iv) उद्योग में जिम्मेदार व्यक्तियों को किसी भी प्रॉक्सी मॉडल का सहारा लिए बिना पारदर्शी रूप से व्यापार करने की अनुमति देना।

---

[40] आबकारी विभाग, जीएनसीटीडी के परिपत्र दिनांक 03.03.2022 के माध्यम से 30.05.2022 तक दो महीने के लिए पहला विस्तार किया गया।
आबकारी विभाग, जीएनसीटीडी के परिपत्र दिनांक 24.05.2022 के माध्यम से 30.07.2022 तक दो महीने के लिए दूसरा विस्तार प्रदान किया गया
आबकारी विभाग, जीएनसीटीडी के परिपत्र दिनांक 01.08.2022 के माध्यम से 31.08.2022 तक एक महीने के लिए तीसरा विस्तार प्रदान किया गया।

(v) दिल्ली के सभी वार्डों/क्षेत्रों में शराब की आपूर्ति की समान पहुंच सुनिश्चित करना ताकि नकली/गैर शुल्क प्रदत्त शराब की समस्या को समाप्त करने के लिए कोई भी गैर-सेवित तथा कम-सेवित इलाके न हों।

(vi) एक सरलीकृत शुल्क तथा मूल्य निर्धारण तंत्र स्थापित करना जिसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

(vii) एकाधिकार तथा उत्पादक संघ के उद्‍गम में की रोकथाम के अलावा राजस्व वृद्धि के संदर्भ में लाइसेंसधारी की ओर से जवाबदेही सुनिश्चित करना

(viii) लोकप्रिय तथा विशिष्ट ब्रांडों की उपलब्धता सुनिश्चित कर उपभोक्ता की पसंद को बढ़ावा देना ताकि ग्राहक के पास व्यापक विकल्प हों।

(ix) तस्करी तथा अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए प्रणालीगत उपाय जैसे खुदरा दुकानों का पर्याप्त प्रसार तथा पड़ोसी राज्यों के साथ मूल्य में नाममात्र अथवा कोई अंतर नहीं होना, जिससे तस्करी के लिए मध्यस्थता समाप्त हो जाए।

8.1.2 आबकारी नीति 2021-22 की विशेषताएं

i) शराब के खुदरा कारोबार से दिल्ली सरकार के निगमों की भूमिका पूरी तरह से हटा दी गई।

ii) बेची गई मात्रा के आधार पर आबकारी शुल्क एकत्र करने के स्थान पर जोनल लाइसेंस आवेदकों द्‍वारा बोली लगाने के लिए आरक्षित मूल्य के तहत आबकारी शुल्क को सम्मिलित किया गया था। 2019-20 की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर प्रकल्पित आबकारी शुल्क और 10 *प्रतिशत* वृद्धि कारक को जोनल लाइसेंस शुल्क में शामिल किया गया था।

iii) शराब की खुदरा बिक्री के लिए दिल्ली को 32 जोन (समान संख्या में ठेके के साथ) में विभाजित किया गया था और प्रत्येक जोन को निविदा के आधार पर एक अलग निकाय को आवंटित किया गया था। एक निकाय को अधिकतम दो क्षेत्र प्रदान किये जा सकते थे।

iv) शराब की थोक आपूर्ति सीमित संख्या में निजी शराब वितरकों (निर्माताओं के अलावा अन्य) के लिए विशेष रूप से आरक्षित थीं।

v) कोई भी निर्माता जो अपने उत्पाद को दिल्ली में बेचना चाहता है, उसे अपने सभी ब्रांडों के लिए एक विशेष वितरक के रूप में भारतीय और विदेशी शराब की आपूर्ति के लिए थोक लाइसेंस रखने वाले और एल31 के लिए बंधुआ गोदाम का लाइसेंस रखने वाले लाइसेंस प्राप्त एल1 वितरक में से एक को चुनना होगा।

vi) प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो खुदरा दुकानों सहित समान रूप से वितरित की जाने वाली शराब की दुकानें खोलना सुनिश्चित किया जाना था।

चार्ट 8.1: शराब वितरण के लिए लाइसेंस के प्रकार

विवरण	लाइसेंस का नाम	चयन का तरीका
आईएमएफएल और एफएल की बिक्री के लिए निर्माता के विशेष एजेंट के रूप में थोक वितरक।	एल-1	आवेदन का आधार
संबंधित बॉन्डेड वेयरहाउस खोलने के लिए उसी इकाई को वेयरहाउस लाइसेंस प्रदान किया जाता है	एल-31	
निजी खुदरा दुकानों का संचालन करने वाले क्षेत्रीय लाइसेंसधारी	एल-7 जेड	बिडिंग
खुदरा विक्रेता (संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसधारी द्वारा खोले गए निजी खुदरा विक्रेता)	एल-7 वी	
परिसर में उपभोग के लिए शराब की खुदरा बिक्री	एल15 (होटल), एल28 (क्लब), एल16, एल 17 (रेस्टोरेंट)	आवेदन का आधार

vii) शराब की वास्तविक आपूर्ति के समय नाममात्र आबकारी शुल्क और मूल्य वर्धित कर वैट 1% प्रत्येक, एकत्र किया गया था।

viii) अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी के निर्धारण के बाद शराब पर छूट के लिए पर्याप्त गुंजाइश के साथ आबकारी शुल्क संग्रह के तौर-तरीकों में बदलाव के आलोक में मूल्य निर्धारण तंत्र को संशोधित किया गया था।

8.2 आबकारी नीति 2021-22 में घटनाओं का कालक्रम

नीचे दिया गया **चार्ट 8.2** नीति निर्माण के लिए घटनाओं के कालक्रम का निरूपक है।

चार्ट 8.2: घटनाओं के कालक्रम

04.09.2020	13.10.2020	31.12.2020	05.02.2021	05.02.2021
विशेषज्ञ समिति का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से किया गया था।	विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।	रिपोर्ट को जनता और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है।	रिपोर्ट और जनता तथा हितधारकों की टिप्पणियों को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा गया	मंत्रिपरिषद ने मंत्रिमंडल के निर्णय संख्या 2942 के तहत राज्य आबकारी सुधारों के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया

22.03.2021	22.03.2021	05.04.2021	15.04.2021	21.05.2021*
मंत्रिपरिषद ने मंत्री समूह द्वारा तैयार दिल्ली आबकारी सुधार पर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।	आबकारी विभाग को जीओएम की रिपोर्ट को लागू करने और आबकारी नीति 2021-22 तैयार करने का निर्देश दिया गया था।	मंत्री समूह ने मंत्री समूह की रिपोर्ट में अतिरिक्त स्पष्टीकरणों/संशोधनों की सिफारिश जो मंत्रिमंडल द्वारा 15/4/2021 को अनुमोदित किया गया था।	मंत्रीपरिषद ने वित्त मंत्री/उप मुख्यमंत्री को नई आबकारी नीति पर मंत्री समूह की रिपोर्ट के समग्र ढ़ांचे के भीतर लघु बदलाव करने हेतु प्रधिकृत किया था जो मंत्रीपरिष्द द्वारा पहले ही अनुमोदित थी।	रा.रा.क्षे.दि.स. के उप-राज्यपाल के परामर्श पर मंत्रीपरिषद निर्णय सं. 3003 के संदर्भ में मंत्रीपरिषद ने उप मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री को दी गई शक्ति वापिस ले ली थी तथा मंत्रीपरिषद द्वारा दिए गए अनुमोदनों में संशोधन की आवश्यकता होने पर मंत्रीपरिषद की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया

आबकारी नीति की तैयारी में देखे गए मुद्दों पर नीचे प्रकाश डाला गया है:

8.2.1 सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना लिए गए निर्णय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मंत्रीपरिषद निर्णय सं. 3003 के उल्लंघन में, नीचे उल्लिखित कुछ निर्णयों जिसका राजस्व पर प्रभाव था मंत्रीपरिषद से अनुमति लिए बिना अथवा उपराज्यपाल की राय प्राप्त किए बिना लिए गए थे।

(i) निर्धारित समय में लाइसेंस शुल्क के भुगतान में चूक के किसी भी मामले में लाइसेंसधारी के प्रति दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में छूट।

(ii) लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी

(iii) गैर-अनुरूप वार्डों में खोली जाने वाली अनिवार्य शराब की दुकानों के बदले अनुरूप क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलना

(iv) आबकारी नीति 2021-22 का विस्तार

(v) हवाईअड्डा क्षेत्र के मामले में अग्रिम धनराशि जमा (ईएमडी) की वापसी

(vi) विदेशी शराब के मामले में एमआरपी की गणना हेतु सूत्रों में सुधार

विवरण **अनुलग्नक XV** में दिया गया है।

ब) इसके अलावा, आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए संशोधित आबकारी नियमों को दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 81(4) के अनुसार अनुमोदन के लिए विधानसभा के समक्ष रखा जाना था।

हालांकि, आबकारी विभाग से प्राप्त उत्तर के अनुसार संशोधित नियमों को अनुमोदन/सुधार के लिए विधानसभा के समक्ष नहीं रखा गया था।

8.2.2 विशेषज्ञ समिति और मंत्री समूह की सिफारिशों के रिपोर्ट की बीच अंतर

दिल्ली में शराब व्यापार में सुधार के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन आबकारी आयुक्त की अध्यक्षता में किया गया जिसमें उप-आयुक्त (आबकारी) तथा अतिरिक्त आयुक्त (व्यापार एवं कर) अन्य सदस्य थे। इस समिति का अधिदेश निम्नलिखित के उपाय सुझाना था।

(i) राज्य आबकारी शुल्क राजस्व में वृद्धि

(ii) शराब मूल्य निर्धारण तंत्र को सरल बनाना

(iii) शराब व्यापार में कदाचार तथा शुल्क की चोरी की रोकथाम करना

(iv) शराब आपूर्ति की साम्यिक पहुँच को सुनिश्चित करना

बाद में, विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट की प्रस्तुति के पश्चात् मंत्रिपरिषद ने उप मु.मं./मंत्री (वित्त) की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) के गठन का निर्णय लिया गया और अन्य सदस्य के रूप में मंत्री (शहरी विकास) तथा मंत्री (राजस्व/परिवहन) थे। जीओएम को वर्तमान प्रणाली के सभी पहलुओं, विशेषज्ञ समिति तथा शेयरधारी की टिप्पणियों इत्यादि की रिपोर्ट की जांच का आदेश था।

विशेषज्ञ समिति तथा जीओएम की सिफारिश के बीच पर्याप्त अंतर ने आबकारी नीति में बदलाव की आवश्यकता के आधार को ही बदल दिया। प्रमुख अंतर **तालिका 8.1** में दिए गए हैं तथा उनमें से कुछ पर तालिका के नीचे चर्चा की गई हैः

तालिका 8.1 विशेषज्ञ समिति तथा मंत्री समूह की सिफारिशों के बीच तुलना

क्र.सं.	विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट	मंत्री समूह की रिपोर्ट
1.	शराब के थोक परिचालनों के लिए सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली राज्य पेय निगम	थोक परिचालनों को शराब व्यापार में पूर्व वितरण अनुभव तथा ₹ 250 करोड़ की न्यूनतम बिक्री वाले निजी निकायों द्वारा संभाला जाएगा।
2.	शराब मूल्य निर्धारण तंत्र में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ शराब पर आबकारी शुल्क प्रति बोतल के आधार पर लगाया जाना था।	आबकारी विभाग द्वारा शराब की एमआरपी न्यूनतम ईडीपी के आधार पर तय की जानी थी परंतु आबकारी शुल्क तथा वैट को खुदरा जोन के लिए बोली लगाने के बाद लाइसेंस शुल्क के रूप में पाये गये अग्रिम रूप से लिया जाना था।
3.	खुदरा क्षेत्र में सरकार की उपस्थिति को कम किया जाएगा।	सभी खुदरा दुकानें केवल निजी खिलाड़ियों को आवंटित की जानी चाहिए।
4.	लाइसेंसधारियों की नियमित मंथन को सुनिश्चित करने के लिए हर दो वर्षों में खुदरा लाइसेंसों के आवंटन (आरक्षित शुल्क पर) के लिए लॉटरी प्रणाली।	खुदरा जोन को एक समय बोली (आरक्षित शुल्क से अधिक) के माध्यम से आवंटित करना तथा उसके पश्चात् वार्षिक रूप से नवीकृत करना।
5.	एक खुदरा दुकान लाइसेंस के लिए केवल एक व्यक्ति आवेदन कर सकेगा ताकि प्रॉक्सी स्वामित्व को कम से कम किया जा सके।	कोई भी निजी कानूनी निकाय अथवा व्यक्ति जिसके पास पिछले तीन निर्धारण वर्षों के आयकर रिटर्न भरने का प्रमाण है, खुदरा जोन के लिए बोली में भाग लेने का पात्र था।

क्र.सं.	विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट	मंत्री समूह की रिपोर्ट
6.	एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकाने आवंटित की जा सकती है।	एक आवेदक अधिकतम दो जोन ले सकता था जिसमें 54 खुदरा दुकानें शामिल हो सकती था।
7.	70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक में एक सरकारी निगम की दुकान और प्रत्येक वार्ड में तीन दुकान।	दिल्ली 32[41] जोनों में विभाजित थी जिसमें प्रत्येक जोन में नौ वार्ड थे तथा प्रत्येक वार्ड में तीन दुकानें होनी थी (कुल 849 दुकानें)।

लेखापरीक्षा को कोई फ़ाइल प्रदान नहीं की गई जिसमें मंत्री समूह रिपोर्ट तैयार करने का आधार बताया गया हो। इन अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा इस रिपोर्ट में किए गए परिवर्तनों के औचित्य के बारे में आश्वासन नहीं दे सका।

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से मंत्री समूह की रिपोर्ट में प्रमुख विचलनों पर प्रकाश डाला गया है।

8.2.2.1 केवल निजी खिलाड़ियों को थोक (एल-1) लाइसेंस जारी करना

विशेषज्ञ समिति ने संबंधित निजी संस्थानों के माध्यम से दोहरे स्वामित्व (थोक तथा खुदरा) के पिछले उदाहरणों और डुप्लीकेट बारकोड के माध्यम से अवैध शराब की आपूर्ति की सुविधा थोक विक्रेताओं की संभावित मिलीभगत के कारण अलग राज्य पेय/ थोक निगम के माध्यम से शराब के थोक व्यापार को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने की सिफारिश की। यहां तक कि जीओएम ने भी अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को स्वीकार किया कि कई थोक व्यापारी प्रॉक्सी स्वामित्व के माध्यम से खुदरा लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम थे और बिना शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री में शामिल होना संभव बनाते थे। फिर भी जीओएम ने केवल निजी खिलाड़ियों को एल-1 लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की। मंत्री समूह रिपोर्ट में ऐसे सरकारी स्वामित्व वाले थोक निगम के गठन नही होने का कारण यह था कि इसके गहन अध्ययन और कार्यान्वयन के लिए समय की आवश्यकता होगी और तब तक एल-1 निजी खिलाड़ियों को दिया जाना चाहिए था।

गौरतलब है कि सरकार के स्वामित्व वाले थोक निगम के गठन का विचार दिल्ली में नया नहीं था। कैबिनेट निर्णय संख्या 1622 (दिनांक 15 फरवरी 2010) में संकेत दिया गया था कि शराब के थोक व्यापार के अधिग्रहण पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

---

[41] 32 जोनों -

- 30 जोन - एमसीडी क्षेत्र में 272 वार्ड हैं, इनमें से 28 जोन में प्रत्येक में 9 वार्ड हैं तथा 2 जोन में प्रत्येक में 10 वार्ड हैं। हालांकि प्रत्येक जोन में 27 दुकानें हैं।
- एक जोन - में एनडीएमसी और छावनी क्षेत्र शामिल हैं जिसमें कुल 29 दुकानें हैं।
- एक जोन - में दिल्ली हवाई अड्डे पर 10 दुकानें हैं।

इसके अलावा वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित आबकारी नीति में यह देखा गया कि थोक संचालन को निजी खिलाड़ियों द्वारा प्रबंधित करने का प्रस्ताव दिया गया था, जो सरकार द्वारा किए गए दावों को झुठलाता है कि निजी थोक संचालन केवल एक अंतरिम उपाय था।

8.2.2.2 आबकारी शुल्क को शराब की वास्तविक बिक्री से अलग कर दिया जाना

विशेषज्ञ समिति ने मूल्य निर्धारण तंत्र के बदलाव के समय पर प्रति बोतल आधार पर आबकारी शुल्क के संग्रह को बनाए रखने का सुझाव दिया। जबकि जीओएम ने लाइसेंस शुल्क के रूप में आबकारी शुल्क के अग्रिम संग्रह का समर्थन किया, जिसे व्यवहारिक रूप से शराब की वास्तविक बिक्री से अलग कर दिया गया था।

8.2.2.3 सीमित निकायों को खुदरा लाइसेंस

विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि अधिकतर खुदरा लाइसेंस प्रॉक्सी स्वामित्व के माध्यम से कुछ खिलाड़ियों के साथ केंद्रित थे। खुदरा लाइसेंस एक व्यक्ति को दिया जाना चाहिए और गुटबंदी को रोकने के लिए एक व्यक्ति को अधिकतम दो खुदरा दुकानें आवंटित की जानी चाहिए। जीओएम ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया कि पूरे खुदरा बाजार को स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी वाले प्रॉक्सी मॉडल के माध्यम से बहुत कम लोगों द्वारा नियंत्रित किया गया था। हालांकि, **इसने अभी भी खुदरा लाइसेंस को उन क्षेत्रों में वितरित करने की सिफारिश की है जहाँ एक इकाई/व्यक्ति को अधिकतम 54 दुकानें (दो जोन) तक मिल सकती है।** उल्लेखनीय रूप से विशेषज्ञ समिति ने सीमित निकायों को खुदरा लाइसेंस देने की कमियों का उल्लेख किया था क्योंकि इसमें सीमित संख्या में लाइसेंसधारियों द्वारा गुटबंदी और बाजार पर कब्जा करने की अत्याधिक संभावना थी। सबसे खराब स्थिति में यदि खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेता संबंधित निकाय होते तो विशिष्ट सिंडिकेट का गठन किया जा सकता था। इसके अलावा लाइसेंसधारी की विफलता/चूक के मामले में राजस्व सुनिश्चित करने तथा आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए कोई आसान विकल्प नहीं होगा।

इस प्रकार इन विचलनों ने कुछ निजी संस्थाओं के बीच स्वामित्व का केन्द्रीकरण और परिणामी बाजार विकृति का जोखिम बढ़ा दिया।

8.2.3 पुरानी आबकारी नीति तथा नई आबकारी नीति की तुलना

पुरानी आबकारी नीति तथा नई आबकारी नीति की तुलना **तालिका 8.2** में दी गई है।

तालिका 8.2: पुरानी आबकारी नीति तथा नई आबकारी नीति की तुलना

क्र.सं.		पुरानी आबकारी नीति (2021-22 की नीति से पूर्व)	नई आबकारी नीति (2021-22)
		थोक लाइसेंस	
1.	थोक लाइसेंस	आईएमएफएल तथा एफएल के लिए अलग थोक लाइसेंस दिए गए थे। निर्माण इकाई को एल-1/एल-3 (आईएमएफएल)।	उन निजी निकायों को एल-1/एल-3 (आईएमएफएल तथा एफएल दोनों के लिए थोक लाइसेंस) दिए गए जो **वितरक (निर्माता नहीं)** थे।
2.	लाभ मार्जिन और ईडीपी	**आईएमएफएल के मामले में, निर्माता (जो थोक लाइसेंसधारी भी था) को लदान कीमत का पांच *प्रतिशत*** का लाभ मार्जिन।	केवल वितरक (जो निर्माता नहीं) को आईएणएफएल की **लदान कीमत का 12 *प्रतिशत*** का लाभ मार्जिन।
3.	गोदाम में प्रयोगशालाएं	नीति में ऐसी कोई स्थिति शामिल नहीं थी।	प्रत्येक लाइसेसधारी को उनके गोदामों में सरकारी अनुमोदित प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी थी।
4.	डीसी (गोदाम)	नीति में ऐसी कोई स्थिति शामिल नहीं थी।	डीसी के नए पद (थोक परिचालन) का सृजन किया जाना था।
		खुदरा लाइसेंस	
5.	खुदरा दुकान की शर्तें	1. प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक लाइसेंस रखने की अनुमति थी। 2. दिल्ली में लगभग 60 *प्रतिशत* दुकाने चार सरकारी निगमों द्वारा संचालित की जाती थी।	1. दिल्ली को 32 खुदरा जोन (एल-7Z लाइसेंस) में विभाजित किया गया था। 2. प्रत्येक जोन में 27 दुकानें होंगी। 3. प्रत्येक व्यक्ति/निकाय को अधिकतम दो जोन (54 दुकानें) का स्वामित्व रखने की अनुमति थी। 4. केवल निजी खिलाड़ियों को खुदरा लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति थी।
6.	लाइसेंस के बंटवारे की प्रक्रिया	**आवेदन** के आधार पर लाइसेंस दिए गए। 2016-17 के बाद कोई नया खुदरा लाइसेंस नहीं दिया गया।	प्रत्येक जोन संचालक को **ई-निविदा तथा बोली** के माध्यम से एल-7Z आवंटित किया गया। लाइसेंस शुल्क के लिए आरक्षित कीमत बोली लगाने का आधार था। आरक्षित कीमत मूल रूप से 2019-20 में अर्जित आबकारी शुल्क/वैट/अतिरिक्त आबकारी शुल्क तथा 10 *प्रतिशत* की वार्षिक वृद्धि को मानते हुए आबकारी शुल्क का अग्रिम संग्रह है।
7.	राजस्व संग्रह	बेची गई प्रत्येक इकाई के लिए प्रति बोतल के आधार पर आबकारी शुल्क एकत्र किया गया।	जोनल लाइसेंस आवेदकों द्वारा बोली के लिए आरक्षित कीमत के अन्तर्गत आबकारी शुल्क को शामिल किया गया था और जोनल लाइसेंसधारियों से अग्रिम मासिक लाइसेंस शुल्क के रूप में एकत्र किया गया था।
8.	छूट	एमआरपी पर कोई छूट अनुमत नहीं थी।	छूट की अनुमति थी।

आबकारी विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को वापस लेने (अगस्त 2022) के पश्चात् वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति के दौरान पुरानी नीति (वर्ष 2021-22 के नीति वर्ष से पहले विद्यमान) की शर्तों को ही लागू किया,

केवल इस अंतर के साथ कि सरकारी निगमों को ही खुदरा दुकानें संचालित करने की अनुमति थी। 2021-22 की नीति से पहले सरकारी निगम की दुकानों के साथ-साथ निजी दुकानें भी चल रही थी।

8.3 आबकारी नीति 2021-22 में राजस्व मॉडल

आबकारी नीति 2021-22 में राजस्व मुख्यतः लाइसेंस शुल्क के माध्यम से अर्जित किया जाना था। जिसे आरक्षित मूल्य[42] (₹ 7,039 करोड़) पर बोली के माध्यम से खोजा गया था, जिसमें 10 *प्रतिशत* की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2019-20 के राजस्व आंकड़ों के आधार पर आबकारी शुल्क तथा वैट को शामिल किया गया था। खोजे गए बोली मूल्य के अनुसार अनुमानित वार्षिक राजस्व ₹ 8,911 करोड़ था। यह नीति अवधि अर्थात 17 नवंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 की अवधि के लिए अग्रिम लाइसेंस के कारण ₹ 7,054 राजस्व को दर्शाता है। इसके अलावा वास्तविक आबकारी राजस्व में थोक लाइसेंस, अन्य आयात पास और परमिट के लिए शुल्क भी शामिल है। इसके अलावा थोक मूल्य का एक *प्रतिशत* आबकारी शुल्क तथा वैट प्रत्येक के रूप में अतिरिक्त लिया जाना था। खुदरा मूल्य को पूर्णांकित करने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त आबकारी शुल्क भी लगाया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कमजोर नीति ढ़ांचे से लेकर नीति के अपर्याप्त कार्यान्वयन तक कई मुद्दों के कारण जैसाकि इस अध्याय में चर्चा की गई है लगभग **₹ 2,002.68** करोड़ की संचयी हानि हुई जिसकी चर्चा **पैराग्राफ 8.5** में की गई है।

8.4 लाइसेंस का डिज़ाइन और प्रदान करना

नई नीति के कार्यान्वयन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु नीति के लिए एक मजबूत ढांचे का डिजाइन था, ताकि इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। हालांकि यह देखा गया कि डिज़ाइन और पुरस्कार प्रक्रिया में

---

[42] किसी क्षेत्र का आरक्षित मूल्य शामिल है

1. जोन में सभी दुकानों की कुल लाइसेंस फीस (पुरानी नीति के अनुसार यानी ₹ 8 लाख प्रति दुकान)।
2. 2019-20 के दौरान देशी शराब की दुकानों को छोड़कर इन सभी दुकानों से कुल उत्पाद शुल्क एकत्र किया गया।
3. 2019-20 के दौरान एकत्र किए गए वैट को उस क्षेत्र की दुकानों में आनुपातिक रूप से विभाजित किया गया था।
4. 2019-20 के दौरान एचसीआर से एकत्र किए गए कुल उत्पाद शुल्क को उस क्षेत्र की दुकानों में आनुपातिक रूप से विभाजित किया गया था।
5. 31.03.2020 को बंधुआ गोदामों में पड़े बफर स्टॉक पर उत्पाद शुल्क।
6. वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के लिए उपरोक्त सभी घटकों के योग पर अतिरिक्त 10 *प्रतिशत।*

निम्नलिखित मुद्दों ने ढ़ाचे को कमजोर कर दिया जिसके परिणामस्वरूप इच्छित उद्देश्यों से विचलन हुआ।

8.4.1 थोक लाइसेंस

जीओएम रिपोर्ट की सिफारिश के बाद, आबकारी नीति 2021-22 ने राज्य भंडारण निगम, जिसका विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी, के स्थान पर निजी संस्थाओं को आईएमएफएल और एफएल दोनों का थोक लाइसेंस प्रदान किया, जो वितरक (निर्माता नहीं) थे। नीति का घोषित उद्देश्य यह था कि भारतीय और विदेशी शराब की आपूर्ति में वैश्विक उद्योग मानकों के बराबर वितरण अनुभव के साथ उच्च अंत पेशेवर व्यावसायिक संस्थाओं को थोक लाइसेंस दिए जाएंगे।

हालांकि, नई नीति के तहत थोक लाइसेंस दिए जाने के तरीके में निम्नलिखित डिजाइन और प्रक्रिया संबंधी मुद्दे देखे गए।

8.4.1.1 लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया

शराब व्यापार में कम से कम पांच साल के लिए थोक वितरण का अनुभव और पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों में हर साल न्यूनतम ₹ 150 करोड़ का कारोबार के पात्रता मानदंडों को पूरा करने वालों से थोक लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने थे।

थोक लाइसेंस आवेदन के आधार पर दिए जाने थे यानी एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसके तहत थोक लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली कोई भी इकाई/व्यक्ति इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता था। व्यक्तिगत आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्णय लेना सक्षम प्राधिकारी का काम था।

पूरी प्रक्रिया से संबंधित सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की लेखापरीक्षा की मांग को पूरा नहीं किया गया। विभाग ने बताया कि थोक लाइसेंस देने के लिए कुल 18 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें आगे बताया गया कि इन 18 आवेदनों में से एक आवेदन आवेदक द्वारा वापस ले लिया गया था, दूसरे को गलत आवेदन के कारण तथा दो अन्य आवेदन प्रक्रिया के दौरान खारिज कर दिए गए थे। हालांकि, इन चारों आवेदनों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इन अभिलेखों के अभाव में,

लेखापरीक्षा इन मामलों में अपनाई गई प्रक्रिया की सत्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं दे सकी।

8.4.1.2 विशिष्टता व्यवस्था से एकाधिकार का खतरा बढ़ रहा है

नीतिगत ढांचे में प्रावधान था कि ये थोक विक्रेता वितरक (निर्माता नहीं) होंगे, जो शराब की आपूर्ति के लिए एक से अधिक निर्माताओं के साथ गठजोड़ कर सकते थे। हालाँकि, निर्माता अपने ब्रांडों की आपूर्ति केवल एक थोक विक्रेता के माध्यम से कर सकता था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस अनिवार्य गठजोड़ ने निर्माताओं को केवल एक थोक विक्रेता के माध्यम से अपने ब्रांडों की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। परिणामस्वरूप, थोक लाइसेंस आईएमएफएल और एफएल की आपूर्ति के लिए आबकारी नीति 2021-22 के तहत 14 व्यावसायिक संस्थाओं को अनुमति दी गई थी, जबकि पुरानी नीति (2020-21) में आईएमएफएल के 77 निर्माताओं और एफएल के 24 आपूर्तिकर्ताओं को दी गई थी। कुछ संस्थाओं तक थोक आपूर्ति के इस संकेंद्रण से एकाधिकार या कार्टेल गठन का जोखिम बढ़ गया जो नई आबकारी नीति के उद्देश्यों में से एक के खिलाफ था जैसा कि **पैराग्राफ 8.4.4** में भी विस्तार से बताया गया है।

8.4.1.3 थोक परिचालन से राजस्व

नई नीति का प्रमुख उद्देश्य राज्य उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि करना था। पिछली नीति के तहत, थोक लाइसेंस शुल्क को ब्रांडों की संख्या और उसके थोक मूल्य से जोड़ा गया था। हालांकि, नई आबकारी नीति के अनुसार, थोक लाइसेंसधारी को ब्रांडों की संख्या की परवाह किए बिना ₹5 करोड़ के वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना था। इसलिए नई नीति में लाइसेंस शुल्क को थोक विक्रेता लाइसेंसधारी के संचालन की सीमा से अलग कर दिया गया। इस बदलाव को विशिष्टता व्यवस्था के कारण थोक परिचालन पर एकाधिकार के जोखिम के संबंध में ऊपर की गई टिप्पणी के आलोक में भी देखा जाना चाहिए।

इसके अलावा, नई नीति के तहत थोक विक्रेता/वितरक मार्जिन की पिछली दर 5 *प्रतिशत* से बढ़कर 12 *प्रतिशत* हो गई। जीओएम द्वारा पेश किया गया औचित्य यह था कि वैश्विक वितरण मानक, गुणवत्ता जांच प्रणालियों के लिए उच्च लाइसेंस शुल्क की भरपाई करना आवश्यक था, जिसका मुख्य रूप से मतलब था कि प्रत्येक एल1

लाइसेंसधारी को उप-निर्माताओं से प्राप्त शराब के प्रत्येक बैच में मानक शराब या नकली शराब की उचित रूप से जांच करने के लिए अपने गोदामों में सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी। इसमें स्थानीय परिवहन की लागत भी शामिल होनी थी।

प्रस्तावित औचित्य को विभिन्न प्रतिकूल कारकों की मात्रा निर्धारित करके और फिर उचित लाभ मार्जिन की अनुमति देकर समर्थित नहीं किया गया था। वितरण मानक में बदलाव, जिसकी लागत अधिक होने की संभावना थी, को जीओएम द्वारा कभी स्पष्ट नहीं किया गया। स्थानीय परिवहन शुल्क वितरक मार्जिन में पर्याप्त वृद्धि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा, जो गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी थीं, जाहिर तौर पर उच्च लागत के साथ, उन्हें स्थापित और संचालित नहीं किया गया (जैसा कि **पैराग्राफ 8.6.5** में चर्चा की गई है)।

इस प्रकार, एक ओर थोक लाइसेंसधारियों के संचालन पैमाने और लाभ मार्जिन का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन दूसरी ओर लाइसेंस शुल्क से होने वाले राजस्व को इससे अलग कर दिया गया। इसे इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि केवल तीन थोक विक्रेताओं ने बेची गई शराब की मात्रा का 70 *प्रतिशत* से अधिक हिस्सा लिया, जैसा कि **पैराग्राफ 8.4.4** में टिप्पणी की गई है। जिससे छोटे परिचालन वाले थोक लाइसेंसधारियों के लिए व्यवस्थित नुकसान पैदा हुआ।

8.4.1.4 संयुक्त उद्यम भागीदारी की प्रकृति

नीति में प्रावधान किया गया है कि संस्थाओं के बीच एक संयुक्त उद्यम की अनुमति है, लेकिन संयुक्त उद्यम भागीदार फर्म में से कम से कम एक के पास व्यक्तिगत रूप से आवश्यक अनुभव और टर्नओवर होना चाहिए। हालांकि, नीति में ऐसी संयुक्त उद्यम व्यवस्था का विवरण या संस्थाओं की प्रकृति और संयुक्त उद्यम भागीदारों के बीच साझेदारी के रूप को निर्दिष्ट नहीं किया गया।

उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच से यह पाया गया कि:

- कम से कम दो थोक विक्रेताओं ने एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया, जहां अपेक्षित शराब वितरण अनुभव और टर्नओवर वाली इकाई के पास साझेदारी में नगण्य हिस्सेदारी, यानी एक *प्रतिशत* से लेकर पांच *प्रतिशत* तक थी।

- आवेदक साझेदारी फर्म में बहुमत भागीदार/प्रबंध भागीदार की पृष्ठभूमि, वित्तीय स्थिति और अनुभव से संबंधित कोई विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए रिकॉर्डों में नहीं पाया गया।
- उपरोक्त मामलों में से एक में, जेवी साझेदारी समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "पहले पक्ष को लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र बनाने के लिए आवश्यक अनुभव और टर्नओवर वाले भागीदार को ₹25,000 की रॉयल्टी का भुगतान करना होगा"। इससे संकेत मिलता है कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली इकाई को जेवी को लाइसेंस के लिए पात्र बनाने के लिए औपचारिकता के रूप में शामिल किया गया था।

ऐसी व्यवस्था की अनुमति देना थोक परिचालन के उच्च स्तरीय, पेशेवर प्रबंधन के घोषित उद्देश्य के विरुद्ध है।

8.4.2 जोनल/रिटेल लाइसेंस

नीति के अनुसार, खुदरा लाइसेंस देने का उद्देश्य दिल्ली के सभी वार्डों/क्षेत्रों में शराब की आपूर्ति की समान पहुंच सुनिश्चित करना था, जिससे नकली/बिना शुल्क चुकाई गई शराब की संभावना खत्म हो सके। इसके अलावा उद्देश्य में एकाधिकार और कार्टेल के उद्भव को रोकने के अलावा राजस्व बढ़ाने के मामले में लाइसेंसधारी की ओर से जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है।

आधार लाइसेंस शुल्क के रूप में आरक्षित मूल्य के साथ ई-निविदा के माध्यम से आवंटन किया जाना था। बोली के लिए कुल 32 जोन रखे गए थे, जिसमें दिल्ली के 272 नगरपालिका वार्डों में फैले 30 जोन और एनडीएमसी/कैंट तथा हवाई अड्डा के लिए एक-एक जोन शामिल थे। बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्रता शर्तों में शामिल थी:

- कोई भी निजी कानूनी इकाई या व्यक्ति जिसके पास पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण था, जोनल लाइसेंस के पुरस्कार के लिए बोली में भाग लेने के लिए पात्र था।
- पात्रता शर्त में प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी के लिए 6 करोड़ की कुल संपत्ति भी अनिवार्य था, जिसके तहत एक इकाई को अधिकतम दो क्षेत्र प्रदान किए जा सकते थे।

- लाइसेंस शर्तों में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी निर्माता या थोक लाइसेंसधारी को जोनल लाइसेंस के लिए बोली लगाने की अनुमति नहीं थी।

निविदा आमंत्रण सूचना (एनटीटी) के माध्यम से तीन कवर निविदा प्रक्रिया के अर्थात पूर्वयोग्यता बोली, तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के द्वारा (ई-निविदा 28 जून 2021 को प्रकाशित हुई थी और ई-बोली जमा करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2021 थी) 32 क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निविदाएं आमंत्रित करते हुए निविदा प्रक्रिया शुरू की गयी। तकनीकी बोली प्रावधान को यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया था कि एक बार बोली लगाने वाले को दो ज़ोन (उच्चतम बोली लगाने वाला घोषित) दिए जाने के बाद, अन्य ज़ोन के लिए उसकी वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।

पहले टेंडर के दौरान, 28 बोलीदाताओं द्वारा 32 ज़ोन के लिए 123 बोलियाँ प्राप्त हुईं (एक बोलीदाता को बाद में अयोग्य घोषित कर दिया गया) जिसके परिणामस्वरूप 13 आवेदकों (एच1) को 19 ज़ोन दिए गए, जबकि 6 बोलीदाताओं को प्रत्येक को दो ज़ोन दिए गए। हवाईअड्डा क्षेत्र के मामले में, हवाईअड्डा प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त नहीं होने के कारण एच1 को लाइसेंस जारी नहीं किया जा सका और एच1 राशि पर एनओसी प्राप्त करने वाले किसी अन्य बोलीदाता को लाइसेंस दिया गया। 12 ज़ोनों के लिए दूसरे एनआईटी में, 12 बोलीदाताओं द्वारा 12 ज़ोनों के लिए 92 बोलियां प्राप्त हुईं, जिसके परिणामस्वरूप चार बोलीदाताओं को दो ज़ोनों के साथ-साथ जोनों का पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार, अंततः 32 में से 20 ज़ोन 10 आवेदकों को आवंटित किए गए, जिनमें से प्रत्येक को दो ज़ोन दिए गए।

हालांकि नई नीति के तहत जोनल/रिटेल लाइसेंस दिए जाने के तरीके में निम्नलिखित डिजाइन और प्रक्रिया संबंधी मुद्दे देखे गए।

8.4.2.1 थोक और खुदरा लाइसेंसधारियों की संख्या में कमी के कारण एकाधिकार का बढ़ता खतरा

नई आबकारी नीति का एक उद्देश्य किसी भी एकाधिकार या कार्टेल के गठन को रोकना था। खुदरा बाज़ार को विशेष रूप से कुछ लोगों द्वारा नियंत्रित किए जाने का मुद्दा दोनों रिपोर्टों यानी जीओएम और विशेषज्ञ समिति में उठाया गया था। हालांकि यह देखा गया कि नीति उन क्षेत्रों में खुदरा लाइसेंस के वितरण के लिए प्रदान की गई है जहाँ एक

इकाई/व्यक्ति को न्यूनतम 27 विक्रेता (1 क्षेत्र) मिलेंगे जैसा कि **पैराग्राफ 8.2.2.3** में टिप्पणी की गई है।

खुदरा विक्रेताओं के उद्देश्य से, दिल्ली को 32 क्षेत्रों (849[43] विक्रेताओं सहित) में विभाजित किया गया था, जिनके लाइसेंस निविदा के माध्यम से 22 संस्थाओं को दिए गए थे जबकि पुरानी नीति के दौरान 377 खुदरा दुकानें चार सरकारी निगमों द्वारा चलाई जाती थीं और 262 खुदरा दुकानें निजी व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती थीं। लाइसेंसों के वितरण का यह तंत्र खुदरा लाइसेंस के स्वामित्व और नियंत्रण को बहुत कम हाथों में केंद्रित करता है, जिससे एकाधिकार और कार्टेल गठन का खतरा बढ़ गया।

8.4.2.2 बोली दस्तावेजों के माध्यम से क्षेत्रीय लाइसेंस आवेदनों की व्यवहार्यता, सुनिश्चित नहीं की गई

यह सुनिश्चित करने के लिए कि समय पर आबकारी राजस्व संग्रहण बाधित न हो, सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि क्या लाइसेंस के लिए बोली लगाने वाली व्यावसायिक निकाय एक चालू निकाय है और वित्तीय रूप से टिकाऊ है कि वह कानूनी और नियामक व्यवस्था का अनुपालन करते हुए संचालन जारी रख सके।

बोली लगाने वाले की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए मांगे गए एकमात्र दस्तावेज पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों 2018-2021 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) और आज की तारीख में नेटवर्थ दिखाने वाला चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) प्रमाणपत्र थे।

यह देखा गया कि क्षेत्रीय लाइसेंसधारी से संभावित व्यय में शामिल हैं:

- बोली जमा करने के दौरान ईएमडी के रूप में ₹30 करोड़
- एल7जेड लाइसेंस जारी करने से पहले, बोली को अंतिम रूप देने के सात दिनों के भीतर सुरक्षा जमा के रूप में लाइसेंस शुल्क का 25 *प्रतिशत* एक क्षेत्र के लिए औसतन ₹ 70 करोड़[44] की राशि।
- महीने के 7वें दिन से पहले अग्रिम के रूप में मासिक लाइसेंस शुल्क प्रति क्षेत्र औसतन ₹ 23 करोड़ है।

---

[43] फरवरी 2022 के दौरान ऑपरेशनल वेंड 580 थे और जुलाई 2022 के दौरान 468 थे।

[44] औसत वार्षिक लाइसेंस शुल्क ₹ 280 करोड़ का 25 *प्रतिशत।*

- किराया/पट्टा व्यय, कर्मचारियों की नियुक्ति, साज-सज्जा और अग्नि शमन/सीसीटीवी/इलेक्ट्रिकल/डिजाइन और स्टॉकिंग व्यय के साथ दुकानें खोलने पर व्यय।

इस प्रकार, बिक्री से राजस्व उत्पन्न करने से पहले लाइसेंसधारी को एक क्षेत्र के लिए कम से कम ₹ 100 करोड़ का अग्रिम व्यय करना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नीति में आवेदक इकाई की वित्तीय स्थिति के संबंध में कोई न्यूनतम योग्यता मानदंड निर्धारित नहीं थे। इससे वित्तीय और प्रबंधकीय रूप से अक्षम संस्थाओं को खुदरा लाइसेंस दिए जाने का जोखिम पैदा हो गया, जिससे संचालन में बाधा आ सकती है, तथा आबकारी राजस्व प्रभावित हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने सफल बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी पाया गया कि:

- 22 में से केवल 10 संस्थाओं ने तीन वर्षों में ₹ 1 लाख से अधिक की आय की सूचना दी।
- नौ संस्थाओं ने तीन में से दो वर्षों में शून्य आय और/या हानि की सूचना दी थी।
- लगभग शून्य आय हानि और शून्य से नगण्य करों की रिपोर्ट करने वाली पांच[45] संस्थाओं को 10 खुदरा क्षेत्र दिए गए, प्रत्येक में दो यह दर्शाते हैं कि लाइसेंस जारी करते समय इन्हें खतरे का संकेत नहीं माना गया था।

8.4.2.3 ए7-जेड जोनल लाइसेंस की नवीकरणीय प्रकृति

आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार, उचित बोली प्रक्रिया के बाद प्रदान किए गए जोनल लाइसेंस हर साल नवीनीकृत किए जा सकते थे, उस अवधि की कोई सीमा रखे बिना जिसके लिए इसे बढ़ाया जा सकता था। वास्तविक बिक्री के आधार पर प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले वार्षिक आधार पर लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की जा सकती थी। हालांकि, आबकारी विभाग ने बाद के वर्षों में संशोधित लाइसेंस शुल्क गणना करने के तौर-तरीके तय नहीं किए।

[45] नोवा गारमेंट्स, खाओ गली रेस्तरां, जेएसएन इंफ्राटेक, पाथ2वे एचआर सॉल्यूशंस और मैगुंटा एग्रो. मगुंटा एग्रो ने वर्ष 2019-20 के लिए ₹2.76 करोड़ का आयकर भुगतान किया, हालांकि, वर्ष के दौरान परिचालन आय शून्य थी। वर्ष 2020-21 के दौरान भी इसमें घाटा हुआ था।

इसके अलावा, दूसरे नवीकरणीय वर्ष के लिए व्यवसायिक निकाय की वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए तौर-तरीके निर्धारित नहीं किए गए थे, यदि निकाय पहले नीति वर्ष परिचालन अवधि के बाद घाटे में चल रही थी और परिणामस्वरूप कम नेटवर्थ, जैसे पाथ 2 वे एचआर सॉल्यूशंस के लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था यद्यपि, 2021-22 की अवधि के लिए निकाय के अपनाए गए वित्तीय विवरणों में मार्च 2022 तक लगभग ₹ 52 करोड़ का घाटा और ₹ 37 करोड़ का ऋणात्मक नेटवर्थ दिखाया गया था।

8.4.2.4 जोनल लाइसेंस सरेंडर करने के लिए नीति प्रावधान का अभाव

जैसा कि **पैराग्राफ 8.4.2.2** में चर्चा की गई है, नीति ने वित्तीय (नेट वर्थ को छोड़कर) के लिए कोई आधार रेखा निर्धारित नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय रूप से कमजोर संस्थाओं को जोनल लाइसेंस दिए गए। अंततः जोनल लाइसेंसधारियों ने आबकारी नीति की समाप्ति से पहले अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए और किसी भी मामले में कोई निविदा पुन: नहीं की गई।

इसके अलावा, नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें लाइसेंसधारकों को जोनल लाइसेंस सरेंडर करने के लिए अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता हो ताकि विभाग पुनः निविदा के लिए कार्रवाई शुरू कर सके। लाइसेंस के अचानक समर्पण के खिलाफ इस तरह की सुरक्षा के अभाव में पुनः निविदा के माध्यम से जोनल लाइसेंस को फिर से आवंटित करने में लगने वाले समय जिसके दौरान कोई लाइसेंस शुल्क नहीं मिलेगा के कारण पर्याप्त राजस्व हानि का जोखिम था। इस प्रकार, खुदरा क्षेत्र के संचालन बंद होने के कारण होने वाली हानि से बचने के लिए नीति में कोई आकस्मिक योजना शामिल नहीं थी क्योंकि जोनल लाइसेंस के लिए पुनः निविदाकरण एक समय लेने वाली प्रक्रिया है।

8.4.2.5 निविदा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच नहीं की गई

निविदा प्रक्रिया के दौरान निविदा प्रतिभागियों/बोलीदाताओं के विरुद्ध नौ शिकायतें (जुलाई 2021 के अंतिम सप्ताह में) प्राप्त हुई थीं। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर शिकायतों की जांच के लिए निविदा मूल्यांकन समिति को अधिकृत किया गया था। ये नौ शिकायतें 14 आवेदकों से संबंधित थे जहां पांच शिकायतें कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन/आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार शराब का कारोबार करने में

अयोग्यता से संबंधित थीं, वहीं अन्य शिकायतें इन जोनल लाइसेंस आवेदकों के कुछ डिस्टिलरी से कथित संबंध से संबंधित थीं। यह निविदा दस्तावेजों में पात्रता की शर्त के खंड 2.3 के खिलाफ था, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि कोई भी निर्माता/थोक विक्रेता खुदरा लाइसेंस के लिए बोली लगाने के लिए पात्र नहीं होगा और खुदरा लाइसेंसधारियों के पास सहयोगी निकाय/संबंधित निकायों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश या विदेश में कोई निर्माण सुविधा नहीं होनी चाहिए।

निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी), जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा शिकायतों की जांच करने का काम सौंपा गया था, ने यह निर्णय लिया कि इन शिकायतों की एक प्रति आवेदकों को (शिकायतकर्ता की पहचान उजागर किए बिना) इस संबंध में उनके स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए भेजी जाए, और यह कि इन फर्मों की साख को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से सत्यापित कराया जाए। शिकायतों में आरोपों को स्पष्ट रूप से नकारते हुए इन आवेदकों से जवाब/दस्तावेज प्राप्त हुए थे। टीईसी ने 3 अगस्त 2021 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समय की कमी और निविदा प्रक्रिया के उन्नत चरण के कारण शिकायत के जवाब में प्रस्तुत शिकायतों/दस्तावेजों की विस्तृत जांच/प्रति-परीक्षण का दायरा सीमित था। इस प्रकार, आवेदकों की सभी शिकायतों, स्पष्टीकरणों दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लिया जाए क्योंकि निविदा शर्तों के अनुसार भविष्य में यदि आवश्यक हो, दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अंततः सभी निकायों को पात्र बोलीदाताओं के रूप में अनुमति दी गई और इन 14 निकायों में से 11 को बोली लगाने के उपरांत सफल घोषित होने के बाद 17 खुदरा जोन आवंटित किए गए। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आबकारी नीति 2021-22 के शामिल होने तक कोई विस्तृत जांच आयोजित नहीं की गई थी।

एल1 और एल7जेड के बीच गठजोड़ के माध्यम से क्रॉस स्वामित्व और अनुचित बाजार प्रथाओं के उदाहरणों से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों को आगामी पैराग्राफ में शामिल किया गया है।

8.4.3 आपूर्ति श्रृंखला में लाइसेंस रखने वाली संबंधित व्यावसायिक निकाय

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 35 में, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारित किया गया है कि थोक लाइसेंस धारी को शराब की खुदरा बिक्री के लिए कोई

लाइसेंस नहीं दिया जाएगा तथा खुदरा लाइसेंसधारी को शराब की थोक बिक्री के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

नई उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में उल्लेख किया गया कि खुदरा लाइसेंसधारकों के पास देश या विदेश में कहीं भी सीधे या किसी सहायक कंपनी/संबंधित निकायों के माध्यम से कोई विनिर्माण सुविधाएं/डिस्टिलरी/ब्रुअरीज/वाइनरी नहीं होनी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, सहयोगी निकायों/संबंधित निकायों का अर्थ यह होगा कि निकायों का सामान्य मालिक या भागीदार या निदेशक नहीं होना चाहिए। स्वामित्व या साझेदारी या कंपनी का अधिकांश स्वामित्व (51 *प्रतिशत* या अधिक) सभी निकायों में एक ही व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। निकाय को होल्डिंग-सहायक संबंध नहीं होना चाहिए या उसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनियां नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, एल1 लाइसेंसधारक (थोक) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी खुदरा विक्रेता का मालिक नहीं होगा।

8.4.3.1 संबंध निर्धारित करने के लिए मानदंड के दायरे को सीमित करना

पहले की आबकारी नीति के प्रांसंगिक प्रावधानों में विशेष रूप से कहा गया था कि थोक वितरण के लिए लाइसेंस रखने वाले किसी भी डिस्टिलरी या शराब की भट्ठी या बॉटलिंग प्लांट में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य को खुदरा लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए डिस्टलरी, शराब की भट्ठी, वाइनरी या बॉटलिंग प्लांट के व्यवसाय में हित रखने वाले व्यक्ति में सहकारी समिति के सदस्य, निदेशक, भागीदार, एजेंट या कर्मचारी के रूप में इन व्यवसायों में हित रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति शामिल है। पहले की नीति के अंतर्गत खुदरा लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय, आवेदकों को यह भी घोषित करना आवश्यक था कि आवेदन की तारीख से पहले पिछले पांच वर्षों में दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत किसी भी लाइसेंसधारी के व्यवसाय में उसकी कोई हित नहीं है।

हालांकि, नई नीति में संबंध निर्धारित करने के मानदंडों का दायरा कम कर दिया गया था। "साझेदार, एजेंट, परिवार के सदस्य के माध्यम से संबंध" और "पिछले पांच वर्षों में किसी भी समय गैर-संबंध" के संबंध में पहले के नीतिगत मानदंड जहां नियंत्रण प्रभाव एक इकाई द्वारा दूसरे पर प्रयोग किया जा सकता था, उदाहरण के लिए सामान्य अल्पसंख्यक शेयरधारिता के माध्यम से, सामान्य प्रवर्तक समूह या आम व्यक्तियों के

माध्यम से दिये गये असुरक्षित ऋण को संबंधित संस्थाओं की परिभाषा से बाहर रखा गया।

नीति की शर्तों में इस तरह की कमी के परिणामस्वरूप उन निकायों को लाइसेंस दिया गया, जिनमें समान हित वाले व्यक्ति थे। कुछ उल्लेखनीय मामले जहां लाइसेंसधारियों/सामान्य लाभकारी स्वामित्व के बीच प्रमाण थे, उनकी चर्चा नीचे की गई है:

- मैसर्स इंडोस्पिरिट जो एक थोक लाइसेंसधारी था और जोनल लाइसेंसधारी मैसर्स खाओ गली रेस्तरां जिनके पास दो जोन थे के बीच संबंध होने का प्रमाण था। खाओ गली रेस्तरां मैसर्स इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की एक सहयोगी कंपनी है और मेसर्स इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की मेसर्स इंडोस्पिरिट (थोक लाइसेंसधारी) में 35 *प्रतिशत* हिस्सेदारी है। इसके अलावा, खाओ गली के निदेशक इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के निदेशक थे।
- थोक लाइसेंसधारी महादेव लिकर 2021 में कॉमन पास्ट पार्टनरशिप और पारिवारिक संबंधों के माध्यम से जोनल लाइसेंसधारी (दो जोन) भगवती ट्रांसफार्मर कॉर्प से जुड़ा था।
- थोक विक्रेता, गौतम वाइन के मामले में यह पाया गया कि पारिवारिक शेयरधारिता ने इसे शराब निर्माताओं, ओएसिस डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और विजेता भगवती बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड से जोड़ा था।
- जोनल लाइसेंसधारी - पॉपुलर स्पिरिट्स एलएलपी कॉमन पार्टनर/निदेशक 2021 में के माध्यम से एक निर्माता बडी (पंजाब) बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित था। बडी (टी1डी) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड एयरपोर्ट ज़ोन के लिए जोनल लाइसेंसधारी 2021 में कॉमन डायरेक्टरशिप के माध्यम से संबंधित था।

सामान्य वर्तमान/अतीत निदेशकत्व के माध्यम से देखे गए अन्य प्रासंगिक कनेक्शन मध्यस्ता संख्याओं में निदेशकत्व, सामान्य शेयरधारिता और प्रबंधन आदि **अनुलग्नक XVI** में सूचित किया गया है।

8.4.3.2 संबध की पहचान करने के लिए अपर्याप्त दस्तावेजीकरण और विश्लेषण

नई नीति के अनुसार आवेदक किसी भी कनेक्शन की अनुपस्थिति की घोषणा करते हुए केवल एक शपथ पत्र (अनुलग्नक बी प्रारूप में) प्रस्तुत करना था। जोनल लाइसेंस

प्रदान करने के लिए दो व्यवसायिक संस्थाओं के बीच सामान्य लाभकारी स्वामित्व को खारिज करने के लिए अपर्याप्त पात्रता का आकलन करने के लिए बोली दस्तावेजों की आवश्यकता थी।

इसके अलावा, विभाग ने संबंधित संस्थाओं से संबंधित नीति शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों की ठीक से जांच नहीं की। यह देखा गया कि बाद की शिकायतों को भी केवल रिकार्ड पर लिया गया और कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई जैसा **पैराग्राक 8.4.2.5** में टिप्पणी की गई है।

संबंधित व्यवसायिक संस्थाओं के उदाहरण के अलावा, लेखापरीक्षा को विषम आपूर्ति पैटर्न के सांख्यकिय साक्ष्य मिले (जैसा कि **पैराग्राफ 8.4.4** में चर्चा की गई है) जो जोनल लाइसेंसधारी और थोक लाइसेंसधारी, जिनके समान, व्यावसायिक हित है, के द्वारा सामान्य आपूर्ति पैटर्न में हेरफेर का परिणाम हो सकता है। इससे विशिष्टता व्यवस्था और ब्रांड को आगे बढ़ाने का जोखिम पैदा होता है।

8.4.4 विशिष्टता व्यवस्था और ब्रांड पुशिंग को जोखिम

ईसीआईएमएस से लिए गए डेटा और ट्रांसपोर्ट परमिट (टीपी) के डेटा में 22 विभिन्न व्यावसायिक निकायों द्वारा स्वामित्व वाला सभी 32 ज़ोन में थोक विक्रेता (एल1) लाइसेंसधारी से खुदरा दुकानों तक ब्रांड-वार आवाजाही शामिल है, जिसका विश्लेषण आपूर्ति/मांग प्रणाली[46] का पता लगाने के लिए किया गया था।

नीति में एक निर्माता और थोक विक्रेताओं के बीच एक विशेष व्यवस्था अनिवार्य थी जिससे किसी विशेष निर्माता के सभी ब्रांडों की संपूर्ण आपूर्ति को केवल एक थोक विक्रेता द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। यह इस तथ्य पर विचार करते हुए विशेष रूप से

---

[46] विश्लेषण के प्रयोजन के लिए-

- शराब की मात्रा (लीटर में) का उपयोग एकत्रीकरण मीट्रिक के रूप में किया गया।
- टीपी का उपयोग दुकानों पर बिक्री के लिए प्रॉक्सी के रूप में किया जाता था।
- विभिन्न क्षेत्रों में ब्रांडों की उपभोक्ता पसंद को एक समान माना गया है। यह ज़ोन 31 (ऑर्गेनोमिक्स इकोसिस्टम) और ज़ोन 32 (बडी टी1डी रिटेल) को छोड़कर सभी ज़ोन के लिए मान्य है क्योंकि ये ज़ोन क्रमशः एनडीएमसी क्षेत्र (बिना वार्ड वाला एक सन्निहित क्षेत्र) और हवाई अड्डे की खुदरा दुकानों को पूरा करते हैं, जिनमें अन्य जोन के लिए प्रत्येक की तुलना में अलग-अलग उपभोक्ता प्राथमिकताएँ होती हैं।
- भारत में निर्मित देशी शराब (आईएमएफएल) शराब की कुल बिक्री का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए डेटा का विश्लेषण केवल आईएमएफएल की आपूर्ति के लिए किया गया है।
- डेटा केवल आबकारी नीति 2021-22 की प्रारंभिक अवधि यानी 17 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक लिया गया है, इस दौरान सभी जोन चालू थे। इस अवधि के बाद, मई और जुलाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का आत्मसमर्पण तुलनात्मकता के साथ समस्याएं उत्पन्न करता है।

प्रासंगिक हो जाता है कि यद्पि दिल्ली में आईएमएफएल के 367 ब्रांड पंजीकृत थे। बिक्री की मात्रा में बहुत कम लोकप्रिय ब्रांडों ने योगदान दिया। दिल्ली में बेची गई शराब में शीर्ष 10 ब्रांडों की हिस्सेदारी 46.46 *प्रतिशत* थी। जबकि शीर्ष 25 ब्रांडों की बिक्री में 69.50 *प्रतिशत* थी। इन 25 सबसे अधिक बिक्री वाले ब्रांडों में से ब्रिंडको और महादेव लिकर ने विशेष रूप से प्रत्येक सात ब्रांडों की आपूर्ति की, इसके बाद इंडोस्पिरिट ने विशेष रूप से छः ब्रांडों की आपूर्ति की।

इसके अलावा, 13 थोक लाइसेंसधारियों द्वारा आपूर्ति किए गए आईएमएफएल के 367 ब्रांडों में से सबसे अधिक ब्रांड विशेष रूप से इंडोस्फिरिट (76 ब्रांड) द्वारा आपूर्ति किए गए थे, इसके बाद महादेव लिकर (71 ब्रांड) और ब्रिंडको (45 ब्रांड) थे। दिल्ली में बेची गई शराब की मात्रा में इन तीन थोक विक्रेताओं की हिस्सेदारी 71.70 *प्रतिशत* थी। बेची गई शराब की मात्रा के संदर्भ में विभिन्न थोक लाइसेंसधारियों की सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी को दर्शाने वाला एक पाई **चार्ट 8.3** में दिया गया है।

चार्ट 8.3: थोक लाइसेंसधारियों की सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी

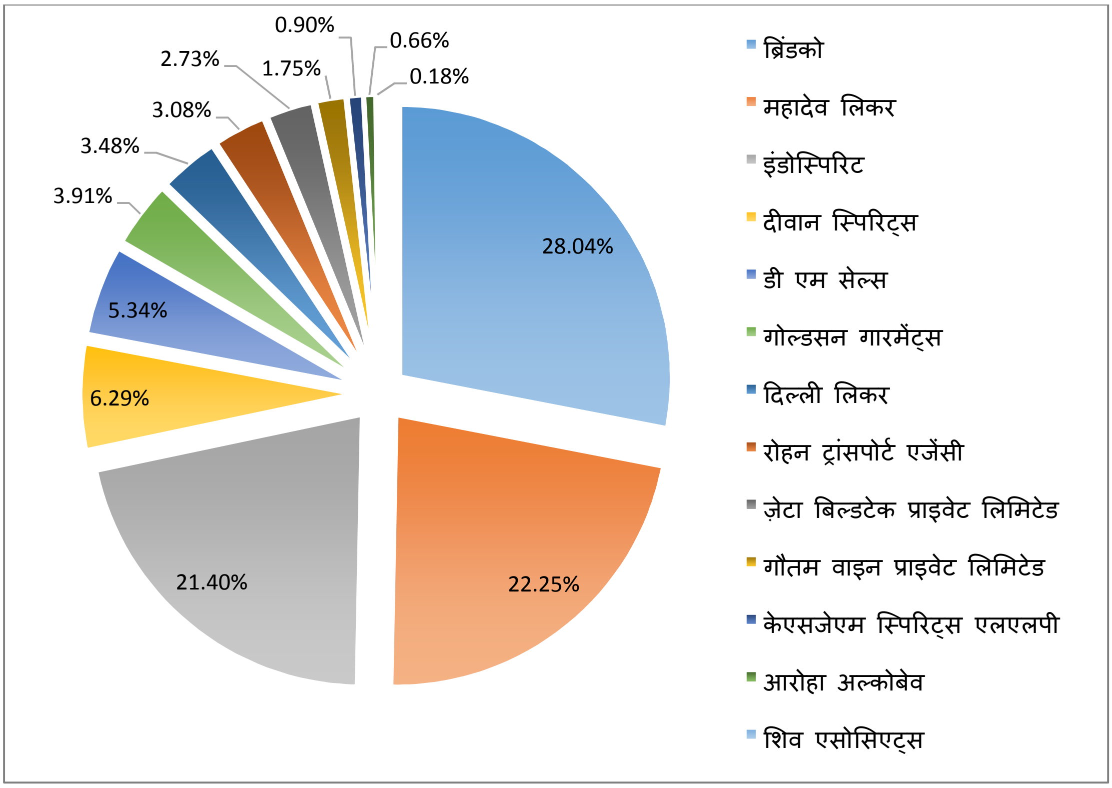

थोक लाइसेंसधारियों से 22 व्यावसायिक निकायों (32 जोन वाले) को शराब की आपूर्ति का विश्लेषण किया गया था। जैसा कि 30 क्षेत्रों (एनडीएमसी क्षेत्र और हवाईअड्डा क्षेत्र को छोड़कर) के लिए उपभोक्ता की वरीयताएँ संपूर्ण दिल्ली में वार्डों के वितरण के

कारण समान मानी जाती हैं फिर भी प्रत्येक थोक विक्रेता से खुदरा निकायों को आपूर्ति एक खुदरा क्षेत्र वाले निकायों के लिए औसतन 3.33 *प्रतिशत* और दो खुदरा क्षेत्र वाले निकायों के लिए 6.66 *प्रतिशत* होनी चाहिए। यह सामान्य है कि सामान्य वितरण के अनुसार आपूर्ति में बदलाव होगा। हालांकि, एक जोखिम है कि कुछ व्यापारिक निकाएं विशिष्ट थोक लाइसेंसधारी से आपूर्ति के एक बड़े हिस्से को अनुपातहीन रूप से हड़प लेंगी। इस प्रकार, थोक विक्रेताओं से (क्षैतिज अक्ष पर दिखाए गए) खुदरा व्यापारियों तक आपूर्ति वितरण का विश्लेषण एक बॉक्स और व्हिस्कर प्लॉट के साथ किया गया है जो आउटलेयर की ओर इशारा करता है, जैसा कि **चार्ट 8.4** में दिखाया गया है। ये आउटलेयर किसी विशेष थोक विक्रेता से स्टॉक का असामान्य रूप से उच्च अनुपात प्राप्त करने वाले क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों को दर्शाते है।

चार्ट 8.4: थोक विक्रेताओं से खुदरा जोन तक अनियमित शराब की आपूर्ति

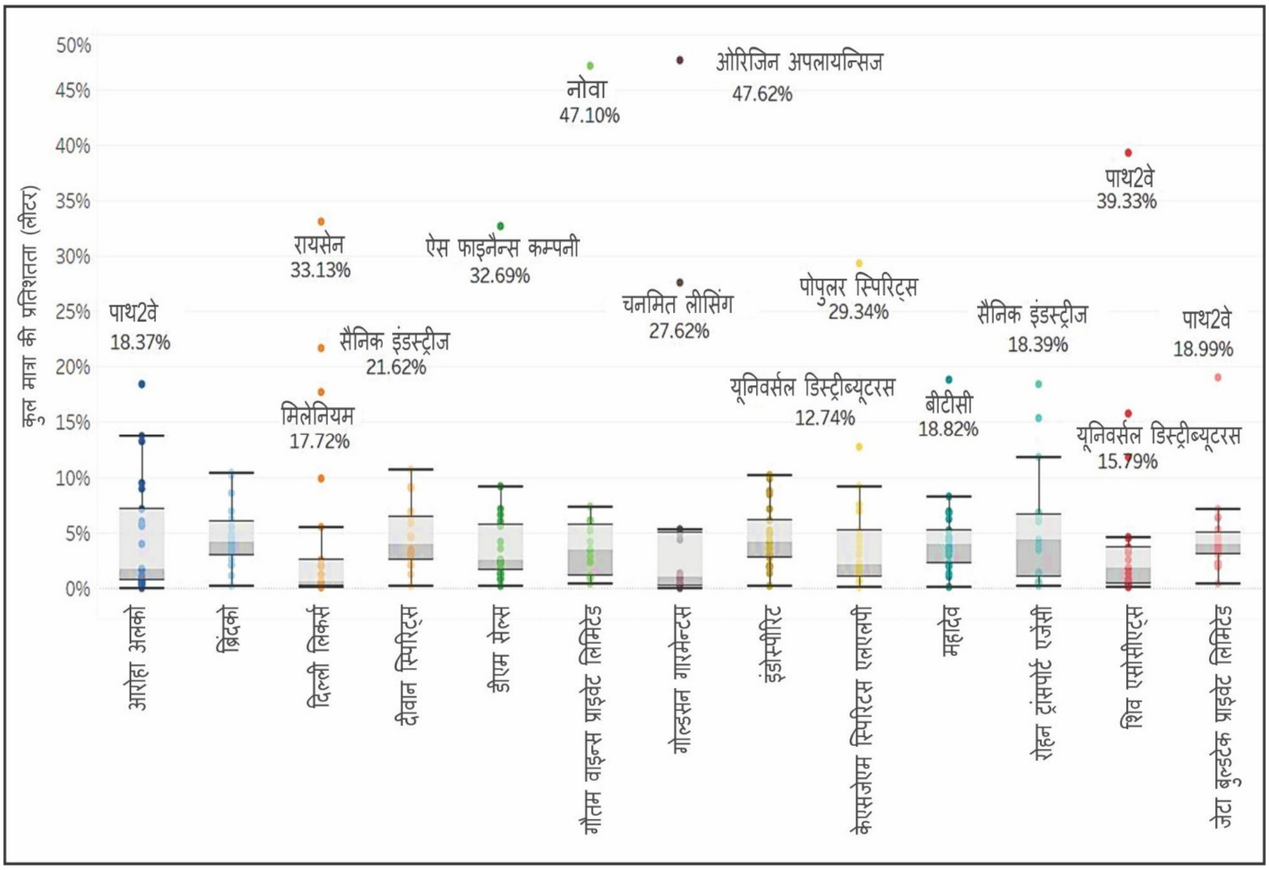

थोक विक्रेता

दिल्ली में शराब की आपूर्ति पैटर्न के समग्र विश्लेषण से निम्नलिखित पता चला:

1. शराब का थोक वितरण बड़े पैमाने पर तीन संस्थाओं इंडोस्पिरिट, ब्रिंडको और महादेव लिकर द्वारा नियंत्रित (71.70 *प्रतिशत*) किया गया था। पहले वाले दो विशेष रूप से यूनाइटेड स्पिरिट्स (डियाजियो), यूनाइटेड ब्रुअरीज (हेनेकेन) और पेरनोड रिकार्ड के ब्रांडों की आपूर्ति करते हैं, जो शराब के तीन सबसे बड़े घरेलू निर्माता हैं।

2. 32 खुदरा क्षेत्र की स्वामित्व वाली 22 व्यावसायिक संस्थाओं में से, 10 जोन की स्वामित्व वाली शीर्ष आठ[47] व्यावसायिक संस्थाओं (प्रति क्षेत्र बिक्री की मात्रा के संदर्भ में) की बिक्री में 44.79 *प्रतिशत* हिस्सेदारी थी। इसके विपरीत, निचले 10 जोन (छः[48] व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अधिकृत) में केवल 16.68 *प्रतिशत* बिक्री हुई।

3. ऐसे उदाहरण थे जहां एक विशेष थोक विक्रेता ने अपने स्टॉक का सांख्यिकीय रूप से बड़ा हिस्सा एक विशेष जोनल लाइसेंसधारी को आपूर्ति की, जो इन थोक लाइसेंसधारियों और संबंधित जोनल लाइसेंसधारियों के बीच अनुकूल व्यावसायिक शर्तों और/या घनिष्ठ संबंध के जोखिम को उजागर करता है। इसके अलावा, कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है जहां एक जोनल लाइसेंसधारी की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा एक विशिष्ट थोक विक्रेता से प्राप्त किया गया था। जबकि लोकप्रिय ब्रांडों की आपूर्ति करने वाले थोक विक्रेताओं से खरीद के मामले में यह कोई मुद्दा नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें ब्रांड को आगे बढ़ाने और सीमित उपभोक्ता विकल्प जैसे निहितार्थ हो सकते हैं। कुछ उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं, जैसा कि चार्ट 8.4 से देखा जा सकता है।

   - डीएम सेल्स ने अपने कुल स्टॉक का 32.69 *प्रतिशत* ऐस फाइनेंस कंपनी होल्डिंग ज़ोन 22 को आपूर्ति की, जबकि आपूर्ति का औसत मूल्य 2.53 *प्रतिशत* था। इसके विपरीत ऐस फाइनेंस ने अपने कुल स्टॉक का 48.46 *प्रतिशत* डीएम बिक्री से खरीदा।

---

[47] मिलेनियम इंफ्रा, चनमीत लीजिंग, पॉपुलर स्पिरिट्स, ओरिजिन अप्लायंसेज, सकरिया, मल्टीसिटी हॉस्पिटैलिटीज, भगवती ट्रांसफॉर्मर कॉर्प (बीटीसी), रायसेन मार्केटिंग

[48] नोवा गारमेंट्स, खाओ गली रेस्तरां, ट्राइडेंट चेम्फर, ऑर्गनोमिक्स इकोसिस्टम, अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर्स, बडी टी1(डी) रिटेल।

- दिल्ली लिकर्स ने अपने कुल स्टॉक का 33.13 *प्रतिशत,* 21.62 *प्रतिशत* और 17.72 *प्रतिशत* तीन क्षेत्रों, क्रमशः रायसेन मार्केटिंग (जोन 13), सैनिक इंडस्ट्रीज (जोन 17) और मिलेनियम इंफ्रा (जोन 9) को आपूर्ति की, जबकि आपूर्ति का औसत मूल्य 0.56 *प्रतिशत* था।

- गौतम वाइंस ने अपने स्टॉक का 47.10 *प्रतिशत* नोवा गारमेंट्स (जोन 11 और जोन 15) को आपूर्ति की, जबकि आपूर्ति का औसत मूल्य 2.32 *प्रतिशत* था।

- खाओ गली रेस्तरां प्रा. लिमिटेड (जोन 2 और 3) ने अपने स्टॉक का 45.26 *प्रतिशत* मेसर्स इंडोस्पिरिट से खरीदा। पिछले खण्ड में, इन दोनों संस्थाओं को संबद्ध बताया गया है।

- गोल्डसन गारमेंट्स ने अपने स्टॉक का 47.62 *प्रतिशत* और 27.62 *प्रतिशत* क्रमशः ओरिजिन अप्लायंसेज (जोन 14 और 16) और चनमीत लीजिंग (जोन 28) को आपूर्ति की, जबकि आपूर्ति का औसत मूल्य 0.36 *प्रतिशत* था।

- केएसजेएम स्पिरिट्स ने अपने स्टॉक का 29.34 *प्रतिशत* पॉपुलर स्पिरिट्स (जोन 30) को आपूर्ति की, जबकि आपूर्ति का औसत मूल्य 2.12 *प्रतिशत* था। विशेष रूप से, ये दोनों संस्थाएं संबंधित संस्थाओं में कॉमन निदेशन के माध्यम से एक-दूसरे से संबद्ध हैं, जैसा कि अनुबंध XVI में बताया गया है।

- महादेव लिकर ने अपने स्टॉक का 18.82 *प्रतिशत* भगवती ट्रांसफार्मर कॉर्पोरेशन (जोन 1 और 27) को आपूर्ति की, जबकि आपूर्ति का औसत मूल्य 3.94 *प्रतिशत* था। इसके विपरीत भगवती ट्रांसफार्मर कॉर्प ने अपने स्टॉक का 50.97 *प्रतिशत* महादेव लिकर से खरीदा। विशेष रूप से, महादेव लिकर और भगवती ट्रांसफार्मर कॉर्प पारिवारिक संबंधों से संबद्ध हैं, जैसा कि **पैराग्राफ 8.4.3.1** में बताया गया है।

- शिव एसोशिएट्स ने अपने स्टॉक का 39.33 प्रतिशत पाथ2वे (जोन 12 और 25) को आपूर्ति की।

- रोहन ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने अपने स्टॉक का 18.39 *प्रतिशत* सैनिक इंडस्ट्रीज (जोन 17) को बेचा, जबकि आपूर्ति का औसत मूल्य 3.61 *प्रतिशत* है।

4. ब्रांड पुशिंग के जोखिम को उजागर करने वाले उदाहरण भी देखे गए जहां किसी विशेष ब्रांड का एक बड़ा हिस्सा (सांख्यिकीय आउटलायर) एक विशेष जोनल लाइसेंसधारी के माध्यम से बेचा गया था। किसी विशेष जोन के लिए ब्रांड की बिक्री सभी जोन में उस ब्रांड की कुल बिक्री की *प्रतिशतता* के रूप में होती है। यह विश्लेषण शीर्ष 100 बिकने वाले ब्रांडों (प्रत्येक 85,785 लीटर से अधिक की बिक्री) के लिए किया गया था, जो विचाराधीन अवधि में बेची गई कुल शराब का 95.25 *प्रतिशत* था। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जहां एक विशेष ब्रांड की 20 *प्रतिशत* से अधिक शराब एक ही जोन द्वारा बेची गई थी। ये उदाहरण जोनल लाइसेंसधारियों और शराब उत्पादों के घरेलू निर्माताओं के बीच संबंधों पर प्रकाश डालते हैं:

- ऐस फाइनेंस (जोन 22) ने रॉयल ग्रीन, डबल ब्लू, हाई इम्पैक्ट और एपिसोड व्हिस्की की क्रमशः 23.89 *प्रतिशत*, 75.64 *प्रतिशत*, 99.20 *प्रतिशत* और 54.61 *प्रतिशत* बिक्री की, सभी की आपूर्ति डीएम सेल्स द्वारा की गई और एडीएस स्पिरिट्स द्वारा निर्मित की गई। एडीएस स्पिरिट के अन्य अपेक्षाकृत कम बिकने वाले ब्रांड, जेनरेशन क्लासिक व्हिस्की और मूनवॉक वोदका भी लगभग विशेष रूप से ऐस फाइनेंस द्वारा बेचे गए थे। ऐस फाइनेंस ने डीएम सेल्स द्वारा आपूर्ति किए गए अन्य ब्रांडों (जैसे बी यंग बियर और गॉडफादर बियर) की 20 *प्रतिशत* से अधिक बिक्री भी की।

- दिल्ली लिकर द्वारा आपूर्ति किए गए सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांडों के लिए भी स्पष्ट पैटर्न उभर कर सामने आया है। रायसेन मार्केटिंग (जोन 13) ने सोम डिस्टिलर्स द्वारा निर्मित और दिल्ली लिकर द्वारा आपूर्ति की गई हंटर बियर और वुडपेकर बियर की 29.71 *प्रतिशत* और 77.65 *प्रतिशत* बिक्री की। इन दो संस्थाओं, रायसेन मार्केटिंग (रिटेलर) और सोम डिस्टिलरीज (निर्माता) के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के माध्यम से संबंध को भी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, जैसा कि अनुबंध XVI में बताया गया है।

- दिल्ली लिकर द्वारा आपूर्ति किए गए अन्य अधिक बिकने वाले ब्रांडों में वेव बियर और इवनिंग स्पेशल व्हिस्की का 80 *प्रतिशत* से अधिक स्टॉक

केवल तीन क्षेत्रों (रायसेन मार्केटिंग, मिलेनियम इंफ्रा और सैनिक इंडस्ट्रीज) द्वारा बेचा गया था।

- गौतम वाइन ने ओएसिस डिस्टिलरीज, ऑल सीजन्स व्हिस्की और बैच 9 व्हिस्की द्वारा निर्मित दो सबसे अधिक बिकने वाले ब्रांडों की आपूर्ति की, जिनमें से 39.59 *प्रतिशत* और 99.41 *प्रतिशत* केवल नोवा गारमेंट्स (जोन 11 और जोन 15) द्वारा बेचे गए थे। नोवा गारमेंट्स ने ओएसिस डिस्टिलरीज द्वारा निर्मित अन्य अपेक्षाकृत कम बिकने वाले उत्पादों में से 90 *प्रतिशत* से अधिक की बिक्री थी। इन दो संस्थाओं, नोवा गारमेंट्स (खुदरा विक्रेता) और ओएसिस डिस्टिलरीज (निर्माता) के बीच संबंध को भी कॉमन निदेशन के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, जैसा कि अनुबंध XVI में बताया गया है।
- यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स (जोन 19 और 29) ने एनवी डिस्टिलरीज द्वारा निर्मित पार्टी स्पेशल व्हिस्की की 46.67 *प्रतिशत* बिक्री की।
- एम्पायर अल्कोब्रेव द्वारा "ओल्ड हैबिट" और "बॉटम्स अप" ब्रांड नामों के तहत निर्मित चार ब्रांडों के लिए, चैनमीट लीजिंग (जोन 28) और ओरिजिन अप्लायंसेज (जोन 14 और 16) ने कुल आपूर्ति का 75 *प्रतिशत* से अधिक बेचा।

थोक और खुदरा लाइसेंस में संबंधित संस्थाओं के अस्तित्व के परिणामस्वरूप शराब के विभिन्न ब्रांडों का वितरण असमान हो गया। यह आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार उपभोक्ताओं को विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य के अनुरूप नहीं था।

8.5 लगभग ₹ 2,002.68 करोड़ की राशि का नुकसान

8.5.1 समय पर अनुमति न लेने के कारण लगभग ₹ 941.53 करोड़ के राजस्व का नुकसान

2007 में मास्टर प्लान दिल्ली (एमपीडी)-2021 के कार्यान्वयन से पहले, चार सरकारी निगमों को पिछले कुछ वर्षों में गैर-अनुरूप[49] क्षेत्रों में 116 खुदरा दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। एमपीडी-2021 ने मिश्रित भूमि उपयोग/गैर-अनुरूप क्षेत्रों में शराब

[49] गैर-अनुरूप क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो शराब की दुकानें खोलने के लिए भूमि उपयोग मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं।

की दुकानें खोलने पर रोक लगा दी है। तब से, गैर-अनुरूपता वाले क्षेत्रों में किसी भी नए खुदरा विक्रेता को अनुमति नहीं दी गई। 2016-17 तक केवल इन 116 खुदरा विक्रेताओं का नवीनीकरण किया गया था, जिसे आगे घटाकर 51 कर दिया गया और उनके लाइसेंस 31 मार्च 2021 तक नवीनीकृत किए गए।

समान कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वार्ड में कम से कम दो खुदरा दुकानें खोलना आबकारी नीति 2021-22 में अनिवार्य कर दिया गया था ताकि दिल्ली में असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों का कोई उदाहरण न हो। हालाँकि, निविदा दस्तावेज़ के अनुसार, दुकानें गैर-अनुरूप क्षेत्र में स्थित नहीं होनी थीं और यदि प्रस्तावित दुकान गैर-अनुरूप क्षेत्र में थी, तो उस पर सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ विचार किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि गैर-अनुरूप वार्डों में दुकानें खोली जानी थीं, विभाग ने निविदा देने से पहले इसके लिए तौर-तरीके तैयार करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की। वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति और लाइसेंस के नियम और शर्तों को 24 मई 2021 को मंजूरी दी गई थी। प्रारंभिक निविदा 28 जून 2021 को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) या दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से टिप्पणियां लिए बिना जारी की गई थी और इस मुद्दे के सुलझने से पहले ही अगस्त 2021 में लाइसेंस आवंटित कर दिया गया। दुकानें 17 नवंबर 2021 से परिचालन शुरू करने वाली थीं। हालांकि, डीडीए ने 16 नवंबर 2021 के पत्र के माध्यम से गैर-अनुरूप वार्डों में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी क्योंकि यह दिल्ली मास्टर प्लान की उद्देश्य के खिलाफ होगा।

लाइसेंसधारियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें 9 दिसंबर 2021 को 67 गैर-अनुरूप वार्डों में अनिवार्य दुकानों के संबंध में किसी भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने से छूट दे दी। इसके परिणामस्वरूप प्रति माह ₹ 114.50 करोड़ की लाइसेंस फीस से छूट मिली। एनआईटी के समक्ष गैर-अनुरूप क्षेत्रों में दुकानों के मुद्दे को न सुलझाने के परिणामस्वरूप यह छूट हुई और लगभग ₹ 941.53[50] करोड़ का संचयी नुकसान हुआ।

---

[50] कुछ दुकानों के लिए राजस्व एकत्र किया गया था, जो गलती से खोले गए थे, गैर-अनुरूपता में थोड़े समय के लिए थे। इस राशि की सटीक गणना करना मुश्किल है और इससे अनुमानित आंकड़े में बहुत ही सीमित सीमा तक ₹ 941.53 करोड़ की कमी हो सकती है।

8.5.2 सरेंडर जोनों की दोबारा निविदा नहीं की गई जिससे लगभग ₹ 890.15 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ

यह देखा गया कि 19[51] जोनल लाइसेंसधारियों ने अगस्त 2022 में नीति समाप्त होने से पहले, चार ने मार्च 2022 में, पांच ने मई 2022 में और दस ज़ोन ने जुलाई 2022 में अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे। हालांकि, इन जोनों में खुदरा बिक्री को चालू करने के लिए आबकारी विभाग द्वारा कोई पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप सरेंडर के बाद के महीनों में इन क्षेत्रों से लाइसेंस शुल्क के रूप में कोई आबकारी राजस्व अर्जित नहीं हुआ। विशेष रूप से, इन क्षेत्रों में शराब की खुदरा बिक्री जारी रखने के लिए कोई अन्य आकस्मिक व्यवस्था नहीं की गई थी।

इन क्षेत्रों से लाइसेंस शुल्क के कारण आबकारी विभाग को लगभग ₹ 890.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो उनके सरेंडर और पुनः निविदा में विभाग की विफलता के कारण हुआ। आबकारी राजस्व की हानि की गणना उन महीनों[52] के लिए वास्तविक लाइसेंस शुल्क के आधार पर जिनमें सरेंडर किए गए जोन गैर-परिचालित थे और गैर-अनुरूप वार्डों के कारण दी गई छूट के लेखांकन के बाद की गई।

यह मुद्दा नई नीति को समय पर लागू करने में असमर्थता, अवधि के अंत में खुदरा लाइसेंस के बंद होने के बाद पुनः निविदा करने में असमर्थता और ऐसी स्थिति को समायोजित करने के लिए लाइसेंस के निबंधन और शर्तों में एक सक्षम खंड डालने में विफल रहने में विभाग के कुप्रबंधन को प्रतिबिंबित करता है।

8.5.3 जोनल लाइसेंसधारियों को कोविड के कारण छूट के अनियमित अनुदान के कारण ₹ 144 करोड़ के राजस्व का नुकसान

डीडीएमए के आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2021 और 4 जनवरी 2022 द्वारा जारी किए गए कोविड प्रतिबंधों के कारण लाइसेंस शुल्क में आनुपातिक छूट/कमी के लिए एल-7जेड लाइसेंसधारियों से आबकारी विभाग को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 06 जनवरी 2022 के अनुसरण में लाइसेंसधारियों

---

[51] जिन 10 व्यावसायिक संस्थाओं को दो-दो जोन दिए गए थे, उनमें से सात संस्थाओं ने मार्च 2022 या मई 2022 में एक-एक जोन सरेंडर कर दिया, जबकि संचालन के लिए दूसरे जोन को बरकरार रखा। एक लाइसेंसधारी ने जुलाई 2022 में दोनों जोन सरेंडर कर दिए और केवल दो संस्थाएं अगस्त 2022 में पॉलिसी अवधि के अंत तक दोनों जोन का संचालन जारी रख सकी।

[52] पांच महीने - चार लाइसेंसधारी, तीन महीने - पांच लाइसेंसधारी, एक महीना - दस लाइसेंसधारी।

द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें विभाग को इस संबंध में स्पष्ट एवं तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।

दिल्ली जीएनसीटी के आबकारी विभाग और वित्त विभाग ने अभ्यावेदन की जांच की थी और जांच के बाद, यह कहा गया:

1) 13 अगस्त 2021 के निविदा दस्तावेजों के खंड 27.1 में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यावसायिक जोखिम लाइसेंसधारी पर होगा।

2) बोली-पूर्व बैठक के दौरान, विभाग ने संभावित बोलीदाताओं को सूचित किया था कि निविदा दस्तावेजों में अप्रत्याशित घटना का कोई प्रावधान नहीं है और सरकार बाद में उचित आदेश जारी कर सकती है।

3) आबकारी विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिक्री के समय में कमी/सम-विषम नियमों के आधार पर दुकानें खोलने/सामाजिक मेलजोल पर प्रतिबंध और सप्ताहांत पर पूर्ण लॉकडाउन जैसे आधारों पर लाइसेंसधारियों की लाइसेंस फीस में कटौती के लिए निविदा दस्तावेज में कोई प्रावधान नहीं है। ये प्रतिबंध वाणिज्यिक जोखिमों की प्रकृति में हैं जैसा कि उपरोक्त उल्लिखित निविदा दस्तावेज़ के खंड 27.1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो लाइसेंस शुल्क में कमी के दावे को उसी तरह से उचित नहीं ठहराता है जैसे त्योहार/शादी के मौसम के दौरान बिक्री में वृद्धि लाइसेंसधारी से लाइसेंस शुल्क की मांग में वृद्धि को उचित नहीं ठहराता है। इसके अलावा, लाइसेंस शुल्क के भुगतान के संबंध में पिछले लॉकडाउन में एचसीआर खंड को सरकार द्वारा दी गई छूट की तुलना वर्तमान खुदरा लाइसेंस शुल्क से नहीं की जा सकती है क्योंकि दोनों लाइसेंस व्यवस्थाएं प्रकृति में पूरी तरह से अलग हैं।

4) इसके अलावा, आबकारी विभाग ने कहा कि 1 दिसंबर 2021 से 27 दिसंबर 2021 तक शराब की बोतलों की बिक्री की तुलना में 28 दिसंबर 2021 से 6 जनवरी 2022 की अवधि के दौरान शराब की बोतलों की बिक्री में नौ *प्रतिशत* की कमी आई है। हालांकि, बिक्री में कमी भी सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान औसत बिक्री में वृद्धि का भी अनुभव हुआ है। यह विश्लेषण भी निर्णायक नहीं है क्योंकि दिसंबर महीने के दौरान खोली गई दुकानों की संख्या अलग-अलग थी और धीरे-धीरे बढ़ती गई क्योंकि दिसंबर में अधिक से अधिक दुकानें खुलीं। इसलिए, कोविड प्रतिबंध के बहाने लाइसेंस शुल्क में छूट की

लाइसेंसधारियों की मांग में कोई दम नहीं है, क्योंकि कोविड प्रतिबंध अवधि के दौरान दिल्ली में शराब की बिक्री की मात्रा पर पूर्व-कोविड प्रतिबंध अवधि की तुलना में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

उपरोक्त कारणों से, आबकारी और वित्त विभागों ने प्रस्ताव दिया कि कोविड प्रतिबंधों के कारण लाइसेंस शुल्क में आनुपातिक छूट/कमी पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसी किसी भी परिस्थिति में लाइसेंस शुल्क में कमी के संबंध में निविदा दस्तावेज़ में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रस्ताव को विभाग के प्रभारी मंत्री ने खारिज कर दिया और 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 की अवधि के दौरान बंद दुकानों के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय लाइसेंसधारी को छूट देने को इस कारण से मंज़ूरी दे दी गई कि पिछले कोविड संबंधित लॉकडाउन अवधि के दौरान, सरकार ने रेस्तरां को आनुपातिक शुल्क माफी का लाभ दिया था। इससे सरकार को लगभग ₹ 144 करोड़ का नुकसान हुआ। लाइसेंस शुल्क के भुगतान के संबंध में पिछले लॉकडाउन में एचसीआर खंड को दी गई छूट की तुलना वर्तमान खुदरा लाइसेंस शुल्क से नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों लाइसेंस व्यवस्थाएं प्रकृति में पूरी तरह से अलग थी। इसके अलावा, कैबिनेट नोट संख्या 3003 (दिनांक 21.05.2021) के अनुसार कार्यान्वयन के समय किए गए किसी भी संशोधन को कार्यान्वयन के समय मंत्रीपरिषद के समक्ष रखा जा सकता है। हालाँकि, लाइसेंसधारियों को यह छूट मंत्रीपरिषद से मंज़ूरी लेने से पहले दी गई थी।

8.5.4 जोनल लाइसेंसधारियों से सुरक्षा जमा की गलत वसूली के परिणामस्वरूप लगभग ₹ 27 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ

निविदा शर्तों के खंड 3.1.3 में दिल्ली आबकारी नियमों के नियम 48(12) का संदर्भ दिया गया है और उल्लेख किया गया है कि "आनुपातिक वार्षिक लाइसेंस शुल्क के 25 *प्रतिशत* के बराबर" सुरक्षा जमा स्वीकृति पत्र जारी होने के सात दिनों के भीतर क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों द्वारा जमा किया जाना था। हालाँकि, दिल्ली आबकारी नियमों के नियम 48(12) में वार्षिक लाइसेंस शुल्क 25 *प्रतिशत* का उल्लेख है न कि आनुपातिक वार्षिक लाइसेंस शुल्क का।

आबकारी विभाग के पास सुरक्षा जमा जोनल लाइसेंसधारी द्वारा संभावित चूक के प्रति जोखिम कवर प्रदान करता है। वार्षिक लाइसेंस शुल्क को 25 *प्रतिशत* की राशि, संक्षेप में संभावित चूक परिदृश्य के प्रति तीन महीने के लिए जोखिम कवर प्रदान करता है अर्थात् यदि लाइसेंसधारी भुगतान में चूक करता है और एक महीने के अंत तक अपना

बकाया नहीं चुका पाता है, तो लाइसेंसधारी के प्रति दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है तथा ज़ोन के लिए दोबारा टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है या तीन महीने के भीतर ज़ोन में परिचालन जारी रखने के लिए वैकल्पिक विकल्प खोजा जा सकता है ताकि विभाग को परिचालन बंद होने पर छोड़े गए राजस्व के कारण हानि न उठानी पड़े।

चूँकि जोनल खुदरा परिचालन नवंबर के मध्य में ही शुरू हो सका, आबकारी नीति 2021-22 के रोलआउट में काफी देरी के बाद, नीति वर्ष 2021-22 केवल साढ़े चार महीने के लिए प्रभावी था। लाइसेंस शुल्क आनुपातिक आधार पर लिया गया था और सुरक्षा जमा आनुपातिक लाइसेंस शुल्क के 25 *प्रतिशत* की दर पर था। इस सुरक्षा कवर ने इसलिए केवल लगभग एक महीने के लिए जोखिम कवर सुनिश्चित किया। इस प्रकार, विभाग लाइसेंसधारी द्वारा चूक के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया। आबकारी विभाग ने 20 जनवरी 2022 को (कैबिनेट से मंजूरी लिए बिना) निर्णय लिया कि आबकारी वर्ष 2021-22 के अंत तक लाइसेंस शुल्क के भुगतान में किसी भी चूक के कारण लाइसेंस रद्द करने की कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे यदि लाइसेंसधारी ने अचानक परिचालन बंद कर दिया तो आबकारी राजस्व खोने का जोखिम बढ़ गया। बीच की अवधि में संचालन जारी रखने के लिए पुन: निविदा देने या व्यवहार्य विकल्प पता लगाने की व्यवहार्यता और भी कम थी।

लेखापरीक्षा में दो मामले देखे गए जहां ज़ोनल लाइसेंसधारियों ने अचानक लाइसेंस छोड़ दिया और सुरक्षा जमा के समायोजन के बाद भी लंबित लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने में विफल रहे। जोन 8 के मामले में, लाइसेंसधारी ने पूरा बकाया भुगतान किए बिना मार्च 2022 में परिचालन बंद कर दिया। आबकारी विभाग के अनुसार, 17 मार्च 2022 तक विभाग पर संचयी बकाया ₹ 47.46 करोड़ था और विभाग के पास सुरक्षा जमा केवल ₹ 30 करोड़ था, जिससे मार्च 2022 के अंत में वसूली योग्य ₹ 17.46 करोड़ रह गया। इसी प्रकार ज़ोन 30 के लाइसेंसधारी ने जुलाई 2022 के मध्य में परिचालन बंद कर दिया और आबकारी विभाग के अनुसार, सुरक्षा जमा के समायोजन के बाद ₹ 9.82 करोड़ लंबित थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27 करोड़ की संचयी राशि अप्राप्त रही।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि उपरोक्त दो क्षेत्रीय लाइसेंसधारियों से वसूली योग्य बकाया राशि, जैसा कि आबकारी विभाग द्वारा गणना की गई थी, सही नहीं थी और **पैराग्राफ 8.6.3** में चर्चा की गई है।

8.6 अन्य मुद्दे

8.6.1 सुपर प्रीमियम दुकानों के लिए निविदा जारी नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने का अवसर नहीं मिला

दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार, पांच सुपर प्रीमियम (एल7-एसपी1) वेंड के रूप में (सहायक उत्पादों को बेचने के लिए 10 *प्रतिशत* जगह के साथ 2500 वर्ग फुट के बड़े फर्श सहित) एक अलग निविदा के माध्यम से एकल इकाई को लाइसेंस जारी किए जाने थे। इन दुकानों का न्यूनतम लाइसेंस शुल्क दिल्ली में एक दुकान के औसत आरक्षित लाइसेंस शुल्क के ढाई गुना के बराबर होना था। इन दुकानों को पहले दिए गए समान खुदरा क्षेत्रों में एक या अधिक खुदरा दुकानों को सुपर प्रीमियम दुकानों में परिवर्तित करके खोला जाना था और तदनुसार लाइसेंस शुल्क के समायोजन करना था। हालाँकि, इन दुकानों के लिए टेंडरिंग नहीं की गई थी। इन सुपर प्रीमियम दुकानों के लिए निविदा देने में विभाग की विफलता के कारण इन दुकानों के लिए प्रस्तावित आरक्षित मूल्य के आधार पर इन दुकानों से अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क अर्जित करने का अवसर खो गया।

8.6.2 गैर-अनुरूपता वाले वार्डों में दुकानों को अनियमित खोलना

एमपीडी-2021 ने मिश्रित भूमि उपयोग/गैर-अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर रोक लगा दी है। कैबिनेट ने 5 नवंबर 2021 को गैर-अनुरूप वार्डों में दुकानें खोलने के लिए आबकारी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और इसे 15 नवंबर 2021 को उपराज्यपाल द्वारा इस शर्त के अधीन मंजूरी दे दी गई थी कि संबंधित एमसीडी और डीडीए से अनुमोदन अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच के लिए यादृच्छिक नमूने के माध्यम से चार जोन (जोन 3, 14, 23 और 25) का चयन किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन चार जोनों में से, जोन 23 की चार दुकानें गैर-अनुरूप वार्डों में खोली गई थीं। ज़ोन 23 में, तीन गैर-अनुरूपता वाले वार्ड 33एन, 30एस और 97एस थे। इन सभी चार वार्डों विवरण **अनुलग्नक XVII** में दिया गया है। विभाग ने खुदरा विक्रेताओं को डीडीए और एमसीडी से कोई अनुमोदन प्राप्त किए बिना गैर-अनुरूपता वाले वार्डों में इन चार दुकानों को खोलने की अनुमति दी थी।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि दिल्ली आबकारी अधिनियम, दिल्ली आबकारी नियमावली, निबंधन और शर्तें तथा आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुसार दुकानों के लिए परिसर की उपयुक्तता का आकलन करने हेतु प्रस्तावित दुकानों के निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण टीमों का गठन किया गया था। इन वार्डों में खोले गए सभी बकाया चार दुकानों का उल्लेख **अनुलग्नक XVII** में दिया गया है। निरीक्षण दल ने घोषणा की कि परिसर अनुरूप/वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- दो दुकानों (अनुलग्नक XVII की क्रम संख्या 1 और 2) के लिए आवेदनों में, लाइसेंसधारी ने स्वयं उल्लेख किया कि दुकान की भूमि उपयोग श्रेणी "मिश्रित भूमि उपयोग"/"आवासीय" थी। इसके अलावा, लाइसेंसधारी ने इन दुकानों के लिए सहायक दस्तावेजों के रूप में वाणिज्यिक सड़क/गली के शहरी विकास (यूडी) विभाग अधिसूचना प्रस्तुत की लेकिन लेखापरीक्षा ने देखा कि क्रम. सं. 1 में दुकान का स्थान लगभग 10 किमी दूर[53] था और क्रम. सं. 2 में दुकान का स्थान लगभग तीन किमी दूर[54] था।
- अनुलग्नक XVII के क्रमांक 3 में दुकान के लिए लाइसेंसधारी ने दुकान के वाणिज्यिक होने के प्रमाण के रूप में रूपांतरण शुल्क पर्ची जमा की थी, लेकिन इससे यह पुष्टि नहीं हुई कि वह रूपांतरण पर्ची मिश्रित भूमि उपयोग या वाणिज्यिक भूमि के लिए थी या नहीं। लाइसेंसधारी ने एमसीडी से यह बताने वाला कोई प्रमाण पत्र भी जमा नहीं किया कि दुकान वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

इन सभी चार दुकानों को जनवरी-फरवरी 2022 में एमसीडी द्वारा सील कर दिया गया था। निरीक्षण टीम द्वारा यह पता लगाने के तरीके से कि ये दुकानें अनुरूप क्षेत्र में स्थित थीं, स्पष्ट रूप से पता चलता है कि निरीक्षण टीम ने परिसर की अनुरूप क्षेत्र में स्थित होने की घोषणा करने से पहले उपर्युक्त दस्तावेजों की ठीक से जांच नहीं की थी।

8.6.3 लंबित लाइसेंस शुल्क राशि की गणना में विसंगतियाँ

निविदा शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारियों को अपना व्यवसाय शुरू करने वाले महीने की 7 तारीख तक लाइसेंस शुल्क का अग्रिम भुगतान करना आवश्यक था। समय पर शुल्क का भुगतान न करने पर देय राशि पर 12 *प्रतिशत* वार्षिक ब्याज और 0.1 *प्रतिशत*

[53] सेक्टर-18, रोहिणी से, जिसका संदर्भ यूडी विभाग अधिसूचना से लिया गया था

[54] मुख्य बदरपुर बाजार से जिसका संदर्भ यूडी विभाग अधिसूचना से लिया गया था

प्रति दिन की दर से जुर्माना भी देना होगा यदि चूक महीने के 15 वें दिन के बाद भी जारी रहता है तो महीने के आखिरी दिन तक सभी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी, लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और दो साल की अवधि के लिए किसी भी अन्य निविदा प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक लगा दी जाएगी।

जोन 8 और 30 के लाइसेंसधारियों ने क्रमशः 17 मार्च 2022 और 12 जुलाई 2022 को लाइसेंस शुल्क, ब्याज और जुर्माना सहित अपने लंबित बकाया का भुगतान किए बिना जोनल लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे। लेखापरीक्षा ने इन क्षेत्रों के संबंध में बकाया की गणना में विसंगतियां देखीं। जोन 8 के लिए, नवंबर और दिसंबर 2021 के महीने के लिए अनुरूप वार्डों के लाइसेंस शुल्क की लंबित राशि के ब्याज की गणना के दौरान, आबकारी विभाग ने 17 मार्च 2022 तक के ब्याज और जुर्माने की गणना नहीं की थी, जैसा कि अन्य महीनों के संबंध में किया गया था। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2022 के महीने के लिए, लाइसेंसधारी ने नियत तारीख से पहले आंशिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया था, लेकिन आंशिक रूप से भुगतान की गई राशि पर छः दिनों के ब्याज को गलती से बकाया में शामिल कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, फरवरी और मार्च 2022 के महीनों में, देय तिथि के बाद की तारीख के बजाय महीने की पहली तारीख से ब्याज लगाने के कारण बकाया राशि पर ब्याज की अधिक गणना हुई थी। गणना में त्रुटियों का निवल प्रभाव बकाया में ₹ 24.20 लाख का परिवर्द्धन था।

इसी प्रकार, ज़ोन 30 के मामले में, कुछ महीनों में, देय तिथि के बाद की अगली तारीख के बजाय महीने की पहली तारीख से ब्याज लगाने के कारण बकाया राशि पर ब्याज की अधिक गणना हुई थी। इसके परिणामस्वरूप बकाया राशि में ₹ 4.65 लाख की वृद्धि हुई।

8.6.4 निगरानी और विनियमन के लिए उपायुक्त (थोक परिचालन) का महत्वपूर्ण पद निर्दिष्ट नहीं किया गया

वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के खंड 3.1.11 के अनुसार "एक अधिकारी को उपायुक्त (थोक संचालन) के रूप में नामित किया जाएगा। अधिकारी की निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ होंगी:- (i) अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना, संचालन की निगरानी करना और थोक डीलरों की समग्र निगरानी सुनिश्चित करना, (ii) मांग आपूर्ति

पैटर्न की लगातार निगरानी करना, आपूर्ति के सामान्यीकरण को सुनिश्चित करना, (iii) निर्माताओं, विक्रेता मालिकों और थोक वितरकों द्वारा नकली और मिलावटी शराब की आपूर्ति को रोकना (iv) थोक विक्रेताओं द्वारा सभी विक्रेताओं के बीच स्टॉक का समान वितरण सुनिश्चित करना, (v) यह सुनिश्चित करना कि कोई भी थोक लाइसेंसधारी ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित न हो, (vi) यह सुनिश्चित करना कि थोक विक्रेताओं द्वारा किसी भी ब्रांडिंग उल्लंघन को प्रोत्साहित न किया जाए, (vii) वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के 4.6.2 के खंड ईएससीआईएमएस के तहत ट्रैक और ट्रेस सुनिश्चित करना"। उपायुक्त (थोक संचालन) की नियुक्ति के संबंध में भी प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उपायुक्त (थोक परिचालन) का पद एक महत्वपूर्ण पद था, जैसा कि नीति में स्पष्ट किया गया था। उपायुक्त (थोक संचालन) को निगरानी और विनियमन से संबंधित कई प्रकार के कार्य करने थे, जिसका शराब की गुणवत्ता, ब्रांड पुशिंग आदि पर प्रभाव पड़ता था। हालांकि, विभाग से प्राप्त उत्तर के अनुसार, "*थोक संचालन*" "उपायुक्त को कोई कार्य नहीं सौंपा गया था"। इस प्रकार, आबकारी वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी अधिकारी को उपायुक्त (थोक संचालन) के रूप में नामित नहीं किया गया था, जो नीति में प्रावधानों की गैर-अनुपालना की ओर इशारा करता है।

8.6.5 आपूर्ति की गई शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई

(i) गोदाम में प्रयोगशाला, विशेषरूप से ईएससीआईएमएस रिपोर्टों का बैच परीक्षण और अपलोड करना

दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 55(10) के अनुसार, प्रत्येक एल1 लाइसेंसधारी को निर्माता से प्राप्त की गई शराब के प्रत्येक बैच में विद्यमान घटिया शराब या नकली शराब की यादृच्छिक जांच करने के लिए अपने गोदामों में सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी और आपूर्ति में कोई भी घटिया शराब या नकली शराब पाए जाने पर निर्माताओं को अनिवार्य रूप से आबकारी विभाग को सूचित करना होगा। आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार, आबकारी विभाग को इस संबंध में अलग से मानक संचालन प्रक्रिया (दिशा-निर्देश) जारी करना था।

लाइसेंसधारियों को लाइसेंस लेने से पहले प्रयोगशालाएँ स्थापित करना आवश्यक था। हालाँकि, आबकारी विभाग ने 9 नवंबर 2021 को प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जबकि आबकारी नीति 17 नवंबर 2021 से लागू की जानी थी। लाइसेंसधारियों में से एक ने प्रतिनिधित्व किया था और प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए छः से आठ सप्ताह का समय मांगा था।

विभाग द्वारा आपूर्ति की गई शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने की आवश्यक पूर्व शर्त को दिशानिर्देश जारी करने में देरी के कारण आबकारी विभाग द्वारा लागू नहीं किया गया था। प्रयोगशाला की स्थापना के लिए लाइसेंसधारियों को शुरुआत में 16 जनवरी 2022 तक दो महीने के विस्तार अवधि की अनुमति दी गई थी, जबकि नीति में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त कोविड से संबंधित कारणों का हवाला देते हुए 31 मार्च 2022 तक का और विस्तार अवधि दी गई। इस विस्तार अवधि के बाद भी 62 गोदामों में से केवल 19[55] में ही प्रयोगशालाएँ स्थापित की गई और इन प्रयोगशालाओं में भी बैच परीक्षण शुरू नहीं किया गया था।

पांच एल-1 लाइसेंसधारियों (मैसर्स इंडोस्पिरिट्स, मैसर्स ब्रिंडको सेल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स महादेव लिकर, मैसर्स डीएम सेल्स और मैसर्स दिल्ली लिकर) में से प्रत्येक के एक गोदाम से संबंधित रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा परीक्षण जांच से पता चला कि प्रयोगशालाएँ 17 जनवरी 2022 से 29 मार्च 2022 के बीच अर्थात 61 से 132 दिनों की देरी के साथ स्थापित की गईं। आबकारी विभाग द्वारा इन प्रयोगशालाओं के निरीक्षण में और देरी हुई क्योंकि ये 15 मार्च 2022 और 4 अप्रैल 2022 के बीच किए गए थे, जिससे इन प्रयोगशालाओं में बैच परीक्षण में देरी हुई, क्योंकि निरीक्षण से पहले परीक्षण शुरू नहीं हो सका।

लाइसेंसधारियों को नियमित आधार पर नमूनों के सभी परीक्षण परिणामों का डेटा ईएससीआईएमएस पोर्टल पर अपलोड करना भी आवश्यक था। हालाँकि, परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने के लिए ईएससीआईएमएस मॉड्यूल को आबकारी वर्ष 2021-22 में कार्यात्मक नहीं बनाया गया था जो कार्यान्वयन के अधीन था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध

[55] 17 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 के बीच स्थापित

कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार, इस संबंध में अंतिम संचार दिनांक 20 जुलाई 2022 को था।

- इसके अलावा आबकारी विभाग का आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2021 के अनुसार, आयात परमिट मॉड्यूल अर्थात एल-1 लाइसेंसधारियों के शराब आयात करने के अधिकार को अवरुद्ध किया जाना था यदि प्रयोगशालाओं की स्थिति समाप्ति तिथि अर्थात 16 जनवरी 2022 तक प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसी तरह, दिनांक 16 मार्च 2022 के परिपत्र के अनुसार, परिवहन परमिट निर्माण को रोक दिया जाना था यदि 31 मार्च 2022 तक प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं होने पर लाइसेंसधारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान था और एल1 लाइसेंसधारी द्वारा प्रयोगशाला की स्थापना के बारे में आबकारी विभाग को सूचित नहीं किया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा को यह नहीं बताया कि 31 मार्च 2022 की विस्तारित समय सीमा के बाद भी प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं करने वाले लाइसेंसधारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी या नहीं।
- आबकारी वर्ष 2022-23 में एल1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम एवं शर्तों में, गोदाम में प्रयोगशाला की स्थापना से संबंधित प्रावधान को बरकरार नहीं रखा गया था। इस प्रकार, आबकारी वर्ष 2021-22 के दौरान गोदामों की प्रयोगशालाओं में बैच परीक्षण की आवश्यक शर्त को लागू नहीं किया गया था, और इसके अलावा वर्ष 2022-23 में गोदामों में प्रयोगशालाओं की महत्वपूर्ण आवश्यकता को नियम और शर्तों से हटा दिया गया था।

गोदामों और बैच परीक्षण में प्रयोगशालाओं की स्थापना की शर्तों को आबकारी वर्ष 2021-22 के नियमों, नीति और नियम और शर्तों में शामिल किया गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माताओं/डिस्टिलरी से प्राप्त शराब आवश्यक गुणवत्ता की हो और नकली शराब न भेजी जाए और दिल्ली, में उपभोक्ता घटिया शराब का सेवन न करें। दिल्ली में आपूर्ति की जाने वाली शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आबकारी विभाग के प्राथमिक उद्देश्य के अनुरूप है, अर्थात शराब की बिक्री और खपत को विनियमित करना, नियंत्रित करना और निगरानी करना।

हालाँकि, उपरोक्त सभी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां इन तथ्यों को बताती है कि आबकारी विभाग ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि गोदामों में प्रयोगशाला की स्थापना और बैच परीक्षण की आवश्यक आवश्यकता को लागू किया गया था, जैसा आबकारी वर्ष 2021-22 के लिए कि संशोधित आबकारी नियमों, आबकारी नीति और एल-1 के लिए नियम और शर्तों द्वारा अनिवार्य है।

(ii) अत्याधुनिक लैब का गठन नहीं किया गया

वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के खंड 4.6.4 के अनुसार, "नकली शराब की आपूर्ति एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए दिल्ली सरकार एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करेगी जो नकली और खराब शराब का पता लगाने में माहिर होगी। हालाँकि, आबकारी विभाग द्वारा कोई भी अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई जैसा कि आबकारी वर्ष 2021-22 की नीति में अनिवार्य है। इससे यह तथ्य और स्थापित हो गया कि विभाग द्वारा शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रावधानों को गंभीरता से नहीं लिया गया।

(iii) नमूना संग्रह के लिए विशेष टीमों का गठन नहीं किया गया

वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के खंड 4.6.3 के अनुसार, "नमूना संग्रह के लिए विशेष टीमों का गठन: अनुबंधित गोदामों, खुदरा विक्रेताओं, होटलों, क्लबों और रेस्तरां से व्यवस्थित रूप से नमूने लेने के लिए टीमों का गठन किया जाएगा"। ब्रांड और उसकी रिपोर्ट वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। किसी भी एल-1 लाइसेंस धारक या खुदरा दुकान के मालिक के पास नकली शराब पाई गई तो उसका पूरा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और लागू कानूनों के अनुसार आपराधिक कार्यवाही के अधीन होगा। उन्हें स्थायी रूप से ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और दिल्ली में काम करने से रोक दिया जाएगा और सद्भावपूर्वक इसकी जानकारी अन्य सभी राज्यों के आबकारी विभागों को प्रदान की जाएगी।

विभाग से नमूना संग्रहण के लिए विशेष टीमों के गठन के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। हालांकि कई अनुस्मारक के बावजूद लेखापरीक्षा को कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसलिए, लेखापरीक्षा द्वारा यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि आबकारी वर्ष 2021 22 के दौरान आबकारी विभाग द्वारा ऐसी विशेष टीमों का गठन किया गया था।

8.6.6 दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र में शराब की बिक्री और खुदरा दुकानों के भौगोलिक वितरण के रुझान

दिसंबर 2021 से अगस्त 2022 तक के नौ महीनों के दौरान बिक्री, जब नई नीति लागू रही, दिसंबर 2018 से अगस्त 2019[56] की तुलनीय अवधि के दौरान बेची गई ₹ 58.19 करोड़ बोतलों की तुलना में ₹ 64.82 करोड़ बोतलें थी। इस प्रकार, नई नीति में पिछली व्यवस्था की तुलना में लगभग 11.40 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गई। हालांकि, नई नीति ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के आधार पर अनुमानित बिक्री के आंकड़े पर अग्रिम राजस्व संग्रह के पक्ष में, प्रति बोतल के आधार पर राजस्व की वसूली और संग्रह को समाप्त कर दिया। बोली के माध्यम से अनुमानित राजस्व संग्रह पर जोर देने से खुदरा विक्रेताओं को सरकार को सहवर्ती राजस्व के बिना बिक्री की मात्रा (पैमाने की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ गहरी छूट के माध्यम से) बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिला।

आबकारी नीति 2021-22 की आधारशिलाओं में से एक गुणवत्तापूर्ण शराब तक पहुंच की सुविधा और अवैध बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए पूरी दिल्ली में शराब की खुदरा दुकानों का समान वितरण था। हालांकि यह उद्देश्य व्यवहार में पूरा नहीं हो सका क्योंकि **पैराग्राफ 8.5.1** में चर्चा की गई परिस्थितियों के कारण योजना के अनुसार दुकानें नहीं खोली जा सकीं। वास्तविक दुकान वितरण (फरवरी 2022) को **चार्ट 8.5** में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। सफेद रंग से चिह्नित वार्डों में एक भी दुकान नहीं थी और छायांकित रंग हल्के से अंधेरे तक पैमाने वाले वार्डों में 1 से 5 तक की दुकानें हैं।

[56] तुलना करने के लिए दिसंबर 2018 और अगस्त 2019 के बीच की अवधि का उपयोग किया गया है क्योंकि यह उन्हीं महीनों को शामिल करने वाली सबसे हाल ही की प्रासंगिक अवधि है, जिसके दौरान बिक्री कोविड-19 प्रेरित प्रतिबंधों के कारण प्रभावित नहीं हुई थी।

चार्ट 8.5: दिल्ली में दुकानों का भौगोलिक वितरण (फरवरी 2022)

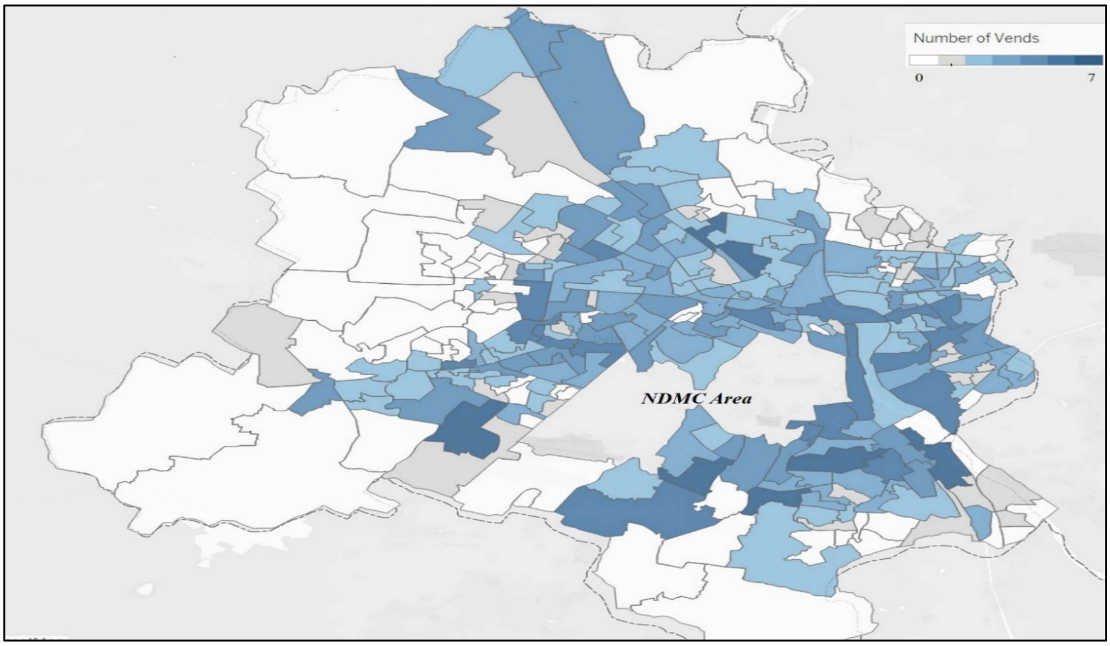

वितरण दर्शाता है कि कुछ वार्डों में बहुत अधिक शराब की खुदरा दुकानें थीं जबकि अन्य में कोई खुदरा दुकानें नहीं थीं।

8.6.7 आबकारी खुफिया ब्यूरो और जब्ती

आबकारी वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी खुफिया ब्यूरो (ईआईबी) और जब्ती का डेटा आबकारी विभाग से मांगा गया था। हालांकि कई अनुस्मारक के बावजूद लेखापरीक्षा को कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसलिए लेखापरीक्षा विभिन्न नशीले पदार्थों की अंतरराज्यीय तस्करी की जाँच के साथ-साथ अवैध शराब व्यापार का पता लगाने सहित ईआईबी के कामकाज की समीक्षा नहीं कर सका।

8.7 निष्कर्ष

आबकारी नीति 2021-22 में आबकारी शुल्क लगाने और संग्रह करने, शराब आपूर्ति श्रृंखला के प्रशासन और खुदरा संचालन के कवरेज से संबंधित कई मूलभूत परिवर्तन किए गए। वास्तविक नीति में ऐसे प्रावधान शामिल थे जो नीति में बदलाव के अंतर्निहित उद्देश्यों और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से भिन्न थे। राजस्व निहितार्थ वाले कुछ निर्णयों में मंत्रिपरिषद से आवश्यक अनुमति की कमी पाई गई। नई नीति डिजाइन के मुद्दों से भरी थी क्योंकि निर्माताओं और थोक विक्रेताओं के बीच थोपी गई विशिष्टता व्यवस्था और न्यूनतम 27 वार्डों के साथ प्रत्येक खुदरा क्षेत्र के गठन से एकाधिकार और कार्टेल गठन का खतरा बढ़ गया था।

वास्तविक कार्यान्वयन अपर्याप्त था और नीति के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये गये थे। गैर-अनुरूप वार्डों में दुकानें नहीं खोली जा सकीं और खुदरा दुकानों का समान वितरण नहीं हो सका। जोनल लाइसेंस के निर्गत और प्रबंधन में बड़ी कमियाँ थीं। व्यावसायिक निकायों के वित्तीय साधनों और प्रबंधन विशेषज्ञता के संबंध में जांच का अभाव था। शराब आपूर्ति श्रृंखला में लाइसेंस रखने वाले संबंधित व्यावसायिक निकायों के उदाहरण देखे गए। शराब आपूर्ति डेटा जोनल लाइसेंसधारियों और थोक विक्रेताओं के बीच विशिष्टता व्यवस्था और ब्रांड पुशिंग को इंगित करता है। विस्तारित नीति अवधि के दौरान जोनल लाइसेंस सरेंडर करने से राजस्व की भारी हानि हुई। नीति में योजनाबद्ध अन्य महत्वपूर्ण उपाय जैसे प्रयोगशालाओं की स्थापना और गुणवत्ता आश्वासन के लिए बैच परीक्षण, सुपर प्रीमियम दुकानों की स्थापना आदि को लागू नहीं किया गया। पाई गई त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली | **(अमन दीप चड्ढा)**

दिनांक: 03 मार्च 2024 | **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक: 04 मार्च 2024 | **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

अनुलग्नक

अनुलग्नक I
(पैराग्राफ 1.4 में संदर्भित)
नमूनीकृत

वर्ग	लाइसेंस के प्रकार	लाइसेंस के प्रकार का विवरण	अद्‌वितीय लाइसेंसधारियों की संख्या (2017-21)	नमूनीकृत मानदंड (सरल याद्दच्छिक नमूनीकृत के अनुसार प्रतिशत चयन)	विस्तृत जांच के लिए चयनित लाइसेंसधारियों की संख्या	विस्तृत जांच के लिए चयनित लाइसेंसधारियों की संख्या (पूर्णांक करने के बाद)	2017-21 के दौरान चयनित लाइसेंसधारियों के कुल लाइसेंस	लेखापरीक्षा को फ़ाइलें (विस्तृत जांच के लिए चयनित लाइसेंसधारियों की संख्या से संबंधित) प्रदान की गईं फाईल
आईएमएफएल और एफएल के निर्माता और बॉण्डेड गोदाम	एल1 और एल31	भारतीय शराब	111	10%	11.1	11	44	11
	एल1एफ और एल32	विदेशी शराब	34	10%	3.4	3	12	3
आईएमएफएल और एफएल के खुदरा दुकानें	एल7	निजी दुकान	87	5%	4.35	4	16	4
	एल 10	निजी दुकान (शॉपिंग मॉल)	178	5%	8.9	9	36	8
	एल6	निगम दुकान	385	5%	19.25	19	76	8
होटल, क्लब और रेस्तरां (एचसीआर)	एल-17/16/15/28	स्वतंत्र रेस्तरां/रेस्तरां/होटल के कमरों/क्लबों में शराब की सेवा	1332	1%	13.32	13	52	12
कुल						**59**	**236**	**46**

अनुलग्नक II

(पैराग्राफ 2.2.2 में संदर्भित)

बिना स्कैनिंग के बिक्री के उच्च प्रतिशत वाले मामले

क्र.सं.	खुदरा दुकान का नाम (एल7/एल10)	बिना स्कैनिंग के बिक्री यानी एमएसआर गैप (लाख में)	स्कैनिंग के माध्यम से बिक्री (लाख में)	स्कैनिंग के बिना बिक्री का प्रतिशत	रिपोर्टिंग की अवधि (2019)
1	ब्रूक्स मैगज़ीन प्राइवेट लिमिटेड	10.29	0.21	98	तीसरी तिमाही
2	वृन्दावन अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड	12.04	0.60	95	अगस्त, सितंबर और अक्टूबर
3	कविंदर	10.39	2.33	82	जनवरी से दिसंबर
4	प्रिस्टिन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	17.10	6.61	72	जनवरी से दिसंबर
5	दीप मोहन सिंह अरनेजा	13.69	3.60	79	जुलाई से दिसंबर
6	चितरंजन सूरी	7.35	1.05	88	तीसरी तिमाही
7	फॉर्च्यून प्लस मार्केटिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	23.83	4.97	83	जुलाई से दिसंबर
8	अशोक टी. गुलराजनी	12.06	2.85	81	तीसरी तिमाही
9	गोल्डनलाइन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	4.99	0.45	92	सितम्बर
10	सतीश कुमार अग्रवाल	6.32	2.74	70	तीसरी तिमाही
11	सुरिंदर गुप्ता	13.05	3.01	81	अप्रैल और मई
12	ग्लो इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड	8.60	1.12	88	अप्रैल और नवंबर
13	जॉय सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	1.76	0.05	97	जनवरी

अनुलग्नक III
(पैराग्राफ 3.2 में संदर्भित)
सामान्य निदेशक (समान वर्ष)

कंपनी समूह	क्र.सं.	सामान्य निदेशकों के नाम	डीआईएन	कंपनी / लाइसेंसधारी का नाम	लाइसेंस के प्रकार	सीआईएन / एलएलपीआईएन	लाइसेंस जारी करने की तारीख	लाइसेंस समाप्ति की तिथि	नियुक्ति की मूल तिथि	समाप्ति की तिथि
बडी- वीतराग	1	**2018-19**								
	1.1	**अमित अरोड़ा**	**01760784**	बडी (टी3 दिल्ली) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	एल10	U52590DL2008PTC178935	24 अप्रैल 2018	21 फरवरी 2019	1 मई 2013	18 जुलाई 2021
				बडी (पंजाब) बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड	एल1, एल31	U15129PB2016PTC045550	14 फरवरी 2019	15 अगस्त 2019	25 जुलाई 2016	16 अक्टूबर 2020
	2	**2019-20**								
	2.1	**अमित अरोड़ा**	**01760784**	बडी (टी3 दिल्ली) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	एल10	U52590DL2008PTC178935	21 फरवरी 2019	21 फरवरी 2020	1 मई 2013	18 जुलाई 2021
				बडी (पंजाब) बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड	एल1, एल31	U15129PB2016PTC045550	25 अक्टूबर 2019	25 जून 2020	25 जुलाई 2016	16 अक्टूबर 2020
एडी - एबी_ग्रेन	1	**2019-20**								
	1.1	**हरिंदर पाल सिंह भाटिया**	**00217313**	एडी ब्रॉस्वोन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	एल1, एल31	U74120DL2010PTC200149	16 अगस्त 2019	30 जून 2020	15 मार्च 2010	-
				एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	एल1, एल31	U15500PB2005PTC027841	14 जनवरी 2020	30 जून 2020	24 अगस्त 2005	-
	1.2	**जसदीप कौर चड्ढा**	**00096530**	एडी ब्रॉस्वोन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	एल1, एल31	U74120DL2010PTC200149	16 अगस्त 2019	30 जून 2020	19 नवंबर 2012	-
				एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	एल1, एल31	U15500PB2005PTC027841	14 जनवरी 2020	30 जून 2020	19 नवंबर 2012	-
	2	**2020-21**								
	2.1	**हरिंदर पाल सिंह भाटिया**	**00217313**	एडी ब्रॉस्वोन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	एल1, एल31	U74120DL2010PTC200149	2 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	15 मार्च 2010	-
				एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	एल1, एल31	U15500PB2005PTC027841	13 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	24 अगस्त 2005	-

	2.2	**जसदीप कौर चड्ढा**	**00096530**	एडी ब्रॉस्वोन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	एल1, एल31	U74120DL2010PTC200149	2 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	19 नवंबर 2012	-
				एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	एल1, एल31	U15500PB2005PTC027841	13 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	19 नवंबर 2012	-
इंडोस्पिरिट - एटूजेड	1	**2017-18**								
	1.1	**समीर महेंद्रू**	**00860038**	इंडोस्पिरिट बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	एल1, एल31	U15100DL2014PTC263174	2 फरवरी 2018	9 अगस्त 2018	7 जनवरी 2014	28 जून 2019
				इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	एल1एफ, एल32	U51909DL2006PLC155940	6 फरवरी 2018	19 अगस्त 2018	28 नवंबर 2006	28 जून 2019
				इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	एचसीआर	U51220DL2014PTC263173	11 जुलाई 2017	27 फरवरी 2018	7 जनवरी 2014	9 दिसंबर 2017
	1.2	**नितिन कपूर**	**01847324**	ए टू जेड ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	एल10	U51909DL2004PTC130377	13 जून 2017	4 मई 2018	15 नवंबर 2007	9 दिसंबर 2017
				इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	एचसीआर	U51220DL2014PTC263173	11 जुलाई 2017	27 फरवरी 2018	2 मई 2016	12 जुलाई 2019
	1.3	**सुदर्शन लाल महेन्द्रू**	**02327811**	इंडोस्पिरिट बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	एल1, एल31	U15100DL2014PTC263174	2 फरवरी 2018	9 अगस्त 2018	9 दिसंबर 2017	19 जुलाई 2021
				इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	एल1एफ, एल32	U51909DL2006PLC155940	6 फरवरी 2018	19 अगस्त 2018	11 अगस्त 2008	15 जुलाई 2021
				इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	एल1एफ, एल32	U51228DL2014PTC262950	2 फरवरी 2018	18 सितंबर 2018	9 दिसंबर 2017	9 जुलाई 2018
	1.4	**गीतिका महेन्द्रू**	**00860061**	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड- नई दिल्ली	एल1एफ, एल32	U51909DL2006PLC155940	6 फरवरी 2018	19 अगस्त 2018	28 नवंबर 2006	-
				इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	एल1एफ, एल32	U51228DL2014PTC262950	2 फरवरी 2018	18 सितंबर 2018	1 जनवरी 2014	22 जुलाई 2019
				इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	एचसीआर	U51220DL2014PTC263173	11 जुलाई 2017	27 फरवरी 2018	7 जनवरी 2014	20 फरवरी 2018
	2	**2018-19**								
	2.1	**गीतिका महेन्द्रू**	**00860061**	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली	एल1एफ, एल32	U51909DL2006PLC155940	20 अगस्त 2018	15 अगस्त 2019	28 नवंबर 2006	-

				इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	एल1एफ, एल32	U51228DL2014PTC262950	19 सितंबर 2018	15 अगस्त 2019	1 जनवरी 2014	22 जुलाई 2019
	2.2	**राहुल तनेजा**	**08174880**	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	एल1एफ, एल32	U51228DL2014PTC262950	19 सितंबर 2018	15 अगस्त 2019	9 जुलाई 2018	16 फरवरी 2021
				ए टू जेड ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	एल10	U51909DL2004PTC130377	4 मई 2018	27 फरवरी 2019	9 जुलाई 2018	15 सितंबर 2018
	3	**2019-20**								
	3.1	**नितिन कपूर**	**01847324**	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	एल1एफ, एल32	U51228DL2014PTC262950	18 अक्टूबर 2019	30 जून 2020	3 मार्च 2020	13 मार्च 2021
				इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	एचसीआर	U51220DL2014PTC263173	1 अप्रैल 2019	31 मार्च 2020	2 मई 2016	12 जुलाई 2019

अनुलग्नक IV
(पैराग्राफ 3.2 में संदर्भित)
सामान्य निदेशक (पिछले पांच वर्ष)

I. बडी- वीतराग																
क्र.सं.	नाम	डीआईएन	लाइसेंस के प्रकार	कंपनी / लाइसेंसधारी का नाम	सीआईएन / एलएलपी आईएन	लाइसेंस की आरंभ तिथि	लाइसेंस समाप्ति की तिथि	लाइसेंस के आरंभ की तिथि मायनस 5 वर्ष	नियुक्ति की मूल तिथि	समाप्ति की तिथि	इस निदेशक का "अन्य" लाइसेंस प्रकार	"अन्य" कंपनी/लाइसेंसधारी का नाम	"अन्य" कंपनी सीआईएन / एलएलपीआईएन	"अन्य" कंपनी नियुक्ति की (मूल तिथि)	"अन्य" कंपनी (समाप्ति की तिथि)	क्या पिछले 5 वर्षों में "अन्य" कंपनी से जुड़े हैं?
	2018-19															
1																
1.1	**अमित अरोड़ा**	**01760784**	एल1/एल31	बडी (पंजाब) बॉटलर्स (पी) लिमिटेड	U15129PB2016PTC045550	14 फरवरी 2019	15 अगस्त 2019	15 फरवरी 2014	25 जुलाई 2016	16 अक्टूबर 2020	एल10	बडी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड,	U51228DL1989PTC035797	10 मई 2010	10 अप्रैल 2017	हाँ
											एल10	बडी (T3 दिल्ली) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U52590DL2008PTC178935	01 मई 2013	18 जुलाई 2021	हाँ
											एल10	बडी मंत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U93030DL2010PTC198501	29 जनवरी 2010	25 मई 2016	हाँ
1.2	**अश्वनी भाटिया**	**03386026**	एल1/एल31	बडी (पंजाब) बॉटलर्स (पी) लिमिटेड	U15129PB2016PTC045550	14 फरवरी 2019	15 अगस्त 2019	15 फरवरी 2014	10 अगस्त 2018	14 जुलाई 2021	एल10	बडी टी1 दिल्ली रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U52590DL2002PTC118181	30 मई 2012	13 दिसंबर 2017	हाँ
											एल10	बडी मंत्रा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U52599DL2009PTC195530	25 मई 2015	29 सितंबर 2017	हाँ

											एल10	वीट्रैग कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	U55100DL2004PTC130291	02 अगस्त 2013	24 मई 2016	हाँ
											एल10	बडी मंत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U93030DL2010PTC198501	14 सितंबर 2013	25 मई 2016	हाँ
	2019-20															
2																
2.1	**अमित अरोड़ा**	**01760784**	एल1/एल31	बडी (पंजाब) बॉटलर्स (पी) लिमिटेड	U15129PB2016PTC045550	25 अक्टूबर 2019	25 जून 2020	26 अक्टूबर 2014	25 जुलाई 2016	16 अक्टूबर 2020	एल10	बडी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड,	U51228DL1989PTC035797	10 मई 2010	10 अप्रैल 2017	हाँ
											एल10	बडी (टी3 दिल्ली) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U52590DL2008PTC178935	01 मई 2013	18 जुलाई 2021	हाँ
											एल10	बडी मंत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U93030DL2010PTC198501	29 जनवरी 2010	25 मई 2016	हाँ
2.2	**अश्वनी भाटिया**	**03386026**	एल1/एल31	बडी (पंजाब) बॉटलर्स (पी) लिमिटेड	U15129PB2016PTC045550	25 अक्टूबर 2019	25 जून 2020	26 अक्टूबर 2014	10 अगस्त 2018	14 जुलाई 2021	एल10	बडी टी1 दिल्ली रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U52590DL2002PTC118181	30 मई 2012	13 दिसंबर 2017	हाँ
											एल10	बडी मंत्रा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	U52599DL2009PTC195530	25 मई 2015	29 सितंबर 2017	हाँ
											एल10	वीतराग कंस्ट्रक्शन्स	U55100DL2004PTC130291	02 अगस्त 2013	24 मई 2016	हाँ

												प्राइवेट लिमिटेड				
											एल10	बडी मंत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड	U93030DL2010PTC198501	14 सितंबर 2013	25 मई 2016	हाँ

II. एडी-एबी ग्रेन

क्र.सं.	नाम	डीआईएन	लाइसेंस के प्रकार	कंपनी / लाइसेंसधारी का नाम	सीआईएन / एलएलपी आईएन	लाइसेंस की आरंभिक तिथि	लाइसेंस समाप्ति की तिथि	लाइसेंस की आरंभिक तिथि माइनस 5 वर्ष	नियुक्ति की मूल तिथि	समाप्ति की तिथि	इस निदेशक के "अन्य" प्रकार के लाइसेंस	"अन्य" कंपनी / लाइसेंसधारी का नाम	"अन्य" कंपनी सीआईएन / एलएलपीआईएन	"अन्य" कंपनी नियुक्ति की (मूल तिथि)	"अन्य" कंपनी (समाप्ति की तिथि)	क्या पिछले 5 वर्षों में "अन्य" कंपनी से जुड़े हैं?
	2017-18															
1																
1.1	**हरिंदर पाल सिंह भाटिया**	**00217313**	एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	05 जनवरी 2018	02 अगस्त 2018	06 जनवरी 2013	15 मार्च 2010	-	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	24 अगस्त 2005	-	हाँ
1.2	**जसदीप कौर चड्ढा**	**00096530**	एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	05 जनवरी 2018	02 अगस्त 2018	06 जनवरी 2013	19 नवंबर 2012	-	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	19 नवंबर 2012	-	हाँ
	2018-19															
2																

2.1	हरिंदर पाल सिंह भाटिया	00217313	एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	03 अगस्त 2018	15 अगस्त 2019	04 अगस्त 2013	15 मार्च 2010	-	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	24 अगस्त 2005	-	हाँ
2.2	जसदीप कौर चड्ढा	00096530	एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	03 अगस्त 2018	15 अगस्त 2019	04 अगस्त 2013	19 नवंबर 2012	-	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	19 नवंबर 2012	-	हाँ
	2019-20															
3																
3.1	गुरबीर सिंह बिंद्रा	02083854	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	14 जनवरी 2020	30 जून 2020	15 जनवरी 2015	19 अक्टूबर 2011	-	एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	19 अक्टूबर 2011	14 दिसंबर 2016	हाँ
3.2	हरिंदर पाल सिंह भाटिया	00217313	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	14 जनवरी 2020	30 जून 2020	15 जनवरी 2015	24 अगस्त 2005	-	एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	15 मार्च 2010	-	हाँ
			एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	16 अगस्त 2019	30 जून 2020	17 अगस्त 2014	15 मार्च 2010	-	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	24 अगस्त 2005	-	हाँ
3.3	जसदीप कौर चड्ढा	00096530	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	14 जनवरी 2020	30 जून 2020	15 जनवरी 2015	19 नवंबर 2012	-	एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	19 नवंबर 2012	-	हाँ

			एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	16 अगस्त 2019	30 जून 2020	17 अगस्त 2014	19 नवंबर 2012	-	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	19 नवंबर 2012	-	हाँ
	2020-21															
4																
4.1	**गुरबीर सिंह बिंद्रा**	**02083854**	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	13 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	15 जुलाई 2015	19 अक्टूबर 2011	-	एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	19 अक्टूबर 2011	14 दिसंबर 2016	हाँ
4.2	**हरिंदर पाल सिंह भाटिया**	**00217313**	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	13 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	15 जुलाई 2015	24 अगस्त 2005	-	एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	15 मार्च 2010	-	हाँ
		00217313	एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	02 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	04 जुलाई 2015	15 मार्च 2010	-	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	24 अगस्त 2005	-	हाँ
4.3	**जसदीप कौर चड्ढा**	**00096530**	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	13 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	15 जुलाई 2015	19 नवंबर 2012	-	एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	19 नवंबर 2012	-	हाँ

		00096530	एल1/एल31	एडी ब्रॉसवॉन ब्रुअरीज प्राइवेट लिमिटेड	U74120DL2010PTC200149	02 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	04 जुलाई 2015	19 नवंबर 2012	-	एल1/एल31	एबी ग्रेन स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड	U15500PB2005PTC027841	19 नवंबर 2012	-	हाँ

III. इंडोस्पिरिट-एटूजेड

क्र.सं.	नाम	डीआईएन	लाइसेंस के प्रकार	कंपनी / लाइसेंसधारी का नाम	सीआईएन / एलएलपी आईएन	लाइसेंस आरंभिक तिथि	लाइसेंस की समाप्ति तिथि	लाइसेंस आरंभिक तिथि माइनस 5 वर्ष	नियुक्ति की मूल तिथि	समाप्ति की तिथि	इस निदेशक का "अन्य" लाइसेंस प्रकार	"अन्य" कंपनी / लाइसेंसधारी का नाम	"अन्य" कंपनी सीआईएन/एलएलपीआईएन	"अन्य" कंपनी नियुक्ति की (मूल तिथि)	"अन्य" कंपनी (समाप्ति की तिथि)	क्या पिछले 5 वर्षों में "अन्य" कंपनी से जुड़े हैं?
	2017-18															
1																
1.1	**समीर महेंद्रू**	**00860038**	एल1, एल31	इंडोस्पिरिट बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड,	U15100DL2014PTC263174	02 फरवरी 2018	09 अगस्त 2018	03 फरवरी 2013	07 जनवरी 2014	28 जून 2019	एचसीआर	इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	U51220DL2014PTC263173	07 जनवरी 2014	09 दिसंबर 2017	हाँ
											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	01 जनवरी 2014	09 दिसंबर 2017	हाँ
											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	28 नवंबर 2006	28 जून 2019	हाँ

			एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	06 फरवरी 2018	19 अगस्त 2018	07 फरवरी 2013	28 नवंबर 2006	28 जून 2019	एचसीआर	इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	U51220DL2014PTC263173	07 जनवरी 2014	09 दिसंबर 2017	हाँ
											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	01 जनवरी 2014	09 दिसंबर 2017	हाँ
1.2	**सुदर्शन लाल महेन्द्रू**	**02327811**	एल1, एल31	इंडोस्पिरिट बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड,	U15100DL2014PTC263174	02 फरवरी 2018	09 अगस्त 2018	03 फरवरी 2013	09 दिसंबर 2017	19 जुलाई 2021	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	09 दिसंबर 2017	09 जुलाई 2018	हाँ
											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	11 अगस्त 2008	15 जुलाई 2021	हाँ
			एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	06 फरवरी 2018	19 अगस्त 2018	07 फरवरी 2013	11 अगस्त 2008	15 जुलाई 2021	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	09 दिसंबर 2017	09 जुलाई 2018	हाँ
			एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	02 फरवरी 2018	18 सितंबर 2018	03 फरवरी 2013	09 दिसंबर 2017	09 जुलाई 2018	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	11 अगस्त 2008	15 जुलाई 2021	हाँ
1.3	**गीतिका महेन्द्रू**	**00860061**	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	02 फरवरी 2018	18 सितंबर 2018	03 फरवरी 2013	01 जनवरी 2014	22 जुलाई 2019	एचसीआर	इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	U51220DL2014PTC263173	07 जनवरी 2014	20 फरवरी 2018	हाँ

										एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	28 नवंबर 2006	-	हाँ
			एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	06 फरवरी 2018	19 अगस्त 2018	07 फरवरी 2013	28 नवंबर 2006	-	एचसीआर	इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	U51220DL2014PTC263173	07 जनवरी 2014	20 फरवरी 2018	हाँ
										एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	01 जनवरी 2014	22 जुलाई 2019	हाँ
	2018-19														
2															
2.1	**समीर महेन्द्रू**	**00860038**	एल1, एल31	इंडोस्पिरिट बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड,	U15100DL2014PTC263174	10 अगस्त 2018	15 अगस्त 2019	11 अगस्त 2013	07 जनवरी 2014	28 जून 2019	एचसीआर	इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	U51220DL2014PTC263173	07 जनवरी 2014	09 दिसंबर 2017	हाँ
											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	01 जनवरी 2014	09 दिसंबर 2017	हाँ
											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	28 नवंबर 2006	28 जून 2019	हाँ
			एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन	U51909DL2006PLC155940	20 अगस्त 2018	15 अगस्त 2019	21 अगस्त 2013	28 नवंबर 2006	28 जून 2019	एचसीआर	इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	U51220DL2014PTC263173	07 जनवरी 2014	09 दिसंबर 2017	हाँ

				लिमिटेड - नई दिल्ली											
											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	01 जनवरी 2014	09 दिसंबर 2017	हाँ
2.2	**सुदर्शन लाल महेन्द्रू**	**02327811**	एल1, एल31	इंडोस्पिरिट बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड,	U15100DL2014PTC263174	10 अगस्त 2018	15 अगस्त 2019	11 अगस्त 2013	09 दिसंबर 2017	19 जुलाई 2021	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	09 दिसंबर 2017	09 जुलाई 2018	हाँ
											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	11 अगस्त 2008	15 जुलाई 2021	हाँ
			एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	20 अगस्त 2018	15 अगस्त 2019	21 अगस्त 2013	11 अगस्त 2008	15 जुलाई 2021	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	09 दिसंबर 2017	09 जुलाई 2018	हाँ
2.3	**गीतिका महेन्द्रू**	**00860061**	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	19 सितंबर 2018	15 अगस्त 2019	20 सितंबर 2013	01 जनवरी 2014	22 जुलाई 2019	एचसीआर	इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	U51220DL2014PTC263173	07 जनवरी 2014	20 फरवरी 2018	हाँ
											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	28 नवंबर 2006	-	हाँ

			एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	20 अगस्त 2018	15 अगस्त 2019	21 अगस्त 2013	28 नवंबर 2006	-	एचसीआर	इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	U51220DL2014PTC263173	07 जनवरी 2014	20 फरवरी 2018	हाँ
											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	01 जनवरी 2014	22 जुलाई 2019	हाँ
2.4	**राहुल तनेजा**	**08174880**	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	19 सितंबर 2018	15 अगस्त 2019	20 सितंबर 2013	09 जुलाई 2018	16 फरवरी 2021	एल10	एट्रूजेड ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड,	U51909DL2004PTC130377	09 जुलाई 2018	15 सितंबर 2018	हाँ
	2019-20															
3																
3.1	**नितिन कपूर**	**01847324**	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	18 अक्टूबर 2019	30 जून 2020	19 अक्टूबर 2014	03 मार्च 2020	13 मार्च 2021	एल10	एट्रूजेड ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड,	U51909DL2004PTC130377	15 नवंबर 2007	09 दिसंबर 2017	हाँ
											एचसीआर	इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	U51220DL2014PTC263173	02 मई 2016	12 जुलाई 2019	हाँ
3.2	**सुदर्शन लाल महेन्द्रू**	**02327811**	एल1, एल31	इंडोस्पिरिट बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड,	U15100DL2014PTC263174	20 अगस्त 2019	30 जून 2020	21 अगस्त 2014	09 दिसंबर 2017	19 जुलाई 2021	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	09 दिसंबर 2017	09 जुलाई 2018	हाँ
											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	11 अगस्त 2008	15 जुलाई 2021	हाँ

			एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	30 सितंबर 2019	30 जून 2020	01 अक्टूबर 2014	11 अगस्त 2008	15 जुलाई 2021	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	09 दिसंबर 2017	09 जुलाई 2018	हाँ
3.3	**गीतिका महेन्द्रू**	**0086 0061**	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	30 सितंबर 2019	30 जून 2020	01 अक्टूबर 2014	28 नवंबर 2006	-	एचसीआर	इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	U51220DL2014PTC263173	07 जनवरी 2014	20 फरवरी 2018	हाँ
											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	01 जनवरी 2014	22 जुलाई 2019	हाँ
3.4	**राहुल तनेजा**	**0817 4880**	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	18 अक्टूबर 2019	30 जून 2020	19 अक्टूबर 2014	09 जुलाई 2018	16 फरवरी 2021	एल10	एट्रूजेड ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड,	U51909DL2004PTC130377	09 जुलाई 2018	15 सितंबर 2018	हाँ
	2020-21															
4																
4.1	**नितिन कपूर**	**0184 7324**	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	17 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	19 जुलाई 2015	03 मार्च 2020	13 मार्च 2021	एल10	एट्रूजेड ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड,	U51909DL2004PTC130377	15 नवंबर 2007	09 दिसंबर 2017	हाँ
											एचसीआर	इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	U51220DL2014PTC263173	02 मई 2016	12 जुलाई 2019	हाँ
4.2	**सुदर्शन लाल महेन्द्रु**	**0232 7811**	एल1, एल31	इंडोस्पिरिट बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड,	U15100DL2014PTC263174	04 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	06 जुलाई 2015	09 दिसंबर 2017	19 जुलाई 2021	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	09 दिसंबर 2017	09 जुलाई 2018	हाँ

											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	11 अगस्त 2008	15 जुलाई 2021	हाँ
			एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	16 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	18 जुलाई 2015	11 अगस्त 2008	15 जुलाई 2021	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	09 दिसंबर 2017	09 जुलाई 2018	हाँ
4.3	**गीतिका महन्दरू**	**00860061**	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड - नई दिल्ली	U51909DL2006PLC155940	16 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	18 जुलाई 2015	28 नवंबर 2006	-	एचसीआर	इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड	U51220DL2014PTC263173	07 जनवरी 2014	20 फरवरी 2018	हाँ
											एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	01 जनवरी 2014	22 जुलाई 2019	हाँ
4.4	**राहुल तनेजा**	**08174880**	एल1एफ, एल32	इंडोस्पिरिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	U51228DL2014PTC262950	17 जुलाई 2020	31 मार्च 2021	19 जुलाई 2015	09 जुलाई 2018	16 फरवरी 2021	एल10	एट्रूजेड ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड,	U51909DL2004PTC130377	09 जुलाई 2018	15 सितंबर 2018	हाँ

अनुलग्नक V
(पैराग्राफ 3.2 में संदर्भित)
संदिग्ध एकाधिक खुदरा लाइसेंस

समूह सं.	वर्ष	लाइसेंस प्रकार	लाइसेंस आईडी	लाइसेंसधारी आईडी	लाइसेंसधारी का नाम	लाइसेंसधारी का पता	भुगतानकर्ता कोड
1	2019-20	एल7	एल7/2003/000026	9वीजी1	विनोद गर्ग	दुकान नंबर-07, डीडीए मार्केट ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक एवं पॉकेट बीसी, सीएससी शालीमार बाग, नई दिल्ली - 110088	5200031
	2019-20	एल7	एल7/2004/000038	9वीजी3	विनोद गर्ग	दुकान नंबर ए1/6, भजनपुरा, वज़ीराबाद रोड, नई दिल्ली - 110053	5200038
	2019-20	एल7	एल7/2004/000039	9वीजी4	विनोद गर्ग	17, 18 और 19 एशियन मार्केट पुष्प विहार, एमबी रोड, नई दिल्ली - 110017	5200039
2	2019-20	एल7	एल7/2004/000040	9एससी3	श्यामली चंदेल	दुकान नं.जी-1, जी-2, निधि प्लाजा, गुलाबी बाग, नई दिल्ली - 110052	5200040
	2019-20	एल7	एल7/2003/000029	9एससी1	श्यामली चंदेल 1	दुकान नंबर-29, हडसन लाइन्स, किंग्सवे कैंप, नई दिल्ली - 110009	5200027
	2019-20	एल7	एल7/2003/000030	9एससी2	श्यामली चंदेल 2	5419, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005	5200028
3	2019-20	एल7	एल7/2003/000012	9आरडी1	राम दिया 1	प्लॉट नंबर 2/724, बाबरपुर रोड, शाहदरा, नई दिल्ली - 110032	5200020
	2019-20	एल7	एल7/2003/000024	9आरडी2	रामदिया2	जी-3 एवं जी-4 ग्राउंड फ्लोर, 2286-87, आर्य समाज रोड करोल बाग , दिल्ली-110005	5200021
4	2019-20	एल7	एल7/2004/000044	9 बीपीएच	ब्रह्म प्रकाश	दुकान नं. 2,5,6, ग्राउंड फ्लोर, दुर्गा कॉम्पलेक्स, प्लॉट न-11, एलएससी, पॉकेट-बी, मयूर विहार, दिल्ली-110091	5200045
	2019-20	एल7	एल7/2004/000042	9बीपीआर	ब्रह्म प्रकाश	दुकान न. ए-2, पार्ट-2, खसरा न. 571, राजपार्क मेन सुल्तानपुर रोड़, सुल्तानपुरी, नई दिल्ली-110086	5200043
5	2019-20	एल10	एल10/2015/03002	पीवी02881	मनोज कुमार	एसओपी नंबर 2 और 2ए ग्राउंड फ्लोर-मॉल प्लॉट नंबर ए-1, नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा , दिल्ली - 110034 पर स्थित है	पीवी02728
	2019-20	एल10	एल10/2016/03396	पीवी03217	मनोज कुमार	दुकान नंबर जी-41,42, डब्ल्यू मॉल, प्लॉट नंबर-9, मंगलम प्लेस, सेक्टर-3 रोहिणी, दिल्ली-110085	पीवी04220

अनुलग्नक VI
(पैराग्राफ 4.2.1 में संदर्भित)
ईडीपी में विवेकाधीन वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप बिक्री में गिरावट के कारण आबकारी राजस्व में गिरावट

क्र.सं.	एल1 का नाम	ब्रांड	आकार (मि.ली.)	वर्ष	ईडीपी (प्रति पेटी ₹ में)	लैंडिड प्राईस (प्रति पेटी ₹ में)	लाभ मार्जिन (प्रति पेटी ₹ में)	प्रति बोतल डब्ल्यूएसपी (₹ में)	प्रति बोतल कुल आबकारी राजस्व (₹ में)	बेची गई पेटियों की कुल संख्या	बोतलों की कुल संख्या (प्रति पेटी में बोतलों की संख्या * xi)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(iix)
1	मोहन गोल्ड वॉटर	कार्ल्स एलीफेंट एसएस बियर (650 मि.ली.)	650 (बोतल*12)	2017-18	461	488.58	24.43	43.00	68.51	1,62,206	19,46,472
		कार्ल्स एलीफेंट एसएस बियर (650 मि.ली.)		2018-19	525	560.79	28.04	49.32	78.09	74,505	8,94,060
		कार्ल्स एलीफेंट एसएस बियर (650 मि.ली.)		2019-20	525	560.79	28.04	49.32	78.09	55321	6,63,852
		कार्ल्स एलिफेंट एसएस बियर (500 मि.ली. कैन)	500 (कैन*24)	2017-18	724	760.77	38.04	33.41	54.25	72,998	17,51,952
		कार्ल्स एलिफेंट एसएस बियर (500 मि.ली. कैन)		2018-19	857	906.38	45.32	39.78	63.78	26,901	6,45,624
		कैल्स एलिफेंट एसएस बियर (500 मि.ली. कैन)		2019-20	857	906.38	45.32	39.78	63.78	21,828	5,23,872

कुल आबकारी राजस्व (₹ में) (xii*x)	कुल लाभ (रिकॉर्ड के अनुसार) (₹ में) (viii*xi)	ईडीपी में बढ़ोतरी से लाभ (आधार वर्ष से अधिक) (₹ में) {(विशेष वर्ष की ईडीपी- उस ब्रांड के आधार वर्ष की ईडीपी)*xi}	लाभ मार्जिन में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ (₹ में) {(विशेष वर्ष का लाभ मार्जिन उस ब्रांड के आधार वर्ष का लाभ मार्जिन)*xi}	शुद्ध लाभ (₹ में) (xiv + xv)	एमआरपी (₹ में) प्रति बोतल	ईडीपी में वृद्धि के कारण आबकारी राजस्व में कमी (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (आधार वर्ष का कुल आबकारी राजस्व-ब्रांड के विशेष वर्ष का कुल आबकारी राजस्व)	ईडीपी में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ में वृद्धि (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (विशेष वर्ष का शुद्ध लाभ-उस ब्रांड के आधार वर्ष का शुद्ध लाभ)
(xiii)	(xiv)	(xv)	(xvi)	(xvii)	(xviii)	(xix)	(xx)
13,33,52,796.72	39,62,692.58			39,62,692.58	140		
6,98,17,145.40	20,89,120.20	47,68,320.00	2,68,963.05	68,57,440.20	160	6,35,35,651.32	28,94,747.62
5,18,40,202.68	15,51,200.84	35,40,544.00	1,99,708.81	50,91,744.84	160	8,15,12,594.04	11,29,052.26
9,50,43,396.00	27,76,843.92			27,76,843.92	110		
4,11,77,898.72	12,19,153.32	35,77,833.00	1,95,839.28	47,96,986.32	130	5,38,65,497.28	20,20,142.40
3,34,12,556.16	9,89,244.96	29,03,124.00	1,58,907.84	38,92,368.96	130	6,16,30,839.84	11,15,525.04

क्र.सं.	एल1 का नाम	ब्रांड	आकार (मि.ली.)	वर्ष	ईडीपी (प्रति पेटी) (₹ में)	लैंडिड प्राईस (प्रति पेटी) (₹ में)	लाभ मार्जिन प्रति पेटी (₹ में)	प्रति बोतल डब्ल्यूएसपी (₹ में)	प्रति बोतल कुल आबकारी राजस्व (₹ में)	बेची गई पेटियों की कुल संख्या	बोतलों की कुल संख्या (xi* एक पेटी में बोतलों की संख्या)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(iix)
2	**एम्पायर अल्कोब्रू**	ओल्ड हैबिट वोदका	750 (बोतल*12)	**2018-19**	1,088	1,147.59	57.38	100.66	179.21	42,653	5,11,836
				2019-20	1,277	1,337.16	66.86	117.25	192.63	35,464	4,25,568
		ओल्ड हैबिट XXX रम	750 (बोतल*12)	**2017-18**	899	956.34	47.82	83.93	165.95	94,537	11,34,444
				2018-19	993	1,052.31	52.62	92.33	172.53	54,793	6,57,516
				2019-20	1,135	1,194.73	59.74	104.79	182.58	66,753	80,1036

कुल आबकारी राजस्व (₹ में) (xii*x)	कुल लाभ (रिकॉर्ड के अनुसार) (₹ में) (viii*xi)	ईडीपी में वृद्धि के कारण लाभ (आधार वर्ष से अधिक) (₹ में) {(विशेष वर्ष की ईडीपी - उस ब्रांड के आधार वर्ष की ईडीपी)*xi}	लाभ मार्जिन में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ (₹ में) {(विशेष वर्ष का लाभ मार्जिन - उस ब्रांड के आधार वर्ष का लाभ मार्जिन)*xi}	शुद्ध लाभ (₹ में) (xiv+xv)	एमआरपी (₹ में)	ईडीपी में वृद्धि के कारण आबकारी राजस्व में कमी (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (आधार वर्ष का कुल आबकारी राजस्व -ब्रांड के विशेष वर्ष का कुल आबकारी राजस्व)	ईडीपी में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ में वृद्धि (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (विशेष वर्ष में शुद्ध लाभ-उस ब्रांड का विशेष वर्ष में शुद्धलाभ)
(xiii)	(xiv)	(xv)	(vix)	(xvii)	(xviii)	(xix)	(xx)
9,17,26,129.56	24,47,429.14			24,47,429.14	360		
8,19,77,163.84	23,71,123.04	67,02,696.00	3,36,198.72	90,73,819.04	400	97,48,965.72	66,26,389.90
18,82,60,981.80	45,20,759.34			45,20,759.34			
11,34,41,235.48	28,83,207.66	51,50,542.00	2,63,006.40	80,33,749.66	340	7,48,19,746.32	35,12,990.32
14,62,53,152.88	39,87,824.22	1,57,53,708.00	7,95,695.76	1,97,41,532.22	370	4,20,07,828.92	1,52,20,772.88

क्र.सं.	एल1 का नाम	ब्रांड	आकार (मि.ली.)	वर्ष	ईडीपी (प्रति पेटी) (₹ में)	लैंडिड प्राइस (प्रति पेटी) (₹ में)	लाभ मार्जिन (प्रति पेटी) (₹ में)	प्रति बोतल डब्ल्यूएसपी (₹ में)	प्रति बोतल कुल आबकारी राजस्व (₹ में)	बेची गई पेटियों की कुल संख्या	बोतलों की कुल संख्या (xi * प्रति पेटी बोतलों की संख्या)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(iix)
3	**एडीएस स्पिरिट्स**	जनरेशन डीलक्स ब्लेंडेड व्हिस्की_ टीजीडीबी	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2018-19**	2,967	3,035.90	151.79	265.89	309.11	4,656	55,872
				2019-20	3,262	3,325.11	166.26	291.2	325.47	1,768	21,216
		रॉयल ग्रीन डीलक्स ब्लेंडेड व्हिस्की_ आरजीडी	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2018-19**	1,321	1,384.96	69.25	121.43	195.95	10,89,501	1,30,74,012
				2019-20	1,518	1,575.88	78.79	138.14	209.23	10,69,033	1,28,28,396
		डबल ब्लू प्रीमियम ब्लेंडेड व्हिस्की	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2017-18**	943	1,004.15	50.21	88.11	169.27	42,100	5,05,200
				2018-19	989	1,051.96	52.6	92.3	172.57	33,129	3,97,548
				2019-20	1,328	1,385.31	69.27	121.46	195.92	18,705	2,24,460
		एपिसोड सुपीरियर ग्रेन व्हिस्की	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2017-18**	706	766.43	38.32	67.31	152.56	47,847	5,74,164
				2018-19	752	814.25	40.71	71.5	155.87	51,066	6,12,792
				2019-20	806	861.74	43.09	75.65	159.22	43,629	5,23,548

कुल आबकारी राजस्व (₹ में) (xii*x)	कुल लाभ (रिकॉर्ड के अनुसार) (₹ में) (viii*xi)	ईडीपी में वृद्धि के कारण लाभ (आधार वर्ष से अधिक) (₹ में) {(विशेष वर्ष की ईडीपी - उस ब्रांड के आधार वर्ष की ईडीपी)*xi}	लाभ मार्जिन में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ (₹ में) {(विशेष वर्ष का लाभ मार्जिन - उस ब्रांड के आधार वर्ष का लाभ मार्जिन)*xi}	शुद्ध लाभ (₹ में) (xiv+xv)	एमआरपी (₹ में)	ईडीपी में वृद्धि के कारण आबकारी राजस्व में कमी (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (आधार वर्ष का कुल आबकारी राजस्व - ब्रांड के विशेष वर्ष का कुल आबकारी राजस्व)	ईडीपी में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ में वृद्धि (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (विशेष वर्ष में शुद्ध लाभ विशेष ब्रांड का विशेष वर्ष में शुद्धलाभ)
(xiii)	(xiv)	(xv)	(vix)	(xvii)	(xviii)	(xix)	(xx)
1,72,70,593.92	7,06,734.24			7,06,734.24	750		
69,05,171.52	2,93,947.68	5,21,560.00	25,582.96	8,15,507.68	800	1,03,65,422.40	1,08,773.44
2,56,18,52,651.40	7,54,47,944.25			7,54,47,944.25	410		
2,68,40,85,295.08	8,42,29,110.07	21,05,99,501.00	1,01,98,574.82	29,48,28,611.07	450	-12,22,32,643.68	21,93,80,666.82
8,55,15,204.00	21,13,841.00			21,13,841.00	330		
6,86,04,858.36	17,42,585.40	15,23,934.00	79,178.31	32,66,519.40	340	1,69,10,345.64	11,52,678.40
4,39,76,203.20	12,95,695.35	72,01,425.00	3,56,517.30	84,97,120.35	450	4,15,39,000,.80	63,83,279.35
8,75,94,459.84	18,33,497.04			18,33,497.04	280		
9,55,15,889.04	20,78,896.86	23,49,036.00	1,22,047.74	44,27,932.86	290	-79,21,429.20	25,94,435.82
8,33,59,312.56	18,79,973.61	43,62,900.00	2,08,110.33	62,42,873.61	300	42,35,147.28	44,09,376.57

क्र.सं.	एल1 का नाम	ब्रांड	आकार (मि.ली.)	वर्ष	ईडीपी (प्रति पेटी) (₹ में)	लैंडिड प्राईस (प्रति पेटी) (₹ में)	लाभ मार्जिन (प्रति पेटी) (₹ में)	प्रति बोतल डब्ल्यूएसपी (₹ में)	प्रति बोतल कुल आबकारी राजस्व (₹ में)	बेची गई पेटियों की कुल संख्या	बोतलों की कुल संख्या (xi* प्रति पेटी में बोतलों की संख्या)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(iix)
4	**बडी (पंजाब) बॉटलर्स**	डायरेक्टर्स स्पेशल ब्लैक डीलक्स व्हिस्की	750 मि.ली.(बोतल*12)	**2018-19**	900	956.30	47.81	83.93	165.95	2722	32664
				2019-20	1043	1,099.55	54.98	96.46	175.92	7219	86628

कुल आबकारी राजस्व (₹ में) (xii*x)	कुल लाभ (रिकॉर्ड के अनुसार) (₹ में) (viii*xi)	ईडीपी में वृद्धि के कारण लाभ (आधार वर्ष से अधिक) (₹ में) {(विशेष वर्ष की ईडीपी - उस ब्रांड के आधार वर्ष की ईडीपी)*xi}	लाभ मार्जिन में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ (₹ में) {(विशेष वर्ष का लाभ मार्जिन - ब्रांड के आधार वर्ष का लाभ मार्जिन)*xi}	शुद्ध लाभ (₹ में) (xiv+xv)	एमआरपी (₹ में)	ईडीपी में वृद्धि के कारण आबकारी राजस्व में कमी (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (आधार वर्ष का कुल आबकारी राजस्व - उस ब्रांड के विशेष वर्ष का कुल आबकारी राजस्व)	ईडीपी में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ में वृद्धि (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (विशेष वर्ष में शुद्ध लाभ उस ब्रांड का विशेष वर्ष में शुद्धलाभ)
(xiii)	(xiv)	(xv)	(vix)	(xvii)	(xviii)	(xix)	(xx)
54,20,590.80	1,30,138.82			1,30,138.82	320		
1,52,39,597.76	3,96,900.62	10,32,317.00	51,760.23	14,29,217.62	350	-98,19,006.96	12,99,078.80

क्र.सं.	एल1 का नाम	ब्रांड	आकार (मि.ली.)	वर्ष	ईडीपी (प्रति पेटी) (₹ में)	लैंडिड प्राईस (प्रति पेटी) (₹ में)	लाभ मार्जिन (प्रति पेटी) (₹ में)	प्रति बोतल डब्ल्यूएसपी (₹ में)	बेची गई पेटियों आबकारी राजस्व (₹ में)	बेचे गए पेटी की कुल संख्या	बोतलों की कुल संख्या (xi * प्रति पेटी में बोतलों की संख्या)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(iix)
5	**एनवी डिस्टिलरीज**	पार्टी स्पेशल रेयर व्हिस्की	750 मि.ली.(बोतल*12)	**2017-18**	758	814.06	40.7	71.48	155.89	4,73,217	56,78,604
				2018-19	805	861.2	43.06	75.6	159.28	4,06,352	48,76,224
				2019-20	948	1,004.63	50.23	88.15	169.22	3,10,166	37,21,992
		पार्टी स्पेशल प्लैटिनम व्हिस्की	750 मि.ली.(बोतल*12)	**2017-18**	948	1,004.63	50.23	88.15	169.22	4,68,807	56,25,684
				2018-19	1,043	1,099.9	55	96.49	175.88	5,19,404	62,32,848
				2019-20	1,138	1,195.2	59.76	104.83	182.53	4,25,902	51,10,824
		ब्लू-मून प्रीमियम वोदका	750 मि.ली.(बोतल*12)	**2017-18**	948	1,004.63	50.23	88.15	169.22	64,262	7,71,144
				2018-19	1,090	1,147.05	57.35	100.62	179.26	41,277	4,95,324

				2019-20	1,280	1,337.62	66.88	117.29	192.58	26,960	3,23,520
		ब्लू मून प्रीमियम डुएट लाइम एन जिन	750 मि.ली.(बोतल*12)	**2017-18**	948	1,004.63	50.23	88.15	169.22	1,06,974	12,83,688
				2018-19	1,090	1,147.05	57.35	100.62	179.26	47,951	5,75,412
				2019-20	1,280	1,337.62	66.88	117.29	192.58	20,743	2,48,916
		क्रेज़ी रोमियो डीलक्स रम	750 मि.ली.(बोतल*12)	**2017-18**	948	1,004.63	50.23	88.15	169.22	4,496	53,952
				2018-19	1,090	1,147.05	57.35	100.62	179.26	18,517	2,22,204
				2019-20	1,280	1,337.62	66.88	117.29	192.58	17,661	2,11,932
		डिस्कवरी एलीट व्हिस्की	750 मि.ली.(बोतल*12)	**2018-19**	1,328	1,385.77	69.29	121.5	195.87	1,27,109	15,25,308
				2019-20	1,517	1,575.33	78.77	138.09	209.29	1,24,331	14,91,972
		ब्लू मून प्रीमियम एक्स्ट्रा ड्राई जिन	750 मि.ली.(बोतल*12)	**2018-19**	3,261	3,324.57	166.23	291.15	325.52	1,885	22,620
				2019-20	4,412	4,479.02	223.95	392.16	391.17	1568	18,816

कुल आबकारी राजस्व (₹ में) (xii*x)	कुल लाभ (रिकॉर्ड के अनुसार) (₹ में) (viii*xi)	ईडीपी में वृद्धि के कारण लाभ (आधार वर्ष से अधिक) (₹ में) {(विशेष वर्ष की ईडीपी - उस ब्रांड के आधार वर्ष की ईडीपी)*xi}	लाभ मार्जिन में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ (₹ में) {(विशेष वर्ष का लाभ मार्जिन - उस ब्रांड के आधार वर्ष का लाभ मार्जिन)*xi}	शुद्ध लाभ (₹ में) (xiv+xv)	एमआरपी (₹ में)	ईडीपी में वृद्धि के कारण आबकारी राजस्व में कमी (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (आधार वर्ष का कुल आबकारी राजस्व -ब्रांड के विशेष वर्ष का कुल आबकारी राजस्व)	ईडीपी में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ में वृद्धि (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (विशेष वर्ष में शुद्ध लाभ- विशेष ब्रांड का आधार वर्ष में शुद्धलाभ)
(xiii)	(xiv)	(xv)	(xvi)	(xvii)	(xviii)	(xix)	(xx)
88,52,37,577.56	1,92,59,931.90			1,92,59,931.90	290		
77,66,84,958.72	1,74,97,517.12	1,90,98,544.00	9,58,990.72	3,65,96,061.12	300	10,85,52,618.84	1,73,36,129.22
62,98,35,486.24	1,55,79,638.18	5,89,31,540.00	29,55,881.98	7,45,11,178.18	330	25,54,02,091.32	5,52,51,246.28
95,19,78,246.48	2,35,48,175.61			2,35,48,175.61	330		
1,09,62,33,306.24	2,85,67,220.00	4,93,43,380.00	24,77,557.08	7,79,10,600.00	350	-14,42,55,059.76	5,43,62,424.39
93,28,78,704.72	2,54,51,903.52	8,09,21,380.00	40,58,846.06	10,63,73,283.52	370	1,90,99,541.76	8,28,25,107.91
13,04,92,987.68	32,27,880.26			32,27,880.26	330		
8,87,91,780.24	23,67,235.95	58,61,334.00	2,93,892.24	82,28,569.95	360	4,17,01,207.44	50,00,689.69
6,23,03,481.60	18,03,084.80	89,50,720.00	4,48,884.00	1,07,53,804.80	400	6,81,89,506.08	75,25,924.54
21,72,25,683.36	53,73,304.02			53,73,304.02	330		
10,31,48,355.12	27,49,989.85	68,09,042.00	3,41,411.12	95,59,031.85	360	11,40,77,328.24	41,85,727.83
4,79,36,243.28	13,87,291.84	68,86,676.00	3,45,370.95	82,73,967.84	400	16,92,89,440.08	29,00,663.82
91,29,757.44	2,25,834.08			2,25,834.08	330		
3,98,32,289.04	10,61,949.95	26,29,414.00	1,31,841.04	36,91,363.95	360	-3,07,02,531.60	34,65,529.87
4,08,13,864.56	11,81,167.68	58,63,452.00	2,94,055.65	70,44,619.68	400	-3,16,84,107.12	68,18,785.60
29,87,62,077.96	88,07,382.61			88,07,382.61	410		
31,22,54,819.88	97,93,552.87	2,34,98,559.00	11,78,657.88	3,32,92,111.87	450	-1,34,92,741.92	2,44,84,729.26
73,63,262.40	3,13,343.55			3,13,343.55	800		
73,60,254.72	3,51,153.60	18,04,768.00	90,504.96	21,55,921.60	1000	3,007.68	18,42,578.05

क्र.सं.	एल1 का नाम	ब्रांड	आकार (मि.ली.)	वर्ष	ईडीपी (प्रति पेटी) (₹ में)	लैंडिड प्राइस (प्रति पेटी) (₹ में)	लाभ मार्जिन प्रति पेटी (₹ में)	प्रति बोतल डब्ल्यूएस पी (₹ में)	प्रति बोतल कुल आबकारी राजस्व (₹ में)	बेची गई पेटियों की कुल संख्या	बोतलों की कुल संख्या (xi* प्रति पेटी में बोतलों की संख्या)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(iix)
6	**रॉक एंड स्टोर्म**	डेनिस स्पेशल व्हिस्की	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2017-18**	948	1,004.35	50.22	88.13	169.24	9,47,325	1,13,67,900
				2018-19	1,043	1,099.64	54.98	96.47	175.91	8,11,205	97,34,460
				2019-20	1,138	1,194.92	59.75	104.81	182.56	6,38,645	76,63,740
		रिवोल्यूशन ओरिजनल वोदका	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2017-18**	901	957.21	47.86	84.01	165.86	41,663	4,99,956
				2018-19	1,090	1,146.78	57.34	100.59	179.29	24,688	2,96,256
				2019-20	1,280	1,337.35	66.87	117.27	192.61	15,337	1,84,044
		रिवोल्यूशन ग्रीन एप्पल वोदका	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2017-18**	901	957.21	47.86	84.01	165.86	39,955	4,79,460
				2018-19	1,090	1,146.78	57.34	100.59	179.29	27,007	3,24,084
				2019-20	1,280	1,337.35	66.87	117.27	192.61	13,491	1,61,892
		रिवोल्यूशन ड्यूट जिन एन लाइम	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2017-18**	901	957.21	47.86	84.01	165.86	27,105	3,25,260
				2018-19	1,090	1,146.78	57.34	100.59	179.29	16,743	2,00,916
				2019-20	1,280	1,337.35	66.87	117.27	192.61	4,808	57,696
		रिवोल्यूशन प्रीमियम XXX रम	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2017-18**	901	957.21	47.86	84.01	165.86	23,811	2,85,732
				2018-19	1,090	1,146.78	57.34	100.59	179.29	11,551	1,38,612
				2019-20	1,138	1,194.92	59.75	104.81	182.56	10,588	1,27,056
		बिग बॉस प्रीमियम व्हिस्की	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2017-18**	758	813.78	40.69	71.46	155.92	1,18,064	14,16,768
				2018-19	806	861.93	43.1	75.67	159.2	1,32,911	15,94,932

				2019-20	948	1,004.35	50.22	88.13	169.24	98,772	11,85,264
		ब्लू आईस प्योर ग्रेन वोदका	750 मि.ली. (बोतल*12)	2018-19	1,280	1,337.35	66.87	117.27	192.61	20,041	2,40,492
				2019-20	1,518	1,576.06	78.8	138.16	209.21	16,716	2,00,592
		ब्लू आईस ग्रीन एप्पल फ्लेवर्ड वोदका	750 मि.ली. (बोतल*12)	2018-19	1,470	1,527.92	76.4	133.94	205.94	19,231	2,30,772
				2019-20	1,708	1,766.63	88.33	154.83	222.53	19,088	2,29,056

कुल आबकारी राजस्व (₹ में) (xii*x)	कुल लाभ (रिकॉर्ड के अनुसार) (₹ में) (viii*xi)	ईडीपी में वृद्धि के कारण लाभ (आधार वर्ष से अधिक) (₹ में) {(विशेष वर्ष की ईडीपी - उस ब्रांड के आधार वर्ष की ईडीपी)*xi}	लाभ मार्जिन में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ (₹ में) {(विशेष वर्ष का लाभ मार्जिन -ब्रांड के आधार वर्ष का लाभ मार्जिन)*xi}	शुद्ध लाभ (₹ में) (xiv+xv)	एमआरपी (₹ में)	ईडीपी में वृद्धि के कारण आबकारी राजस्व में कमी (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (आधार वर्ष का कुल आबकारी राजस्व - विशेष ब्रांड के विशेष वर्ष का कुल आबकारी राजस्व)	ईडीपी में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ में वृद्धि (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (विशेष वर्ष में शुद्ध लाभ उस ब्रांड का आधार वर्ष में शुद्धलाभ)
(xiii)	(xiv)	(xv)	(vix)	(xvii)	(xviii)	(xix)	(xx)
1,92,39,03,396.00	4,75,74,661.50			4,75,74,661.50	330		
1,71,23,88,858.60	4,46,00,050.90	7,70,64,475.00	38,61,335.80	12,16,64,525.90	350	21,15,14,537.40	7,40,89,864.40
1,39,90,92,374.40	3,81,59,038.75	12,13,42,550.00	60,86,286.85	15,95,01,588.75	370	52,48,11,021.60	11,19,26,927.25
8,29,22,702.16	19,93,991.18			19,93,991.18	320		
5,31,15,738.24	14,15,609.92	46,66,032.00	2,34,042.24	60,81,641.92	360	2,98,06,963.92	40,87,650.74
3,54,48,714.84	10,25,585.19	58,12,723.00	2,91,556.37	68,38,308.19	400	4,74,73,987.32	48,44,317.01
7,95,23,235.60	19,12,246.30			19,12,246.30	320		
5,81,05,020.36	15,48,581.38	51,04,323.00	2,56,026.36	66,52,904.38	360	2,14,18,215.24	47,40,658.08
3,11,82,018.12	9,02,143.17	51,13,089.00	2,56,463.91	60,15,232.17	400	4,83,41,217.48	41,02,985.87
5,39,47,623.60	12,97,245.30			12,97,245.30	320		
3,60,22,229.64	9,60,043.62	31,64,427.00	1,58,723.64	41,24,470.62	360	1,79,25,393.96	28,27,225.32
1,11,12,826.56	3,21,510.96	18,22,232.00	91,400.08	21,43,742.96	400	4,28,34,797.04	8,46,497.66

4,73,91,509.52	11,39,594.46			11,39,594.46	320		
2,48,51,745.48	6,62,334.34	21,83,139.00	1,09,503.48	28,45,473.34	360	2,25,39,764.04	17,05,878.88
2,31,95,343.36	6,32,633.00	25,09,356.00	1,25,891.32	31,41,989.00	370	2,41,96,166.16	20,02,394.54
22,09,02,466.56	48,04,024.16			48,04,024.16	290		
25,39,13,174.40	57,28,464.10	63,79,728.00	3,20,315.51	1,21,08,192.10	300	-3,30,10,707.84	73,04,167.94
20,05,94,079.36	49,60,329.84	1,87,66,680.00	9,41,297.16	2,37,27,009.84	330	2,03,08,387.20	1,89,22,985.68
4,63,21,164.12	13,40,141.67			13,40,141.67	400		
4,19,65,852.32	13,17,220.80	39,78,408.00	1,99,421.88	52,95,628.80	450	43,55,311.80	39,55,487.13
4,75,25,185.68	14,69,248.40			14,69,248.40	440		
5,09,71,831.68	16,86,043.04	45,42,944.00	2,27,719.84	62,28,987.04	490	-34,46,646.00	47,59,738.64

क्र.सं.	एल1 का नाम	ब्रांड	आकार (मि.ली.)	वर्ष	ईडीपी (प्रति पेटी) (₹ में)	लैंडिड प्राईस (प्रति पेटी) (₹ में)	लाभ मार्जिन प्रति पेटी (₹ में)	प्रति बोतल डब्ल्यूएसपी (₹ में)	प्रति बोतल कुल आबकारी राजस्व (₹ में)	बेची गई पेटियों की कुल संख्या	बोतलों की कुल संख्या (xi*प्रति पेटी में बोतलों की संख्या)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(iix)
7	**यूनाइटेड ब्रुअरीज**	किंगफिशर प्रीमियर लेजर बियर	650 मि.ली.(बोतल*12)	**2017-18**	333	342.88	17.14	30.25	49.45	7,91,489	94,97,868
				2018-19	406	416.1	20.8	36.66	58.94	6,74,272	80,91,264
				2019-20	406	416.1	20.8	36.66	58.94	5,15,976	61,91,712

कुल आबकारी राजस्व (₹ में) (xii*x)	कुल लाभ (रिकॉर्ड के अनुसार) (₹ में) (viii*xi)	ईडीपी में वृद्धि के कारण लाभ (आधार वर्ष से अधिक) (₹ में) {(विशेष वर्ष की ईडीपी - उस ब्रांड के आधार वर्ष की ईडीपी)*xi}	लाभ मार्जिन में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ (₹ में) {(विशेष वर्ष का लाभ मार्जिन - उस ब्रांड के आधार वर्ष का लाभ मार्जिन)*xi}	शुद्ध लाभ (₹ में) (xiv+xv)	एमआरपी (₹ में)	ईडीपी में वृद्धि के कारण आबकारी राजस्व में कमी (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (आधार वर्ष का कुल आबकारी राजस्व - विशेष वर्ष के उस ब्रांड का कुल आबकारी राजस्व)	ईडीपी में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ में वृद्धि (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (विशेष वर्ष में शुद्ध लाभ- विशेष वर्ष का उस ब्रांड का शुद्धलाभ)
(xiii)	(xiv)	(xv)	(vix)	(xvii)	(xviii)	(xix)	(xx)
46,96,69,572.60	1,35,66,121.46			1,35,66,121.46	100		
47,68,99,100.16	1,40,24,857.60	4,92,21,856.00	24,67,835.52	6,32,46,713.60	120	-72,29,527.56	4,96,80,592.14
36,49,39,505.28	1,07,32,300.80	3,76,66,248.00	18,88,472.16	4,83,98,548.80	120	10,47,30,067.32	3,48,32,427.34

क्र. सं.	एल1 का नाम	ब्रांड	आकार (मि.ली.)	वर्ष	ईडीपी प्रति पेटी (₹ में)	लैंडिड प्राईस प्रति पेटी (₹ में)	लाभ मार्जिन प्रति पेटी (₹ में)	प्रति बोतल डब्ल्यूएसपी (₹ में)	प्रति बोतल कुल आबकारी राजस्व (₹ में)	बेची गई पेटियों की कुल संख्या	बोतलों की कुल संख्या (xi * प्रति यूनिट में बोतलों की संख्या)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(iix)
8	**बकार्डी**	बकार्डी एप्पल डीलक्स ऑरिजिनल एप्पल रम	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2017-18**	2,176	2,242.44	112.12	196.46	255.92	4,313	51,756
				2018-19	2,366	2,433.01	121.65	213.14	269.23	4,403	52,836
				2019-20	2,698	2,766	138.3	242.28	292.59	4,634	55,608
		बकार्डी लिमोन डीलक्स ओरिजिनल साइट्रस रम	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2017-18**	2,176	2,242.44	112.12	196.46	255.92	15,625	1,87,500
				2018-19	2,366	2,433.01	121.65	213.14	269.23	19,108	2,29,296
				2019-20	2,698	2,766	138.3	242.28	292.59	23,709	2,84,508
		बकार्डी ऑरेंज डीलक्स ओरिजिनल ऑरेंज रम	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2017-18**	2,176	2,242.44	112.12	196.46	255.92	3,678	44,136

				2018-19	2,366	2,433.01	121.65	213.14	269.23	3,767	45,204
				2019-20	2,698	2,766	138.3	242.28	292.59	3,848	46,176
		बकार्डी कार्टा ब्लैंका सुपीरियर व्हाइट रम	750 मि.ली. (बोतल*12)	2018-19	2,602	2,670.99	133.55	233.96	285.92	27,049	3,24,588
				2019-20	2,697	2,766.27	138.31	242.3	292.57	28,867	3,46,404
		बकार्डी ब्लैक ओरिजिनल प्रीमियम क्राफ्टिड रम	750 मि.ली. (बोतल*12)	2018-19	1,273	1,338	66.9	117.32	192.55	35,692	4,28,304
				2019-20	1,368	1,433.28	71.66	125.66	199.21	58,245	6,98,940
		बकार्डी कार्टा ओरो सुपीरियर गोल्ड रम	750 मि.ली. (बोतल*12)	2018-19	2,744	2,813.41	140.67	246.42	295.97	1,788	21,456
				2019-20	2,851	2,920.73	146.04	255.81	302.52	1,875	22,500
		बकार्डी प्रीमियम + क्रैनबेरी	275 मि.ली. (बोतल*24)	2018-19	643	651.49	32.57	28.63	47.1	9,556	2,29,344
				2019-20	680	688.6	34.43	30.25	49.45	8,191	1,96,584
		बकार्डी प्रीमियम + लैमोनेड	275 मि.ली. (बोतल*24)	2018-19	643	651.49	32.57	28.63	47.1	5,581	1,33,944
				2019-20	680	688.6	34.43	30.25	49.45	4,485	1,07,640
		बकार्डी प्रीमियम + कोला	275 मि.ली. (बोतल*24)	2018-19	643	651.49	32.57	28.63	47.1	4,234	1,01,616
				2019-20	680	688.6	34.43	30.25	49.45	2,404	57,696
		बकार्डी प्रीमियम + ऑरेंज	275 मि.ली. (बोतल*24)	2018-19	643	651.49	32.57	28.63	47.1	7,102	1,70,448
				2019-20	680	688.6	34.43	30.25	49.45	5,852	1,40,448
		ब्रीज़र प्रीमियम ब्लैकबेरी क्रश	275 मि.ली. (बोतल*24)	2018-19	643	651.49	32.57	28.63	47.1	19,546	4,69,104
				2019-20	680	688.6	34.43	30.25	49.45	16,010	3,84,240
		ब्रीज़र प्रीमियम ब्लूबेरी	275 मि.ली. (बोतल*24)	2018-19	643	651.49	32.57	28.63	47.1	12,752	3,06,048
				2019-20	680	688.6	34.43	30.25	49.45	11,328	2,71,872
		ब्रेज़र प्रीमियम जमैका पैशन	275 मि.ली. (बोतल*24)	2018-19	643	651.49	32.57	28.63	47.1	26,091	6,26,184

				2019-20	680	688.6	34.43	30.25	49.45	22,572	5,41,728
		ब्रीज़र प्रीमियम ट्रॉपिकल क्रैनबेरी	275 मि.ली. (बोतल*24)	**2018-19**	643	651.49	32.57	28.63	47.1	36032	864768
				2019-20	680	688.6	34.43	30.25	49.45	30438	730512
		ब्रीज़र प्रीमियम ट्रॉपिकल ऑरेंज	275 मि.ली. (बोतल*24)	**2018-19**	643	651.49	32.57	28.63	47.1	20,860	5,00,640
				2019-20	680	688.6	34.43	30.25	49.45	19,159	4,59,816

कुल आबकारी राजस्व (₹ में) (xii*x)	कुल लाभ (रिकॉर्ड के अनुसार) (₹ में) (viii*xi)	ईडीपी में वृद्धि के कारण लाभ (आधार वर्ष से अधिक) (₹ में) {(विशेष वर्ष की ईडीपी - उस ब्रांड के आधार वर्ष की ईडीपी)*xi}	लाभ मार्जिन में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ (₹ में) {(विशेष वर्ष का लाभ मार्जिन - ब्रांड के आधार वर्ष का लाभ मार्जिन)*xi}	शुद्ध लाभ (₹ में) (xiv+xv)	एमआरपी (₹ में)	ईडीपी में वृद्धि के कारण आबकारी राजस्व में कमी (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (आधार वर्ष का कुल आबकारी राजस्व -उस ब्रांड के विशेष वर्ष का कुल आबकारी राजस्व)	ईडीपी में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ में वृद्धि (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (विशेष वर्ष में शुद्ध लाभ - उस ब्रांड का आधार वर्ष में शुद्धलाभ)
(xiii)	**(xiv)**	**(xv)**	**(vix)**	**(xvii)**	**(xviii)**	**(xix)**	**(xx)**
1,32,45,395.52	4,83,573.56			4,83,573.56	590		
1,42,25,036.28	5,35,624.95	8,36,570.00	41,960.59	13,72,194.95	630	-9,79,640.76	8,88,621.39
1,62,70,344.72	6,40,882.20	24,18,948.00	1,21,318.12	30,59,830.20	700	-30,24,949.20	25,76,256.64
4,79,85,000.00	17,51,875.00			17,51,875.00	590		
6,17,33,362.08	23,24,488.20	36,30,520.00	1,82,099.24	59,55,008.20	630	-1,37,48,362.08	42,03,133.20
8,32,44,195.72	32,78,954.70	1,23,76,098.00	6,20,701.62	1,56,55,052.70	700	-3,52,59,195.72	1,39,03,177.70
1,12,95,285.12	4,12,377.36			4,12,377.36	590		
1,21,70,272.92	4,58,255.55	7,15,730.00	35,899.51	11,73,985.55	630	-8,74,987.80	7,61,608.19
1,35,10,635.84	5,32,178.40	20,08,656.00	1,00,740.64	25,40,834.40	700	-22,15,350.72	21,28,457.04
9,28,06,200.96	36,12,393.95			36,12,393.95	680		
10,13,47,418.28	39,92,594.77	27,42,365.00	1,37,406.92	67,34,959.77	700	-85,41,217.32	31,22,565.82
8,24,69,935.20	23,87,794.80			23,87,794.80	400		

13,92,35,837.40	41,73,836.70	55,33,275.00	2,77,246.20	97,07,111.70	420	-5,67,65,902.20	73,19,316.90
63,50,332.32	2,51,517.96			2,51,517.96	710		
68,06,700.00	2,73,825.00	2,00,625.00	10,068.75	4,74,450.00	730	-4,56,367.68	2,22,932.04
1,08,02,102.40	3,11,238.92			3,11,238.92	95		
97,21,078.80	2,82,016.13	3,03,067.00	15,235.26	5,85,083.13	100	10,81,023.60	2,73,844.21
63,08,762.40	1,81,773.17			1,81,773.17	95		
53,22,798.00	1,54,418.55	1,65,945.00	8,342.10	3,20,363.55	100	9,85,964.40	1,38,590.38
47,86,113.60	1,37,901.38			1,37,901.38	95		
28,53,067.20	82,769.72	88,948.00	4,471.44	1,71,717.72	100	19,33,046.40	33,816.34
80,28,100.80	2,31,312.14			2,31,312.14	95		
69,45,153.60	2,01,484.36	2,16,524.00	10,884.72	4,18,008.36	100	10,82,947.20	1,86,696.22
2,20,94,798.40	6,36,613.22			6,36,613.22	95		
1,90,00,668.00	5,51,224.30	5,92,370.00	29,778.60	11,43,594.30	100	30,94,130.40	5,06,981.08
1,44,14,860.80	4,15,332.64			4,15,332.64	95		
1,34,44,070.40	3,90,023.04	4,19,136.00	21,070.08	8,09,159.04	100	9,70,790.40	3,93,826.40
2,94,93,266.40	8,49,783.87			8,49,783.87	95		
2,67,88,449.60	7,77,153.96	8,35,164.00	41,983.92	16,12,317.96	100	27,04,816.80	7,62,534.09
4,07,30,572.80	11,73,562.24			11,73,562.24	95		
3,61,23,818.40	10,47,980.34	11,26,206.00	56,614.68	21,74,186.34	100	46,06,754.40	10,00,624.10
2,35,80,144.00	6,79,410.20			6,79,410.20	95		
2,27,37,901.20	6,59,644.37	7,08,883.00	35,635.74	13,68,527.37	100	8,42,242.80	6,89,117.17

क्र.सं.	एल1 का नाम	ब्रांड	आकार (मि.ली.)	वर्ष	ईडीपी (प्रति पेटी) (₹ में)	लैंडिड प्राईस (प्रति पेटी) (₹ में)	लाभ मार्जिन (प्रति पेटी) (₹ में)	प्रति बोतल डब्ल्यूएसपी (₹ में)	प्रति बोतल कुल आबकारी राजस्व (₹ में)	बेचे गए पेटी की कुल संख्या	बोतलों की कुल संख्या (xi*प्रति पेटी में बोतलों की संख्या)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(iix)
9	**बत्रा ब्रुअरीज**	ऑफिसर्स चॉइस ब्लू डीलक्स ग्रेन व्हिस्की	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2017-18**	994	1,051.81	52.59	92.28	172.59	10,15,558	1,21,86,696
				2018-19	1,040	1,099.63	54.98	96.47	175.91	10,88,063	1,30,56,756
				2019-20	1,135	1,194.91	59.75	104.81	182.56	8,98,534	1,07,82,408
		जॉली रोजर प्रीमियम XXX रम	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2017-18**	899	956.53	47.83	83.95	165.93	43,941	5,27,292
				2018-19	945	1,004.35	50.22	88.13	169.24	36,643	4,39,716
				2019-20	1,277	1,337.34	66.87	117.27	192.61	12,686	1,52,232
		स्टर्लिंग रिजर्व बी7 रेयर ब्लैंडिड व्हिस्की	750 मि.ली. (बोतल*12)	**2018-19**	1,325	1,385.48	69.27	121.48	195.89	1,33,974	16,07,688
				2019-20	1,515	1,576.06	78.8	138.15	209.22	2,09,474	25,13,688

कुल आबकारी राजस्व (₹ में) (xii∗x)	कुल लाभ (रिकॉर्ड के अनुसार) (₹ में) (viii∗xi)	ईडीपी में वृद्धि के कारण लाभ (आधार वर्ष से अधिक) (₹ में) {(विशेष वर्ष की ईडीपी - उस ब्रांड के आधार वर्ष की ईडीपी)∗xi}	लाभ मार्जिन में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ (₹ में) {(विशेष वर्ष का लाभ मार्जिन - उस ब्रांड के आधार वर्ष का लाभ मार्जिन)∗xi}	शुद्ध लाभ (₹ में) (xiv+xv)	एमआरपी (₹ में)	ईडीपी में वृद्धि के कारण आबकारी राजस्व में कमी (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (आधार वर्ष का कुल आबकारी राजस्व - विशेष वर्ष के उस ब्रांड का कुल आबकारी राजस्व)	ईडीपी में वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ में वृद्धि (आधार वर्ष 2017-18) (₹ में) (विशेष वर्ष में शुद्ध लाभ - विशेष वर्ष में उस ब्रांड का शुद्धलाभ)
(xiii)	(xiv)	(xv)	(vix)	(xvii)	(xviii)	(xix)	(xx)
2,10,33,01,862.64	5,34,08,195.22			5,34,08,195.22	340		
2,29,68,13,947.96	5,98,21,703.74	5,00,50,898.00	26,00,470.57	10,98,72,601.74	350	-19,35,12,085.32	5,64,64,406.52
1,96,84,36,404.48	5,36,87,406.50	12,66,93,294.00	64,33,503.44	18,03,80,700.50	370	13,48,65,458.16	12,69,72,505.28
8,74,93,561.56	21,01,698.03			21,01,698.03	320		
7,44,17,535.84	18,40,211.46	16,85,578.00	87,576.77	35,25,789.46	330	1,30,76,025.72	14,24,091.43
2,93,21,405.52	8,48,312.82	47,95,308.00	2,41,541.44	56,43,620.82	400	5,81,72,156.04	35,41,922.79
31,49,30,002.32	92,80,378.98			92,80,378.98	410		
52,59,13,803.36	1,65,06,551.20	3,98,00,060.00	19,96,287.22	5,63,06,611.20	450	-21,09,83,801.04	4,70,26,232.22
		1,14,78,68,627.00				**1,65,00,00,706.32**	**1,13,90,18,501.85**

अनुलग्नक VII

(पैराग्राफ 5.3 में संदर्भित)

परीक्षण प्रयोगशालाओं का विवरण

क्र.सं.	प्रयोगशाला	टिप्पणी
1	बाली प्रयोगशाला	प्रयोगशाला एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं है
2	डियाजियो (इन-हाउस)	यूनाइटेड स्पिरिट्स टेक्निकल सेंटर (डियाजियो) एनएबीएल से मान्यता प्राप्त नहीं है डियाजियो इंडिया (एनएबीएल द्वारा अनुमोदित नहीं) (प्रयोगशाला यूनाइटेड स्पिरिट से संबंधित है)
3	एफआईसीसीआई अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, द्वारका	एनएबीएल मान्यता प्राप्त (अल्कोहल के परीक्षण के लिए)
4	इंटरस्टेलर परीक्षण केंद्र	एनएबीएल मान्यता प्राप्त (अल्कोहल के परीक्षण के लिए)
5	आईटीए लैब, गोवा	अल्कोहल पर जैविक विश्लेषण करने के लिए अधिकृत नहीं
6	जगदंबा लेबोरेटरीज, जयपुर	एनएबीएल मान्यता प्राप्त (अल्कोहल के परीक्षण के लिए)
7	सार्वजनिक विश्लेषक, पंजाब	सरकारी लैब, एनएबीएल अधिकृत नहीं
8	एसजीएस	एसजीएस, अल्कोहल पर परीक्षण करने के लिए अधिकृत नहीं है
9	श्री राम परीक्षण प्रयोगशालाएँ	एनएबीएल द्वारा अल्कोहल पर परीक्षण के लिए अधिकृत नहीं है
10	सामग्री विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	एनएबीएल मान्यता प्राप्त (अल्कोहल के परीक्षण के लिए)
11	वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट	अल्कोहल पर जैविक विश्लेषण करने के लिए अधिकृत नहीं है। परीक्षण का नमूना एलाइड ब्लेंडर्स औरंगाबाद द्वारा पुणे में प्रस्तुत किया गया है। नमूना मात्रा 1 लीटर है (संभवतः बैच से नहीं)
12	फेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	एनएबीएल मान्यता प्राप्त (अल्कोहल के परीक्षण के लिए)
13	दिल्ली विश्लेषणात्मक अनुसंधान प्रयोगशाला	एनएबीएल मान्यता प्राप्त (अल्कोहल के परीक्षण के लिए)
14	एजीएसएस विश्लेषणात्मक अनुसंधान प्रयोगशाला	एनएबीएल मान्यता प्राप्त (अल्कोहल के परीक्षण के लिए)
15	परिष्कृत औद्योगिक सामग्री विश्लेषणात्मक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	अल्कोहल पर रासायनिक विश्लेषण करने के लिए अधिकृत नहीं

अनुलग्नक VIII
(पैराग्राफ 5.4.1 में संदर्भित)
एल1 लाइसेंसधारियों की परीक्षण रिपोर्ट का विवरण

1. बीआईएस मानक (एल1) के कॉन्फार्मिंग परीक्षणों का अनुपालन

वर्ग	कंपनियों की संख्या	ब्रांडों की संख्या	बीआईएस के अनुसार किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या	बीआईएस के अनुसार वास्तव में किए गए परीक्षणों की संख्या	बिल्कुल नहीं किए गए परीक्षणों की संख्या	बीआईएस के अनुसार नहीं किया गया/आंशिक रूप से किया गया	पता लगाने की कोई सीमा नही/अस्पष्ट है
व्हिस्की	8	43	516	262	161	0	93
रम	5	27	378	262	104	9	3
बियर	3	31	356	169	171	16	0
जिन	2	9	126	50	40	6	30
वोदका	3	19	247	147	82	3	15
वाईन	1	8	160	36	111	13	0
कम अल्कोहल वाला पेय	2	36	540	281	194	0	61
	जोड़	**173**	**2323**	**1211**	**863**	**47**	**202**
			प्रतिशतता	**52%**	**37%**	**2%**	**9%**

2. पानी की गुणवत्ता का विवरण (एल1)

वर्ग	कंपनियों की संख्या	ब्रांड की संख्या	बीआईएस के अनुसार किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या	बीआईएस के अनुसार वास्तव में किए गए परीक्षणों की संख्या	नहीं किए गए परीक्षणों की संख्या	आंशिक रूप से किया गया
व्हिस्की	8	43	43	0	43	0
रम	5	27	27	0	21	6
बियर	3	31	31	0	31	0
वोदका	3	19	19	0	18	1
वाईन	1	8	8	0	8	0
कम अल्कोहल वाला पेय	2	36	36	0	36	0
जिन	2	9	9	0	9	0
		जोड़	**173**	**0**	**166**	**7**
				प्रतिशतता	**96%**	**4%**

3. सूक्ष्मजैविक परीक्षणों का विवरण (एल1)

वर्ग	कंपनी	ब्रांड	बीआईएस के अनुसार परीक्षणों की संख्या	वास्तव में किए गए परीक्षणों की संख्या	नहीं किये गये परीक्षणों की संख्या
बियर	3	31	31	6	25
वाईन	1	8	8	0	8
	जोड़	**39**	**39**	**6**	**33**
	प्रतिशतता			**15%**	**85%**

4. हानिकारक सामग्री का विवरण (एल1)

वर्ग	कंपनी	ब्रांड	बीआईएस के अनुसार किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या	वास्तव में किए गए परीक्षणों की संख्या	नहीं किये गये परीक्षणों की संख्या	बीआईएस के अनुसार नहीं/आंशिक रूप से किया गया
बियर	3	31	31	0	31	0
जिन	2	9	9	0	9	0
रम	5	27	27	0	24	3
वोदका	3	19	19	0	19	0
वाईन	1	8	8	0	8	0
कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थ	2	36	36	13	23	0
व्हिस्की	8	43	43	0	43	0
		जोड़	**173**	**13**	**157**	**3**
			प्रतिशतता	**8%**	**91%**	**2%**

5. मिथाइल अल्कोहल टेस्ट (एल1) का विवरण

वर्ग	कंपनी	ब्रांड	बीआईएस के अनुसार किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या	वास्तव में किए गए परीक्षणों की संख्या	नहीं किये गये परीक्षणों की संख्या	बीआईएस के अनुसार नहीं/आंशिक रूप से किया गया	पता लगाने की कोई सीमा नहीं/अस्पष्ट
बियर	3	31	31	29	2	0	
जिन	2	9	9	3			6
रम	5	27	27	26	1		
वोदका	3	19	19	15	1	0	3
वाईन	1	8	8	8			
कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थ	2	36	36	14	0		22
व्हिस्की	8	43	43	18			25
		जोड़	**173**	**113**	**4**	**0**	**56**
			प्रतिशतता	**65%**	**2%**	**0%**	**32%**

अनुलग्नक IX
(पैराग्राफ 5.4.2 में संदर्भित)
एल1एफ लाइसेंसधारी की परीक्षण रिपोर्ट का विवरण

1. परीक्षण रिपोर्ट का सारांश - बीआईएस/अंतर्राष्ट्रीय मानक (एल1एफ) के अनुसार परीक्षण

	परीक्षण रिपोर्ट की कुल संख्या	किये जाने वाले परीक्षणों की संख्या	किए गए परीक्षणों की संख्या, लेकिन बीआईएस/अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार नहीं किए गए	सही बीआईएस/अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार किए गए परीक्षणों की संख्या	नहीं किये गये परीक्षणों की संख्या	आंशिक रूप से किए गए परीक्षणों की संख्या	किए गए परीक्षणों की संख्या, जहां मूल्य/पहचान सीमा प्रस्तुत नहीं की गई है
व्हिस्की	130	1560	4	650	904	2	0
बियर	51	576	0	162	414	0	0
वाईन	127	2540	0	862	1675	3	0
रम	4	56	0	16	40	0	0
वोदका	26	338	0	106	231	1	0
जिन	15	210	0	86	124	0	0
जोड़	**353**	**5280**	**4**	**1882**	**3388**	**6**	**0**
प्रतिशतता			0.07%	35.64%	64.17%	0.11%	0.00%

2. परीक्षण रिपोर्ट का सारांश - स्वतंत्र लैब, रिपोर्ट अंग्रेजी में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मानक (एल1एफ)

	परीक्षण रिपोर्ट[1] की कुल संख्या	उन रिपोर्टों की संख्या जहां प्रयोगशाला स्वतंत्र नहीं है या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है	उन रिपोर्टों की संख्या जो अंग्रेजी में नहीं हैं (और इसलिए बीआईएस आदि के अनुसार परीक्षण परिणामों के सारांश में शामिल नहीं हैं)	आवेदन तिथि या परीक्षण तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुरानी रिपोर्टों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है	उन रिपोर्टों की संख्या जहां अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू नहीं किए गए/मानकों का उल्लेख नहीं किया गया या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई
व्हिस्की	130	98		69	88
बियर	51	46		22	40
वाईन	159	44	32	84	92
रम	4	2		2	2
वोदका	26	24		14	22
जिन	15	12		5	10
जोड़	**385**	**226**	**32**	**196**	**254**
प्रतिशतता		58.70%	8.31%	50.91%	65.97%

3. मिथाइल अल्कोहल टेस्ट (एल 1एफ) का विवरण

	परीक्षण रिपोर्ट[2] की कुल संख्या	मिथाइल जांच की गई
व्हिस्की	130	82
बियर	51	5
वाईन	127	27
रम	4	2
वोदका	26	19
जिन	15	11
	353	**146**
	मिथाइल परीक्षण डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया	**207**
		58.64%

[1] 32 परीक्षण रिपोर्ट जो कि अंग्रेजी में नहीं हैं सारांश में शामिल नहीं की गई है।

[2] 32 परीक्षण रिपोर्ट जो कि अंग्रेजी में नहीं हैं सारांश में शामिल नहीं की गई है।

4. माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट (एल1एफ) का विवरण

	परीक्षण रिपोर्ट की कुल संख्या	माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण किया गया	माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया	प्रतिशतता
बियर	51	11	40	78.43 %
वाईन	127	2	125	98.43 %
	178	**13**	**165**	

5. पुरानी परीक्षण रिपोर्ट का विवरण (एल1एफ)

	परीक्षण रिपोर्ट की कुल संख्या	कोई रिपोर्ट या पुरानी रिपोर्ट नहीं
व्हिस्की	130	18
बियर	51	7
वाईन	159	2
रम	4	2
वोदका	26	4
जिन	15	2
	385	**35**

अनुलग्नक X

(पैराग्राफ 7.2.2 (ii) में संदर्भित)

निरीक्षण रिपोर्ट में स्टॉक संबंधी टिप्पणियों का सारांश

क्र.सं.	लाइसेंस का प्रकार	केस संदर्भ (लाइसेंसी/निरीक्षण की तारीख)	निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां	क्या निरीक्षण रिपोर्ट में मुद्दों से संबंधित कोई टिप्पणी उल्लिखित है
1	एचसीआर	मैसर्स रोअर (31 अगस्त 2019)	1. पांच संदिग्ध शराब की बोतलें 2. बिना बारकोड वाली सात खाली बोतलें 3. पूरी बोतल परोसी 4. ब्रांड प्रमोशन	हाँ
2	एचसीआर	मैसर्स रोअर (13 अक्टूबर 2019)	1. अन्य विक्रेता की खाली बोतल 2. डीवीआर स्थापित नहीं किया गया था	नहीं (निरीक्षण के दौरान अन्य दुकानों की खाली बोतलें मिलने के बावजूद स्टॉक संबंधी समग्र मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं है)
3	एचसीआर	मैसर्स रोअर (28 मार्च 2021)	1. कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसना 2. पूरी बोतल परोसना 3. शराब की दुकान और बार काउंटर की औचक जांच की गई और वैध पाया गया 4. टीपी फ़ोल्डर को यादृच्छिक रूप से जांचा गया और वैध पाया गया 5. सीसीटीवी कैमरे मिले 6. सीट कवर स्वीकृत पाया गया	हाँ
4	एचसीआर	बाई द वे (18 अप्रैल 2019)	1. शराब के स्टॉक की यादृच्छिक जांच की गई और वैध पाया गया। 2. ब्रांड प्रमोशन 3. स्टॉक रजिस्टर संधारित 4. टीपी फ़ोल्डर क्रम में मिला	हाँ
5	एचसीआर	रास्ता (12 सितंबर 2016)	रेस्तरां के नाम परिवर्तन	नहीं
6	एचसीआर	रास्ता (23 सितंबर 2017)	1. बार काउंटर और स्टोर पर शराब की दुकान की यादृच्छिक जांच की गई और वैध पाया गया। 2. कोई एनडीपीएल और एक्सपायर्ड बोतल नहीं मिली 3. कम उम्र वालों को बेचने का कोई मामला नहीं मिला 4. कोई ब्रांड प्रचार नहीं 5. सीट कवर अनुमेय सीमा के अन्तर्गत थे 6. चेतावनी बोर्ड नहीं मिला 7. छत पर कोई सीट कवर नहीं 8. नाम परिवर्तन 9. सीसीटीवी कैमरा मिला 10. आग बुझाने वाले उपकरण मिले 11. स्टॉक रजिस्टर संधारित किया गया	हाँ

क्र.सं.	लाइसेंस का प्रकार	केस संदर्भ (लाइसेंसी/निरीक्षण की तारीख)	निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां	क्या निरीक्षण रिपोर्ट में मुद्दों से संबंधित कोई टिप्पणी उल्लिखित है
7	एचसीआर	रास्ता (25 नवंबर 2017)	1. नाम परिवर्तन 2. बार काउंटर और स्टोर पर शराब की यादृच्छिक जांच की गई और वैध पाया गया 3. स्वीकृत से अधिक सीट कवर मिले 4. दो बार काउंटर मिले 5. खुली छत पर शराब परोसी गई 6. कम उम्र के लोगों को शराब परोसने का कोई मामला नहीं मिला	हाँ
8	एचसीआर	रास्ता (17 फरवरी 2019)	1.कुल स्वीकृत 48 सीटें के प्रति सापेक्ष सीटों में 116 पाई गईं 2. छत पर शराब परोसी गई 3. दो परिचालन बार काउंटर 4. भंडारण क्षेत्र के बाहर मिली शराब 5. स्टॉक की रैंडम जांच के दौरान एक्सपायर्ड बियर मिली 6. ब्रांड प्रमोशन पाया गया	हाँ
9	एचसीआर	हॉल ऑफ फेम (5 सितंबर 2015)	1. रात 1:00 बजे के बाद शराब परोसी गई, प्रवेश शुल्क लगेगा 2. टीम ने बार काउंटर में पड़ी 20 शराब की बोतलों को एचएचटी के जरिए स्कैन किया; उन सभी बोतलों को वैध टीपी के माध्यम से पहुँचाया गया था	नहीं (टिप्पणी केवल बार काउंटर पर मिली शराब के लिए की गई है। दुकान पर मिली शराब के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।)
10	एचसीआर	हॉल ऑफ फेम (18 सितंबर 2016)	1. रेस्तरां के नाम परिवर्तन 2. अनुमत समय से परे संचालन 3. 17 बिना बारकोड वाली शराब की बोतलें	नहीं (बिना बारकोड वाली 17 शराब की बोतलें मिलने के बावजूद स्टॉक संबंधी समग्र मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं है)
11	एचसीआर	हॉल ऑफ फ़ेम (15 अक्टूबर 2017)	1. बार काउंटर और स्टोर पर शराब की दुकान की यादृच्छिक जांच की गई और वैध पाया गया। 2. कोई एनडीपीएल और एक्सपायर बोतल नहीं मिली 3. कम उम्र वालों को बेचने का कोई मामला नहीं मिला 4. ड्राई स्टोर एल-16 स्टोर के साथ जुड़ा हुआ था 5. सीट कवर अनुमेय सीमा के भीतर थे 6. चेतावनी बोर्ड नहीं मिला 7. नाम परिवर्तन 8. सीसीटीवी कैमरा मिला 9. फायर स्प्रिंकलर मिले 10. स्टॉक रजिस्टर संधारित किया गया	हाँ
12	एचसीआर	हॉल ऑफ फ़ेम (24 जनवरी 2018)	1. बार काउंटर और स्टोर पर शराब की दुकान की यादृच्छिक जांच की गई और वैध पाया गया। 2. कोई एनडीपीएल और एक्सपायर बोतल नहीं मिली 3. दो बार काउंटर मिले 4. ड्राई स्टोर एल-16 स्टोर के साथ जुड़ा हुआ था 5. सीट कवर अनुमेय सीमा के भीतर थे 6. कम उम्र वाले को बेचने का कोई मामला नहीं 7. नाम परिवर्तन 8. सीसीटीवी कैमरा मिला 9. स्टॉक रजिस्टर संधारित किया गया	हाँ

क्र.सं.	लाइसेंस का प्रकार	केस संदर्भ (लाइसेंसी/निरीक्षण की तारीख)	निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां	क्या निरीक्षण रिपोर्ट में मुद्दों से संबंधित कोई टिप्पणी उल्लिखित है
13	एचसीआर	हॉल ऑफ फेम (12 अप्रैल 2018)	1. रेस्तरां का नाम परिवर्तन 2. शराब के स्टॉक की याद्दच्छिक रूप से जांच की गई और पाया गया कि 200 बोतलें अन्य दुकानों से संबंधित हैं 3. कोई एनडीपीएल नहीं मिला 4. कम उम्र वालों को बेचने/परोसने का कोई मामला नहीं 5. सीट कवर अनुमेय सीमा के भीतर पाए गए 6. स्टॉक रजिस्टर संधारित किया गया	हाँ
14	एचसीआर	अनकल्चर्ड, (5 अप्रैल 2019)	1. शराब के स्टॉक की याद्दच्छिक जांच की गई और 47 एक्सपायर हो चुकी बीयरें मिलीं 2. दो बार काउंटर मिले 3. अतिरिक्त सीट कवर	हाँ
15	एचसीआर	अनकल्चर्ड, (1 जून 2019)	1. दो बार काउंटर मिले 2. अतिरिक्त सीट कवर मिले 3. तीसरी मंजिल पर खुले आसमान के नीचे शराब परोसी जाती थी 4. शराब के स्टॉक की याद्दष्छिक जांच की गई और वैध पाया गया 5. स्टॉक रजिस्टर संधारित किया गया 6. टीपी फोल्डर का रखरखाव किया गया	हाँ
16	एचसीआर	अनकल्चर्ड, (25 फरवरी 2021)	1. दूसरी और तीसरी मंजिल के लिए लाइसेंस स्वीकृत था लेकिन खुले क्षेत्र और ऊपरी छत पर शराब परोसी गई 2. अतिरिक्त सीट कवर मिले 3. दो बार काउंटर मिले 4. शराब के स्टॉक की याद्दच्छिक रूप से जांच की गई और अन्य दुकानों से संबंधित बोतलें पाई गईं 5. क्षतिग्रस्त बार कोड वाली बोतलें मिलीं	हाँ
17	एचसीआर	मेसर्स डीए कोड (2 दिसंबर 2018)	1. बंद होने का समय 2. कम उम्र में शराब पीना 3. अतिरिक्त सीट 4. कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं 5. निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इंकार	नहीं
18	एचसीआर	मेसर्स डीए कोड एल17- (13 जून 2019)	1. निरीक्षण में बाधा 2. समापन का समय. 3. एनडीपीएल 4. स्टॉक की याद्दष्छिक जांच के दौरान अन्य वेंड स्टॉक की बोतलें मिलीं 5. बिलिंग प्रणाली में छेड़छाड़	हाँ
19	एचसीआर	मैसर्स बारशाला (इंडोस्पिरिट्स बार्स प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई), 2, सामुदायिक केंद्र, ईस्ट ऑफ कैलाश- (16 अगस्त 2016)	1. विभिन्न ब्रांडों के निप्स और लघु बोतलें परोसी गई 2. स्टॉक की याद्दच्छिक जांच के दौरान "गोदाम" पर दर्शाई गई स्थिति वाली 12 बियर की बोतलें मिलीं 3. स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन न होना 4. ब्रांड प्रमोशन 5. सीसीटीवी फुटेज का न मिलना 6. बार काउंटर पर कोई वैधानिक चेतावनी नहीं	हाँ

क्र.सं.	लाइसेंस का प्रकार	केस संदर्भ (लाइसेंसी/निरीक्षण की तारीख)	निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां	क्या निरीक्षण रिपोर्ट में मुद्दों से संबंधित कोई टिप्पणी उल्लिखित है
20	एचसीआर	माई बार-एचक्यू-17/09/2016	1. सीट कवर ठीक है 2. स्टॉक की याद्दच्छिक रूप से जांच की गई और वैध पाया गया 3. अन्य विक्रेता बोतलें 4. सीसीटीवी मिला 5. अग्निशामक यंत्र मिले 6. कम उम्र का कोई मामला नहीं मिला	हाँ
21	एचसीआर	माई बार-एचक्यू- (24 नवंबर 2017)	दुकान के बाहर 50 पेटियां	नहीं
22	एचसीआर	माई बार-एचक्यू- (8 नवंबर 2019)	1.कम उम्र के लोगों को शराब परोसना 2. ब्रांड प्रमोशन 3. शराब बाहर रखना 4. स्टॉक की आकस्मिक जांच की गई और वैध पाया गया 5. स्टॉक रजिस्टर संधारित किया गया 6. टीपी फोल्डर का रखरखाव किया गया	हाँ
23	एचसीआर	माई बार-एचक्यू- (20 अक्टूबर 2020)	1.निरीक्षण रजिस्टर में छेड़छाड़ 2. ब्रांड प्रमोशन 3. सीट कवर सीमा के अंतर्गत थे 4. स्टॉक की आकस्मिक जांच की गई और वैध पाया गया।	हाँ
24	एचसीआर	माई बार-पहाड़गंज - (24 जुलाई 2016)	1. एक्सपायर्ड टीपी बोतलें 2. रेस्टोरेंट का नाम परिवर्तन	नहीं
25	एचसीआर	नुक्कड़ कैफे एवं बार (16 सितंबर 2017)	1. स्वीकृत 36 सीट कवर के स्थान पर खुले क्षेत्र सहित 48 सीट कवर 2. शराब के स्टॉक की याद्दष्छिक जांच की गई और वैध पाया गया	हाँ
26	एचसीआर	सफदरजंग एन्क्लेव (25 अगस्त 2020)	1.स्टॉक भिन्नता 2. अतिरिक्त स्टॉक	हाँ
27	एचसीआर	लार्ड ऑफ ड्रिंक (22 जनवरी 2020)	टीपी भौतिक रूप से प्राप्त हुई और केवल टीपी से संबंधित बोतल ही दुकान पर मौजूद थी जिसकी स्थिति "पारगमन में" दर्शायी जा रही थी।	नहीं (केवल एक्सपायर्ड टीपी से संबंधित स्टॉक की जांच की गई थी)
28	एचसीआर	इम्परफेक्टो (23 नवंबर 2019)	1. कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसना 2. विभिन्न भागो में विभिन्न नाम 3. दो स्थानों पर सीट कवर मिले 4. तीन बार काउंटर मिले 5. स्टाफ ने ग्राहक को पूरी बोतल परोसी 6. ब्रांड प्रमोशन 7. शराब के स्टॉक की याद्दष्छिक जांच की गई और वैध पाया गया	हाँ

अनुलग्नक XI
(पैराग्राफ 7.2.2 (iii) में संदर्भित)
संदिग्ध बोतलों की स्थिति (एचसीआर)

लाइसेंसधारी का प्रकार		होटल	क्लब	कुल योग
लाइसेंसधारियों की संख्या		9	1	10
उन निरीक्षणों की संख्या जिनमें बोतलें पाई गईं		11	1	12
संदिग्ध बोतलों की कुल संख्या		548	3044	3592
निरीक्षण रिपोर्ट/टीसीएस रिपोर्ट/कारण बताओ नोटिस के अनुसार संदिग्ध बोतलों की स्थिति	एमएसआर गैप/स्टॉक बेचा गया (लाइसेंसधारी द्वारा पहले बेचा गया घोषित)	0	0	0
	"गोदाम पर दिखाई गई" स्थिति	12	0	12
	"किसी अन्य दुकान पर बेची गई के रूप में दिखाई गई" की स्थिति	298	0	298
	बारकोड नहीं मिला	25	0	25
	क्षतिग्रस्त बारकोड/ स्कैन योग्य नहीं	6	0	6
	एक्सपायर्ड बोतलें	143	0	143
	बोतलें एक्सपायर्ड टीपी की हैं	7	0	7
	संदिग्ध बोतल (संदेह का कोई कारण नहीं बताया गया)	5	0	5
	जब्त की गई बोतले	0	0	0
	स्टॉक भिन्नता (अतिरिक्त बोतल मिली)	0	1	1
	स्टॉक भिन्नता (दुकान पर कम बोतल मिली)	0	3043	3043
	जांच के बाद नकली/डुप्लीकेट घोषित किए गए बारकोड की संख्या	0	0	0
	एनडीपीएल घोषित बोतलों की संख्या	52	0	52
	जब्त की गई बोतलों की संख्या	52	0	52

अनुलग्नक XII
(पैराग्राफ 7.2.4 (i) में संदर्भित)
संदिग्ध बोतलों की स्थिति (खुदरा विक्रेता)

लाइसेंसधारी का प्रकार		एल10	एल7	एल6	कुल
लाइसेंसधारियों की संख्या		2	2	3	**7**
निरीक्षणों की संख्या		5	2	3	**10**
संदिग्ध बोतलों की कुल संख्या		1391	6699	29	**8119**
निरीक्षण रिपोर्ट/टीसीएस रिपोर्ट/कारण बताओ नोटिस के अनुसार संदिग्ध बोतलों की स्थिति	एमएसआर गैप/स्टॉक बेचा गया (लाइसेंसधारी द्वारा पहले बेचा हुआ घोषित किया गया	869	763		**1632**
	अन्य दुकानों की बोतलें	15	0	0	**15**
	अमान्य/ईएससीआईएमएस का हिस्सा नहीं	21	1	0	**22**
	डिस्टिलरी से भेजा गया/बीडब्ल्यूएच पर प्राप्त/बीडब्ल्यूएच पर क्षतिग्रस्त	0	330	0	**330**
	बोतलें एक्सपायर्ड टीपी की हैं (दुकान पर उपलब्ध)	300	0	0	**300**
	निरीक्षण के समय पहले दुकान में बेचा सामान पाया गया	72	0	0	**72**
	एक्सपायर्ड बोतलें	120	75	0	**195**
	स्टॉक भिन्नता के रूप में दिखाया गया (अतिरिक्त स्टॉक मिला)	0	632	0	**632**
	स्टॉक भिन्नता (गुम स्टॉक)	0	4784	0	**4784**
	संदिग्ध बार कोड (समान 1डी और 2डी बारकोड/समान बारकोड वाली बोतलें/मुद्रित और स्कैन किए गए बारकोड समान नहीं)	0	55	0	**55**
	दुकान पर वापिस किया गया	0	59	0	**59**
	निम्न गुणवत्ता वाली शराब	0	0	4	**4**
	फर्जी ग्राहक को स्कैन किए बिना बेचा गया	0	0	1	**1**
	सीमा से अधिक शराब बेची गई (फर्जी ग्राहक को)	0	0	24	**24**
	सबूत के तौर पर या आगे की जांच के लिए जब्त की गई बोतलों की संख्या	1	48	4	**53**
	जांच के बाद एनडीपीएल/अवैध शराब घोषित	0	0	0	**0**
	जांच के बाद फर्जी घोषित किए गए बारकोड की संख्या	0	0	0	**0**
	निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित लेकिन एससीएन में नहीं ली गई बोतलों की संख्या	2	0	0	**2**

अनुलग्नक XIII
(पैरा 7.2.4 (iii) में संदर्भित)
अन्य विक्रेताओं को जारी एससीएन की स्थिति

क्र.सं	लाइसेंस का प्रकार	मामले का संदर्भ (लाइसेंसी/निरीक्षण की तारीख)	निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाया गया	क्या एससीएन अन्य शामिल लाइसेंसधारी को जारी किया गया है
1	एचसीआर	मैसर्स रोअर (13 अक्टूबर 2019)	अन्य दुकान की खाली बोतल, कोई डीवीआर स्थापित नहीं	कोई एससीएन जारी नहीं किया गया
2	एचसीआर	हॉल ऑफ फेम (12 अप्रैल 2018)	नाम परिवर्तन, 200 विदेशी विक्रेता बोतलें	कोई एससीएन जारी नहीं किया गया
3	एचसीआर	अनकल्चर्ड (25 फरवरी 2021)	खुली छत पर शराब परोसी गई, स्वीकृत क्षमता से अधिक सीटें, अतिरिक्त बार काउंटर, एक विदेशी विक्रेता की बोतल, आठ बारकोड नहीं मिले (संग्रहीत डेटा में खोजे जा रहे हैं), छह स्कैन अयोग्य /क्षतिग्रस्त बारकोड	कोई एससीएन जारी नहीं किया गया
4	एचसीआर	मेसर्स डीए कोड (13 जून 2019)	निरीक्षण में बाधा, बंद करने का समय, एनडीपीएल, अन्य वेंड स्टॉक, बिलिंग प्रणाली में छेड़छाड़	कोई एससीएन जारी नहीं किया गया
5	एचसीआर	मैसर्स बरशला (इंडोस्पिरिट्स बार्स प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई), 2 सामुदायिक केंद्र, ईस्ट ऑफ कैलाश (16 अगस्त 2016)	विभिन्न ब्रांडों के निप्स और मिनिएचर परोसना, "गोदाम" पर दिखाई गई स्थिति वाली 12 बियर की बोतलें, स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन न होना, ब्रांड प्रचार, सीसीटीवी फुटेज की अनुपलब्धता और बार काउंटर पर कोई वैधानिक चेतावनी नहीं (टीसीएस रिपोर्ट = रिपोर्ट के अनुसार 1 बोतल गोदाम में प्राप्त हुई थी, एक बोतल गोदाम में क्षतिग्रस्त हो गई थी और 10 बोतलें 29 नवंबर 2016 को बरशाला को बेची गई दिखाई गई थीं)	कोई एससीएन जारी नहीं किया गया
6	एल 10	बर्च होल्डिंग- (11 अक्टूबर 2017)	अन्य वेंड बोतल, एक्सपायर्ड बियर "अमान्य" बारकोड मामले	कोई एससीएन जारी नहीं किया गया
7	एल10	मेसर्स बिग वे एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (15 जून 2015)	व्हिस्की की पांच बोतलें स्कैन नहीं की जा सकीं (निरीक्षण दल ने कुछ रिकॉर्ड और परिवहन परमिट की जांच के आधार पर, निरीक्षण रिपोर्ट में इन बोतलों की स्थिति "एट वेंड" के रूप में दिखाई)	30 जून 2015 को मेसर्स ब्रिंडको सेल्स लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मेसर्स इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था।

अनुलग्नक XIV
(पैराग्राफ 7.2.5 में संदर्भित)
बार-बार होने वाले उल्लंघनों का सारांश

क्र.सं.	लाइसेंस का प्रकार	केस संदर्भ (लाइसेंसी/निरीक्षण की तारीख)	निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाया गया	जुर्माने की राशि	क्या भविष्य में इस विशेष लाइसेंसधारी के लिए इसी तरह के उल्लंघन नोट किए गए हैं?	भविष्य के निरीक्षण के दौरान नोट किए गए उल्लंघन	जुर्माने की राशि
1	एचसीआर	मैसर्स रोअर (31 अगस्त 2019)	पांच संदिग्ध शराब की बोतलें, बिना बारकोड वाली सात बोतलें, ब्रांड प्रमोशन, पूरी बोतल परोसी गई	₹ 31.88 लाख (लाइसेंस शुल्क के 100% के लिए ₹ 1.25 लाख और चौबीसों घंटे सेवा के लिए ₹ 10.63 लाख)	हाँ	पूरी बोतल परोसी गई (निरीक्षण दिनांक 28 मार्च 2021)	₹ 0.50 लाख
2	एचसीआर	रास्ता (12 सितंबर 2016)	रेस्तरां का नाम परिवर्तन	₹ 0.63 (लाइसेंस शुल्क का 10%)	हाँ	रेस्तरां का नाम परिवर्तन और वैधानिक चेतावनी का कोई प्रदर्शन नहीं (निरीक्षण दिनांक 23 सितंबर 2017) रेस्तरां का नाम परिवर्तन, खुली छत पर शराब परोसी गई, कुल सीटें स्वीकृत 48 के प्रति 128 थीं, दो चालू बार काउंटर (निरीक्षण दिनांक 25 नवंबर 2019)	दिनांक 23 सितम्बर 2017 के निरीक्षण पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी दिनांक 25 नवंबर 2019 के निरीक्षण में पाए गए सभी उल्लंघनों के लिए ₹ 7.00 लाख का सामूहिक जुर्माना
3	एचसीआर	रास्ता (25 नवंबर 2017)	रेस्तरां का नाम परिवर्तन, खुली छत पर शराब परोसी गई, कुल सीटें स्वीकृत 48 के प्रति 128 थीं, दो बार काउंटर चालू	₹ 7.00 लाख	हाँ	खुली छत पर शराब परोसी गई, दो चालू बार काउंटर, कुल सीटें स्वीकृत 48 के प्रति 116 पाई गईं (निरीक्षण दिनांक 17 फरवरी 2019)	₹ 9.37 लाख (सभी उल्लंघनों के लिए सामूहिक)
4	एचसीआर	हॉल ऑफ फेम (5 सितम्बर 2015)	रात्रि 1:00 बजे के बाद शराब परोसी गई , प्रवेश शुल्क योग्य	चेतावनी	हाँ	रेस्टोरेंट का नाम परिवर्तन, रात एक बजे के बाद शराब परोसी गई, बिना बारकोड वाली 17 शराब की बोतलें (निरीक्षण दिनांक 18 सितंबर 2016)	₹ 2.50 लाख सभी उल्लंघनों के लिए सामूहिक

क्र.सं.	लाइसेंस का प्रकार	केस संदर्भ (लाइसेंसी/निरीक्षण की तारीख)	निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाया गया	जुर्माने की राशि	क्या भविष्य में इस विशेष लाइसेंसधारी के लिए इसी तरह के उल्लंघन नोट किए गए हैं?	भविष्य के निरीक्षण के दौरान नोट किए गए उल्लंघन	जुर्माने की राशि
5	एचसीआर	हॉल ऑफ फ़ेम (18 सितंबर 2016)	रेस्टोरेंट का नाम परिवर्तन, रात एक बजे के बाद शराब परोसी गई, बिना बारकोड वाली 17 शराब की बोतलें	₹ 2.50 लाख	हाँ	रेस्तरां का नाम परिवर्तन , एल-16 स्टोर से जुड़ा ड्राई स्टोर (निरीक्षण दिनांक 15 अक्टूबर 2017) नाम परिवर्तन , दो चालू बार काउंटर, एल-16 स्टोर से जुड़ा ड्राई स्टोर (निरीक्षण दिनांक 24 जनवरी 2018) रेस्तरां का नाम परिवर्तन, विभिन्न दुकानों की 200 बोतलें (निरीक्षण दिनांक 12 अप्रैल 2018)	दिनांक 15 अक्टूबर 2017 एवं 24 जनवरी 2018 के निरीक्षण में कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभी उल्लंघनों के लिए ₹ 5.00 लाख सामूहिक (निरीक्षण दिनांक 12 अप्रैल 2018)
6	एचसीआर	हॉल ऑफ फेम (15 अक्टूबर 2017)	रेस्तरां का नाम परिवर्तन, ड्राई स्टोर एल-16 स्टोर से जुड़ा	कोई कार्रवाई नहीं	हाँ	नाम परिवर्तन, दो चालू बार काउंटर, एल-16 स्टोर से जुड़ा ड्राई स्टोर (निरीक्षण दिनांक 24 जनवरी 2018)	कोई कार्रवाई नहीं
7	एचसीआर	हॉल ऑफ फ़ेम (24 जनवरी 2018)	नाम परिवर्तन, दो चालू बार काउंटर, एल-16 स्टोर से जुड़ा ड्राई स्टोर	कोई कार्रवाई नहीं	हाँ	रेस्तरां का नाम परिवर्तन, अलग-अलग दुकानों की 200 बोतलें (निरीक्षण दिनांक 12 अप्रैल 2018)	सभी उल्लंघनों के लिए ₹ 5.00 लाख सामूहिक (निरीक्षण दिनांक 12 अप्रैल 2018)
8	रेस्टोरेंट	अनकल्चर्ड (5 अप्रैल 2019)	खुली छत पर परोसी गई शराब, एक्सपायर्ड बियर, स्वीकृत क्षमता से अधिक सीटें, अतिरिक्त बार काउंटर	₹ 3.96 लाख (एक्सपायर्ड बियर - ₹ 0.10 लाख, अतिरिक्त बार काउंटर - ₹ 0.10 लाख, अतिरिक्त सीटें - लाइसेंस शुल्क का 50% यानी ₹ 3.76 लाख)	हाँ	खुली छत पर शराब परोसी गई, स्वीकृत क्षमता से अधिक सीटें, अतिरिक्त बार काउंटर (निरीक्षण दिनांक 1 जून 2019) खुली छत पर परोसी गई शराब, स्वीकृत क्षमता से अधिक सीटें, अतिरिक्त बार काउंटर, अन्य विक्रेताओं की और क्षतिग्रस्त बार कोड वाली बोतलें (निरीक्षण दिनांक 25 फरवरी 2021)	₹ 8.37 लाख (अतिरिक्त बार काउंटर के लिए लाइसेंस शुल्क का 10%- ₹ 0.84 लाख, लाइसेंस शुल्क अंतर का 100%- ₹ 7.52 लाख) (निरीक्षण दिनांक 1 जून 2019) ₹ 9.70 लाख (अतिरिक्त सीट कवर के लिए ₹ 8.28 लाख, अतिरिक्त बार काउंटर के लिए लाइसेंस शुल्क का 10% - ₹ 0.92 लाख और खुले आसमान में परोसी जाने वाली शराब के लिए ₹ 0.50 लाख)

क्र.सं.	लाइसेंस का प्रकार	केस संदर्भ (लाइसेंसी/निरीक्षण की तारीख)	निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाया गया	जुर्माने की राशि	क्या भविष्य में इस विशेष लाइसेंसधारी के लिए इसी तरह के उल्लंघन नोट किए गए हैं?	भविष्य के निरीक्षण के दौरान नोट किए गए उल्लंघन	जुर्माने की राशि
9	रेस्टोरेंट	अनकल्चर्ड 1 जून 2019)	खुली छत पर शराब परोसी गई, स्वीकृत क्षमता से अधिक सीटें, अतिरिक्त बार काउंटर	₹ 8.37 लाख (अतिरिक्त बार काउंटर के लिए लाइसेंस शुल्क का 10%- ₹ 0.84 लाख, लाइसेंस शुल्क का 100% अंतर- ₹ 7.52 लाख)	हाँ	खुली छत पर परोसी गई शराब, स्वीकृत क्षमता से अधिक सीटें, अतिरिक्त बार काउंटर, अन्य विक्रेताओं की और क्षतिग्रस्त बार कोड वाली बोतलें (निरीक्षण दिनांक 25 फरवरी 2021)	₹ 9.70 लाख (अतिरिक्त सीट कवर के लिए ₹ 8.28 लाख, अतिरिक्त बार काउंटर के लिए लाइसेंस शुल्क का 10% - ₹ 0.92 लाख और खुले आसमान में परोसी जाने वाली शराब के लिए ₹ 0.50 लाख)
10	रेस्टोरेंट	मेसर्स डीए कोड (2 दिसंबर 2018)	रेस्तरां अनुमत समय से अधिक समय तक खुला पाया गया, कम उम्र के लोग शराब पी रहे थे, अधिक सीटें थीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया था।	₹ 3.99 लाख	हाँ	रेस्तरां अनुमत समय के पश्चात् खुला पाया गया, बोतल अन्य विक्रेता से संबंधित पाई गई, बिलिंग सिस्टम में जानबूझकर गलत समय निर्धारित किया गया था (निरीक्षण दिनांक 13 जून 2019)	आबकारी विभाग ने लाइसेंस रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने लाइसेंसधारक को नए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की इजाजत दे दी
11	रेस्टोरेंट	माई बार-मुख्यालय (24 नवंबर 2017)	दुकान के बाहर 50 पेटियां	₹ 0.10 लाख	हाँ	कम उम्र के लोगों को शराब परोसी गई, ब्रांड प्रमोशन, शराब का स्टॉक दुकान के बाहर रखा पाया गया (निरीक्षण दिनांक 8 नवंबर 2019)	सभी उल्लंघनों के लिए सामूहिक रूप से ₹ 1.00 लाख

अनुलग्नक XV
(पैराग्राफ 8.2.1 में संदर्भित)
कैबिनेट की मंजूरी और/या उपराज्यपाल की राय लिए बिना लिया गया फैसला

1. **निर्धारित समय के भीतर लाइसेंस शुल्क के भुगतान में किसी भी चूक के मामले में लाइसेंसधारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में छूट** - पॉलिसी के खंड 4.1.3 (iii) के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी सभी बकाया राशि (ब्याज और देरी से भुगतान के लिए जुर्माना सहित) का भुगतान महीने के आखिरी दिन तक करने में विफल रहता है तो सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा टेंडर किया जाएगा। हालाँकि, लाइसेंसधारी, नियमित रूप से, उस महीने के अंत तक भी लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे थे जिसमें सभी भुगतान देय थे। इस संबंध में, बकाया भुगतान में किसी भी चूक के कारण लाइसेंस रद्द करने की दंडात्मक कार्रवाई को उत्पाद वर्ष 2021-22 के अंत तक स्थगित रखा जाने का प्रस्ताव विभाग द्वारा 20 जनवरी 2022 को अनुमोदित किया गया था। यह निर्णय कैबिनेट की मंजूरी और उपराज्यपाल की राय के बिना लिया गया और लागू किया गया। उल्लेखनीय रूप से, दो लाइसेंसधारियों ने जैसा कि पैराग्राफ संख्या 8.5.4 में उल्लिखित हैं, लाइसेंस शुल्क के भुगतान में चूक की।
2. **लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी -** लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹ 144 करोड़ की छूट जनवरी 2022 में डीडीएमए के आदेशों के तहत लगाए गए कोविड प्रतिबंधों के कारण कैबिनेट की मंजूरी के बिना खुदरा लाइसेंसधारियों को दी गई।
3. **नॉन-कॉन्फार्मिंग वार्डों में खोली जाने वाली अनिवार्य शराब की दुकानों के बदले कॉन्फार्मिंग क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलना-** उपराज्यपाल ने नॉन-कॉन्फार्मिंग वार्डों में शराब की दुकानें खोलने के मुद्दे की जांच के लिए डीडीए के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था तथा उचित सिफ़ारिशें दी थी। समिति ने नॉन-कॉन्फार्मिंग वार्डों में आने वाली दुकानों के बदले कॉन्फार्मिंग वार्डों में अतिरिक्त दुकानें खोलने की सिफारिश की। इसके बाद, लाइसेंसधारियों को कैबिनेट की अपेक्षित मंजूरी या उपराज्यपाल की राय के बिना, एक महीने की अवधि में नॉन-कॉन्फार्मिंग वार्डों के बदले में अतिरिक्त दुकानें खोलने की अनुमति दी गई।

4. **आबकारी नीति 2021-22 का विस्तार-** दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के नियम 34(2) के अनुसार, "सरकार किसी भी वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले किसी भी गैर-नवीकरणीय लाइसेंस (जैसे थोक लाइसेंस) की अवधि को आगे की अवधि या निर्धारित की गई फीस का अग्रिम भुगतान करने पर उचित समझी जाने वाली अवधि के लिए बढ़ा सकती है। हालाँकि, आबकारी नीति 2021-22 (जिसमें गैर-नवीकरणीय लाइसेंस भी शामिल था) को शुरू में 31 मई 2022 तक और फिर 31 जुलाई 2022 तक कैबिनेट की मंजूरी या उपराज्यपाल की राय लिए बिना बढ़ा दिया गया था।

5. **एयरपोर्ट जोन के मामले में बयाना राशि जमा (ईएमडी) की वापसी** - एयरपोर्ट जोन के लिए निविदा 28 जून 2021 को जारी की गई थी। इसके बाद, बोली पूर्व प्रश्नों के जवाब में, 9 जुलाई 2021 को आदेश दिया गया कि यदि आवेदक 30 दिनों के भीतर हवाई अड्डे के अधिकारियों से शराब की दुकानें खोलने के लिए एन ओ सी प्रति करने के विफल रहता है तो (ईएमडी) वापस कर दिया जाना चाहिए।

6. **विदेशी शराब के मामले में एमआरपी की गणना के सूत्रों में सुधार** - 1 नवंबर 2021 को बियर और विदेशी शराब की दरों की गणना के लिए सूत्रों में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव को मंजूरी देते समय यह उल्लेख किया गया था कि जीओएम और कैबिनेट द्वारा अनुसमर्थन बाद में किया जा सकता है। यह दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 54(1) का उल्लंघन था, जिसके अनुसार प्रत्येक लाइसेंस वर्ष के लिए शराब के थोक या एमआरपी के निर्धारण के मानदंड सरकार यानि उपराज्यपाल की मंजूरी के साथ उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा तय किए जाएंगे।

अनुलग्नक XVI
(पैराग्राफ 8.4.3.1 में संदर्भित)
क्रॉस स्वामित्व

लाइसेंसधारी का नाम	लाइसेंसधारी प्रकार	इकाई के साथ जुड़ाव	जुड़ी हुई इकाई के प्रकार	टिप्पणी
महादेव लिकर्स	एल1	मेडुसा बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	निर्माता/ डिस्टलर्स	सनी मारवाह, महादेव लिकर में पार्टनर हैं और अगस्त 2019 तक मेडुसा बेवरेजेज में निदेशक थे।
महादेव लिकर्स	एल1	जेमिनी डिस्टिलरीज (पटियाला) प्राइवेट लिमिटेड	निर्माता/ डिस्टलर्स	महादेव लिकर के पार्टनर अर्पण सूद अप्रैल 2021 तक जेमिनी डिस्टिलरीज, पटियाला के निदेशक थे।
महादेव लिकर्स	एल1	भगवती ट्रांसफार्मर निगम	एल7जेड	महादेव लिकर में पार्टनर सनी मारवाह कुलविंदर नाथ मारवाह के बेटे हैं जो भगवती ट्रांसफार्मर कॉर्प में पार्टनर हैं। सनी मारवाह जुलाई 2021 के पार्टनरशिप डीड के अनुसार भगवती ट्रांसफार्मर कॉर्प में एक सेवानिवृत्त पार्टनर भी हैं।
मैसर्स इंडोस्पिरिट्स	एल1	इंडोस्पिरिट बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	निर्माता/ डिस्टलर्स	इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से मेसर्स इंडोस्पिरिट्स में पार्टनर समीर महंद्रू जून 2019 तक इंडोस्पिरिट बेवरेजेज के निदेशक भी थे। इंडोस्पिरिट बेवरेजेज के निदेशक विभूति शर्मा जुलाई 2021 तक इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन के निदेशक थे।
मैसर्स इंडोस्पिरिट्स	एल1	इंडोस्पिरिट बार्स प्राइवेट लिमिटेड (एचसीआर)	एचसीआर	गीतिका महंद्रू इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन में निदेशक हैं जो इंडोस्पिरिट बार्स को एक सहयोगी कंपनी घोषित करता है।
मैसर्स इंडोस्पिरिट्स	एल1	खाओ गली रेस्तरां प्राइवेट लिमिटेड	एल7जेड	श्याम कुंदन लाल कपूर (खाओ गली के निदेशक) 2021 में करमचंद डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स (इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की एक संबद्ध कंपनी) के निदेशक थे। इंडोस्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन मेसर्स इंडोस्पिरिट में पार्टनर है।
पोपुलर स्पिरिट्स	एल7जेड	बडी (पंजाब) बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड	निर्माता/ डिस्टलर्स	साहिल अरोड़ा जुलाई 2021 तक बडी (पंजाब) बॉटलर्स के निदेशक थे।
पोपुलर स्पिरिट्स	एल7जेड	बडी (टी1डी) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	एल7जेड	साहिल अरोड़ा बडी (टी1डी) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड में जुलाई 2021 तक के निदेशक थे।
केएसजेएम स्पिरिट्स	एल1	बडी (टी1डी) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	एल7जेड	अमित अरोड़ा, (टी1डी) रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के सक्रिय निदेशक हैं जो केएसजेएम स्पिरिट्स के जुलाई 2021 तक पार्टनर है।
केएसजेएम स्पिरिट्स	एल1	बडी (पंजाब) बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड	निर्माता/ डिस्टलर्स	अश्वनी भाटिया को जुलाई 2021 तक केएसजेएम स्पिरिट्स में पार्टनर और बडी (पंजाब) बॉटलर्स में निदेशक नामित किया गया था।
नोवा गारमेंट्स	एल7जेड	ओएसिस डिस्टिलरीज लिमिटेड	निर्माता/ डिस्टलर्स	मार्च 2021 तक नोवा गारमेंट्स में निदेशक इरावत सिंह ओएसिस डिस्टिलरीज में एक सक्रिय निदेशक हैं। वह नोवा गारमेंट्स की दो शेयरधारक कंपनियों (संधू इलेक्ट्रॉनिक्स और गणपति डिटर्जेंट) में एक सक्रिय निदेशक भी हैं।
गौतम वाइन	एल1	ओएसिस डिस्टिलरीज, और विजेता बेवरेजेज लिमिटेड	निर्माता/डिस्टलर्स	डिंपी मल्होत्रा, गौतम महोल्ट्रा आदि की सामान्य शेयरधारिता और प्रबंधन।

लाइसेंसधारी का नाम	**लाइसेंसधारी प्रकार**	**इकाई के साथ जुड़ाव**	**जुड़ी हुई इकाई के प्रकार**	**टिप्पणी**
ऑर्गनोमिक्स इकोसिस्टम	एल7जेड	नेथ्रावती डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड	निर्माता/ डिस्टलर्स	वैभव डुव्वुर जुलाई 2021 तक ऑर्गनोमिक्स के निदेशक और जून 2021 तक नेथ्रावती डिस्टिलरीज के निदेशक थे।
रायसेन मार्केटिंग	एल7जेड	सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड	निर्माता/ डिस्टलर्स	सोम ग्रुप 2019-20 में रायसेन मार्केटिंग का प्रमोटर था। बाद में सोम डिस्टिलरी का एक शेयरधारक (अविनाश चलाना) चालन एंड कंपनी के माध्यम से रायसेन मार्केटिंग में बहुसंख्यक हितधारक था।
खाओ गली रेस्तरां पाइवेट लिमिटेड	एल7जेड	मगोंता एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड	एल7जेड	खाओ गली रेस्तरां के लिए, ईएमडी का एक हिस्सा (₹ 15 करोड़) ज़ैनब ट्रेडिंग द्वारा भुगतान किया गया था तथा मैगुंटा एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए ईएमडी का भुगतान हाईवाइड इंटरप्राइज (₹ 5 करोड़), प्राइमस एंटरप्राइजे (₹ 30 करोड़) तथा बबली ब्रुअरिज (₹ 25 करोड़) द्वारा किया गया था। विशेष रूप से, ज़ैनब ट्रेडिंग और हाईवाइड एंटरप्राइज एक ही व्यावसायिक पता और एक ही निदेशक साझा करते हैं। इसी तरह, बबली ब्रुअरीज, खाओ गली रेस्तरां के साथ एक ही व्यावसायिक पता साझा करते है तथा यह पिछले निदेशक के माध्यम से इंडोस्पिरिट समूह की कंपनियों से जुड़ा हुआ है।

अनुलग्नक XVII
(पैराग्राफ 8.6.2 में संदर्भित)
नॉन कॉन्फार्मिंग वार्डों में खुले जोन-23 की दुकानें

क्र.सं.	क्षेत्र	वार्ड	पता	दुकान की स्थान स्थिति के संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण की तारीख और दुकान के स्थान की प्रदान की गई स्थिति	लाइसेंस जारी करने की तिथि	वार्ड के कॉन्फार्मिंग न होने पर एमसीडी ने दुकान सील कर दी
1	23	33 एन	प्लॉट नं 1, खसरा नं. 10/9, जीएफ, ब्लॉक-बी, राजीव नगर, ग्राम बेगमपुर, दिल्ली-110086	1. शपथपत्र 2. आवेदन पत्र में प्रस्तावित दुकान के परिसर की भूमि के रूप में मिश्रित भू-मि उपयोग बताया गया 3. वाणिज्यिक सड़क की यूडी अधिसूचना - सेक्टर -18 रोहिणी आंतरिक सड़क - बी -8/64 से बी -2/1 तक।	8 नवंबर 2021 कॉन्फार्मिंग क्षेत्र	19 नवंबर 2021	हाँ, जनवरी 2022 में
2	23	97 एस	दुकान नं. 5,6,7,8 जीएफ, आई-ब्लॉक, गली नंबर 21, मेन टंकी रोड नगर मार्केट, हरि नगर एक्सटेंशन - III, दिल्ली - 110044	1.शपथपत्र 2. आवेदन पत्र में प्रस्तावित दुकान के भू-उपयोग परिसर के रूप में आवास 3. वाणिज्यिक सड़क-मुख्य बदरपुर बाजार, बदरपुर की यूडी अधिसूचना बताया गया	8 नवंबर 2021 व्यावसायिक	23 नवंबर 2021	हाँ, फरवरी 2022 में
3	23	30 एस	ए-49-ए, दशरथ पुरी, दिल्ली-110045	1. शपथपत्र 2. प्रस्तावित दुकान के भू-मि उपयोग परिसर का व्यावसायिक बताया गया है। 3. एमसीडी कन्वर्जन चार्ज स्लिप और हाउस टैक्स स्लिप।	8 नवंबर 2021 रूपांतरण पर्ची के आधार पर कॉन्फार्मिंग क्षेत्र	16 नवंबर 2021	हाँ, जनवरी 2022 में
4	23	30 एस	1-ए, खसरा नंबर 14/13, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल, ग्राम डाबरी कॉलोनी, हरिजन बस्ती, दिल्ली-110045	1. शपथपत्र 2. प्रस्तावित दुकान के भूमि उपयोग 3. परिसर को यूडी अधिसूचना में व्यावसायिक सड़क बताया गया है अम्बेडकर स्मृति स्मारक से एसके टेलीकॉम सेंटर (आरएचएस)	8 नवंबर 2021 कॉन्फार्मिंग क्षेत्र	17 नवंबर 2021	हाँ, जनवरी 2022 में

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in